(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक- 1 नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का नवम् दिवस संख्या-7

शुक्रवार,

23 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

[श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 35

पाली जिले के हैण्ड पम्प

35. **श्री अचला राम (देसूरी) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुए है ? कितने हैण्ड पम्प उपयोग में आ रहे हैं ? कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? कितने हैण्ड पम्पों में पानी नहीं है और असफल है ? कितने हैण्ड पम्पों में फ्लोराइड वाटर है ?

(2) जहां पर हैण्ड पम्प असफल हैं, नलों द्वारा या वाटर टैंक द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पेयजल की क्या व्यवस्था की जायेगी ? संख्या सची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जवाई बांध या हेमावास बांध या अन्य किन्हीं बांधों से पाली जिले के लिये पेयजल की व्यवस्था करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी : (श्री मोहन मेघवाल) (1)-माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में कुल 3268 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं। इनमें से 2858 हैण्ड पम्प उपयोग में आ रहे हैं। 410 हैण्ड पम्प काम में नहीं आ रहे है। इनमें से 78 हैण्ड पम्प में पानी सूख गया है व 332 हैण्ड पम्प विभिन्न तकनीकी कारणों से ठीक नहीं किए जा सकते हैं। 157 हैण्ड पम्पों के पानी में 3 मिलिग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा है।

(2) जिन गांवों में हैण्ड पम्प असफल हो गये हैं उनमें हैण्ड पम्प पुनः खुदवाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूची के लिए: कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि जवाई बांध

(श्री अचला राम)

और हेमावास बांध या अन्य किन्हीं बांधों से पाली जिले के लिए पेयजल की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है या है। जवाई या हेमावास बांध से किन-किन गांवों में पेयजल की व्यवस्था होगी? क्या इन गांवों की सूची प्रस्तुत हुई है?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची आपको दी है, संलग्न है वह आपने देख ली होगी। जवाई बांध और हेमावास बांध की व्यवस्था करने का विचार है, उसका सर्वेक्षण हो गया है और शीघ्र ही इस योजना में हम काम चालू करने वाले हैं।

श्री अचला राम : पेयजल की जो व्यवस्था है किसी टेंकर द्वारा या कोई पेयजल की लाइन डालकर की जायेगी या किस तरीके से होगी?

श्री भंवर लाल शर्मा : वैसे तो लाइन डाल करके करेंगे लेकिन आवश्यकता पड़ी और उस समय तक अगर नहीं हुआ तो टेंकर से व्यवस्था करेंगे।

श्री अचला राम : जब तक लाइन की व्यवस्था नहीं हो तब तक टेंकर की व्यवस्था हो जाय तो बड़ी सुविधा होगी मंत्री महोदय।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सदस्य मैं यह मानता हूं कि इस काम में थोड़ी देरी हुई है लेकिन अब जितनी गति से हम कर सकेंगे, करेंगे और अगर ऐसा लगा कि यह कार्य पूरा नहीं हुआ और पानी की कमी रहेगी तो फिर टेंकर से, किसी व्यवस्था से हम यह व्यवस्था करेंगे ताकि पानी समय पर मिल जाय।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जलदाय विभाग के अन्तर्गत जो हैण्ड पम्प बांटे थे उनके रख रखाव का जो अमाउण्ट था उसको पंचायत समिति को यह कह कर कि हम डी–सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं और वह अमाउण्ट भी उधर ट्रान्सफर कर दिया। हालत माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में यह हो गयी कि न तो इन हैण्ड पम्पों को जलदाय विभाग देखता है और पंचायत समितियों के पास जो मिस्त्री रखे हुए हैं वे इतने अन–ट्रेण्ड होते हैं, शार्ट ट्रेनिंग पाये हुए होते हैं कि उनकी मरम्मत नहीं कर पाते। दूसरा, मेरा प्रमुख सवाल है कि जो मेजर डिफेक्ट हैण्ड पम्प में पैदा होते हैं वह विभाग करता है और माइनर डिफैक्ट छोटा छोटा होता है, कहीं नट बोल्ट कसने होते हैं जिनको जो पंचायत समिति में मिस्त्री रखे हुए हैं वे करते हैं। इस प्रकार इस दोहरी व्यवस्था के कारण हैण्ड पम्प की मशीनरी ओपन पड़ी रहती है। न तो इसके ताला होता है और न ही कोई कूंदा होता है। बच्चे खड़खड़ाते हैं और औरतें भी खड़खड़ाती रहती है। इस प्रकार से ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं हम जब कभी भी गांवों में जाते है तो हर गांव में यह शिकायत मिलती है कि हैण्ड पम्प चालू नहीं हैं, हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो व्यवस्था पंचायत समितियों या पंचायतों की दी गई है इसको वापस

(श्री हीरासिंह चौहान)

विभाग में ली जावे और विभाग में देने के बाद पुनः सारा रिपेयर का काम एक मेजर अभियान चलाया जाकर किया जाय होता क्या है कि पिछले दिनों में पूर्व सरकार ने अभियान चलाया, किसी जगह बडे-बडे जो हैण्ड पम्प के डिफेक्ट्स हो रखे थे वे ठीक नहीं हुए और हर जगह शिकायत वैसी की वैसी रही। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि राज्य सरकार इस व्यवस्था को रद्दोबदल करके पुनः पेयजल विभाग के अण्डर में दिया जाय। दूसरा निवेदन है, एक टी. एस. एस. की योजना और है, ग्रामीण जलदाय जिसको पंचायतें चलाती है। यह भी पिछली सरकार ने घोषणा की थी। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इसको भी वापस सरकार लेवे।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि पाली जिले के अन्दर गांवों में पेयजल योजना स्वीकृत है। पर विशेष परिस्थितियों में उन अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जहां पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, पाइप लाइन नहीं है, क्या राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों को नजर रखते हुए हैण्ड पम्प उन बस्तियों में खुदवाकर पेयजल समस्या का समाधान रखने का विचार रखती हैं ?

श्री टीकम चन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ हैण्ड पम्पों में क्लोराइड ज्यादा है विशेष कर पाली, सिरोही जालोर इन क्षेत्रों के अन्दर पानी के अन्दर क्लोराइड की मात्रा आवश्यकता से अधिक है उसके कारण कई रोग फैलते हैं। तो क्या यह तय है कि सभी हैण्ड पम्पों का पानी हम टेस्ट करवायेंगे और अगर नहीं करवाते हैं तो क्या पुनः हम व्यवस्था कर पायेंगे कि सारे हैन्ड पम्पों का पानी पीने योग्य है या नहीं है। इस प्रकार का सर्वेक्षण हो पायेगा ?

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न रखे हैं, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि हैण्ड पम्प के रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायत समितियों को दी हुई है। एक हैण्ड पम्प को ठीक करने के लिए 200 रुपया प्रति हैण्ड पम्प पंचायत समिति को देते है। उस व्यवस्था में सन्तोषद काम नहीं होता है इसलिए जब कल हमारी विभाग की बैठक थी उसमें यह तय किया गया 15 अप्रैल तक जितने भी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और जो ठीक किये जा सकते हैं, पी. एच. ई. डी. एक अभियान चला करके 15 अप्रैल तक ठीक करा दें, और 15 जुलाई तक यह व्यवस्था विभाग के पास ही रहेगी। इस बीच में यदि कोई खराबी होती है या कोई आवश्यकता पड़ती है तो यह विभाग ही इसकी देखरेख करेगा। 15 जुलाई के बाद यह व्यवस्था किसके पास रहेगी, पी. एच. ई. डी. करे या पंचायत करे यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है, जिस पर विचार किया जावेगा। (व्यवधान)

(श्री भंवर लाल शर्मा)

यहां आपने कहा कि हरिजन मोहल्लों में क्या व्यवस्था की जायेगी। यह तो हरिजन मोहल्लों में व्यवस्था करते ही हैं उसको अलग नहीं रखते फिर भी यदि आपके ध्यान में कोई ऐसा मोहल्ला बचता हो कि जहां विभाग उसको देख नहीं सका हो, देखने से रह गया हो और व्यवस्था न हो तो आप बता दे, कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। हरिजन मोहल्लों में तो पहले करेंगे।

जहां तक आपने कहा कि तीन मिलिग्राम प्रति लीटर से अधिक क्लोराइड की मात्रा है। इस बारे में कुछ तथ्य सामने आये हैं। आपका सुझाव ठीक है। वह जांच करवा कर अगर पेयजल पीने योग्य नहीं है, पीने से कोई बीमारी होती है तो फिलहाल उसका उपयोग कम से कम पीने के लिए नहीं हो यह व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार। जैन

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि 15 अप्रैल तक एक अभियान चला कर हम इन हैण्ड पम्पों को ठीक कर रहे है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय के पास जैसाकि पाली जिले और सभी जिलों की रिपोर्ट है और सभी विधायकों ने यह रिपोर्ट दी है कि आधे से अधिक हैण्ड पम्प पूरी गहराई तक नहीं खोदे जाने की वजह से खराब पड़े हैं। क्या 15 अप्रैल तक ऐसे सारे हैण्ड पम्पों को भी आप पूरी गहराई तक खुदवा देंगे और कितनी मशीनों का आपने इंतजाम कर दिया है और हर जिले में कितनी मशीनें भिजवा दी हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय हरि कुमार जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय ने एक नीति संबंधी बात कही है कि 15 अप्रैल तक जितने हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, सब ठीक करा दिये जायेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस कार्यक्रम के अन्दर उस क्षेत्र के जो जन प्रतिनिधि हैं, उनका भी इन्वोल्व होना चाहिये वर्ना इनके डिपार्टमेंट के लोग लिखाते क्या है और शिकायत लोगों की बराबर बनी रहती है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात का भी ख्याल रखा जावे कि इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों का इन्वोल्वमेंट बराबर होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंह।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी में यह बात है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के बैनपुरा गांव में क्लोराइडयुक्त पानी पीने से वहां के जन्म लेने वाले हर व्यक्ति 15 साल की किशोरावस्था में आते आते, कुबड़ेपन का शिकार हो जाते हैं? आज तक पत्र-पत्रिकायें इस बात को लिखती रही हैं, सदन में भी यह मामले उठते रहे हैं, आज तक कोई भी इसका कारगर हल ढूंढ़ा

(श्री गुलाब सिंह)
नहीं गया। सांडेराव से वहां की पेय-जल के लिये जो पाइप लाइन है. ले ली गयी. क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि वह पाइप लाइन कहीं लगी हुई है, पानी उसमें एक बूंद भी नहीं आ रहा है, इसका जवाब दें और इसका हल अब निकालेंगे इस बात की जानकारी सदन को दी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मन्त्री महोदय ने बताया कि चार हजार में से केवल चार सौ हैंडपप असफल हैं या पानी कम है। क्या यह सही है और आपकी रिपोर्ट में है ? मेरे हिसाब से, मैं समझता हूं कि यह जो आपने रिपोर्ट बतायी है 6 महीने 12 महीने पहले की होगी। बाकी अब तो जो हैंड पप है, तीन चार साल से अकाल है, पानी नीचे चला गया। कहीं खोदने में कमी रही है, ऐसी स्थिति में केवल आपने चार सौ हैंड पंप ही असफल और खराब बताये हैं, ये आपके आंकड़े सही नहीं है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो जवाई बांध से पाली जिले की स्कीम बनाने की बात आपने बतायी है, आपको मालूम है अप्रेल के अंत में जवाई बांध में पानी बिल्कुल एक छांट नहीं रहेगा। जब यह स्थिति आज है, तो फिर आप एक नई स्कीम बना करके रोहित और लूणी क्षेत्र के अन्दर जो सौ, सवा सौ गांव हैं, जिनकी जवाई बांध से स्कीम बनाई हुई है और उसके बाद में मई, जून के अन्दर त्राहि, त्राहि मच जायेगी, पूरे एरिये के अन्दर। यह तो जवाई बांध की स्थिति है। उनमें जो आपने उन गांवों को जोड़ने की जो योजना बनाई है आप पानी कहां से लायेंगे और पानी इस तरह उपलब्ध करायेंगे, तो क्या आप आइन्दा सिंचाई के अन्दर कितना पानी रहना चाहिये, पीने के लिये कितना पानी रहना चाहिये, इस तरह की कोई सीमा तय करेंगे ? बाकी तो आपकी पाली से आने वाली माननीय विधायिका, जो आज मन्त्री है, उन्होंने आपको मालूम है, पहले हड़ताल की थी। यहां पर कई बातें की हैं कि नहीं भई, किसानों को पानी दिया जाना चाहिये। हम भी किसानों के पक्ष में है। एक तरफ तो आप किसानों की पैरवी भी करते हैं, दूसरी तरफ आप पानी की योजना बना कर पूरे पाली जिले को पानी देना चाहते हैं। आखिर आपके क्या इरादे हैं ? किस तरह से पानी देना आप उचित समझेंगे और क्या स्थिति बनेगी, उस को आप स्पष्ट बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय गहलोत जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसी उन्होंने योजना बतायी है कि 15 अप्रेल तक सब पूरा कर दिया जायेगा, लेकिन मैं यह भी पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो हैंड पम्प ड्राई हो गये, जो कि अब बिल्कुल ठीक होने के लायक नहीं रहे, उन ड्राई हैंड पम्पों को भी क्या बदलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? या क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होगा ? वहां मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी बना कर उसका पूरे राजस्थान में यह बनाने की बात आपने कही है, वह तो स्वागत योग्य है, लेकिन ड्राई हैंड पंपों

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत) को बदलने के बारे में आपका क्या इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंह ।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों से सेंडीय एरिया में हैंड पम्प खोदे नहीं गये । आपके अधिकारियों से पूछने से यह मालूम हुआ कि सेंडीय एरिये के अन्दर खोदने की मशीनें उपलब्ध नहीं थीं । क्या राज्य सरकार सेंडीय एरिये के अन्दर खोदने को मशीनें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्या जी ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वैसे तो ठीक है कि गर्मी आ रही है और इसलिये इसकी युद्ध स्तर पर जो योजना चल रही है, वह चलती रहेगी । उसमें विशेष कोई परिवर्तन अभी करना उचित भी नहीं है, परन्तु क्या यह सही है कि अधिकांशत: पानी जमीन के नीचे जाने की वजह से हैंड पंपों में पानी खराब आने लगा है । जमीन के भीतर के केमिकल्स आने लगे हैं, क्लोराइड भी आने लगा है, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों की और विभाग की गड़बड़ी की वजह से अधिकांशत: हैंडपम्प्स इनकम्प्लीट भी पड़े हैं । जो हैंड पम्प एबंडन कर दिये जाते हैं, उनको तो हटा दिया जाता है, उसमें रोड्स रह जाते हैं । परन्तु उनको कम्प्लीट कर, दूसरा नहीं लगाया जाता है । गर्मियां आने वाली हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आने वाली है । तो क्या यह सही नहीं है कि हैंड पंपों की योजनायें स्वयं में ही नानफिजीबल है और बिल्कुल गलत योजना है जिसको दुबारा सोचे जाने की जरूरत है । विभाग और सरकार ने ऐसा लगता है कि हैंड पम्प अर्थात् वाटर सप्लाई की कोई सोच को सोचना ही बंद कर दिया । यह अनइकोनोमिकल और बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने खराब हैंड पम्प के आंकड़ों को चुनौती दी है कि कितने हैंड पम्प में पानी आ रहा है, कितने खराब पड़े हैं और कितनी सर्विसेज में नहीं हैं, यह आंकड़े आपकी सरकार ने तैयार किया था, मुझे खुशी है कि आप अपने ही सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे रहे हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर गलत आंकड़े दिये, तो हमारी उपलब्धि ही यही है । आपको जांच करनी चाहिये नेता महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जांच कर रहा हूं, यही माननीय सदस्य, कि आपकी सरकार ने जो गलत आंकड़े दिये, वे कितने गलत हैं, इसकी मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा । बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अपने पास तो अब ठन ठन गोपाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत आंकड़े देने, यदि आपकी उपलब्धि है, तो मैं समझता हूं, आपको इस उपलब्धि के लिये बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया, जवाई और हेमावास के सम्बन्ध में कि सिंचाई के लिये कितना पानी निर्धारित होगा और पीने के पानी के लिये कितना निर्धारित होगा लेकिन इस समय राजस्थान में पीने के पानी का जिस प्रकार का संकट है, उस संकट को देखते हुए मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि पीने के पानी को प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये कि पंचायत समितियों को देने के कारण से इनकी समय पर रिपेयर नहीं हुई, इसको मैं भी महसूस करता हूं। पिछली सरकार ने किन परिस्थितियों में आकर इस प्रकार का निर्णय लिया था, और पंचायत समितियों को देकर किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने करनी चाही थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। मोटे रूप से हमने कल की बैठक में यह फैसला किया है कि 15 अप्रेल तक जो हैंड पम्प खराब हो गये हैं और जिनकी थोड़ी बहुत भी रिपेयर करने के कारण यदि उनमें पानी आ सकता है, तो, 15 अप्रेल तक उन हैंड पम्पस् को विभाग से मरम्मत करायी जाये और उनकी रिपेयर्स करायी जाये। इससे कुछ स्थानों पर रिलीफ मिलेगी। जहां तक सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हैंड पम्प की योजना ही ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। आखिर तत्काल लोगों को पानी कहीं उपलब्ध कराने के लिये कुएं खोदने में कितना समय लगता है, बाकी की समस्याओं का समाधान करने में कितना समय लगता है, तो कई बार इमरजेंसी में हैंड पम्पस भी आवश्यक हो जाते हैं और खुदवाये जाते हैं। इसलिये इस दृष्टि से विचार करेंगे कि हैंड पम्पस् की योजना कितनी लाभकारी रहती है, भविष्य में कितनी लाभकारी रहेगी, इसको बता रहा हूं....।

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब आपने ठीक दिया है, हैंड पम्प का दुरूपयोग तो आप समझ ही गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि मैंने और आपने दोनों ने इस हैण्ड पम्प योजना के बारे में क्या-क्या कहा, आपको भी मालूम है और मुझे मालूम है, इसलिये उस चीज को दुहराइये नहीं तो ज्यादा अच्छा है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्या ने यह भी कहा कि कुछ केमिकल्स जो हेल्थ के लिये हानिकारक है, वे केमिकल्स पानी में आने लग गये हैं, यह सम्भव हो सकता है, मैं कोई इसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारा प्रयास यह होगा कि इस प्रकार के दूषित पानी को लोगों को न देकर हम शुद्ध पानी उनको दे सकें, उसकी चेष्टा करें। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का एक सबसे बड़ा संकट आज राजस्थान में है। मैं सबसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अधिक प्राथमिकता पानी उपलब्ध कराने के काम को दूंगा। इस पर कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की विषम परिस्थितियों में हम फंस गये है, आप तत्काल उसका उपचार करना चाहें, तो भगवान ही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यह प्रयास होगा कि सरकार के जितने साधन हैं, उन साधनों को, चाहे मुझे डाइवर्ट करना पड़े और कहीं से साधन लाना पडे, चाहे लोगों से भीख मांगनी पड़े, कर्जा लेना पड़े राजस्थान की पानी की समस्या का समाधान कराने की चेष्टा करूंगा, इससे ज्यादा आश्वासन मैं नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय चुन्नीलाल जी।

खण्डार से रामेश्वर तक सड़क निर्माण

36. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) सवाई माधोपुर जिले की तहसील खण्डार में खण्डार से रामेश्वर तक बनने वाली सड़क की पूर्ण होने की अवधि क्या थी ? इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? इस अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने हेतु किस ठेकेदार को ठेका दिया गया ?

(2) क्या उस ठेकेदार ने निर्धारित अवधि में निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुरूप सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो उस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या इस सड़क में घटिया सामग्री प्रयोग में लाई गई ?

(5) क्या इस सड़क के ठेकेदार को बिना निर्धारित अवधि व मापदण्ड तथा निर्माण कार्य कराये बिना ही भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(6) अब सरकार का उक्त सड़क को कब तक पूर्ण कराने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री
(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) सवाई माधोपुर जिले की तहसील खण्डार में, खण्डार से रामेश्वर घाट तक बनने वाली सड़क को कि. मी. 05.0 से 10.5 तक पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष है। उक्त सड़क के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रुपये 10.50 लाख है। सड़क का कार्य करवाने के लिए श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, ठेकेदार, विचपुरी वाले को ठेका दिया गया है।

(2) उक्त कार्य को पूरा करने की निर्धारित अवधि एक साल है तथा पूर्ण

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

होने का निर्धारित दिनांक 16-8-1990 है। कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराया जा रहा है।

(3) निर्धारित अवधि के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 16-8-1990 है, अतः कार्य प्रगति पर है। धीमी गति से कार्य करने के कारण ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है।

(4) उपलब्ध सूचना के अनुसार घटिया सामग्री प्रयोग में नहीं लाई गई है।

(5) जी नहीं। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि एक वर्ष है। कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराया जा रहा है। ठेकेदार को रनिंग भुगतान उसके द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के अनुसार किया जाता है। चूंकि अभी कार्य प्रगति पर है अतः फिलहाल जिम्मेदारी निर्धारित करने वाली स्थिति नहीं है।

(6) किलोमीटर 5 से किलोमीटर 10.5 तक की सड़क को वर्ष 1990-91 में पूर्ण किये जाने की आशा है।

श्री चुन्नी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को जनता गवर्नमेंट शासन में सेंक्शन मिली थी, उसके बाद में दो टुकड़ों में जो इसका कार्य चला है, कुल मिलाकर टोटल जो डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भेजी है यह कतई निराधार है। जहां सड़क पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है और मिट्टी भी बरसात से बह चुकी है, बिल्कुल समतल जमीन पड़ी हुई है और यह जो ठेकेदार है यह पंचायत समिति खण्डार के वर्तमान प्रधान केशव चन्द्र शर्मा का भतीजा है और अब तक जितने भी पेमेण्ट उठाये गये हैं वह अफसरों की मिली-भगत से उठाये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसकी अगर जांच करवा ली जाय तो ज्यादा अच्छा है ताकि सारा नतीजा सरकार के सामने आ जायेगा और सड़क की प्रगति जिन अधिकारियों ने बताई है उनको भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस सड़क को बनने में कुल पांच माह का समय और शेष रह जाता है। 16-8-90 को इस सड़क को पूर्ण होने का सरकार ने जो वादा किया है, यह 16-8-90 तक किसी भी स्थिति में सड़क पूर्ण नहीं सकती। यह रिपोर्ट जो भेजी है। यह बिल्कुल असत्य है और इसकी जांच करवा कर इस रोड़ का काम दूसरे ठेकेदार को देकर दोबारा करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि 14-6-78 को इस सड़क के लिए 0 से 5 किलोमीटर तक की स्वीकृति पांच लाख रुपये की की गई और उसमें उसी वर्ष 0 से 5 किलोमीटर तक की डामर सड़क का निर्माण करवा दिया गया। इस सड़क की कुल लम्बाई 17.60 किलोमीटर है। 0 से 5 तो जनता राज के समय वह सड़क बन गई। 5 से 10.5 तक की जो स्वीकृति है इसके लिए बहुत समय लगा है। वह बात मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। 14-6-1984 को सबसे पहले साढ़े दस लाख रुपये की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई, 1984 में स्वीकृति करने के बाद लगातार इसमें विभिन्न प्रकार की बातें।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रही। यह देरी क्यों हुई है, क्यों रही, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा। उसके पश्चात् जैसा मैंने मेरी जानकारी के अनुसार, विभाग की जानकारी के अनुसार बताया कि एक वर्ष में यह काम 5 किलोमीटर से 10.5 किलोमीटर का हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा कि जो जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई उसमें अगर कमी है तो न केवल जांच की जायेगी किन्तु गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध भी एक्शन लिया जायेगा। जिन्होंने काम नहीं किया है, गलत पेमेण्ट लिया है उनके विरुद्ध भी लिया जायेगा और अगर इस सारे कोड के अनुसार ऐसा लगा कि ठेकेदार को बदलना आवश्यक है तो वह भी किया जायेगा। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि साढे दस किलोमीटर तक की तो हमारी योजना है, यह 17.60 किलोमीटर है और इसके लिए मैंने 90-91 कहा है, मैं जानता हूं कि रामेश्वर घाट एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और मेला भरने पर लाखों लोग वहां तक जाते हैं। किसी भी हालत में 91-92 तक इस सड़क को पूरा करा कर उन लोगों को राहत देने की हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37.

जालोर में ग्रेनाइट काम्पलेक्स

37. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा 1978 में सदन में यह घोषणा की गई थी कि जालोर में ग्रेनाइट की प्रचुरता को दृष्टि में रखते हुए वहां "ग्रेनाइट काम्पलेक्स" का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो उस घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब सरकार जालोर में ग्रेनाइट काम्पलेक्स का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(3) सरकार के समक्ष जालोर जिले के ग्रेनाइट उद्यमियों की क्या-क्या समस्याएं विचाराधीन हैं ? इन समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित किया जाता है। आपको इसका उत्तर मिल जायेगा। यदि सेशन में दोबारा नहीं लगा तो आपको इसका उत्तर मिल जायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको इसका जवाब मिल जायेगा। श्रीमती उजला अरोड़ा

मोती कटला जयपुर डिस्पेंसरी का भवन

38. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोती कटला डिस्पेंसरी, जयपुर का पुराना भवन क्षति-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ग्रस्त है ? यदि हां, तो कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त है ?

(2) उक्त डिस्पेंसरी भवन की मरम्मत किये जाने और उसका विस्तार किये जाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों !

(3), उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों, कम्पाउण्डर्स व सहायकों के लिये क्वाटर्स बनाने की योजना को कब तक क्रियान्वित किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

(1) जी हां। पुराने भवन का 2926.63 वर्गफीट क्षेत्र क्षतिग्रस्त है।

(2) पुराना भवन 80 वर्ष से अधिक समय पूर्व का है, जिसके उपयोग की अवधि पूरी हो चुकी है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी मरम्मत की जाकर उपयोग में लिया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं बताया गया है।

(3) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि 1977 में यह भवन 98 बल्लियों पर टिका हुआ था। आपकी और सरकार की मेहरबानी से 78 बल्लियां हटकर उस पर भवन बन गया है और वह इस समय चिकित्सार्थ कार्य आ रहा है। यह जो अनुमान आपको दिया गया है, गलत दिया गया है। 975 वर्गगज जमीन का तो शायद कुल ही उसका एरिया होगा–जो बना हुआ हैं, क्षतिग्रस्त है और खाली इलाका पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि अब वहां पर केवल 25 बल्लियां लगी हुई है। जो स्थान स्टोर के काम में आ रहा है और जहां पर चिकित्सक निवास है वह इल का क्षतिग्रस्त है। इस प्रश्न को लेने के बाद आधा हिस्सा गिर गया, आधा हिस्सा बचा है। यह आपके देखने की बात हैं कि स्टोर का सामान कहां रखा जायेगा और चिकित्सक कहां रहें क्योंकि अगर चिकित्सक वहां नहीं रहे तो इस चिकित्सालय का कोई अर्थ नहीं रहता। मेरा निवेदन है कि आपको यह भी बताया गया होगा कि उस पर कितना पैसा व्यय आयेगा ? इस निर्वाचन क्षेत्र में अन्यत्र इस प्रकार की कोई डिस्पेंसरी नहीं है और यह बहुत पिछड़ा इलाका है, रामचन्द्र जी की चोकड़ी, गंगापोल के शहरी भाग का, इस पर अगर यह चिकित्सालय पूरा काम नहीं करेगा तो दबाव एस. एम. एस. अस्पताल पर पड़ेगा और यहां की जो गरीब जनता है उसको वहां तक जाने में परेशानी होगी। आप कृपया इन सब को दोबारा दिखवाइये और इसमें कोई खास लागत आने वाली नहीं है। सन् 1977 के बाद इस डिस्पेंसरी में कोई पैसा व्यय नहीं हुआ। जो भी आपका बजट निर्धारण है, यह जो 25 बल्लियां केवल शेष बची हैं उनको हटवा कर उतने इलाके की मरम्मत करवाने का आप श्रम करें जिसको कि उपयोग के लिए अत्यन्त आवश्यकता है, यह मेरा आपसे निवेदन है। यह जो आपको बताया गया है कि इतना पैसा लग जायेगा इसको आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
पुनः दिखवाइये और बिल्कुल गलत सूचनायें दी हैं और जिन्होंने आपको गलत सूचनायें दी हैं उनका आप क्या करने वाले हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इस सारे भवन में 1977 में यह बात तय हो गयी थी कि यह भवन पुराना है और गिरने की स्थिति में है। इसी कारण 28-2-78 को 1.48 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो गयी, नवीन ब्लाक का निर्माण 1980 में उसी नाते से 2.10 लाख की लागत पर पूर्ण हो गया और नये ब्लाक में डिस्पेंसरी पूर्ण रूप से चालू है। प्रश्न केवल चिकित्सक के निवास का आता है और दूसरा स्टोर का सामान थोड़ा-सा एक कमरे में पड़ा है, उसका आता है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस भवन को तो हम निश्चित रूप से गिराने वाले हैं, नये ब्लाक में काम चल रहा है। अब जैसा माननीय सदस्या ने बताया है मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं 27 डिस्पेंसरियां जयपुर शहर में हैं जिसमें से दो डिस्पेंसरियों में ही चिकित्सक के आवास बने हुए हैं। इस बारे में अगर माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं तो एक कमेटी जनता की बनायें और जनता के सहयोग से चिकित्सक के आवास की व्यवस्था वहां पर की जा सके। अगर वहां पर कर देंगे तो 27 वाले मेरे प्राण ले लेंगे। जमीन उपलब्ध है, जमीन की गारण्टी मैं लेता हूं। भूमि मैं मुहैया कराऊंगा। हमने गांवों के लिये भी यही बात बना रखी है तो अगर जन सहयोग से भवन का निर्माण हो, अगर शहरों में यह करने लगे तो जो पीड़ित और उत्पीड़ित इस प्रकार के गांव में रहने वाले लोग हैं उनके साथ हम न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में सम्बन्धित भवन जन सहयोग से निर्मित करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने जो आदेश दिया, आग्रह किया उसको मैं करूंगी परन्तु एक बात यह जानना चाहती हूं कि आप उसकी बाउण्डरी वॉल जो वहां नहीं बनाये जाने से रोज कांच टूटते हैं रोज आसपास के बच्चे करते हैं वह भी बना पायेंगे या वह भी जन सहयोग से बनानी पड़ेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्या को पूरा सहयोग दूंगा जन सहयोग प्राप्त करने में वह उसको इनीशियेट करें मैं सहयोग दूंगा बाउण्डरी वॉल भी बनेगी और आवास भी बनेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात और। मैं वह जानना चाहती हूं कि जो ध्वस्त किया जाने वाला इलाका है यह भी मैं जन सहयोग से कर दूं अगर आप आज्ञा दें तो।

श्री अध्यक्ष : अगला। आपका इसमें क्या दखल है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि जन सहयोग से करा लें तो डिस्पेन्सरी की बाउण्ड्री तो सरकार के जिम्मे आती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका मामला नहीं है, मेरा मामला है मैं खुद सुलट लूंगी। आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए आपने कभी किया भी नहीं है। पिछले 10 साल में मैं बहुत दुखी रही हूं कोई सहयोग नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : दोनों ने मान लिया तो और भी ज्यादा करने को तैयार हैं।

प्रश्न संख्या 39.

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जोधपुर को पेयजल

39. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर लिफ्ट योजना द्वारा जोधपुर शहर को पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(2) जोधपुर लिफ्ट योजना पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

प्रशासनिक व्यवस्था, निर्माण कार्य, विद्युत, मशीनरी आदि हेतु मद वार व्यय अनुमान बताते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस राशि में से अब तक अलग-अलग मदों पर कितनी राशि व्यय हो गयी है ?

(4) राज्य सरकार 31 मार्च, 1991 तक कुल कितनी राशि इस योजना पर व्यय करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री मोहन मेघवाल) : (1) जोधपुर लिफ्ट योजना द्वारा जोधपुर शहर को जून, 1992 तक पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

(2) जोधपुर लिफ्ट योजना अनुमानित लागत 103.14 करोड़ रुपये है। मदवार राशि का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) वर्ष 1990-91 में इस परियोजना के लिये 45.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसे मिलाकर मार्च, 1991 तक कुल लगभग 78 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर लिफ्ट केनाल की आज क्या स्थिति है। आज तक जितने काम हो चुके हैं और कितना व्यय हुआ है। खण्ड-दो में जोधपुर लिफ्ट केनाल के लिये लिफ्ट करने के लिये कितनी विद्युत की आवश्यकता है। उसकी क्या प्रगति हुई है या हो रही है। लिफ्ट करने के लिये कितनी पम्प मोटर चाहिए, उसकी डिजाइन बनी या नहीं बनी, उसका ऑर्डर दिया गया या

(श्री राजेन्द्र गहलोत)
नहीं दिया गया। इसकी सूचना दें। प्रस्तावित 1992 तक केनाल का क्या निर्माण कार्य होने जा रहा है। उसके लिये सरकार कितनी गम्भीर है क्योंकि जोधपुर शहर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। जोधपुर के आसपास 100 किलोमीटर में जो सिंचित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से जोधपुर को लम्बे समय से पानी दिया जा रहा है जिसके कारण आसपास के किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार की अदूरदर्शिता के के कारण यह सिंचित क्षेत्र दिनों दिन पानी की गम्भीर कठिनाई में पड़ जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर लिफ्ट केनाल का जो कार्य प्रस्तावित है सरकार उसकी स्पष्ट घोषणा करे कि अब पानी कब तक उपलब्ध करा देंगे और इस वर्ष कितनी राशि खर्च होगी। मुझे बतायें कि समयबद्ध क्या कार्यक्रम लेते हैं और जोधपुर को कब तक पानी मिलेगा?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही अहम प्रश्न है और जोधपुर का जल संकट का समाधान इससे जुड़ा हुआ है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि जो गति इसमें आनी चाहिए थी जिस गति से काम होना चाहिए था वह हम नहीं कर पाये और इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं रहता और जितना पैसा चाहिए था, समय पर मिलता रहता और अन्य कारण नहीं होते तो यह काम काफी प्रगति पर जा सकता था। मैं माननीय सदस्य को अब तो यही विश्वास दिलाता हूं कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : राजनैतिक लोगों की फाइल आपके पास नहीं आती? आप मंत्री हैं तो राजनैतिक हस्तक्षेप कैसे हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी हलचल का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसे आप हस्तक्षेप कर रहे हैं ना मेरे बोलने में यह फाइल पर कहां लिखा हुआ है। आप कहना चाहते हैं वह मैं भी कह सकता हूं कि किन-किन ने किया लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य को युद्ध स्तर पर लिया जायेगा योग्य अधिकारी लगा दिये हैं और माननीय सदस्य को जानकारी है कि पिछले दिनों में जो प्रगति हुई है वह काफी सन्तोषजनक है। कल विभाग के लोगों ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि जून, 1992 तक इसको पूरा करके पानी दे देंगे। इसी को एक चुनौती मानकर पूरा विभाग और मैं स्वयं इसकी देखरेख करूंगा और देखते हैं कि यह काम समय पर पूरा हो जाय। मैं समझता हूं कि इससे अधिक कुछ कहने में लाभ नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान पम्प मोटर्स की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी डिजाइन के लिये 15 महीने से निर्णय लेने के लिये विभाग के पास फाइल दबी हुई हैं आज तक इसकी मोटर के डिजाइन तैयार नहीं हुए तो केनाल बन जाने के बाद भी सदैव की भांति उसमें मिट्टी भर जायेगी

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

और निर्णय कब तक हो जायेगा और कब तक पम्प हाउस वहां बन जायेंगे। इसके विषय में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वास्तव में यह विलम्ब हुआ है लेकिन अब इसमें अधिक विलम्ब नहीं होगा और इस बारे में चर्चा करेंगे और जो फर्मस यह पम्प दे सकती है और यदि एक दे सकती है तो एक सैट और एक से अधिक देने में सक्षम होंगी तो अधिक से यह काम प्रारम्भ कर दिया है। मैं समझता हूं जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। एक विशेष अधिकारी को इस काम के लिए मैं नियुक्त करूंगा जो इसकी देख-रेख करके पूरा करे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत कार्य के विषय में क्या प्रगति करने के लिए आप कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जोगेश्वर जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में पानी देने के लिए जो योजना लगातार खटाई में पड़ रही है उसके कारण जो दुष्प्रभाव हमारे क्षेत्र में पड़ रहा है इसके बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। जंवाई बांध....

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में मत कहिए, प्रश्न पूछिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जंवाई बांध के बनने के कारण जो हमारे....

श्री अध्यक्ष : यह जवाई बांध कहां से आ गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इसका सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : जोधपुर की लिफ्ट योजना को....

श्री जोगेश्वर गर्ग : जोधपुर में जब तक इस लिफ्ट योजना से पानी नहीं मिलेगा जब तक जोधपुर और पाली जंवाई बांध से पानी लेते रहेंगे तब तक हमारे क्षेत्र की जनता को दबाया जाता रहेगा मैं इस बात को सदन में कहना चाहता हूं। जंवाई बांध का पानी सुमेरपुर पंचायत समिति, जालोर पंचायत समिति शाला पंचायत समिति को मिलना चाहिए उनका गला घोंट कर पानी रोका जा रहा है। यह जोधपुर हमारा है और वह मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर लिफ्ट योजना को आज लटकाये रखा गया, जिसका परिणाम यह होगा कि पाली जिला आप पेय जल के संकट से....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या पूछ रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि लिफ्ट योजना पूरी होने के बाद जंवाई बांध का पानी क्या पाली जिले की जनता

(श्री गुलाब सिंह)

को पीने के लिए और सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा और जंवाई बांध के पानी की आवक बढ़ाने के लिए बारिश कम होती है, आवक बढ़ती नहीं है। क्या सरकार के पास योजना है कि जंवाई बांध और हेमावास बांध की पानी की आवक बढ़े, पेय जल समस्या का निवारण हो, मवेशियों के लिए पीने का पानी मिले, काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय कल्ला जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जोधपुर लिफ्ट का काम कब शुरू किया गया, पिछले वर्ष उस पर कितनी राशि खर्च हुई और अब तक कितने कि. मी. जोधपुर लिफ्ट का निर्माण हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : शेरगढ़ के माननीय सदस्य।

श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो जोधपुर लिफ्ट योजना शेरगढ़ तहसील के गांवों से आ रही है क्या मंत्री महोदय जिन गांवों में शेरगढ़ तहसील में पानी की विकट समस्या है, नहर वहां से गुजरेगी उन गांवों को छोटी-छोटी पाइप लाइने जोड़ने का विचार रखते हैं और नहीं तो क्यों और पिचाणियां रातरानाहड़ा की योजना जो शेरगढ़ की तहसील के आधे गांवों की पेय जल की व्यवस्था करती है इसको पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल।

श्री मिश्री लाल चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्षमहोदय, जोधपुर पेय जल की योजना जो राजस्थान नहर से पहले प्रस्तावित हुई उसके बाद इन्दिरा गांधी नाम इसका रखा गया इसके बारे में मेरे मंत्री महोदय से दो सवाल हैं ? आज तक जो खटाई में पड़ी हुई योजना है उसका हिन्दुस्तान में करोड़ों खर्चों के बाद भी, सीमेंट हिन्दुस्तान के कोने-कोने तक पहुंच चुका है और हिमालय का पानी सौ डेढ सौ कि.मी. तक जोधपुर नहीं पहुँच पाया, इसकी ओर मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्यों नहीं यह काम सेना को सौंप दिया जाये और दूसरा जो ज्यादा अड़चन पैदा हो गई राजस्थान नहर का नाम इन्दिरा गांधी नहर रख दिया गया है क्यों नहीं इसका नाम बदल कर राजस्थान नहर रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने अभी जवाब में बताया कि राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण यह नहीं हुआ। अब जब आप मंत्री बने है तो क्या अपेक्षा करें कि कितने दिनों के अन्दर, दो साल क्यों लगाते है आप इसको दो महीने में, तीन महीने में या चार महीने में क्यों नहीं कर देते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है इस लिफ्ट कैनाल को पूरा करने के बारे में। मैं सोचता हूं राजस्थान कैनाल के बारे में वह आश्वासन विभिन्न सरकारों के रहे, वह बड़े अजीब हैं। दो साल का मतलब हमेशा 10 साल से ऊपर निकलता है। इस नहर के बारे में जो पहली बात थी वह यह थी कि लिफ्ट कैनाल की बिजली जो शक्ति उत्पादन है कहां से होगा, कहां से बिजली आयेगी कितनी आयेगी, क्या वहां समुचित व्यवस्था हो सकेगी और किस जगह से होगी एक तो यह ? दूसरा यह कि जो लाइनिंग बन रही है उसे लाइनिंग बनाने के लिए पूरी व्यवस्था, पूरा सामान, पूरा मैटेरियल किस तरह से उपलब्ध होगा और उसमें जो लॉसेज होंगे क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कैनाल का वाटर जहां से लेंगे और जिस तरह सिंचाई करेंगे जैसा मैं समझता हूं कुछ सदस्यों ने इस तरह की मांग पैदा की है कि इसके बीच में से पानी लाये। क्या यह सम्भावना है कि इस कैनाल में जोधपुर के बजाय सारे जोधपुर जिले को या कुछ और इलाकों में पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाये तो पानी कितना होगा, कितना लिया जायेगा, कितने उसके लॉसेज होंगे यह सारी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वही मेरा मूल प्रश्न था। विद्युत उपलब्धता होने के बाद में जब तक आपकी ट्रिपिंग होगी, या विद्युत सप्लाई नहीं होगी तो इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए क्या प्लान बताया गया ? क्या सोचा गया ? कृपया स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि चूंकि यह नहर का मामला है इसलिये नहर के मामले को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से लेकर सिंचाई विभाग को सुपुर्द कर दिया जाये क्योंकि उनके पास नहर बनाने की ज्यादा दक्षता है, मशीनरी है। तो मैं समझती हूं यह काम ज्यादा जल्दी और आसान होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल परमार।

श्री अमृत लाल परमार (बाली) : अध्यक्ष जी, अभी हमारे जोधपुर के श्री राजेन्द्र गहलोत जी ने बताया, जोधपुर के लिए मैं भी बताना चाहता हूं। जवाई बांध का जो पानी जोधपुर जा सकता है तो बाली के एरिये, जहां से पानी निकलता है, जो हमारी तहसील लगती है, वह तहसील भूखी मरेगी या प्यासी मरेगी। इस का कोई इलाज है ? कई सालों से हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं। वहां की सारी फसल चौपट हो चुकी है। इसी प्रकार बाली का जो बांध बना हुआ है सवाडी का. उस सवाडी बांध के कारण पूरी जमीन गांव नुगदा से सांचोर तक चौपट

(श्री अमृतलाल परमार)

हो गयी है, तो बाली के लिए क्या लिफ्ट की योजना नहीं बना सकते ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप कैसे होगा। आपके ध्यान में है आपकी सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री माधो सिंह जी दीवान ने जोधपुर में घोषणा की थी कि 1990 के अन्त तक इस नहर का पानी जोधपुर पहुँच जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : उन्होंने यह भी कहा था कि अगर 1990 तक नहीं पहुंचेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा और खड़ा नहीं होऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे जानकारी दी है। मैं उनका बहुत आभारी हूं, लेकिन यह बात सही है कि 1990 तक पानी नहीं पहुंच सका। उन्होंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया लेकिन जनता ने उनको त्याग पत्र दे दिया। प्रश्न यह आता है, कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि इसका कितना काम हुआ है; प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 80 किलोमीटर में तो खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, 32 किलोमीटर में लाइनिंग का काम हो चुका और बिजली की 75 किलोमीटर लाइन खेंच दी गई है। इसके उपरान्त भी कई माननीय सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किया कि बिजली उपलब्ध होगी कि नहीं। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य तो अभी से ट्रिपिंग की भी चिन्ता करने लग गये। मैं समझता हूं कि उनकी जागरूकता की तो दाद देनी चाहिए, लेकिन बिजली की लाइन खींच जायेगी उसके बाद में ट्रिपिंग का व्यवधान पैदा होगा। मैं आपको अर्ज करूं जिस समय ऐसी कोई स्थिति आयेगी उस समय आप और हम सब यहीं हैं, उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

कुछ प्रश्न आये जालोर के और पाली जिले के। यह बात सही है कि जंवाई बांध जिस पर्पज के लिये बनाया गया था उस पर्पज के लिये उसके पानी का उपयोग कम हो रहा है। वास्तव में यह बांध सिंचाई के लिये बनाया गया था लेकिन जोधपुर में पानी का संकट आया तो जोधपुर में हेमावास के पहले और उसके बाद जवाई से हमने जोधपुर शहर को पानी देना शुरू किया। उसके कारण से यह निश्चित है कि जालोर जिले में भी कुछ संकट उत्पन्न हुआ है और पाली जिले में विशेष रूप से संकट उत्पन्न हुआ है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जोधपुर जिले को पानी देने के लिये मथानिया में हमने टयूबवैल्स बनाये थे, उसका परिणाम यह निकला कि जोधपुर जिले का सबसे हरा भरा क्षेत्र, पानी वहां से लेने के कारण सूखा सा लगने लगा है इसी तरह से रणसी गांव से हमने पानी लेना शुरू किया है, रणसी गांव की भी इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। पीपाड़ से भी हमने पानी लेना शुरू किया है, वहां भी इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। तो उस स्थिति के बारे में परिचित नहीं हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका उपाय यह है कि लिफ्ट कैनाल जल्दी से जल्दी बने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और जल्दी से जल्दी बनकर जोधपुर जिले की जल की कमी पूर्ति करे ताकि जालोर और पाली के लिये जवाई का पानी बच सके। बाकी के क्षेत्रों में जो ट्यूबवैल खोदकर पानी ला रहे हैं और जिसके कारण खेती नष्ट हो रही है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है वह भी रुक सके।

एक माननीय सदस्या ने सुझाव दिया कि इसको सिंचाई विभाग को दे दिया जाये। मैं समझता हूं पहले शायद सिंचाई विभाग ही इस पर काम कर रहा था। पुरानी सरकार ने इस पर विचार करके पी. एच. ई. डी. को दिया है। उसमें यदि कोई ढिलाई बरती गयी हो तो हमारी विभाग विशेष में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। हमारी रुचि यह है कि राजस्थान की लिफ्ट कैनाल ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बने और अच्छी प्रकार से बने।

शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रास्ते में इससे गांवों-गांवों में पानी दिया जायेगा कि नहीं दिया जायेगा। यह दो प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ओपन चैनल आता है तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था इस प्रकार की होगी। मुझे सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए मैं अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पानी का इसी प्रकार का संकट रहा तो इस योजना में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि जोधपुर शहर को जल्दी से जल्दी पानी मिल सके।

जहां तक डिफेन्स का प्रश्न आता है, इस प्रश्न के ऊपर भी हम विचार कर रहे है। जोधपुर शहर में आर्मी का हैड क्वार्टर है, देश की सीमा के ऊपर जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, यदि जोधपुर शहर में पीने के पानी का प्रबन्ध तत्काल नहीं किया गया तो सुरक्षा की दृष्टि से भी, और सेवा का वहां पर जमाव रहे इस दृष्टि से भी, हमारे सामने समस्या पैदा होगी।

मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने यह सुझाव दिये, उनका धन्यवाद करता हूं और मैं इस दृष्टि से भारत सरकार को लिखना चाहूंगा कि वह डिफेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस नहर के तुरन्त निर्माण के अन्दर हमारा किसी न किसी प्रकार से योगदान करे। इस सुझाव के ऊपर हम निश्चित रूप से काम करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : डिफेन्स ने पार्टीसिपेट करना स्वीकार किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसों की दृष्टि से डिफेन्स पार्टीसिपेट इसमें कर रहा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। उसके निर्माण में डिफेन्स डिपार्टमेंट किस प्रकार से योगदान कर सकता है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से चर्चा करूंगा। 1992 के पहले हम डिफेन्स डिपार्टमेंट के सहयोग से आर्थिक और फिजिकल दोनों प्रकार के सहयोग से यदि हम जल्दी निर्माण करवा सके तो कराने की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

40. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की गई है ? यदि हां तो कब तक प्रारम्भ की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट ने निदेशक, कृषि अनुसंधान, निदेशक पशुपालन अनुसंधान, निदेशक कृषि विस्तार के मुख्यालय उप कुलपति कार्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत बीकानेर में स्थापित करने हेतु निर्णय ले लिया था ? यदि हां, तो कब तक उक्त निर्णय की क्रियान्विति हो जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(1) प्रश्न ही नहीं उठता, पूर्व में ही चल रही है।

(2) यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल ने निदेशालय (कृषि अनुसंधान, पशु विज्ञान अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा) के मुख्यालय बीकानेर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था। इसमें से निदेशालय पशु विज्ञान अनुसंधान का मुख्यालय, माह अक्टूबर, 1989 को जयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित किया जा चुका है। निदेशक, विस्तार शिक्षा के कार्यालय स्थानान्तरण हेतु पूर्व मुख्य मन्त्री के मार्च, 1989 के विधानसभा बजट में की गई घोषणानुसार आदेश दिया गया है कि उक्त निदेशालय उदयपुर में ही रखा गया है और इसकी गतिविधियां यथावत उदयपुर में ही रहेंगी। राज्य सरकार में कृषि शोध के बारे में उचित समन्वय हेतु, कृषि अनुसंधान निदेशालय को फिलहाल जयपुर में ही रखा जा रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में एम. एस. सी. एग्रीकल्चर की कक्षाएं चूंकि 1987 में विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुआ अभी थर्ड ईयर इस साल आयेगा और नेक्स्ट ईयर 1990-91 में एम. एस. सी. (प्रिवियस) की कक्षाएं प्रारम्भ होनी चाहिए थी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या अगले शिक्षा सत्र में एम. एस. सी. (एग्रीकल्चर) की कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि, क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन सचिव ने आदेश देकर के विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ मैनेजमेंट के निर्णयों को रोककर उन मुख्यालयों को वहां नहीं रखने के आदेश दिये और यदि यह आदेश दिये तो क्या विश्वविद्यालय की स्वायत्ता भंग नहीं हुई ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर विश्वविद्यालय के अन्दर जो कक्षाएं, आपने पूछा कि वह चल रही हैं। शायद आपका अभिप्राय उन स्कूल, उन संस्थाओं से है महारानी सुदर्शन कालेज बीकानेर, डूंगर कालेज दोनों से ही हैं, उनमें अभी नहीं है, बाकी तो बीकानेर की

(श्री दिग्विजय सिंह)
यूनिवर्सिटी के अन्दर जो कक्षाएं आपने स्पष्ट किया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं नहीं चल रही हैं। एम. एस. सी. (एग्रीकल्चर) कक्षाएं नहीं चल रही हैं। बी. एस. सी. (एग्रीकल्चर) चल रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसके बारे में यह निर्णय है कि राज्य सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करना सम्भव होगा। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, और जो आपने बात कही है, तो जानकारी कर के अगले सत्र से चालू हो सके उस पर विचार करेंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने कृषि ए. पी. एस. के बारे में कहा कि वहां आगे की कार्यवाही रोक दी गयी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मण्डल ने यह निर्णय लिया था, जिसमें आप स्वयं भी उसमें एम. एल. ए. की हैसियत से मैम्बर थे, मन्त्री और आपने यकायक वहां यह निर्णय करा लिया था कि ये जो प्रस्ताव रखा था कि मुख्यालय बीकानेर रहने का प्रस्ताव रखा था जिसमें निर्णय लिया गया था कि मुख्यालय, बीकानेर स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया पर कुलपति द्वारा सुविधानुसार क्रियान्विति का निर्णय लिया जाये। इस बैठक में कृषि सचिव उपस्थित नहीं थे और ना ही इस आशय का कोई एजेण्डा बैठक में विचार करने के लिये पूर्व में रखा था। श्री कल्ला ने, जो उस समय शिक्षा मन्त्री थे, बैठक में ही इस प्रकार का प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन किया गया। उसके बाद में जब यह राज्य सरकार के सामने आया तो तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने इसको रोक दिया। इसलिए कृषि सचिव के रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन सचिव ने विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखी। बोर्ड आफ मैनेजमेंट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, उसके बाद उसको, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को भंग किया गया। दूसरी बात, इन्होंने अपने लिखित उत्तर में यह कहा है कि पूर्व मुख्य मन्त्री ने यहां यह घोषणा की। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि कृषि विस्तार और कृषि अनुसंधान निदेशालय को बीकानेर नहीं लाया जाये। उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि उदयपुर में जो पढ़ाई चल रही है, जो एम. एस. सी. कक्षाएं चल रही हैं, एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कालेज चल रहा है, उनको वहीं यथावत रखा जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आई.सी.ए.आर. ने विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिये हैं कि विश्वविद्यालय जब बीकानेर मुख्यालय में स्थापित किया गया है तो क्यों नहीं वहां पर सहायक कृषि विस्तार निदेशालय और कृषि अनुसंधान निदेशालय भी रखा जाये ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब जो बात कह रहे हैं, मूल जो सिद्धान्त है वह सही है और आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि यह घोषणा पूर्व मुख्य मन्त्री जी की

(श्री दिग्विजय सिंह)

वह घोषणा पढ़कर सुनाता हूं तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि राज्य के उदयपुर विश्वविद्यालय को यह सामान्य विश्वविद्यालय रखकर एवं क्यों कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। किन्तु उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय का हाउस कैम्प रहेगा जिसमें वर्तमान में कृषि संकाय की जो भी प्रवृत्तियां चल रही हैं वह यथावत रहेंगी।

इसके अतिरिक्त एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी एक स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय और वर्तमान में जो शेयर है वह कम हो जायेगा और शिक्षा का स्तर भी सुधर जायेगा।

इन प्रस्तावों के सन्दर्भ में हमारा प्रयास यह रहेगा कि राज्य के सभी संभागों में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित हो जाय और वर्षों से चली आ रही क्षेत्रीय मांग की पूर्ति हो और संतुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव हो सकेगा। यह बजट के अन्दर उन्होंने उल्लेख किया था।

श्री बुलाकी दास कल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि संकाय में कृषि विस्तार निदेशालय नहीं आता है। मैं आज भी कहता हूँ कि पूर्व मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणायें की थीं उनका हम स्वागत करेंगे लेकिन कृषि संकाय में कृषि, आप माननीय मन्त्री जी नये नये हैं आप अपने अधिकारियों से सलाह ले लें कि एग्रीकल्चर फैकल्टी....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपसे पहले मन्त्री बन गया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां बन गये थे। आपको अनुभव बहुत है लेकिन एग्रोकल्चर फैकल्टी में कृषि विस्तार नहीं आता है कहीं। एग्रीकल्चर फैकल्टी से सम्बन्धित कक्षायें आप वहां रखें उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज आप चाहे रखें लेकिन जो बोर्ड आफ मैनेजमेण्ट ने यह निर्णय किया है एग्रीकल्चर रिसर्च का डाइरेक्ट और कृषि विस्तार का निदेशालय बीकानेर रखा जाय इसमें किसी भी विभाग के सचिव को यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा कि विभाग का सचिव विश्वविद्यालय की स्वायत्ता भंग करे। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर चोट पहुंचायी है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि कृषि सचिव ने कोई निर्देश नहीं दिये थे। यह आदेश दिये गये थे पूर्व कृषि मन्त्री जी के आदेशानुसार।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ और बता भी दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पढ़कर नहीं, सदन की मेज पर रख दें। कृषि उत्पादन सचिव को मन्त्री जी ने कोई चिट्ठी लिखी है तो सदन की मेज पर रखें।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय कल्ला साहब, सदन की मेज पर भी आ जायेगी और आपको भी दिखा दूंगा आप सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सन्तुष्ट नहीं होऊंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्ता भंग की है और यह पूर्व मुख्यमन्त्री जी का नाम लेकर यह कहना चाहते हैं कि कृषि संकाय वहां रखने की बात है और कृषि विस्तार निदेशालय को बीकानेर रखने का जो निर्णय किया गया है उस निर्णय का उल्लंघन किया गया है और विश्वविद्यालय की स्वायत्ता भंग करके नुकसान पहुंचाया है। हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है। पहले व्यवस्था सुन लीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 37. (स्थगित)

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

38. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

(2) व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, राज्य में अन्य कितने स्थानों पर एवं कब तक प्रारम्भ किये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या योजनाएं बनाई गयी हैं ?

(4) व्यावसायिक शिक्षा के कितने पाठयक्रम कहां-कहां अध्ययन अधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना के अनुसार माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण 10% बालक/बालिकाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसी नीति के अनुसरण में वर्ष 1987 से ही +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। अपेक्षा यह है कि इन पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने पर उक्त छात्र या तो स्वरोजगार करेंगे अथवा संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की उनके लिये सम्भावनायें बढ़ जायेगी।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) वर्तमान में 125 सिनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 3 संस्थाओं में व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ हैं। इसलिये वर्तमान में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम राज्य में अन्य कितने स्थानों एवं कब तक प्रारम्भ किये जायेंगे।

(3) जी हां। योजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति बिन्दु संख्या 2 पर अंकित हैं।

(4) राज्य में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम जिन विद्यालयों में चल रहें है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालौर जिले में कृषि कनेक्शन के बिल

39. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जालौर जिले में कुओं में पानी नहीं होने के उपरान्त भी न्यूनतम चार्ज के बिल विद्युत् विभाग द्वारा कृषकों को भुगतान हेतु भेजे गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के अधिकांश कृषकों के विद्युत संबंध बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण काटे जाने की स्थिति में है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में न्यूनतम चार्ज की वसूली निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुओं में पानी नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम चार्ज माफ करने के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 10-11-1989 को आदेश जारी किये गये हैं। जालोर जिले में जिन कृषि उपभोक्ता ने कुएं में पानी नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित मण्डल कार्यालय में प्रार्थना-पत्र देकर उक्त आदेश के तहत अपना विद्युत् सम्बन्ध विच्छेद करवा लिया है, उनको न्यूनतम चार्ज के बिल भुगतान हेतु नहीं भेजे गये हैं। जिन कृषि उपभोक्ताओं ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है उन्हें ही न्यूनतम चार्ज के बिल भेजे गये हैं।

(2) उपरोक्त दर्शायी गई स्थिति अन्तर्गत ऐसे कृषि उपभोक्ता जिन्होंने अपने कुएं के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं करवाये हैं उनके कनेक्शन विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने के कारण नियमानुसार काटा जाना स्वाभाविक है।

(3) राज्य सरकार के निर्देश सं. 87 दिनांक 14-9-89 की अनुपालना में मण्डल द्वारा अपने आदेश सं. 6531 दिनांक 10-11-89 द्वारा उपरोक्त स्थिति में न्यूनतम चार्जेज माफ करने के निर्देश जारी किये हुये हैं।

जिला सतर्कता एवं अभाव अभियोग समितियों की बैठक

40. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या मुख्य (सतर्कता) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सतर्कता एवं अभाव अभियोग समितियों की बैठक नियमानुसार कितने समय में होना आवश्यक है ?

(2) क्या सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ये बैठकें निर्धारित अवधि में सम्पन्न हो रही हैं ? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन उत्तरदायी है और भविष्य में कब तक ऐसी व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां, सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट–1, 2, 3, 4)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारह मोरी (ब्रह्मपुरी) के पास पुलिया का निर्माण

41. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :—क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माऊंट रोड़ के निर्माण के 8—10 वर्ष पश्चात् अभी तक भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बारह मोरी (ब्रह्मपुरी) के पास पुलिया नहीं बनायी गयी है। यदि हां, तो क्यों तथा उक्त पुलिया कब तक बना दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क विभिन्न स्थानों से टूटी हुई है उस पर गहरे-गहरे खड्ढे बने हुए हैं फिर भी उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ?

(3) क्या उक्त मार्ग पर नहर के गणेश जी (ब्रह्मपुरी) के पास एक खतरनाक मोड है, जहां आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग के ज्यादातर हिस्से पर अभी तक रोड लाईट नहीं लगाई गई है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक लगा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माउंट रोड के निर्माण के समय बारह मोरी (ब्रह्मपुरी) के पास पुलिया निर्माण का प्रस्ताव नहीं था। अतः पुलिया न बनाई जाकर काज-वे का ही निर्माण करवाया गया था।

(2) जी हां। सड़क कई स्थानों पर टूटी हुयी है एवं गड्ढे भी है उस सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु दिनांक 27-3-90 को निविदायें प्राप्त की जावेगी एवं निविदायें प्राप्त होने के पश्चात् सड़क मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(नगरीय विकास मंत्री)

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित माउंट रोड पर ब्रह्मपुरी के पास एक मोड दिया हुआ है। ऐसे मोड पर उपरोक्त रोड पर अन्य जगह भी दिये गये है। रोड के दोनों तरफ जगह-जगह मकानात, नाले एवं सिटीवाल आ जाने से मोड दिये गये थे। इन मोडों को मौके की परिस्थिति के कारण सीधा किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) इस बाइपास पर रामगढ़ क्रासिंग से प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष लगभग रुपये 84000/= का कार्य प्रस्तावित था जिसमें लगभग 50,000/= का कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कर दिया गया है, एवं शेष भाग पर राज. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कार्य लिया जाना है, जिसके लिये रुपये-- 67,000/= प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिये गये है।

सहकारी स्पिनिंग मिल्स द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दान

42. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में सहकारी क्षेत्र में चलने वाली स्पिनिंग मिलों द्वारा किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि दान स्वरूप दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स व गंगापुर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्रत्येक के द्वारा मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष में पांच लाख रुपये की राशि सहायतार्थ दी गयी है ? यदि हां, तो क्या मिल के पास इतनी बड़ी राशि दान स्वरूप देने हेतु कोष या प्रावधान है ? यदि नहीं, तो यह राशि किस कोष से दी गई ?

(3) इन मिलों की वित्तीय स्थिति क्या है तथा क्या ये मिलें राज्य सरकार की या अन्य संस्थाओं की देनदारियों से मुक्त है।

उत्तर

(1) वर्ष 1989—90 में सहकारी क्षेत्र में चलने वाली स्पिनिंग मिलों द्वारा जिन-जिन संस्थाओं को जो राशि दान स्वरूप दी गई है उसकी सूचना परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) जी हां। इन दोनो मिलों के पास इतनी राशियां दान स्वरूप देने हेतु कोष उपलब्ध नहीं है। इन मिलों ने उक्त राशियां अपनी कार्यशील पूंजी से राज्य सरकार की स्वीकृति की अपेक्षा में दी थी।

(3) इन मिलों की वित्तीय स्थिति व राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं की देनदारियों की स्थिति परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पटवारियों के बकाया यात्रा बिल

43. श्री अमीन खां (शिव) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर के कितने पटवारियों के यात्रा भत्ते कब से

(श्री अमीन खां)

बकाया पड़े हैं और क्यों ? तहसीलदार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुराने यात्रा भत्ते के बिलों का शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बजट की कमी के कारण जिला बाड़मेर के 211 पटवारियों तथा जिला जैसलमेर के 57 पटवारियों के यात्रा भत्तों के बिल भुगतान के लिए बकाया पड़े हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) इस मद में अतिरिक्त बजट आवंटित कर राज्य सरकार ऐसे बकाया बिलों के शीघ्र भुगतान हेतु प्रयत्नशील है। इस मद में मार्च, 90 में जिला बाड़मेर एवं जिला जैसलमेर को क्रमशः 1.00 लाख रुपये एवं 45 हजार रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित कर दिया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

संजय कॉलोनी (अलवर) में विकास कार्य

44. श्री जीतमल जैन (अलवर) :— क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में आकाशवाणी के पास नगर सुधार न्यास द्वारा संजय कॉलोनी में बिना विकास शुल्क लिये विकास कार्य यथा-सड़कें, नालियां आदि का निर्माण करवाये जा रहे हैं ?

(2) यदि हां तो न्यास द्वारा इसी प्रकार वहां की अन्य निजी कालोनियों में विकास के कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) आकाशवाणी के पीछे संजय कालोनी जिसका ले आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया है, में न्यास द्वारा सड़कों व नालियों के कार्य किये जा रहे हैं। इसके आराजी खसरा संख्या 64/1.64/2 ग्राम खौहरा के पैरिफैरियल विकास शुल्क 3/- रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से धनराशि 8542/13 पैसा जमा हो चुकी है। नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) न्यास द्वारा अन्य निजी कालोनियों में विकास शुल्क प्राप्त होने पर विकास कार्य करवाये जा सकेंगे।

भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति

45. श्री राम नारायण वर्मा (नैनवा) :- क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सरकारी संस्था अधिनियम के तहत कितने भूमि विकास बैंक हैं और उनकी वित्तीय स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब है, क्या सरकार उनकी

(श्री रामनारायण वर्मा)

हालत को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सहकारी संस्था अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा जिला/उप जिला/खंड स्तर पर 34 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, इनकी 30-6-89 की वित्तीय स्थिति सदन के पटल पर रख दी गई है। [परिशिष्ट "अ" व "ब"]

(2) जी हां। नाबार्ड के सुझावानुसार राज्य के कमजोर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पुनर्वास समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश दि. 1-1-1987 के द्वारा किया गया। इस समिति की बैठक दिनांक 4 मई 1987 में राज्य के क्रमशः 8 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, पाली एवं उदयपुर) का पुनर्वास हेतु चयन किया गया इनकी पुनर्स्थापना के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा निश्चित किया गया है। इन बैंकों को नाबार्ड से 4 लाख रुपये प्रति बैंक के हिसाब से हिस्सा पूंजी अंशदान दिया गया तथा राज्य भूमि विकास बैंक के स्तर पर 40.50 लाख का संदिग्ध ऋण संचय कोष रखा गया है। राज्य के शेष रहे कमजोर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय पुनर्वास समीक्षा समिति में विचार किया जाकर पुनर्वास कार्यक्रम बनाया जावेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

भीनमाल जालौर में 33 के. वी. ग्रिड सब–स्टेशन

46. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) :– क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा ग्राम सेरणा, तह. भीनमाल जिला जालौर के लिए 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 47

(स्थगित)

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन की घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारो वित्तीय समितियों अर्थात् जनलेखा समिति, 1990–91, राजकीय उपक्रम समिति, 1990–91, प्राक्कलन समिति (क), 1990–91 तथा प्राक्कलन समिति (ख) 1990–91 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :—

29

(श्री अध्यक्ष)

(1) मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना	—	दिनांक 26 मार्च, 1990 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक
(2) मनोनयन पत्रों की जांच	—	दिनांक 26 मार्च, 1990 को म. प. 4.00 बजे से
(3) मनोनयन वापस लेना	—	दिनांक 27 मार्च, 1990 के म. प. 3.00 बजे तक,
(4) मतदान यदि आवश्यक हो	—	दिनांक 29 मार्च, 1990 को म. पूर्व 11.00 बजे से म. प. 3.00 बजे तक
(5) मतपत्रों की गणना	—	दिनांक 29 मार्च, 1990 को म. प. 3.30 बजे से

व्यवस्था

व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था सरकारी उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति संबंधी

माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरणा ने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 294 के अन्तर्गत सरकारी उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया है। श्री मदेरणा के कथनानुसार राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन (अधिनियम, 1956 की धारा 5 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सरकारी उप मुख्य सचेतक वह सदस्य नियुक्त होगा जो विधान सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का हो। श्री मदेरणा के अनुसार सर्वाधिक संख्या बल रखने वाला शासक दल भारतीय जनता पार्टी है, अतः सरकारी उप मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही नियुक्त हो सकता है, जबकि वर्तमान सरकारी उप मुख्य सचेतक जनता दल के नियुक्त किये गये हैं जो सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले दल के सदस्य नहीं हैं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (2) के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

"इस धारा के प्रयोजनों के लिए" "सरकारी मुख्य सचेतक" या सरकारी उप मुख्य सचेतक" से राजस्थान विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो इस सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का तत्समय, मुख्य सचेतक या उप-मुख्य सचेतक है।"

जनरल क्लाजेज एक्ट के अनुसार एक वचन (सिंगुलर) वाले शब्द के अन्तर्गत बहुवचन भी आयेगा। अतः यदि कहीं किसी एक वचन के शब्द का उपयोग हुआ हो तो उसमें बहुवचन भी सम्मिलित होता है।

(श्री अध्यक्ष)

इस निर्वचन के प्रकाश में उक्त स्पष्टीकरण में एक वचन के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल" में बहुवचन भी सम्मिलित माना जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में उक्त अभिव्यक्ति का निर्वचन सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दलों के रूप में होगा। चूंकी इस समय शासक दल में दो दल क्रमशः भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सम्मिलित है, अतः जब अभिव्यक्ति "सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल" को बहुवचन के रूप में प्रयोग में लिया जावे तो स्पष्ट है कि सरकारी उप मुख्य सचेतक, शासन में सम्मिलित दोनों दलों में से किसी भी एक दल का सदस्य हो सकता है।

अतः मेरी सम्पत्ति में श्री परसराम मदेरणा, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न सारहीन है।

अब आप इन्फार्मेशन क्या दे रहे थे ?

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, आपकी व्यवस्था तो मुझे शिरोधार्य है लेकिन जो इन्टरप्रिटेशन किया है वह न तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैसेज एक्ट है न ऐसा कोई बिजनैस है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूलिंग को चुनौती दे रहे हैं क्या आप ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रूलिंग को शिरोधार्य माना है वह तो अपनी बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक तरफ रूलिंग को शिरोधार्य माना है और फिर आपने इन्टप्रिटेशन किया है वह गलत है। आप मेरी लाइन पर चलेंगे ना ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : बिलकुल विरोध पक्ष में वैसे ही चलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तब तो ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तो अध्यक्ष जी की, सदन के नेता महोदय रूलिंग शिरोधार्य है। न मुझे उस पर एतराज है और न मैं उसको चुनौती दे रहा हूं। लेकिन एक बिन्दु अध्यक्ष जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन्टप्रिटेशन जो अधिनियम है, एक्ट है उसको यहां पर इनको इन्टरप्रेट करने का अधिकार है चेअर को, आसन को। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनेस में या कान्स्टीट्यूशनल मैटर, बिजनैस के समय में इन्टरप्रटेशन करना आपका अधिकार है लेकिन यह अधिनियम है और अधिनियम इस सदन के द्वारा पारित है, उसमें भाषा, बहुत स्पष्ट है और सम्मानीय सदन के नेता के पास बैठे हुये हैं जनता दल के नेता इनके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है इसलिये मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री नत्थीसिंह : उनकी नियुक्ति मेरी सहमति से हुई है, इसमें कोई कुठाराघात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दूं कि वह अपने स्वयं के कथन को ही काट रहे हैं और मेरी पुष्टि कर रहे हैं। यदि मुझे अधिकार नहीं है इन्टरप्रटेशन का तो फिर उनका क्वेश्चन औचित्य का चला जाता है। उस पर व्यवस्था देने का सवाल नहीं है, मैंने यह इन्टरप्रिटेशन नहीं किया है एप्लिकेशन की है, लॉ एप्लाई किया है। कानून के अन्तर्गत लॉ कैसे एप्लाई किया जा सकता है उसमें जनरल क्लाजेज एक्ट का हवाला दिया है। इसलिये यह एप्लिकेशन का सवाल है।

मैं एक बात की और सूचना कर दूं कि आज शून्यकाल दोनों दलों के नेताओं की सहमति से नहीं है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत।

प्रतिवेदन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1987-88 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक),

(2) वर्ष 1987-88 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां),

(3) वर्ष 1986-87 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

(4) वित्त लेखे वर्ष 1986-87, एवं

(5) विनियोग लेखे वर्ष 1986-87।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1989-90 का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989-90 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वर्ष 1983-84 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन।

अतिरेक मांगें वर्ष 1983-84 का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1983-84 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

घोषणा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों द्वारा अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। अब तक जो स्थिति दलों की है, वह मैं आपके सामने रख देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 6 घण्टे 35 मिनिट दिये थे जिसमें से 4 घण्टे 32 मिनिट उपयोग किये गये। दो घण्टे 3 मिनिट उनके लिए बाकी है। जनता दल को चार घण्टे तीस मिनिट दिये थे। उसमें से तीन घण्टे 53 मिनिट यूज किये उनके 33 मिनट बाकी है। कांग्रेस आई को 4 घण्टे दिये गये थे उन्होंने 6 घण्टे 18 मिनट का उपयोग किया, माइनस 2 घण्टे, यानि कांग्रेस पार्टी का कोई समय बचा नहीं है। 2 घण्टे ज्यादा हो गया। सी. पी. आई. (एम) का दस मिनट बोलना बाकी है। निर्दलीयों को 45 मिनट दिये गये थे जिसमें से 23 मिनट बाकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ? कि पांच बजे माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। अभी जो मेरे पास यह लिस्ट आयी है उस लिस्ट में यदि आप समय को ध्यान में रखते हुये बोलेंगे तो साढ़े चार बजे तक सभी लोग बोल सकते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन चूंकि माननीय हरिदेव जी जोशी बोलने वाले हैं इसलिए एक घण्टा मैं उनको एक्स्ट्रा देता हूं। पांच आदमियों की आपने सूची दी है। एक घण्टे में आपको पांचों को बोलना पड़ेगा।

श्री प्रद्युमन सिंह : मैं एक निवेदन कर दूं। आप स्थान ग्रहण करें तो कर दूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जो सूची आपको प्रस्तुत की है, सचिव महोदय के मार्फत, उसमें मैंने नाम दिये हैं कि हमारे दल की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता को अतिरिक्त समय दिया जाता रहा है वह आमतौर पर कभी भी शामिल नहीं होता है, श्रीमन्। दूसरी बात यह है कि आज पूर्व मुख्य मंत्री पहाड़िया जी और हमारे वरिष्ठ सदस्य मदेरणा जी बोलना चाहते हैं, बाकी नेता महोदय की जैसी इच्छा हो। मदेरणा जी के डिबेट में भाग लेने से सरकार को कुछ लाभ ही होगा, कुछ नये बिन्दु सामने आयेंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो मदेरणा जी को भी थोड़ा वक्त दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिये एक घण्टा दिया है कि आपने जिन माननीय सदस्यों के नाम लिये हैं उनको बोलना आवश्यक है। इसलिए एक्स्ट्रा टाईम दिया है। हरिदेव जी जोशी चार बजे शुरू करेंगे, पांच बजे मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री प्रद्युमन सिंह : श्रीमन्, वह तो सही है, इसका मतलब मैं यह नहीं समझूं हमारे किसी और माननीय सदस्य को बोलने का आज—

श्री अध्यक्ष : यह जो आपने पांच नाम दिये हैं, इनके लिए एक घण्टे का समय एक्स्ट्रा दिया है।

श्री प्रद्युमन सिंह : ठीक है साहब, धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का चार घण्टे का समय था, उन्होंने 6 घण्टे ले लिये। उनको, पहले भी बार-बार हमने निवेदन किया था कि ज्यादा समय मत लीजिए, उसके बावजूद लेते रहे। अब एक घण्टा और दे रहे हैं। कल भी हमने कहा था। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप पुरानी परम्पराएं देख लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले भी ऐसा होता रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय का बंटवारा तो हमेशा हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्टली फोलो नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभी अपने-अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आप सब की आपत्तियां सुन ली हैं। मैंने जो व्यवस्था दी है उस पर मैं कायम हूं। (व्यवधान)

आप भी बोलेंगे, आपका भी नाम लिख लिया मैंने।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो व्यवस्था दी है, उसमें कांग्रेस को एक्स्ट्रा दो घण्टे का टाइम दिया है। क्योंकि दोनों पक्षों की जो विचार धाराएं हैं उनसे मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा भिन्न है और आपने सिर्फ गणित की दृष्टि से समय रखा है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं रखा है इसलिए समय मुझे अलग दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आसन से हर बात का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। आप बोलेंगे, दस मिनट का समय है और आप पांच मिनट अधिक बोलेंगे तो आसन आपको जबर्दस्ती बिठाता नहीं है। यह तो सामान्य बात है।

मैं माननीय सदस्यों से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया बोलते समय अपने समय का ध्यान रखें। दूसरा, ऐसी उत्तेजनात्मक भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं करे जिससे आपके बोलने में व्यवधान पैदा हो। एक माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उसको टोकाटोकी नहीं करे और उसको टोकाटोकी करनी है तो उसकी भाषा को समझिए, वह कैसे की जा सकती है जिसमें रुचि हो सुनने वाले को आनन्द आये। अगर आप किसी पर फब्ती कस रहे है और उसको भी मजा आये तो बात समझ में आती है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं चर्चिल ने हाउस ऑफ कामन्स में एक बार कहा कि

"Half the members of this House are fools."

इससे मतलब नहीं, हाउस ऑफ कामन्स के हैं, इस सदन के आधे सदस्य मूर्ख हैं। जब उसने यह कहा था तो बड़े जोर से हल्ला मचा। कई सदस्यों ने आवाज उठाई कि इसको वापस लो, आपने मूर्ख कैसे बताया तो उसने खड़े होकर कहा

"All right, half are not."

(श्री अध्यक्ष)

खड़े होकर कहा, अच्छा, आधे मूर्ख नहीं हैं। अब देखिये उसने अपनी बात भी रख ली, आधे मुर्ख है आधे नहीं हैं। अपनी बात रखी, लेकिन बात ऐसी कहीं....

श्री परसराम मदेरणा : विन्स्टन चर्चिल ने आगे यह फिर कहा कि

"It is better to look fool rather than open the mouth and prove it."

श्री अध्यक्ष : इस तहत से आप शिष्ट भाषा में चुटकी लेना जानते हैं तो अवश्य लीजिए, लेकिन प्रोवोकेशन करके सदन का समय व्यर्थ गवाना उचित नहीं है, मैं निवेदन करूंगा।

माननीय श्री हीरासिंह चौहान,

श्री शिवचरण माथुर : मेरा निवेदन यह है कि यह नवीं विधान सभा का पहला सत्र है और मेरी जानकारी में पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन रखे गये है। मैं समझता हूं कि थोड़ी देर बैठ कर भी, आप देर से भी जवाब दें तो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सदस्यों का ओप्शन तो रहेगा ही। वह सदन का ओप्शन है। आप चाहे सदन बढ़ाना तो बढाईये, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सदन का जो ओप्शन हैं वह तो है ही। मैं उसे नहीं छीन रहा। मैंने अपनी व्यवस्था दी हैं। सदन चाहे समय बढ़ाना दो घण्टे चार घण्टे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री मोहमम्द माहिर आजाद : आपने 37 मिनट का समय बाकी बताया है। अभी काफी सदस्य बोलने वाले हैं, आधा-पौन घण्टा और समय देने का कष्ट करें। (व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं नदबई से आये हुये माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह जी, जिन्होंने राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, उसको प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने पिछले दो चुनावों में लोक सभा में और विधान सभा में जो इस प्रदेश की पूर्व सरकार असंवेदमशील थी, चारों तरफ अन्धकार छा गया था, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की जिस ढंग से सुनवाई होनी चाहिएथी, जिस प्रकार से एक अच्छी सरकार को कान्फिडेंस लेनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं ली, इसीलिए राजस्थान की जनता को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ हमारे

(श्री हीरासिंह चौहान)

राष्ट्रपिता ने ऐसी कल्पना की थी कि इस देश में राम राज्य आयेगा और राम राज्य आने के साथ ही, आजादी के साथ ही- (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखे, आपस में बात नहीं करें।

श्री हीरासिंह चौहान : देश में खुशहाली आयेगी। एक इस प्रकार का नया राष्ट्र बनेगा, जिसमें चारों तरफ खुशहाली नजर आयेगी। खेतों में हरियाली नजर आयेगी, पानी पहुंचाया जायेगा। कल्पना यह थी कि भारत ऐसा भारत बनेगा जिसमें चारों तरफ खुशहाली होगी। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के 43 वर्ष बाद भी इस देश में और हमारे प्रदेश में चारों तरफ कमियां ही कमियां नजर आ रही है जिन खेतों को हमें पानी देना था, जो व्यवस्था बनानी थी कि हमारे राजस्थान के खेत लहलाते रहेंगे, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आयेगा। गावों में पानी हो, तालाबों में पानी हो, नहरों में पानी हो और इस देश और प्रदेश में खुशहाली आये लेकिन पिछले 40 साल में, जनता राज केवल 2½ साल रहा था, 40 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, उस कांग्रेस की हुकूमत ने इस प्रदेश के 80 प्रतिशत जो किसान हैं जिनके जीवन यापन का एक मात्र साधन खेती है लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुंचाया राजस्थान में अगर सरकार सोचती, इस पर गम्भीरता लेती तो गंगा और यमुना से पानी पहुंचाया जा सकता था और प्रदेश में खुशहाली लाई जा सकती थी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहले यह निवेदन है कि राजस्थान की अगर आर्थिक हालत सुधारनी है, अगर जनता में खुशहाली लानी है तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि चारों तरफ जहां हमारे खेतों में पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचाया जाये। इस समय अपने प्रदेश में जो इन्दिरा गांधी नहर आ रही है, मेरे सम्मानीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि यह राजस्थान नहर थी, राजस्थान प्रान्त की, इस नहर का जो स्वरूप था बहुत बड़ा था लेकिन पिछली शासक पार्टी ने इसको व इन्दिरा गांधी नहर के नाम से इसका नाम परिवर्तित किया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस नहर का नाम पुनः परिवर्तन करके जिस प्रकार से यह राजस्थान के नाम से जानी जाती है, विश्व-विख्यात नहर है, शायद संसार में सबसे बड़ी नहर है इसका पुनः नाम राजस्थान नहर किया जाये।

(12.22 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

और इसी राजस्थान नहर की भांति जिस प्रकार अन्तरर्राज्यीय समझौते होते है उसके अनुसार गंगा से, यमुना से इस राजस्थान प्रदेश को और पानी दिया जाये क्योंकि राजस्थान प्रदेश में इस परकार की कोई अन्तर्राज्य नदिया नहीं बह रही है। एक माही है, एक चम्बल है जहां पर आलरैडी अच्छे-अच्छे डैम बन गये हैं। इनसे जितनी

(श्री हीरासिंह चौहान)

पानी की सप्लाई होनी चाहिये, हो रही है लेकिन जो अन्य शहर है, हमारा पाली जिला है, जोधपुर का बहुत सारा हिस्सा है, अजमेर का हिस्सा है, यह पानी के बिना यहां के किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। उनका रोजगार ठप्प हो रहा है। इस लिये मेरा निवेदन है कि कम से कम इस प्रकार की योजना बनाई जाये और खेतों में पानी पहुंचाया जाये।

माननीय सभापति महोदया, जनता राज के समय 1977 में राजस्थान में परिवर्तन आया था, एक लहर आई थी। यहां पर जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री बने थे। कांग्रेस द्वारा 1977 के पहले इस राजस्थान के बहुत सारे जिलों को ड्राई जिलें घोषित किये थे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और पाली और प्रकार के दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में भी मद्य निषेध नीति लागू करके पूर्व सरकार ने मद्य निषेध लागू किया था। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने हिम्मत करके पूरे राजस्थान में मद्य निषेध की नीति लागू की लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1980 में गये, श्रीमान पहाडिया साहब का शासन आया, शराब की नीति को तोड़ कर कर पूरे प्रदेश में होटलों की तरह शराब की दुकानें लगाई गई ...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, इस बात पर थोड़ा विचार कर लें। मैंने नशबन्दी को लगातार चालू रखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय पहाड़िया साहब से माफी चाहूंगा, मैंने दो चार पूर्व के सदस्यों से जानकारी ली थी, उन्होंने ऐसा बताया। शासन बदला था, उसी समय इस मद्य निषेध नीति को तोड़ दिया गया था। शिवचरण माथुर साहब ने इस नीति को तोड़ा, तोड़ा ही नहीं, जिस नीति को लागू किया मैं उस नीति की तरफ इंगित करना चाहता हूं। पुराने समय में जो छोटे छोटे ठेकेदार थे, गांव में ठेके लेते थे और जगह जगह कोटा सिस्टम से बिक्री होती थी लेकिन इन्होंने तो एक बहुत बड़ा रेकेट बना दिया, जिसे कहना चाहिये पूंजीवाद का रेकेट बना दिया, कि दो-दो, तीन-तीन चार-चार जिलों में इस प्रकार से ठेकेदारों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाकर के ग्रुप में ठेका लेना शुरू किया। आप ताज्जुब करेंगे, शराब के दामों में भारी परिवर्तन आया। एक शराब की बोतल बर में पचास रुपये में मिलती है, वही शराब की बोतल जयपुर में 110 और 120 रुपये मिलती है ब्यावर में 90 रुपये में और अजमेर में 100 रुपये में मिलती है यह है अंग्रेजी शराब की कीमत। देशी शराब के बारे में कहना चाहता हूं वास्तव में गुलाब या प्लेन की मूल कीमत 14 या 15 रुपये है लेकिन जयपुर में 50 और 100 रुपये लेते है, अजमेर में इसके 30, 40 रुपये लेते हैं ब्यावर में 40–50 रुपये लेते है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, एक चीज, एक माल....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप कहां से खरीदते है ?

श्री हीरासिंह चौहान : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर से निवेदन करना चाहता हूं मैं ऐसी बात कह रहा हूं, जिसको बहुत से लोग उपयोग में लेते हैं और लूट हो रही है। मैं कहां से खरीदता हूं मेरे खरीदने का सवाल नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, अपने को उसका अनुभव नहीं होता है, अपन उसको उपयोग में नहीं लेते हैं लेकिन लूट खसोट हो रही है चारों तरफ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप आगे होकर बता रहे हैं सस्ती कहां मिलती है।

श्री सभापति : आपस में डायलाग नहीं माननीय सदस्य,

श्री हीरासिंह चौहान मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व वर्षों में भी मैंने और पूर्व सदस्य नाथूसिंहजी ने कई बार इस सवाल को उठाया था कि इस नीति में परिवर्तन किया जाये। यह जो जगह-जगह तरह-तरह के भाव चल रहे हैं, इसका मतलब ठेकेदार की मर्जी से माल बिकता है और इसके अलावा देशी शराब की बोतलों की सफाई नहीं होती है। हर उपभोक्ता को जो चीज देनी चाहिये उस पर लिखा होना चाहिये कि शुद्ध है। इनकी बोतलों की सफाई नहीं होती। इन पर कार्क नहीं होते। बोतलों के अलावा अध्धा और पव्वा देशी शराब में मिलता नहीं है। इसलिये इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि क्योंकि अभी मार्च का महीना है, ठेके हो जायेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले में एक कमेटी बनायी जाये और यह तय किया जाये कि देशी शराब का वितरण किस प्रकार राजस्थान में चालू रखा जाये और उसकी क्या नीति होनी चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कमेटी बना दी जाय और उस कमेटी में यहां के माननीय सदस्यों को भी शामिल किया जाये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय जनार्दनसिंह जी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, कमेटी में इस सदन के ही सदस्य होते हैं और जो इस प्रकार की अन्धाधुन्ध बिक्री चल रही है, लूट खसोट चल रही है, अगर इसको हम भी चालू रखेंगे तो हम भी जिम्मेदार होंगे। इसलिये इस नीति को पुनः एक कमेटी बनाकर तय किया जाये, किस प्रकार देशी शराब का प्रचलन इस राज्य में रखा जाये। भावों में असमानता नहीं होनी चाहिये। एक चीज का एक भाव होना चाहिये। और हर बात में उपभोक्ता को शुद्ध चीज मिलनी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इसको बन्द ही करवा दो। काहे को इसके चक्कर में पड़ते हो, पूरा ही बन्द करवा दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इनको छोड़कर बाकी सबके लिये बन्द करवा दीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सरकार के सोचने का काम है। मेरा निवेदन करने का काम है। सरकार उसको बन्द

(श्री हीरासिंह चौहान)

करवाये या चालू रखे लेकिन इसमें जो भेदभाव चल रहा है, भावों में ऊंच नीच चल रही है, उसके बारे में निवेदन कर रहा था।

मेरा दूसरा निवेदन है। जनता राज में पंचायत राज संस्थाओं को बहुत मजबूत किया गया था। पंचायत राज संस्थायें यहां की प्राथमिक इकाईयां होती है और गांव की प्राथमिक इकाई के साथ में उसका बाकायदा एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के तहत वह पंचायत काम करती है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो जनता राज के समय में इन पंचायत राज संस्थाओं को बहुत अधिकार दिये गये थे और अधिकार देने के बाद उनको दस-दस हजार के काम करने के पावर दिये गये और उनके अनुदान की राशि, सन् 1960 में पंचायतों का चुनाव होना शुरू हुआ था, 1960 से लेकर 1978 तक पूर्व कांग्रेस सरकार ने इनको केवल चार आने दिये लेकिन जब जनता राज आया चार आने की जगह 2।। रुपये किये। और 2।। करने के बाद उनको कुछ अनुदान की राशि मिलने लगी, पंचायतें कुछ सक्षम हुई, कुछ काम करना शुरू किया लेकिन कांग्रेस सरकार ने सन् 1988 में चार आने और बढ़ाये और 2।।। रुपये कर दिये लेकिन जैसा मेरे पड़ौस में माननीय लक्ष्मीनारायण जी जो सौजत के विधायक हैं वह कह रहे हैं, वह प्रधान भी रहे हुए है, कि वह चार आने की अनुदान की राशि भी अभी तक पंचायतों को नहीं दी है और जबकि उसी बजट वर्ष में नगरपालिकाओं को जो पांच रुपये मिलते थे उसकी जगह दस रुपये कर दिये। यह एक भेदभाव पूर्ण नीति है क्योंकि नगर और गांव दोनों को रख रखाव के लिये अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा इसमें निवेदन था कि यह जो 2।।। रुपये की राशि की गई है, पंचायत की अनुदान की राशि बढ़ाकर पांच रुपये की जाये। यह जो प्राथमिक इकाई की गांव की संस्था है यह बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना चाहती है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि गांव में कौन-कौन से काम जरूरी हैं, उस जनता राज में जहां सक्षम सरपंच थे, वार्ड पंच थे, उन्होंने बहुत भवनों का निर्माण करवाया, बडे-बडे स्कूल के भवन बनाये, औषधालय बनाये, नई सड़कें बनाई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और कहीं पर सिंचाई के लिये पीने के पानी के लिये पोखर आदि का निर्माण कराया तो मेरा निवेदन है कि इस पंचायती राज को सुदृढ़ किया जावे। उनको अधिकार दिये जावे। पिछली सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिये थे उसको घटा दिया इसके साथ एन. आर. ई. पी. आर. एल. ई. जी. पी. इस प्रकार की योजनायें लागू करके उसमें रद्दोबदल किया जावे और पंचायतों को सक्षम किया जाये ताकि स्थानीय इकाईयां गांवों का विकास कर सके। आफिसरों के भरोसे गांव का विकास नहीं हो सकता। जिला कलक्टर या अधिकारी जिनके हाथों हमने बडे–बडे काम सौंप रखे हैं, उनके भरोसे गांवों का विकास नहीं छोड़ा जा सकता है। सभापति महोदय मैं उदाहरण देना चाहता हूं, डी. डी. पी.

(श्री हीरासिंह चौहान)

डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हमारे छः जिले पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर आते हैं। इसमें तीस करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत सरकार देती है लेकिन यह तीस करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पाता है। यह जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है। कई बार हमने जिला लेवल पर बैठ कर के, पूर्व मंत्री श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत जब पाली आते थे, हम उनको निवेदन करते थे, एक बार जब फरवरी में आये थे उस समय तक करोड़ों रुपया बेलेन्स में पड़ा था। मैं इस वर्तमान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस राशि का सदुपयोग हो, समय पर सदुपयोग हो, जनप्रतिनिधि जिस काम को इंगित करे, जनहित में काम जहां चाहे वहां हो और वह राशि समय पर खर्च हो जाये क्योंकि वह राशि लेप्स होती है और बाद में उसका उपयोग नहीं होता है। वह जो विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं का पैसा हमारे प्रदेश को मिलता है, उसका सदुपयोग करने के लिये, किस प्रकार खर्च किया जाये, उसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बने और मार्च के बजट पूर्व यह खर्च हो जाना चाहिये इस प्रकार की नीति लागू करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान: सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है, स्वच्छ प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। यह हमारी सरकार की नीति है कि हम किस-किस प्रकार के कार्य करना चाहते है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो भ्रष्टाचार कहां हो रहा है। पहले हम नीचे के स्तर पर जायें, पुलिस स्टेशन पर भयंकर भ्रष्टाचार होता है। पटवारी, रेवेन्यु इन्सपेक्टर के यहां भ्रष्टाचार होता है, जहां लोग रजिस्ट्रियां करवाते हैं, वहां भ्रष्टाचार होता है। वन विभाग है। छोटे–छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें इसके लिये तहसील स्तर पर एक कमेटी बनानी पड़ेगी और ऐसे लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी कि प्रति माह उसकी एक बार बैठक हो। इसके साथ ही कौन-कौन भ्रष्ट आफिसर है, किस-किस प्रकार की रिश्वतखोरी वहां पर चलती है बाकायदा उसकी रिपोर्ट हो इस प्रकार से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

तारानगर से आने वाले हमारे सदन के वयोवृद्ध सदस्य ने यह कहा कि यह तो विपक्ष ने एक नारा दिया था। विपक्ष ने हल्ला गुल्ला बहुत मचाया कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। इसलिये जनता ने आपको जनादेश दे दिया। वास्तव में यह बात नहीं है। वास्तविक बात यह है कि पिछले शासन काल में जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। चारों तरफ की व्यवस्था चरमरा गयी थी। उसे चरमराई व्यवस्था को बदलने के लिये लोग आतुर थे और लोगों ने उसको बदला। अब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जिस उमंग और आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को जो जनादेश दिया गया है उसको पूरा करने के लिये जो वायदे, घोषणायें हमने की है उनको

(श्री हीरासिंह चौहान)

हमें तत्काल पूरा करना पडेगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था देनी पडेगी कि जनता यह महसूस करे कि वास्तव में शासन बदला है। बदली हुई शासन व्यवस्था में राजस्थान आगे बढ़े। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सारी व्यवस्था पर पुनर्विचार करे ताकि जनता यह महसुस कर सके कि पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में बहुत अन्तर है। यह अन्तर महसूस करवा सकें और जो वायदे हमने घोषणा पत्र में किये हैं, जनता के साथ जो वायदे कर चुके हैं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दस हजार के कर्जे माफ करना है। केन्द्रीय सरकार के बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं...

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : 15 से आगे की बात करो।

श्री हीरासिंह चौहान : 15 तो आप लोगों ने किया था। हमने 10 का कहा है और दस ही करेंगे। आपने केवल कागजी घोषणा की थी। हमने कागजी घोषणा नहीं की है। वास्तव में इसको लागू करेंगे। आपने तो स्थगित किया था उसके बाद भी कुर्कियां आई। हम वास्तव में कर्जा माफ करना चाहते हैं। आपकी नीयत साफ नहीं थी। हमारी नीयत साफ है हम साफ नीयत के साथ काम करना चाहेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो वायदा किया गया है उसको पूरा करें।

अंत में सभापति महोदया मेरे क्षेत्र के बारे में दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने दस मिनट का समय तय किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : संक्षेप में दो मिनट।

सभापति महोदया, 1968 में हमारे एरिया में रायपुर बांध बनाया गया था। इस रायपुर बांध के बनने के बाद से उसके नीचे के 20 गांव बिलकुल ड्राई हो गये, उनके कुएं सूख गये और जो एकमात्र परिवार के पालन पोषण का जरिया था खेती के द्वारा वह बिलकुल बंद हो गया। मेरा निवेदन है कि रायपुर बांध का पानी रायपुर नदी में दिया जाना नितान्त आवश्यक है। यह हमारे किसानों की मांग है। कमाण्ड एरिया इस एरिया का बहुत थोड़ा है, दस हजार है परन्तु पानी इतना कम आता है कि मुश्किल से तीन, चार हजार बीघा जमीन की पिलाई होती है लेकिन शेष नीचे के 15/20 गांव बिलकुल ड्राई हो जाते हैं। इसलिये मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका प्लान बनाया जाये कि क्या मौजूदा नहर से नदी में पानी छोड़ा जाये या जो आउटलेट है उसको कम किया जाये या आउटलेट के पास एक दूसरी छोटी मोरी निकाल कर के, बहुत लम्बाई नहीं है, 15 किलोमीटर तक नदी में पानी देना है और पिलाई भी कुछ नहीं होती है और इस बांध से ज्यादा रेवेन्यु भी नहीं मिलती है, लेकिन किसान तबाह हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बांध को खोलने की व्यवस्था की जाये।

दूसरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी आती है। यह बहुत

(श्री हीरासिंह चौहान)

सुखी है, हरी भरी नहीं है इसलिये अरावली पर्वत विकास मण्डल बनाया जाये जैसी कि पूर्व में माननीय हरिदेव जोशी ने 1987 के बजट में केन्द्रीय सरकार से सहायता लेकर अरावली-पर्वत श्रेणी को हरा भरा बनाने की योजना बनायी थी। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि भारत सरकार इसकी मन्जूरी दे रही है। सभापति महोदया, राज्य में स्थिर मुख्य मंत्री नहीं होता है तब तक विकास नहीं होता है। इनके आपस के झगड़े चलते रहे और इस उठा-पटक में कई योजनाएं रह जाती हैं। हम जनता से वायदा कर के आये हैं स्थिर सरकार देंगे। स्थिर सरकार का अर्थ है राज्य मुख्य मंत्री स्थिर हो। उसको सारे प्लान याद रहते हैं, सारी योजनाएं याद रहती हैं। यदि उसमें रद्दो-बदल होता है तो सारी की सारी योजनाएं खटाई में पड़ जाती हैं। इसके लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोमला में श्री सुखाड़िया जी के समय एक बांध बनाया गया था ब्यावर को पेयजल देने के लिये। उस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये। बांध बनाया गया और एक नहर खोदी गयी कम से कम 40 किलोमीटर तक लेकिन बाद में वह वहां की वहां रह गयी। नहर से पानी नहीं आया। प्रशासन बदला, राज्य के मुख्य मंत्री बदले तो सारी योजनाएं बदल जाती हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने 1987 में यह घोषणा की थी कि अरावली पर्वत को हरा भरा किया जायेगा, उसमें एनीकेट बनाये जायेंगे, फलदार दरख्त लगाये जायेंगे और साथ ही इस प्रकार की योजना बनायी जायेगी कि लोगों को रोजगार मिले।

श्री रामसिंह विश्नोई : मौजूदा मुख्य मंत्री को कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय रामसिंह जी, जिस जनादेश के साथ हम आये हैं, हमारा कार्यकाल पूरा करेंगे। उसके बाद भी मैं आपको विश्वास देता हूं कि हम इतना अच्छा काम करेंगे कि आप वापस शासन में आना भूल जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : हम वास्तव में पूरी व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि अरावली पर्वत मण्डल बनाया जाये, उसको लागू किया जाये। समय का अभाव है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भंडारी।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य गण, आप सभी को प्रणाम करती हुई...

श्री सभापति : केवल चेयर को सम्बोधित करें।...

माननीय सदस्या, पहली बार बोल रही हैं।...

श्रीमती तारा भंडारी : सभापति महोदया, मुझे मालूम नहीं था।

(श्रीमती तारा भंडारी)

निवेदन करती हूं कि जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, जिन आकांक्षाओं के साथ हमें इस सदन में चुन कर भेजा है उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये जनता पिछले चालीस वर्ष से इन्तजार कर रही है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, फिजूलखर्चों एवं अव्यवस्थाओं से नाराज होकर जनता ने हमें यह जनादेश दिया है। अतः हमारा यह पहला कर्तव्य होगा कि जनता ने जिन भावनाओं के साथ चुन कर हमें यहां भेजा है इसलिये सर्वप्रथम उनको पूरा करने का प्रयास करें। जो व्यवस्था हमें विरासत में मिली है उसमें भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है और रिश्वत का नाम कमीशन पड़ चुका है। ऐसी कठिन परिस्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय एवं राजस्थान की नई सरकार ने स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन देने का जो बीड़ा उठाया है वह न केवल धन्यवाद के योग्य है बल्कि एक सराहनीय कदम है। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण से राजस्थान की सरकार को एक नई दिशा मिली है। राजस्थान की प्रगति का द्वार खुला है।

राजस्थान खनिज सम्पदाओं से भरपूर एक साधन सम्पन्न प्रान्त है, यहां का निवासी जुझारू प्रकृति का है। हर कठिन परिस्थिति में कठोर परिश्रम करके, संघर्ष करके जीने की क्षमता रखता है। परन्तु पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज राजस्थान सबसे पिछड़ा प्रान्त माना जाता है। पिछले चालीस वर्षों में यह सरकार बिजली, शिक्षा, रोजगार, आवास चिकित्सा इत्यादि मूलभूत सुविधाएं भी समुचित रूप से नहीं दे पायी है। यहां तक कि राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल का एक गिलास भी मुहैया नहीं करा पाई।

सभापति महोदया, आज सिरोही जिले में पेयजल समस्या भयंकर रूप ले चुकी है। पानी प्राप्त करने के लिये हमारी बहिनें रोज ही लड़ती हैं, भाई-भाई का दुश्मन हो रहा है, पड़ोसी-पड़ोसी का दुश्मन हो रहा है। रोज मुकदमेबाजी चल रही। सिरोही जिले के कई गांवों का पानी इतना खारा है कि आदमी तो क्या जानवर भी नहीं पी सकता। सभापति महोदया, पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमान राजीव गांधी जब सिरोही पधारे तो मैंने उस पानी का एक चुल्लु भर कर श्रीमान राजीव गांधी को प्रस्तुत किया था पीने के लिये। परन्तु फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्रीमती तारा भंडारी : सभापति महोदया, भगवान किसी को विकलांग बनाये तो मंजूर किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है लेकिन चालीस वर्ष बाद भी यदि पीने के पानी को पीकर भला चंगा आदमी कुबड़ा और टेढ़ा मेढ़ा हो जाय तो ऐसी सरकार को किस उपाधि से अलंकृत किया जाय यह फैसला मैं सदन पर ही छोड़ती हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब पानी पीयेंगे वह कुबड़े नहीं होंगे।

श्रीमती तारा भंडारी : जो कुबड़े हो चुके उनका इलाज क्या होगा ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह कालीचरण सराफ कर देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : इनकी गलती नहीं थी, जोशीजी की सरकार विकलांग थी।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्रीमती तारा भंडारी : सभापति महोदया, यदि आपको मेरी बात आश्चर्यजनक लगे तो मेरे क्षेत्र शिवगंज तहसील के गांव सगालिया, अंडोर, लोटीवाड़ा, उम्मेदगड़ा, गोला बुडेरी आदि गांवों के पानी की जांच करवा लें। शिवगंज जैसा आज व्यावसायिक रूप से समृद्ध है, पूर्व में पानी एवं सिंचाई के लिये समृद्ध था। जवाई बांध के निर्माण से पूर्व वहां पर हर 10—15 फीट पर पानी उपलब्ध था परन्तु जवाई बांध के निर्माण से वहां का भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया, सिंचाई के समस्त स्रोत सूख गये। आज स्थिति यह है कि जिन घरों में पेयजल हेतु हैंडपम्प लग गये थे उसी शिवगंज के हर दरवाजे पर पानी लेने के लिये दस दस फीट गहरे खड्डे खोदे गये हैं। आज पानी के लिये जनता में त्राहि त्राहि है। रोज महिलाएं खाली मटकों से प्रदर्शन करती हैं, परसों भी किया है, आज मेरे पास तार आया है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से नई सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है, यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाये गये तथा जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो जनता हमारा पानी उतार देगी। सिरोही को पेयजल देने के लिये तथा जवाई बांध से शिवगंज को पेयजल देने के लिये दोनों ही स्थानों की योजनाएं पिछली सरकार के पास विचाराधीन थीं। मैं आपके माध्यम से नई सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि उन योजनाओं पर विचार करके शीघ्र ही सिरोही की जनता को पेयजल किल्लत से मुक्त कराया जाय।

सभापति महोदया, निरन्तर पड़ते अकाल एवं वर्षा की कमी के कारण सिरोही जिले के कुओं का जलस्तर बहुत ही नीचे चला गया है। पानी एवं बिजली की भारी कमी के कारण हमारा काश्तकार अपने प्रिय पुश्तैनी धन्धे को छोडकर गुजरात की ओर पलायन कर रहा है। हिन्दुस्तान का अन्नदाता आज दाने दाने को मोहताज है। ग्रामीण गृहणियां निराई और बुवाई के काम को प्रायः भूलती सी जा रही है। आज किसान का बेटा बेरोजगारी की हालत में दिशाहीन हो गया है।

सभापति महोदया, आज मेरे क्षेत्र की जनता सूकड़ी इनडेशन योजना जिसे पांचतेला बांध भी कहा जाता है, का कार्य प्रारम्भ होने की आशा लगाये बैठी है। यह बांध पूर्व में बना हुआ था परन्तु रखरखाव के अभाव में बह गया। इसकी नहरें आज भी यथावत हैं मात्र बांध के निर्माण से 3066 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सभापति महोदया, यह योजना पूर्व सरकार के पास विचाराधीन थी। मैं आपके माध्यम से नई सरकार को निवेदन

(श्रीमती तारा भंडारी)

करना चाहती हूं कि इस योजना को शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाय तथा सिरोही जिला मरुस्थल में परिवर्तित नहीं हो जाय उससे पूर्व इसे मरु विकास कार्यक्रम में जोड़ा जाकर सिरोही की जनता को लाभान्वित किया जाय।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की नई सरकार का ध्यान सिरोही जिले की सूखती हुई फसलों एवं भीषण अकाल की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। सभापति महोदया, जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं, महिला समुदाय बड़े ही करुण और मार्मिक शब्दों में कहती है, बहिनजी, फेमिन ही लाट्यो, भूखा मरां। महिलाओं को अपना घर चलाना पड़ता है, परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। आज की भीषण महंगाई और अकाल की मार ने उनकी कमर तोड़ दी है। अकाल उनकी नियति बन चुका है। सभापति महोदया, मुझे हार्दिक खुशी है कि नई सरकार ने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया है तथा अकाल राहत कार्यों के बारे में पंचवर्षीय योजना बनाने का मानस बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है, लोगों के पास खाने के लिये अनाज है नहीं। अतः सिरोही जिले में तुरन्त ही अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किया जाय तथा पिछले बकाया भुगतानों की व्यवस्था करायी जाय।

शिक्षा के नाम पर अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी आज राजस्थान का शिक्षा स्तर जो चालीस वर्ष पूर्व था, वही है। आज सिरोही जिले का शिक्षा स्तर 20% है उसमें भी ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा स्तर 1% से भी कम है। गांवों में शिक्षण संस्थाओं की भारी कमी है। सड़क सम्पर्क एवं साधनों की कमी होने के कारण शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। बालकों को गांवों से बाहर भेज करके पढ़ाने की माता-पिता की क्षमता नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई रुक जाती है। जहां स्कूल स्वीकृत है, वहां भवन नहीं है और जहां भवन है तो अध्यापक नहीं है। आये दिन छात्रों को अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए आन्दोलन करना पड़ता है। संस्कृत विद्यालय की हालत तो इससे भी बुरी है। सिरोही तहसील का बावनी गांव के संस्कृत विद्यालय में 250 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही अध्यापक थे। छात्रों ने आन्दोलन किया, धरना दिया तब सरकार ने झाड़ोली गांव के स्कूल से तीन अध्यापकों को बावनी गांव में नियुक्त किया। नतीजा यह हुआ कि आज दोनों विद्यालयों के छात्र स्टाफ की कमी के कारण नुकसान उठा रहे हैं।

मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि सिरोही जिले के समस्त विद्यालयों में, जहां भी आवश्यक हो, भवन, स्टाफ एवं शैक्षणिक साधनों की पूर्ति की जाय। सिरोही के बराड़ा, महादर, ऊड़, अठवारा एवं गोयली में सैकेण्डरी विद्यालय खोले जाय। चूनी एवं छीबा गांव में मिडिल स्कूल खोले जाय। प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र शिवगंज में कई सालों से कॉलेज की मांग चली आ रही है। मैं आपके माध्यम से नई सरकार से निवेदन करती हूं कि शिवगंज में कॉलेज तथा सिरोही मुख्यालय पर

(श्रीमती तारा भंडारी)

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करके सिरोही की जनता को कृतार्थ किया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती तारा भंडारी : दो मिनट। सभापति महोदया, बेरोजगारी की समस्या उद्योगों से जुड़ी हुई है। सिरोही जिले को पिछड़ा क्षेत्र मानकर उद्योगों का विस्तार तो वहाँ हुआ लेकिन आज उद्योगों की हालत बड़ी खराब है। उद्योग प्रारम्भ होने के साथ ही बीमार अवस्था में चल रहे हैं। शिवगंज के अधिकांश उद्योग आज बीमार अवस्था में है। बिजली एवं पानी की औद्योगिक क्षेत्र में भारी कमी है। ऊपर से आर. एफ.सी. द्वारा लोन देने के 18 महीने बाद ही वसूली की किश्तें प्रारम्भ हो जाती हैं। इतने कम समय में बिजली पानी आदि के कनेक्शन होकर उत्पादन शुरू नहीं हो पाता। उद्योग लगाने में व्यवसायियों को बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से आर. एफ.सी. की धमकियों के कारण शिवगंज के औद्योगिक क्षेत्र की हालत बड़ी खराब है। उद्योगों को केन्द्र एवं राज्य से मिलने वाली सबसिडी भी बन्द हो गई है। इसके कारण सिरोही मुख्यालय पर औद्योगिक विकास की सम्भावना कम होती जा रही है।

सिरोही में बेरोजगारी की समस्या भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। रोजगार के अभाव में हमारे नौजवानों में निराशा आती जा रही है। सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उद्योगों को प्रोत्साहन देने एवं औद्योगिक नीतियों पर विचार करने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि सिरोही में औद्योगिक विकास के लिए पूर्व की तरह सब्सिडी पुनः प्रारम्भ की जाय। शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में पानी एवं बिजली की आपूर्ति विशेषतया की जाय। औद्योगिक क्षेत्र को बिजली सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय की स्थापना जोधपुर की बजाय सिरोही में की जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती तारा भंडारी : उद्योगों से फैलने वाले प्रदूषण को भी रोकने के लिए कारगर कदम उठावें क्योंकि शुद्ध पर्यावरण भी हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। आज पिंडवाड़ा एवं आबू में लगी सीमेंट फैक्ट्रियां बड़ी भारी मात्रा में प्रदूषण फैला रही है। जे. के. सीमेंट फैक्ट्री द्वारा वहां के आदिवासियों की भूमि कौड़ियों के माल ली गई और उन्हें रोजी रोटी से मोहताज करके जंगल काटने को विवश किया गया। इसका असर भी पर्यावरण पर पड़ रहा है। जे.के. फैक्ट्री द्वारा होने वाले प्रदूषण से वनस्पति एवं आदिवासी जीवन के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

सभापति महोदया, पिछली सरकार द्वारा काश्तकारों का बनास बांध का पानी जे. के. फैक्ट्री को दिया गया जिससे समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। सिंचाई के साधनों की भारी कमी होते हुए भी किसानों के हक का पानी जे. के. फैक्ट्री को दिये जाने से वहां के काश्तकारों में भारी रोष है।

(श्रीमती तारा भंडारी)

उन्होंने कई बार आन्दोलन भी किया परन्तु कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट नुमाइन्दों के बिचौलिएपन के कारण इस समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। हरे-भरे जंगलों से भरपूर अनूठा सौन्दर्य एवं बेजोड़ कला के कारण विश्व में विख्यात आबू की पहाड़ियां आज अपनी पेड़ों से रहित नग्न अवस्था पर आंसू बहा रही हैं होटलों के बढ़ते हुए व्यवसाय और वनों की निर्मम कटाई के कारण आबू अपनी शीतलता खो रहा है। इसी कारण वर्षा की साल दर साल कमी होती जा रही है। यही कारण है कि सिरोही जिले में हमेशा अकाल की छाया मण्डराती रहती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से नई सरकार को यह कहना चाहती हूं जिसका अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है। पर्यावरण हमारे जंगलों के लिए अति आवश्यक है। अतः इसको शुद्ध रखने के लिए सिरोही जिले के पेड़ों की निर्मम कटाई रोकी जाय।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्या, यह ठीक है कि आपकी मैडन स्पीच है। मगर अध्यक्ष महोदय ने समय सीमा बांध रखी है।

श्रीमती तारा भंडारी : एक मिनट, सभापति महोदया, चिकित्सा की स्थिति हमारे जिले की बडी खराब है। सिरोही जिला मुख्यालय का अस्पताल असुविधा से भरा पड़ा है। पानी की कमी के कारण गन्दगी का साम्राज्य हो रहा है। एक्स-रे और सब मशीनें खराब है और गरीबों के लिए दवाओं का वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। सभापति महोदया, वहां 471 विभिन्न पदों की जो पोस्टें हैं उनमें 150 से अधिक रिक्त पद पिछली सरकार के खोखलेपन को दर्शा रहे हैं। हमारे जिले में कई गांव तो ऐसे हैं जहां चिकित्सा सुविधा बिल्कुल नहीं है। यदि वहां का व्यक्ति बरसात के दिनों में बीमार हो जाय तो उसका इलाज परमात्मा ही कर सकता है। वाडका, मोजाल, लखमावा और तलेटा इस प्रकार के गांव हैं कि बरसात आती है तो वहां टापू बन जाता है और वह किसी भी प्रकार की जन सुविधा से वंचित हो जाते हैं।

सभापति महोदया, अन्त में मैं नई सरकार को शुभ कामनाएं देती हुई यही निवेदन करती हूं कि सिरोही जिले के इतिहास में पहली बार भा.ज.पा. को भारी बहुमत मिला है। जनता ने कांग्रेस का सफाया करके विकास के प्रति आस्था रखकर हमें यहां भेजा है। अतः मैं निवेदन करती हूं कि नई सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सार्थक करेगी। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय, का अभिभाषण किसी भी प्रादेशिक सरकार के विगत वर्षों की उपलब्धि और आगामी नीतियों और कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। विगत सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना करूं, खास तौर से ऐसे वक्त जब यह सरकार सत्ता खोकर विपक्ष में बैठी है तो मुझे एक दोहा याद आता है कि "बीती को बिसारिये,

(श्रीमती मदन कौर)

आगे की सुधि लेय", और वर्तमान सरकार को चूंकि उतने थोड़े दिन हुए हैं काम सम्भाले, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूं या प्रशंसा करूं तो मैं समझती हूं कि उसके लिए भी कोई उपयुक्त समय नहीं है। फिर भी वर्तमान मुख्य मंत्री ने 77-79 के वर्षों में जनता सरकार का नेतृत्व किया था उस समय भी उस शासन की "अन्त्योदय' और "काम के बदले अनाज योजना की मेरे जैसे सदस्यों ने विरोध पक्ष में बैठ कर भी सराहना की थी। "अन्त्योदय' यानि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सहारा मैं समझती हूं कि किसी भी सरकार के कल्याणकारी होने के दावे को प्रमाणित करती है। लेकिन, सभापति महोदय, असहाय और गरीब को तो मदद मिले इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन इस देश और प्रदेश में एक ऐसा वर्ग भी उपस्थित है जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति के आधार पर अपने सीमित आर्थिक साधनों के आधार पर मेहनत करता है, जोखिम उठाता है, अपने पांवों पर खड़ा होने का प्रयास करता है और इस क्रम में देश को भी कुछ देता है। उस मेहनतकश और परिश्रमी वर्ग का कौन सहारा बनेगा? उसको सम्बल कौन देगा। मैं समझती हूं कि यह राज्य सरकार का दायित्व है। ऐसे मेहनतकश और परिश्रमी वर्ग को सम्बल दें, उसे समाज और शासन के शोषण से बचायें, यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए ता कि उस वर्ग से दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। मेरा ऐसा विचार है कि इस मंत्र के अलावा देश को समृद्ध बनाने, देश को मजबूत बनाने का और कोई रास्ता इस सरकार के पास नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदया, विभिन्न सरकारें समय-समय पर अपने राज्य के विकास की गति के आंकड़े पेश करती आयी हैं। कोई भी सरकार अस्पताल बना सकती है, स्कूलें खोल सकती हैं, बांध और नहरें बना सकी है, सड़कों का निर्माण करवा सकती है। लेकिन मैं आज इस सदन के सामने यह सवाल रखना चाहती हूं कि विकास की गति को क्या सीमित आंकड़ों में मापना पर्याप्त होगा? क्या चरित्र निर्माण के अभाव में यह सारे विकास के आंकड़े अर्थहीन साबित नहीं हो जायेंगे? पंजाब ने विकास के कौन से कीर्तिमान स्थापित नहीं किये थे? बांध वहां थे, नहरें वहां थीं, सड़कें वहां थीं, विश्वविद्यालय थे, अस्पताल थे, उद्योग धन्धे पनपे थे, हरित-क्रान्ति थी। इसलिए मैं इस मौजूदा सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस नये जनादेश को, इस सत्ता के नये परिवर्तन को, व्यवस्था के परिवर्तन का माध्यम बनाये और ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनायें जिसमें इन्सान को सच्चा इन्सान बनने का अवसर मिल सके। यही एक रास्ता है जिससे यह नयी सरकार इस प्रदेश की बेहतर सेवा कर सकेगी।

माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की चर्चा की थी और इसी सन्दर्भ में मुख्य मंत्री पद को स्वयं मुख्य मंत्रीजी की पहल पर लोकायुक्त के दायरे में लेने का निर्णय किया गया है। मैं इसका स्वागत करती हूं। लेकिन आज

(श्रीमती मदन कौर)

भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, भ्रष्टाचार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इस एक निर्णय से, इस शार्ट ट्रीटमेण्ट से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं होगा। इसलिये जब भ्रष्टाचार को शासन ने ही नहीं समाज ने भी एक तरफ से मान्यता प्रदान कर दी है कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई दुराव तक नहीं और यहां तक कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक बड़ी गम्भीर चुनौती है इस भ्रष्टाचार को मिटाने की। अगर समय रहते इस भ्रष्टाचार के राष्ट्रीय स्वरूप पर प्रहार नहीं किया गया तो जो स्वच्छ सरकार देने का हमारा सपना है वह धरा का धरा रह जायेगा। माननीय सभापति महोदया, इसी सन्दर्भ में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन पदों पर, जिन विभागों में भ्रष्टाचार की अधिक सम्भावना हो, जो भ्रष्टाचार के प्रति अधिक सम्वेदनशील हो, उन विभागों और पदों पर सरकार को चाहिये कि खास तौर से निगरानी रखे और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें भ्रष्टाचार की रोक थाम का काम सौंपा जाय उन्हें भारी आर्थिक इनाम देकर बोनस देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और इसके साथ ही साथ ऐसे कुशल ईमानदार और प्रतिभाशाली जन सेवकों को यदि पदोन्नति में, पद स्थापन में नियम और प्रक्रिया से अलग हट कर के भी कोई राहत मिल सके तो इसमें मैं समझती हूं कि प्रदेश का लाभ होगा। इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ पकड़ने की ही प्रक्रिया नहीं आय के अनुपात में लोगों के पास कितनी अर्जित सम्पत्ति है, कितना खर्चा है, उनके रहन सहन का क्या स्तर है इस पर सरकार को कड़ाई से लेकिन निरपेक्षभाव से ध्यान देना होगा। इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जनता का सहयोग भी आपेक्षित है। आज इस प्रदेश की जनता प्रशासन से इतनी कटी हुई है कि कोई सच्ची साक्षी देने में भी वह आगे नहीं आती। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक अपने आचरण से, अपने क्रिया कलापों से, अपने निर्णय और फैसलों से ऐसा वातावरण बनायें, ऐसा माहौल बनायें कि जनता भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये आगे आये।

माननीय सभापति महोदया, इसी के साथ साथ में देश और प्रदेश में उपलब्ध दो प्राकृतिक सम्पदाओं की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जल और भूमि, यह मनुष्य जीवन के लिए बहुमूल्य हैं। एक ऐसी सम्पदा है जो बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 40 साल आजादी के बाद ईन दो बहुमूल्य सम्पदाओं के सदुपयोग के सम्बन्ध में किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। भूमि के कटाव का दुरुपयोग, नित नये क्षेत्र में बड़े-बड़े क्षेत्रफल में ईंटों के लिए जमीन की कटाई, लम्बे चौड़े क्षेत्रफल में आवासीय भवन, मैं समझती हूं कि इन सब के जरिये इस बहुमूल्य सम्पदा के साथ में अन्याय किया जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस राज्य सरकार को प्रदेश में उपलब्ध भूमि का कहां कहां, कैसे उपयोग किया जाय, कितना उपयोग किया जाय इस

(श्रीमती मदन कौर)

सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करनी चाहिये, किसी तरह की नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

इसी के साथ-साथ पानी की बात मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बूंद बूंद के लिए आदमी तरसता है और दूसरी तरफ टैंकों में ओवर फ्लो होना, नहरों का टूटना पाइपों का टूटना, नलों में मामूली वाशर की कमी से समय बे समय पानी का बहना, यह हम कतई बर्दास्त नहीं करेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसके सम्बन्ध में हमें सतर्कता बरतनी होगी। जो दो सम्पदाएं हमें विरासत में मिली हैं अगर हम इसमें बढ़ोदरी नहीं कर सके, अगर इसमें हम सुधार नहीं कर सके तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी।

माननीय सभापति महोदया, अंत में आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जो काम काज हम इन वर्षों में, हाथ में लेने वाले हैं, जो विकास कार्य हम हाथ में लेने वाले हैं, इसके सम्बन्ध में हमें हमारे प्रदेश में जो सेवा निवृत्त जन सेवक हैं, जो प्रतिभाशाली है, कुशल है, जिनका कार्यकाल अच्छा रहा है, उनके अनुभवों का भी हमें फायदा उठाना चाहिये। उन्हें स्वेच्छिक और अवैतनिक रूप से हमारे काम काज में सलाह देने का अवसर मिलना चाहिये। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, सामाजिक वानिकी हो, सिंचाई हो लगभग सभी विकास कार्यों में हमारे प्रतिभाशाली सेवा निवृत्त जन सेवक निश्चित रूप से इस काम में आगे आयेंगे और उन्हें इस बात की खुशी होगी कि हमारे अनुभवों का यह सरकार उपयोग ले रही है और वे स्वयं भी अपने आपको गौरान्वित अनुभव करेंगे। मैं इस सदन का आज अधिक समय लेना नहीं चाहती। अंत में जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में माननीय नदबई से आने वाले सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए शासन को धन्यवाद देते हुए, अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (ओसियां) : माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पिछले चार दिनों से वादविवाद इस सदन में चल रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक अधिकृत वक्तव्य होता है और इस वक्तव्य में सरकार ने यह बात कही है कि उनको दो तिहाई जनादेश मिला है और इसलिये वह सत्ता में आये हैं। लोकतन्त्र का मूल मंत्र यही है, सभापति महोदया और इंडियन रिपब्लिक और हिन्दुस्थान के संविधान में इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि लोकसभा और विधान सभा के चुनाव हर पांच साल के बाद होंगे और पांच साल के बाद राजनीतिक दल जनता के सम्मुख जनादेश लेने के लिये जायेंगे और लोकतन्त्र का मूल मंत्र ही जनादेश है। अपने घोषणा पत्र के [illegible] राजनीतिक दल जनता के सम्मु[illegible]

(श्री परसराम मदेरणा)

वायदे करते हैं और उन वायदों के ऊपर कुछ उम्मीदें और अपेक्षायें और आशायें रख कर जनमत दिया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों दलों को मिला कर 46.59 प्रतिशत मत मिले। इसलिये यह कहना कि सरकार आपकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको दो तिहाई प्रतिशत मत मिले नहीं हैं इस राजस्थान के अन्दर, और मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि लोकसभा में जो आपको मत मिले, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बी. जे. पी. है, इसके वोटों में लोकसभा की तुलना में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जनता दल के 4.22 प्रतिशत गिरावट आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के कितनी आयी है ?

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस के भी जनमत में गिरावट आयी है। लेकिन वह 3.40 प्रतिशत ही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के मुकाबले में दोनों ही पार्टियों की दो महीने के भीतर-भीतर जनमत के पर्सेंटेज में गिरावट आयी है और आपकी पापुलरिटी का ह्रास हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे की बात बता रहा हूं, आपको भी मालूम है, आपको भी कमिट करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर जो सरकार बनी है, वह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार है, जिसमें ज्यादा सदस्य जनता दल के हैं। राष्ट्रीय मोर्चे के तो दो या तीन माननीय सदस्य लोकसभा के होंगे। आप उसका बाहर से समर्थन कर रहे हैं। माननीय नेता महोदय और यहां पर आपके साथ जनता दल क नेता जो बिराजमान हैं, उनका सरकार में सहयोग है, लेकिन वहां पर आपने उनके साथ सहयोग नहीं किया है। उनके साथ सहयोग ही नहीं, आज जो इस देश में लोकतन्त्र को विकृत करने की बात महम में कही जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले वहां चुनाव कराने के लिये और मुख्यमंत्री को वहां से हटाने के लिये अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी जो बी.जे.पी. के नेता भी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वह चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उनके पास में बैठने वाले माननीय सदस्य की...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको क्यों दर्द हो रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे इस बात का दर्द है कि जो कुछ राजनीतिक परिदृश्य केन्द्र में और यहां पर है और आप यह मान कर चलें कि जब आपको 1977 में जनमत मिला था और 79 में जब केन्द्र की सरकार गिरी तो आप भी उसके साथ टिके हुए थे, तो धड़ाम से नीचे आये और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वहां पर जो सरकार बनी है, वह अल्पमत की सरकार है और बाहर से समर्थन देने वाली पार्टी बी. जे. पी और कम्युनिष्ट पार्टी है। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि विचारों में और उनके

(श्री परसराम मदेरणा)

सिद्धांतों में बहुत बड़ा मतभेद इसमें भी है और बी. जे. पी. में भी है और शायद आज जनतादल में भी होगा। थोड़ा बहुत चुनाव में हाथ मिला लिया तो बात दूसरी है। लेकिन निश्चित तौर पर मतभेद आपके हैं और सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद है तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, वह सैद्धांतिक मतभेद कम्युनिस्टों और बी.जे.पी. में सबसे ज्यादा है। उनकी सोच में, भारी अन्तर है उनके सिद्धांतों में, उनके कार्य-क्रम में, उनकी नीतियों में और मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे से तो दुश्मनी रखिये आप, लेकिन हम आपके ज्यादा नजदीक है, हमसे इतनी दुश्मनी आप मत रखिये और क्योंकि हमारे विचार और आपके विचार सभी तो नहीं मिलते हैं, 100 प्रतिशत तो, लेकिन कई उसमें समानताएं हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, कि दो विचार-धाराओं की पार्टियां, एक पार्टी कैपिटेलिज्म में विश्वास करती है दूसरी सोशलिज्म में विश्वास करती है। एक पार्टी फंडामेंटलिस्ट है दूसरी पार्टी सेकुलर है और इनकी हालत यह है, चाहे बिजली पहुंच गयी हो, माननीय सदस्य से, जानते हैं, जब नीगेटिव एण्ड पोजिटिव वायर लिपटे हुए नहीं होते हैं, लेकिन 77–80 की तरह नंगे रह जाते हैं और नंगे रहने के बाद में कहीं पर टकरा जाते हैं तो स्पार्क कोई नहीं होता, लेकिन शार्ट सर्किट होता है और शार्ट सर्किट का अंजाम यह होता है कि या तो फ्यूज उड़ता है या आग लगती है, यह बात निश्चित है। हम तो यह चाहते हैं कि पांच साल तक केंद्र में आपकी सरकार रहे और हम यहां पर ईमानदारी से कह रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विरोधी हवा में हम लोग बड़ी मुश्किल से जीत कर आये हैं इसलिये आप मजबूती से कायम रहें, हम तो खुद यह चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जनता के पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, जनता ने फैसला किया है, फैसला केवल आपकी पार्टी के हक में नहीं किया है, दोनों पार्टियों को मिला करके आपने एक सरकार बनायी है और मिली जुली सरकार है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ताऊ के इस्तीफे से तो लोकतन्त्र मजबूत हुआ है लेकिन अब जो वहां के उद्योग मंत्री जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाला है उससे लोकतन्त्र कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? अभी नये-नये आये हैं, उन्होंने यह कहा कि सरकार बहुत सतर्क है, बहुत सक्रिय है, होना भी चाहिये। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और यह बात मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल महोदय से कहलवायी भी है तो जवाबदेह प्रशासन जनता के प्रति होना चाहिये, जनता को सदा सहभागी बनाया जायेगा। जनता के साथ में समन्वय बैठाया जायेगा। हर बात जनता से पूछ करके की जायेगी, यह बात उन्होंने यहां पर कही है। मैं यह कह रहा हूं कि हमारी कुछ फेल्योर्स रह सकती हैं, हमारी कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और मिस्टेक्स जान-बूझ कर नहीं की गयी, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिये ट्रुथफुली कि हमारी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। जनता हमसे अप्रसन्न हुई है, तब तो हमको वोट नहीं दिया है। लेकिन आप सरकार अगर इतना बढ़िया चलाने की क्षमता रखते हैं, तो तीन

(श्री परसराम मदेरणा)

साल के अंदर आप भी यहां सरकार में रहे। आपकी नीति बहुत प्रोग्रेसिव थी, आपने जितनी भी व्यवस्थाएं की उनको बदल करके, संशोधन, परिवर्तन करके और जनता के प्रति प्रशासन को जवाबदेह बनाया था, तो फिर आपकी वह दुर्गती क्यों हुई 1980 के अंदर? और, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह अनवरत प्रक्रिया है डेमोक्रेसी है और जनता जब उस पर अपनी मैनडेट देती है, मैनडेट तो दोनों पार्टियों को दिया है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिये और बिस्तृत नहीं करना चाहिये। अभी मैं यह निवेदन करूं कि सरकार को बने हुए आज करीबन 19 दिन हुए हैं यह सरकार के कार्यकलापों का, उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियों का हम कोई लेखा-जोखा आज नहीं दे सकते हैं और गुढ़ामलानी से आने वाली माननीय सदस्या बिल्कुल सही कह रही थी कि न आलोचना कर सकते है, न उसकी प्रशंसा कर सकते है। मैं भी उनकी इस राय में सहमत हूं। आपने कुछ संशोधन, परिवर्तन, कुछ-कुछ साधन वगैरह जुटाने की बातें कही हैं, आपके इस अभिभाषण में आपने यह कहा है कि हम प्रदेश का तेजी से विकास करना चाहते हैं, वित्त व्यवस्था चरमरा गयी है, उसे ठीक करने के लिये हम संकल्पित हैं, राजनीतिक इच्छा की पूर्व में कमी थी, इसलिये आपके पास में असीमित भंडार है, इसलिये उस इच्छा का आप यहां प्रदर्शन करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनर्वालोकन कर प्रक्रिया में सुधार किये जायेंगे। राजस्व अभियान और शिविर लगायेंगे, साम्प्रदायिक दंगों पर काबू करेंगे और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, आपका एक इन्टव्यू पढ़ा था अखबार में कि आप राजधर्म का भी पालन करेंगे। राज्य का कोई धर्म नहीं होता और इसलिए आपके उस वक्तव्य की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। लेकिन आपकी पार्टी की नीतियां जो हैं वह मेल खाती हैं या नहीं, यह यहां पर सोचने की बात है। योजना देते हैं-प्राथमिकताओं के कार्यक्रमों का पुनः आप निर्धारण करेंगे, प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में एक श्वेत-पत्र सदन में प्रस्तुत करेंगे, किसानों के ऋणों को माफ करने के लिये आप भारत सरकार से परामर्श कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए "गोपाल" नाम की एक विशेष योजना का प्रारम्भ करेंगे, भूजल के दोहन की तरफ आप विशेष ध्यान देंगे, नये कुओं के लिये आप बीमा की व्यवस्था लागू करेंगे, अन्तर्राज्जीय विवादों के अन्दर राजस्थान के लोगों की पूर्व सरकार रक्षा नहीं कर सकी इसलिये अब आप दबाव में नहीं आयेंगे और झुकेंगे नहीं, अटल रहेंगे, पेयजल प्रयासों की समीक्षा कर जनता की भागीदारी स्थापित करेंगे, प्रस्तावित बिजली योजनाओं को मंजूर करवाने में कारगर ढंग से पैरवी करेंगे, नई औद्योगिक नीति का निर्धारण करेंगे, गरीब व्यक्ति को "गणेश" मानकर उसे केन्द्र बिन्दु बनायेंगे और जो पहले विकृतियां आ गई हैं इस गरीब को मदद देने में, उसका उन्मूलन करेंगे। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के कार्यक्रमों का मूल्यांकन और समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करेंगे। परिवहन का एक मास्टर प्लान बनायेंगे और अकाल पड़ने पर अकाल की पंचवर्षीय योजना और यह जो फाइव ईयर प्लान है इन दोनों का डोफ्लेनिंग करेंगे।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सभापति महोदया, जो कुछ भी अभिभाषण में बातें कही गई हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक सरकार इन समस्याओं के ऊपर विचार कर रही है और वह निर्णय नहीं ले सकी है। आपकी अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं क्या हैं, आपकी प्रोयर्टीज क्या है? प्रायर्टीज आप निश्चित करेंगे लेकिन प्रायर्टीज क्या हैं इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आपके कार्यक्रम क्या है, किस तरह से आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत थोड़ा समय हुआ है और उनके सामने कई चुनौतियां हैं। राजनीतिक चुनौती भी हैं, प्रशासनिक चुनौती भी है और वित्तीय चुनौती भी है। मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जगह-जगह यह कहा है कि उनको खजाना खाली मिला है। जब राजस्थान के रिसोर्सेज की या राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं की या राजस्थान के विकास की बात सोची जाती है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक और जो राजस्थान का विशाल क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास की समस्याओं का एक बहुत बड़ा अम्बार है और इसीलिए, उसका समाधान और निदान करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए व्यापक संसाधनों की जरूरत होती है और राजस्थान के पास इतने संसाधन नहीं है। इसलिए राजस्थान कैनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल की इतनी बड़ी योजना, जो आज कई वर्षों से चल रही है, यह इसलिए चल रही है कि हमारे पास साधनों की कमी थी। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको खजाना खाली मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पर आपने पहला हक गरीब का रख दिया है। खजाना खाली और उसका हक आपने रख दिया लेकिन खजाने के अन्दर कुछ है भी नहीं? तो उसका उद्धार कैसे होगा? यह एक प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन को आप जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना चाहते हैं और उसको संवेदनशील बनाना चाहते हैं, वह प्रशासनिक चुनौती आपके सामने है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक मशीनरी काफी ढीट हो गई है और प्रशासनिक मशीनरी में करप्शन भी है। मैं इसको इन्कार नहीं करता। हम आपसे यह आश्वासन लेना चाहते हैं कि आप इस करप्शन के उन्मूलन में, जैसा अभी गुढामालानी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी और सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी, करप्शन के बारे में जो भी कारगर कदम आप उठायेंगे, लेकिन आपको बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यह करप्शन इतना गहरा चला गया है कि एक बीमारी है और वह बीमारी इन्क्यूरेबल नहीं बने इसलिए प्रतिपक्ष की ओर से और मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि करप्शन के उन्मूलन में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा।

लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, वह है राजनीतिक। आपके घोषणा-पत्र अलग-अलग, आपके दलों में गुटबाजी। कल गंगानगरसे आने वाले माननीय सदस्य यहां पर कुछ बातें कह गये, लेकिन यहां पर आपके दल में भी

(श्री परसराम मदेरणा)

तीन गुट हैं और जिनका सीधा सम्बन्ध सेन्ट्रल लीडर से है और केन्द्रीय नेतृत्व भी खेमों में बंटा हुआ है और फिर आपके आका वहां से आपको क्या आदेश देते हैं ? उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसलिये आप जो इतनी बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी एक्टिव हो गई है और पहले जो कुछ भी व्यवस्थायें थी वह व्यवस्थाएं-नया-नया मुल्ला जोर से बांग देता है एक दो 295 के स्टेटमेन्ट में खड़े होकर एक वक्तव्य दे दिया, यह चीज पांच साल तक निरन्तर रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं समझता हूं कि नहीं रहेगी और इसीलिये आज जो आप आशायें लगाये बैठे हैं, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि हमने डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की वायटेलिटी को शेष कर दिया है बिलकुल। आप मुझे यह बताइये मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर डेमोक्रेटिक इन्स्टीटयूशन है चाहे वह पार्लियामेंट है, चाहे वह असेम्बली है, चाहे वह ज्यूडिशि है, चाहे वह गवर्नर का इन्स्टीटयूशन है, गवर्नर के इन्स्टीटयूशन की जो अभी आपने हालत बिगाड़ी है, उसको आप भूल गये हैं माननीय सदस्य, गंगानगर से आने वाले और यह बात भी नहीं, जो डेमोक्रेसी में फोर्थ ऐस्टेट प्रेस है उसकी मेहम में आपने जोरदार पिटाई की उस वक्त तो आपके डिस्टोर्शन और विसंगति आई नहीं, आपके इस इन्स्टीट्यूशन के अन्दर ? इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं या फेलियर्स हमारे हैं तो आपको निरन्तर उसके आगाह रहना चाहिए और वह गलती नहीं करनी चाहिए। यहां पर इस अभिभाषण के अन्दर पूर्व सरकारों के ऊपर भी कुछ छीटाकशी की गई है। सबसे पहली छीटाकशी तो यह है कि लम्बे समय तक सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल का एकाधिकार प्रदेश में निरंकुशता, भ्रष्टाचार, जन हितों के बारे में उदासीनता और भाई-भतीजा वाद फैलाता है। अगर हम निरंकुश होते तो हमारी पार्टी के जो लीडर हैं और प्रति पक्ष के नेता हैं वह नौ बार बराबर लगातार उसी कांस्टीट्वेन्सी से जीत कर कैसे आते ? आप तो स्वयं जानते हैं मुख्य मंत्री जी कि....

श्री यदुनाथ सिंह : और बार-बार बदला क्यों मुख्य मंत्रियों को।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो एक चुनावी प्रक्रिया है...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रियों को नहीं, मुख्यमंत्री जो है वह अपनी कान्स्टीट्वेन्सी बदलते हैं। पहले दांतारामगढ़ से थे, फिर श्री माधोपुर आये, श्रीमाधोपुर से किशनपोल आ गये, किशनपोल से मध्य प्रदेश चले गये...

श्री चम्पालाल बांठिया : राजस्थान के किसी कोने से जीत सकते हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाकी औरों की कहिये। एक विपक्ष के नेता ही हैं जो बराबर आये हैं, बाकी औरों के क्या हाल है वह भी बताइये...

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : मध्य प्रदेश से छबड़ा आये और छबड़ा से निम्बाहेड़ा चले गये और निम्बाहेड़ा से धौलपुर चले गये। पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या एक प्रश्न पूछ रही है, मैं समझता था कि आप मेरे वक्तव्य के अंत में प्रश्न पूछते तो ज्यादा उचित रहता, क्योंकि यह परिपाटी गलत पड़ेगी। क्योंकि हम शुरू-शुरू में आये हैं और मैं भी सातवीं दफे आया हूं और आप भी सातवीं दफे आये हैं। मैं इस सदन में सातवीं दफे जन प्रतिनिधि की हैसियत से आया हूं। आपने कांस्टीटयूएंशी बदली हैं, मैंने नहीं बदली है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप ओसियां और भोपालगढ़ से बराबर आये हैं और मैं भी दो ही जगह से आयी हूं। मैंने भी तीसरी जगह नहीं बदली है।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। 1952 से वहीं भोपालगढ़ क्षेत्र है पहले वह कान्स्टीट्यूएंशी सात थी फिर आठ हुयी फिर नौ हुयी। मेरा क्षेत्र छोटा होता चला गया है लेकिन 1952 में जो गांव थे आज भी वे गांव मेरे क्षेत्र के अन्दर है। आप सदन को गुमराह मत कीजिये। आपने क्षेत्र बदला है इधर से उधर गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जैसा आपने किया है वैसा ही मैंने किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने दो ही बदली है।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो जैसे साड़ी बदलती हैं वैसे पार्टी बदलती रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के आप इस तरह की बात न करें तो अच्छा होगा। मैं समझती हूं यह आपको साड़ी-वाड़ी का शब्द कहना शोभा नहीं देता है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने नहीं बदली है प्रोफेसर केदार ने नहीं बदली है।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले 10 वर्षों में प्रशासन में गिरावट आयी है और फिजूलखर्ची बढ़ी है। हमारे ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि पुरानी सरकारों पर कि पिछले 10 वर्ष में जनता और प्रशासन के बीच एक खाई पैदा हो गयी है। पिछले वर्षों में सार्वजनिक कोष का बेदर्दी से दुरुपयोग हुआ....

श्री सभापति : कनक्लुड करें माननीय सदस्य। बीस मिनट हो गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जस्ट शार्ट इट। राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है। राजनैतिक इच्छा की कमी के कारण प्रशासन जनहित के प्रति उदासीनता बरतने लगता है, प्रशासन की उदासीनता बढ़ती जा रही है और अन्त में यहां पर यह बात कही कि राज्य द्वारा प्रस्तावित धौलपुर, सूरतगढ़, माण्डलगढ़ ताप विद्युत परियोजनायें भारत सरकार में अटकी पड़ी हैं। कारगर ढंग से पैरवी नहीं किये जाने के कारण पिछली सरकारें इन्हें मंजूर नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

करा पायीं थीं। ऐसा ही हाल पलाना लिग्नाइट योजना का है। यदि यही हालत रही तो आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग व सप्लाई का अन्तर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अथोरिटी इन इलेक्ट्रीसिटी, पावर सर्वे आफ इंडिया, सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी का अध्ययन कर रहा था और उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अभी 2624 मेगावाट इन्स्टाल केपेसिटी और फर्म केपेसिटी 1691 है। यह जो 35 प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो अभी शॉर्टेज 29 प्रतिशत है और आपने 1994-95 में आपकी इन्स्टाल केपेसिटी बढ़कर। हजार मेगावाट बढ़ेगी और 3601 मेगावाट हो जायेगी। उसके बाद फर्म केपेसिटी 2111 मेगावाट रहेगी तब जाकर आपका 35.42 अन्तर रहेगा। तो कहने का मतलब यह है यह अजूम करके चले गये हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पावर जनरेशन एक हजार मेगावाट एड होगी। आप कह रहे हैं और कल माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्टीकरण दे दिया था और मैं समझता हूं कि इतनी योजनाएं आपके पास हैं यह एक योजना नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी यह परसों 21 तारीख को प्रश्न आया था इन योजनाओं के अलावा जो आज सैण्ट्रल पावर अथोरिटी के पास, इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी के पास विचाराधीन है भारत सरकार के सामने वे 9 योजनाएं हैं। उनकी कास्ट है 3194 करोड़ रुपये। आज आपके बजट में जो योजना स्वीकृत हुयी है आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम साल के लिए वह 870 करोड़ की है और 870 करोड़ है उसमें से 25 फीसदी 220 करोड़ बिजली के लिये हैं और आप देखेंगे कि राज्याध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट सन् 82-83 में पढ़ी थी उसमें एक प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया है उसको थम्ब रूल कहा जाता है इसका मतलब है कि पावर जनरेशन और मेन्टीनेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर बराबर इन्वेस्टमेण्ट होना चाहिये अगर 3 हजार करोड़ की योजनाएं मंजूर हो जाती है और अन्तराज्यीय हाइडियल पावर प्रोजेक्ट है जिन पर कारगर ढंग से पैरवी करके उन योजनाओं पर भारत सरकार के स्तर पर कोशिश करके लेंगे तो इन योजनाओं पर खर्चा होगा मेंटीनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में ईन्वेस्टमेण्ट का वर होगा 6388 करोड़ का और यह संशोधन रमारे पास नहीं हैं।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं आपको दे रहा था कि आपके पास अब तक....

श्री सभापति : यह सब बातें पहले बता देते।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 10 हजार तक के कर्जे माफ करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था या किसी तरह की बात नहीं है। जो अभी केन्द्रीय वित्तमंत्री ने बजट रखा है उसमें 2842 रुपये से राइट ऑफ करने का और राजस्थान के लोगों पर कितना अमाउण्ट बनता है 10 हजार से ऊपर जो कामर्शियल बैंक या दूसरों का है, गवर्नमेण्ट उसको लाभ

(श्री परसराम मदेरणा)

करेगी या नहीं। इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है? इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

पेयजल के सम्बन्ध में आपने बात कही, पेयजल समस्या बहुत डिफिकल्ट समस्या है और मैंने उसका अध्ययन किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर 2/3 रेगिस्तानी इलाका जोगरोफिकली सिच्युरेट है और वहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर की बहुत बड़ी समस्या है और यह जो राज्य सभा के मेम्बर चुने गये हैं मेनन साहब उन्होंने जोधपुर कनवोकेशन को एड्रेस करते समय 1976 में इस बात को स्वीकार किया था कि यहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर बहुत कम है। इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में जब तक री-चार्ज की कोई व्यवस्था नहीं होगी एक समय ऐसा आयेगा कि जब ह्यूमन पापुलेशन को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और इसलिए राजस्थान कैनाल ही एक सिल्वर लाइन है इन 6–7 जिलों के अन्दर और माननीय सभापति महोदय, उस समय मैंने एक सर्वे भी कराया था जिसमें उस समय की प्राइज लागत के हिसाब से तीन हजार करोड़ थी वह केबिनेट के सामने नहीं आया लेकिन मैंने एक सर्किल क्रियेट करके इन इलाकों में परमानेण्ट पानी का क्या सोल्युशन हो सकता है वह किया था। मैंने उसमें यह भी सजेशन दिया था पी.एच.ई.डी मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में अगर कई पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार इन योजनाओं को लेना पड़े तो यह होगा। यह मैंने स्पीच दी थी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर की केपेसिटी में।

श्री सभापति : I hope you wan't quote it.

श्री परसराम मदेरणा : इसकी चार कापियां मैं सदन की मेज पर रखता हूं ताकि सदन के माननीय सदस्य जो अलग-अलग पार्टीज के हैं उनको जानकारी हो जाये कि राजस्थान में पानी की समस्या कितनी विषम है, कितनी भयंकर है और इसका मेग्नीट्यूट कैसा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट आफ आर्डर। यह कापी सदन की मेज पर क्यों रख रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए कि मैंने इसका सजेशन दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपके कन्सीडरेशन के लिए है।

श्री सभापति : बिना परमिशन के।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाइये मुझे दीजिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके जो माननीय सदस्य आये हैं सब नये-नये हैं यह विषय उनकी जानकारी में नहीं है इसलिए हम हमारे अनुभव का लाभ आपके नये सदस्यों को देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह-मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह लाभ मुझे भी पहुंचाना चाहते हैं और सदस्यों को भी पहुंचाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहते हैं वह मेज पर रख दिया तो किसी को लाभ नहीं मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय नेता महोदय, आप अपनी एप्रोच नकारात्मक मत रखिए। आपकी निगेटिव एप्रोच है, जैसे आई.आर.डी.पी. जवाहर योजना है यह सब कुछ अच्छी नहीं हैं और इसके अन्दर बहुत कमियां हैं। आप अन्त्योदय योजना ला रहे हैं पर उसमें भी बहुत बड़ी कमियां हैं और दूसरे लोगों ने क्या बात कही पर मैं स्वयं इस सदन में था और आप मुख्य मंत्री थे मैंने उस योजना में जो कमियां थी उस तरफ आपका ध्यान भी आकर्षित किया था। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इन योजनाओं के अन्दर अच्छी बातें हैं उनका समावेश ग्रामीण विकास के लिए, गरीब आदमी की उन्नति के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए। आपने अभिभाषण के अन्दर क्रोप इंशोरेंस के सम्बन्ध में एक बात भी नहीं कही है। हमारे ताऊजी ने यह कहा है कि लोकसभा के अन्दर 316 किसान आये हैं मैं समझता हूं 110 से कम यहां भी नहीं होंगे और क्रोप इंशोरेंस के बिना कोई भी योजना चाहे आप अकाल के लिए पंचवर्षीय योजना, परमानेण्ट सोल्युशन की कर लें वह बेकार जायेगी और पुरानी सरकार ने जो यह निर्णय लिया था मैं उससे सहमत नहीं था मैंने एक चिट्ठी भी उस वक्त के मुख्य मंत्री को लिखी थी कि यह योजना 22 राज्यों में से 20 राज्यों में लागू है केवल राजस्थान और एक प्रान्त ही उससे वंचित है। 86-87 में लागू करके उसको बंद कर दिया तो सुझाव है कि आप इस योजना का इसमें समावेश कीजिए।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, अन्तिम अनुच्छेद पर आ रहा हूं। सभापति महोदया, अन्तिम अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दे दलगत राजनीति से ऊपर हैं। सभी की भागीदारी, आपसी सहयोग, सार्थक विचार विमर्श, एक दूसरे की बात समझने की भावनायें सामन्जस्य स्थापित करने के आश्वासन के उत्तर में मैं प्रतिपक्ष की ओर से और मेरी पार्टी की ओर से आपको सहयोग और आश्वासन देता हूं। लेकिन आपने अपने घोषणा-पत्र में बहुत सी बातें कही हैं कि सभी हाथों को काम मिल जायेगा, सभी को मकान मिल जायेगा, बुजुर्गों की पेंशन बंध जायेगी और युवक बेरोजगारों को भत्ता मिल जायेगा, किसानों को उपज का उचित दाम मिल जायेगा, हर क्षेत्र में पानी मिल जायेगा, किसानों के ऋण माफ हो जायेंगे, मंहगाई में कमी हो जायेगी, किन्तु जो बजट आया है यह कमर तोड़ने वाला बजट है। अभिभाषण जो आपका है वह शब्दों का आडम्बर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सरकार की नीतियों में कोई मौलिक परिवर्तन इस अभिभाषण में रिफलेक्ट नहीं हो रहा है और सभी वर्गों को राजी करने के लिए अभिभाषण में अधकचरा प्रयास किया गया है इसलिए नकारात्मक दिशाहीन और दलगत राजनीति से ओत-प्रोत अभिभाषण का समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदया, दिनांक 16 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि चालीस साल हुये जिसमें पिछले 10 साल का भी हिसाब ले लिया जाये तो पिछले 10 साल से राजस्थान प्रदेश के अन्दर विकास के नाम पर अंधेरा छाया हुआ था। जो पूर्व मुख्य मंत्री बने वह घोषणायें करने में जरूर विश्वास करते थे लेकिन उनकी क्रियान्विति में विश्वास नहीं रखते थे। माथुर साहब एक बार मुख्य मंत्री बने। मुख्य मंत्री बन कर हट गये। दुबारा फिर मुख्य मंत्री बने। जनता तो क्या इनके दल के सदस्यों और संसद सदस्य भी इनकी घोषणाओं से घबरा गये थे। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार जब मुख्य मंत्री बने थे तब बूंदी जिले के अन्दर एक बांध का पत्थर इन्होंने रखा था। इन्हीं के दल के संसद सदस्य श्री धारीवाल जी बूंदी गये और सात साल के बाद भी जब इसका कार्य शुरू नहीं हुआ तो जनता ने उनका घेराव किया। इन संसद सदस्य ने मजबूर होकर तीन सौ आदमियों को साथ लेकर जो पत्थर रखा गया था उस पत्थर को जीप में रख कर माननीय मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर के बंगले पर रख दिया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सरकार की विकास के नाम पर कौनसी इच्छा शक्ति थी? योजनायें जरूर बनाते थे इन योजनाओं को बनाने के साथ साथ ही उनके विभाग का जो मंत्री होता था वह योजना को पूरी करने में विश्वास नहीं रखता वह इस बात में विश्वास रखते थे कि योजना पांच साल के लिए बनी है तो किस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार के तरीके ढूंढे जाये और भ्रष्टाचार के माध्यम से उस योजना को पांच साल के बजाय 15 साल और 20 साल में पूरा करते थे। सभापति महोदया, यह सच है कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर पीने के पानी का भारी संकट है। कुछ हिस्सों के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड वाटर काफी नीचे चला गया। वहां पानी की उपलब्धता नहीं है लेकिन जो हिस्सा राजस्थान का ऐसा है जिसके अन्दर पानी की कमी नहीं है, नदियां वहां पर बहती है और हर साल सारा पानी वहकर बाहर चला जाता है उस पानी को रोकने के लिए सरकार की ओर से कौनसी योजनायें बनायी गयी। कोटा डिवीजन के अन्दर झालावाड़ जिले में 15 नदियां ऐसी हैं जिनका पानी बह कर बाहर चला जाता है लेकिन उनके ऊपर या उनके पानी के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी। सौभाग्य से ढाई साल के लिए राजस्थान के अन्दर जनता सरकार आई थी माननीय भैरोंसिह जी शेखावत के नेतृत्व में। उस वक्त जो योजनायें हाथ में ली गयी उनमें दो योजनायें शुरू की गयी छापर बांध की योजना शुरू की गयी थी माननीय सभापति महोदया, 1979 के अन्दर वह योजना शुरू हुई। पांच साल में वह योजना पूरी होनी थी लेकिन आज 1990 आ चुका है। उस योजना के अन्दर हर साल पांच लाख, दस लाख का बजट दिया जाता है। कभी 25 लाख का बजट

(श्री अनंग कुमार जैन)

दिया जाता है। वह पैसा तनख्वाह में बंट जाता है लेकिन वह योजना जहां की जहां धरी है। वह योजना जो 16 करोड़ की थी आज 47 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और यदि उस पर काम नहीं हुआ तो वह 47 करोड़ से भी बढ़ सकती है। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी की वर्षा कम होने से तो कमी रही ही है लेकिन पूर्व सरकार ने जो भ्रष्टाचार उसके अन्दर फैलाया है उसकी वजह से ही पीने के पानी की समस्या राजस्थान के अन्दर पैदा हुई। पाइप घोटाला काण्ड जो राजस्थान विधान सभा के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने और मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने इसको उठाया था। माननीय सभापति महोदया, उसका सारा पैसा, जो जन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कई बड़े अधिकारी और सामने बैठने वाले कई बड़े लोगों का हाथ बताया है। तो माननीय सभापति महोदया, जो पैसा उसमें खर्च होना था यदि हैण्ड पम्प के ऊपर पैसा खर्च होता तो हैण्ड पम्प से पानी निकलता लेकिन वह पानी जो बड़े लोग सामने बैठे हैं उनके पेट में पहुंच चुका है जब उनके पेट से पानी निकाला जायेगा तो अपने आप उस हैण्ड पम्प के अन्दर पानी पहुंच जायेगा। माननीय सभापति महोदया, इस सारे भ्रष्टाचार की जिम्मेदार पूर्व सरकार थी। इसके बारे में इस अभिभाषण के अंदर कुछ बातें कही गयी हैं उनके लिए सामने बैठने वाले सदस्य काफी एतराज करते हैं कि इसके अन्दर हमको गालियां दी गई है। लेकिन इसके अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय, ने पूर्व सरकार द्वारा जो विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार फैलाया गया उसका सही दिग्दर्शन किया है। सभापति महोदया, पीने के पानी के मामले में जो योजनायें 1984 और 1980 से लागू थी उन योजनाओं के ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं की गयी। यह कृत्रिम संकट इसलिए पूर्व सरकार द्वारा पैदा किया गया था। इसके बारे में मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड जिले में 1980 के अंदर जो री-ओर्गेनाइजेशन स्कीम बना कर भेजी गयी उस वक्त वह स्कीम 31 लाख रुपये की थी। आज वह स्कीम 80 लाख रुपये की हो गयी और वह समयबद्ध कार्यक्रम से पूरी नहीं होने के कारण आज झालावाड़ और झालरापाटन पूरे जिले के अन्दर पानी का संकट फैला हुआ है। पांच साल तक उस योजना के अन्दर मात्र एक फिल्टर प्लाण्ट मंजूर करना था वह फिल्टर प्लान्ट मंजूर नहीं किया गया लेकिन धीरे-धीरे करके यह स्थिति प्रदेश के अन्दर बन गयी कि कांग्रेस का पर्याय भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार की पर्याय कांग्रेस हो गयी।

सभापति महोदया, जब श्रीमान् हरिदेव जी जोशी मुख्य मंत्री थे और तीन वर्ष पहले जब झालावाड़ पधारे तो वहां अधिकारियों ने उनको खुश करने के लिए एक दिन उस योजना को चालू करके बिना फिल्टर किया हुआ पानी झालावाड़ की जनता को जरूर सप्लाई किया। जैसे ही उनकी कार जयपुर की तरफ रवाना हुई उस योजना से पानी देना बंद कर दिया

(श्री अनंग कुमार जैन)

गया। सभापति महोदया, जिस प्रकार के उनके काम करने का तरीका था इसलिए जनता ने इस बात को महसूस किया कि इस कांग्रेस पार्टी के हाथों प्रदेश की जनता का विकास नहीं होगा यह सोच कर उन्होंने बदलाव की दिशा दी। उसके लिए मेरे सामने बैठने वाले सदस्य यही कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गाली दी गयी है। सभापति महोदया, जो प्रदेश के बिजली के पानी के, जो इन्टर-स्टेट मैटर्स हैं, जिनको अपना हिस्सा पूरा मिलना चाहिए उसके बारे में पिछले दस साल 1980 से 1989 तक पिछली सरकार ने क्या कोशिशें कीं लगातार राजस्थान के हितों की बलि देते गये। जो भी कमजोर मुख्य मंत्री बनते थे वह ऊपर जाकर राजस्थान के हितों की बलि देते थे। ऐसे समझौते करके आते थे जिससे राजस्थान के हिस्से में ना पूरा पानी मिला, ना ही पूरी बिजली मिली। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैं, और डिस्प्यूट साइबा कौण्डी बांध, सतलज, रावी व्यास, हाइडल प्रोजेक्ट, आनन्दपुर साहब हाइडल प्रोजेक्ट, इराडी कमीशन इन तमाम योजनाओं के अन्दर 1980-89 तक जो भी सरकार द्वारा कोशिश की गयी और राजस्थान के हितों की बलि दी गयी उसके लिए मैं शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि एक श्वेत-पत्र जारी करें कि पूर्व सरकार द्वारा जो राजस्थान के हितों की बलि दी गयी है वह राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ सके।

सभापति महोदया, इसी प्रकार जो सहकारी विभाग है उसके अन्दर भी पूर्व सरकार ने सरकारीकरण किया और आज सहकारी विभाग की स्थिति यह हो गयी कि वह खाऊ-पीऊ विभाग हो गया। उसके अन्दर जो शीर्ष अधिकारी बैठे हुये हैं या जो कुछ बड़े लोग जिनको चेयरमैन बनाया गया था और जिनको वहां पदस्थापित किया गया वे लोग उस पर सांप की तरह कुण्डली मारकर बैठे हुये हैं और वहां का सारा पैसा भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता है। जिस सहकारी विभाग के माध्यम से जनता का विकास होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर काश्तकारों का विकास होना चाहिए उनको समय पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए लेकिन वह सब सुविधायें समाप्त होती जा रही हैं और धीरे-धीरे वह पैसा कुछ लिमिटेड लोगों की जेबों में आकर रह गया है। ऐसी कोई सहकारी समितियां माननीय सभापति महोदया, नहीं है जिसके अन्दर दो लाख के, तीन लाख के या पांच लाख के घोटाले नहीं हुए हों और जो बैंक्स वगैरह हैं उनके अन्दर करोड़ों रुपयों का घोटाला है। उस घोटाले की बात जब पूर्व सरकार के सामने उठायी तो कोई जांच नहीं की गयी। सरकारी विभाग के अन्दर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी जांच करवायी जाकर जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दी जाये।

सभापति महोदया, जो शिक्षा की नीति है, राज्य सरकार के द्वारा पिछले एक साल के अन्दर कोई घोषणा नहीं की गई लेकिन

(श्री अनंग कुमार जैन)

जाते-जाते दो महीने के अन्दर काफी संख्या में स्कूल खोले गये हैं उन स्कूलों के आज तक प्रारम्भ होने का कोई साधन नहीं है। वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है, रिकार्ड पर तो उनकी घोषणाएं जरूर कर दी गई हैं लेकिन कोई स्कूल प्रारम्भ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल खोले गये हैं वहां यह स्थिति है कि जहां पांचवीं तक स्कूल है वहां दो दोसौ, तीन-तीनसौ बच्चे स्कूल के अन्दर पढ़ते हैं लेकिन वहां एक अध्यापक रहता है जो 150-200 बच्चों को देखता है और उनको पढ़ाता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का स्तर भी कितना ज्यादा गिरता जा रहा है। इसलिए मैं नई सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो स्कूल खोले गये हैं उनके अन्दर शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की जाये और जितनी वहां पर स्ट्रेन्थ है उसके अनुसार पद भरे जाकर शिक्षक नियुक्त किये जायें।

जहां तक चिकित्सा का सवाल है, चिकित्सा विभाग के अन्दर भी जिस प्रकार के चिकित्सालय खोले गये हैं, चिकित्सा विभाग में भी ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर पद रिक्त नहीं होंगे और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति तो और भी खराब है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय खोले गये हैं जहां तीन-तीन, पांच-पांच वर्ष से न तो कोई डाक्टर गया है, न कम्पाउण्डर गया है। रिकार्ड पर वह चिकित्सालय जरूर चल रहा है। वहां पर यदि किसी की नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति वापस हाथों हाथ ही कैन्सिल हो जाती है और पांच-पांच साल से वहां पर कोई चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है। सभापति महोदया, कई ऐसे गांव हैं जहां आने का कोई साधन नहीं है। रास्ते बारिश के अन्दर बन्द हो जाते हैं, आस-पास 25-25 किलोमीटर तक के रास्ते बन्द हो जाते हैं। नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो वहां का आदमी सब तरफ से घिर जाता है। वहां ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए चिकित्सा का कोई साधन नहीं रहता है और फिर वहां समय पर न डाक्टर उपलब्ध है, न कम्पाउण्डर उपलब्ध रहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय खोले गये हैं वहां पर समुचित व्यवस्था डाक्टरों की हो, कम्पाउण्डरों की हो और स्टाफ की वहां समुचित व्यवस्था की जाये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी की समस्या के बारे में सरकार काफी चिन्तित है। निश्चित रूप से हमें यह आशा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। झालावाड़ जिले के बारे में ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजनाएं झालावाड़ जिले की राज्य सरकार के पास भेजी हुई है, जो पिछले 8--10 साल से लम्बित पड़ी हुई हैं, उन योजनाओं को देखकर उनके ऊपर आवश्यक बजट आवंटन कर उनकी क्रियान्विति के ऊपर ध्यान दिया जाये। झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी एक ऐसा स्थान है जो औद्योगिक नगरी है वहां पर जिस जगह से पानी लाया जाता था उस जगह का पानी भी समाप्त हो चुका है और विभाग द्वारा यहां पर यह रिपोर्ट भी भेजी

(श्री अनंग कुमार जैन)

जा चुकी है कि भवानी मण्डी कस्बे को अगले 8 दिन से अधिक पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार की ओर से कोई ऐसी अल्टरनेट व्यवस्था की जाये जिससे वहां की जनता को समय पर पीने का पानी मिल सके क्योंकि उस डैम में पानी समाप्त होने के बाद वहां पर जो ट्यूबवैल खोदे गये थे वे ट्यूबवैल भी अनसक्सैसफुल है। विभाग द्वारा एक स्कीम सजेस्ट की गई है गांधी सागर डेम से साढ़े बाइस किलोमीटर की लाइन डालकर इसमें पानी लाया जाये। लेकिन मैं यह भी मानता हूं, सभापति महोदया, कि इतने कम समय के अन्दर इस योजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है। जब पानी टैंक से सप्लाई करने की बात की जाती है तो यह बात की जाती है कि जहां तीन किलोमीटर और पांच किलोमीटर मे ऊपर पानी आता है वहीं सरकार टैंक की व्यवस्था करेगी।

सभापति महोदया, जहां वैस्टर्न राजस्थान का सवाल आता है वहां पानी की सप्लाई के लिये इस प्रकार के टैंकों की व्यवस्था की जाती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों के अन्दर पानी वास्तव में ही समाप्त हो गया है, हैण्ड पम्प स्कीम फैल्योर हो चुकी, अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है तो ऐसे गांवों के अन्दर आगामी मई और जून के महीने में, झालावाड़ जिले के लिए भी कुछ टैंकरों की व्यवस्था की जाये। जो वास्तव में बहुत ही पानी के लिहाज से समस्याग्रस्त गांव हैं या जो ऐसे कस्बे हैं जहां पानी का कोई सोर्स ही उपलब्ध नहीं हैं तो वहां टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाय।

मैं इतना ही कहकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदया, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सत्र में दिये गये नीति परक व ऐतिहासिक अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। दस साल के अन्तराल के बाद इस प्रदेश की जनता ने यह महसूस किया है कि उनकी जन-आंकाक्षाओं को पूरा करने वाली, लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाये रखने वाली उनकी खुद की सरकार आ गयी है। पिछली सरकार, जिसकी बुनियाद भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी के आधार पर रखी गई थी और इस सरकार की बुनियाद नई उम्मीद नये राजस्थान का निर्माण, नई आशा के आधार पर रखी गई है।

सभापति महोदया, सरकार का संकल्प कि सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया जाये, यह सरकार की काम करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। राजस्थान जो कि पिछले दस सालों के अन्दर भ्रष्टाचार की भूल-भुलैया में गुम होकर रह गया था अब नये राजस्थान का निर्माण इस सरकार के माध्यम से होगा इस तरह की उम्मीद राजस्थान की जनता

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

को है। अभिभाषण के अन्दर स्वायत्त शासी संस्थाएं, जिन संस्थाओं में लोकतान्त्रिक परम्पराओं का गला घोंट दिया था उन संस्थाओं के दुबारा चुनाव कराने की घोषणा स्वागत योग्य है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्वयं यह कहना कि मुख्य मंत्री के आचरण को लोकायुक्त की परिधि में शामिल किया जाये, यह इस बात का द्योतक है कि सरकार संकल्पबद्ध है कि ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार की जड़ कायम हो चुकी है, जिसके बारे में कांग्रेस के वयोवृद्ध सदस्य माननीय परसराम जी मदेरणा ने कहा कि जो पिछली कांग्रेस की संस्कृति की देन है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नई सरकार संकल्पबद्ध है। पूर्व में राजस्व अभियान प्रारम्भ किया गया। उसके पीछे यह मंशा थी कि गांवों के अन्दर अधिकारीगण जाकर गांव के लोगों के बीच में बैठकर गांव की समस्याओं का समाधान करें, परन्तु कांग्रेस के शासन के अन्दर राजस्व अभियान व्यर्थ हो गया कि गांव के अन्दर भ्रष्टाचार अपनाने वाले लुटेरों की फौज भेज दी जाये और जब राजस्व अभियान की घोषणा की जाती थी तो गांव के लोगों के मन में एक आतंक पैदा हो जाता था कि लूटने वाले लोग अपने दफ्तरों को छोड़कर गांवों की ओर कूच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार राजस्व अभियान शुरू करके पुनः गांव के लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जो नीतिपरक समस्याएं हैं उनको गांव के चौपाल के अन्दर बैठकर हल करने का काम करेगी। अभिभाषण के अन्दर ट्यूबवैल बीमा योजना एक अनुकरणीय योजना है। राजस्थान के अन्दर सिंचाई के पानी की बहुत ज्यादा कमी है ट्यूबवैल बीमा योजना के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर सरकार ट्यूबवैल खोदने के अन्दर सब्सिड़ी भी देना शुरू कर दे तो शायद किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही ट्यूबवैल के कनेक्शन देने के अन्दर जो बिजली विभाग है वह अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाये और प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के अन्दर अगर जनप्रतिनिधियों को शामिल करें तो मैं समझता हूं इससे भ्रष्टाचार का अन्त होगा और किसानों का जो उचित हक है वह मिलेगा।

राजस्थान के अन्दर जो सिंचाई योजनाएं हैं वह योजनाएं शुरू होने के बाद हनुमानजी की पूंछ की तरह समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। पूर्व में राजस्थान के हितों पर जो कुठाराघात हुआ है। सिंचाई की योजना और बिजली परियोजना के अन्दर जो अन्तर्राज्यीय

(2.00 म.प.)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव, सभापति, पदासीन)

समझौते हुये हैं उसमें जो राजस्थान के हक थे। उसके लिए पूर्व में किये गये समझौते के अनुसार राजस्थान को अपना हक लेने के लिए इस नई सरकार को संकल्पबद्ध होकर संघर्ष करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, 25 वर्ष पूर्व चूरू जिले के अन्दर गांवों में पानी पहुंचाने के लिये गंधेली-साहवा योजना बनाई गई थी। 25 वर्ष पूर्व 340 गांवों को पानी देने का

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

संकल्प किया गया था तत्कालीन सरकार द्वारा, परन्तु आज 25 साल के पश्चात चूरू में 62 गांवों के अन्दर पीने का पानी पहुंचाना है। आज भी इस गंधेली साहबा योजना के अन्तर्गत बूचावास इन्तजार करते करते उनकी आंखों में पानी आ गया और नयी सरकार आने के बाद उनके चेहरे पर रौनक आयी है, चेहरे पर नूर आया है और मन में उम्मीद बन्धी है कि शायद नयी सरकार पेयजल की समस्या जो वर्षों से लटकी पड़ी है, उस समस्या का समाधान करेगी।

मैं जिस जिले से चुनकर आया हूं जिस तहसील से चुनकर आया हूं, सभापति महोदय वह मरुस्थलीय तहसील है। उस तहसील के अन्दर आज भी आजादी के 42 साल के बाद लोग पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। चूरू जिले के 24 गांवों के अन्दर आज भी पीने का पानी नही है। जमीन के अन्दर जो पानी है वह खारा पानी है और बरसात के पानी के ऊपर सारे गांव वाले निर्भर करते हैं। इन गांवों के अन्दर पानी पहुंचाने की कोई समुचित व्यवस्था नही है। आज चूरू जिला मुख्यालय में 42 टैंकर पिछले 5 साल से खराब पड़े हैं और मात्र 2 टैंकर ईन 24 गांवों में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। एक-एक हफ्ते के पश्चात् एकाध गांव के अन्दर कभी इनके टैंकर आते हैं तो लोगों में जो भगदड़ मचती है उसको देखते हुये यह महसूस होता है कि वास्तव में शासन नाम की कोई चीज नही है। आज पीने के पानी की मांग लोग करें इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कांग्रेस शासन के अन्दर कागजों के अन्दर योजना बनायी और योजनायें बनाकर कहा कि टैंकरों द्वारा प्रतिदिन हर गांव के अन्दर पानी पहुंचाया जायेगा। परन्तु मुझे यह कहते हुये आश्चर्य होता है कि जो भी योजनायें हैं वह योजनायें मात्र कागजों में हैं। इसलिये मैं आज इस शासन से यह मांग करता हूं कि चूरू तहसील के अन्दर खारे पानी के जो गांव हैं उन गांवों के अन्दर पीने का पानी मुहैया करवाया जाय।

हमारे प्रदेश की जलवायु इस तरह की है कि अकाल एक स्थायी समस्या बनकर रह गया है। अकाल राहत काम के दौरान हमेशा करोड़ों--लाखों रुपये लगाकर जो काम किये जाते हैं वह योजनाबद्ध नहीं होने के कारण उन अकाल राहत कार्यों के काम का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं नयी सरकार से कि इस बार पक्के कार्य करवाये जायं और अकाल राहत काम को योजनाबद्ध बनाकर, एक योजनाबद्ध तरीके से इन कामों को चालू किया जाय।

हमारा प्रदेश जिसे अधिकांश भू-भाग एक फसली इलाके का है। इस अभिभाषण के अन्दर शुल्क खेती की चर्चा की गई है। मैं मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नयी शुल्क खेती की नयी तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के लिए कृषि विभाग को दायित्व सौंपा जाय।

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

कांग्रेस सरकार के अन्दर सबसे ज्यादा अगर खिलवाड़ हुआ है तो शिक्षा जगत के साथ हुआ है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने वाह-वाही लूटने के लिए एक विश्वविद्यालय के तीन टुकड़े किये और प्री-मैच्यौर डिलीवरी की तरह 3 विश्वविद्यालय पैदा कर दिये। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसके अन्दर जो इलिजिबलिटी रखी गई हैं। उन इलिजिबलिटी को इन यह तीनों विश्वविद्यालयों, ने कांग्रेस के लोगों ने जब यह महसूस किया कि शासन के दिन लद रहे हैं तो इन्होंने तीन नये विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की। इसमें एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अर्हतायें होनी चाहिये उनकी वह पूर्ति करता हो।

राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग को यहां से कोटा स्थानान्तरित करके कोटा के अन्दर एक बिल्डिंग में स्थापित करके यह कहा गया कि यह खुला विश्वविद्यालय कोटा है। कोटा के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। इसी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग था उस परीक्षा विभाग को अजमेर के अन्दर राजकीय महा विद्यालय के छात्रावास में स्थानान्तरित करके उसका नाम दे दिया एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी, अजमेर। इसी तरह से उदयपुर विश्वविद्यालय का जो कृषि संकाय था, उस संकाय के अन्दर जो अधिकारी बैठा करते थे उनको बीकानेर के अन्दर डूंगर महाविद्यालय है उस की बिल्डिंग में बैठाकर नाम दे दिया कि महाविद्यालय बीकानेर। इस तरह से शिक्षा के साथ उस शासन के अन्दर भयंकर खिलवाड़ हुआ है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं नयी सरकार से कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इलिजिबिलिटीज हैं उनकी पूर्ति करती हुई इन तीनों महाविद्यालयों को पूर्णरूपेण विश्वविद्याय में करने का कार्य करेगी और शिक्षा जगत को अच्छा वातावरण देगी।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी का बुरा बेहाल है। आज प्रदेश का नौजवान काम की तलाश के अन्दर सड़क पर चलते चलते समय से पहले बुढ़िया जाता है। नौजवान गांव से काम की तलाश में शहर की तरफ भागते हैं और शहर से थपेड़ें खाकर वापस गांव की तरफ जाते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि "युवा सहकार उद्योग योजना" नयी सरकार को बनानी चाहिये। इस सहकार योजना के अन्दर 5-6 बेरोजगार युवक एक सहकार समिति बनाकर किसी भी कुटीर उद्योग को लगाने का काम करें उसके लिये सरकार उनको विशेष सुविधा दे। जिससे कि "युवा सहकार योजना" के जरिये बेरोजगारी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है।

साक्षरता के अन्दर हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को जिस तरह से एन. एस. एस. की स्कीम चलती है उसी तरह से पाठ्यक्रम के अन्दर एक अनिवार्यता बना दी जाय कि

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

प्रत्येक व्यक्ति जो स्नातक हो, वह 5 व्यक्तियों को साक्षर करेगा। इस तरह से शायद साक्षरता के अन्दर हमारा स्थान ऊंचा चला जाय।

सभापति महोदय, मैं पहली बार इस सदन में आया हूं। मुझे सदन के बाहर सड़क पर भाषण देने की तो आदत है पर इस सदन के अन्दर अपनी बात कहने का पूरा अनुभव नहीं है। इसलिये अधिक कुछ न कहते हुए मैं माननीय राज्यपाल महोदय, द्वारा दिये गये अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुये पूरे दक्षिण राजस्थान की जो जन समस्यायें हैं उनकी ओर थोड़ा सदन को स्मरण कराऊंगा।

निवेदन इस प्रकार है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में दर्शाया है, मैंने पढ़ा और देखा उससे यह जाहिर हुआ है कि देहाती एरिया में 60 प्रतिशत राशि खर्च करके पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिये प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है।

निवेदन इस प्रकार है कि शिक्षा के सम्बन्ध में, गत समय में राजस्थान का दौरा करने का मुझे मौका मिला, जगह-जगह पर आदिवासी छात्रावासों और प्राथमिक विद्यालयों को देखने से मुझे यह अनुभव हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में एक मास्टर है, 1 से लेकर 5 तक कक्षायें हैं, किसी एक कक्षा में सवाल हो रहा है बाकी सभी बालक उस काले बोर्ड की तरफ देख रहे हैं इसलिये प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जितने कमरे हों उतनी कक्षायें और अध्यापक होने चाहिये अन्यथा शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो सकती है। इसी सन्दर्भ में मैं गत सरकार के शिक्षा मंत्रीजी से मिला उन्होंने आश्वासन भी दिये, प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आश्वासन भी दिया लेकिन वह आश्वासन नहीं के बराबर रहा। राजनीतिक व्यवस्था में ही पता गया। इसलिये मैं वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल, बामनपाड़ा, बोरी, बरसियाड़ा, और दूधका यह ऐसे स्थान है जहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मेरी मांग है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर डिवीजन जंगली और पहाड़ी

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

इलाका है । दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी हैं, किसान हैं जंगल और अपने पशु-धन से वहां वह अपना जीवन यापन करते थे लेकिन इन गत 40 वर्षों में गत सरकार ने जंगलों को बर्बाद करने का काम किया पूरा जंगल ठेके में देकर रवाना कर दिया और 1959 में जो नये जंगल लगाने की योजना राज्य सरकार ने हाथ में ली, वह मान्यवर, नहीं के बराबर थी और जो रियासती समय से जंगल थे वह जंगल दिनों दिन बरबाद होते चले गये और किसानों के जो पशु थे वह नहीं के बराबर हो गये । आज बाहर से हमें पशु मंगाकर दूध और चाय का इंतजाम करना पड़ता हैं । अतः मेरी मांग हैं कि दक्षिणी राजस्थान में जो जंगल का इलाका बरबाद हो रहा हैं, उसकी तुरन्त रोक की जाय और साथ ही उन जंगलों को पनपाने के लिये नदी और नालों पर डेम और एनीकट बनायें जाय ताकि जंगल हरे हों, पेड़ पोधे जिन्दा रहें जिससे बरसात होने में सहायता मिलें और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी और पिछड़ा तबका जो बरसात के आधार पर खेती करता था वह अपना जीवन सुख शांति से यापन कर सकें । मान्यवर, मेरा निवेदन हैं कि दक्षिणी राजस्थान पहाड़ी इलाका होने से सड़कें नहीं के बराबर हैं । कई अधिकारियों और मंत्रियों से मेरे को मिलने का मौका मिला । अधिकारी गण यह कहते हैं, कि वहां पर पहाड़ी इलाका है, गाड़ी जाती नहीं हम किस के सहारे से सर्वे करें । अतः मेरी मांग है कि कच्ची सड़कें रहे तो रहे लेकिन नदी और नालों पर पुलियों की व्यवस्था पहले की जाय । ताकि अधिकारी लोग गाड़ियों में घूमकर सड़के बनाने के लिए उसकी सर्वे कर सकें और विकास की जो धीमी गति है, उसमें तेजी लाई जाय । मान्यवर, मेरा निवेदन इस प्रकार से है कि दक्षिणी राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में पंचायती राज हैं जहां पर 32 ग्रामदानी गांव हैं, उन ग्रामदानी गांवों के आदिवासी जागीरदारी से परेशान हो रहे हैं । जिस तरह से रियासती टाइम में लोगों से बेगार कराई जाती थी उसी तरह से ग्रामदानी गांवों का जो चैयरमैन है, वह परेशान कर रहा हैं । इनको कोर्ट के पावर दे रखे हैं, एस. डी. ओ को पावर दे रखे हैं और नामान्तरण, जमीन को बेचना, खातेदारी अधिकार, यह सब उसने अपने अंडर में ले रखे हैं । वहां के ग्रामदानी पब्लिक की मांग हैं कि यह ग्रामदानी गांव समाप्त किए जाय और उनको ग्राम पंचायतों के रूप में तब्दील किया जाय । कारण कि कई वर्षो से आज तक इनके चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे पब्लिक परेशान है अतः मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्रामदानी गांवों को समाप्त करके ग्राम पंचायतों के रूप में रखने का निर्णय लिया जाय ।

मान्यवर, स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान में कई राजनीतिक नेताओं की व्यवस्था रही हैं । हमारा बांसवाड़ा जिला पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का रहा, जहां पर गत 40 वर्षो में काम होने की पुकार रेकार्ड में की जाती रही, लेकिन मौके पर देखा जाय तो काम नहीं के बराबर हैं । माही डेम की जो थोड़ी व्यवस्था हुई है और पानी की जो व्यवस्था हुई है, जब-जब मैं इस सत्र में विधान सभा

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

भवन में खड़ा होता हूं तो कहा जाता है, बांसवाड़ा जिला हरा-भरा हो गया है और माही डेम से फूल खिल गये हैं। इस तरह की वाहवाही यहां की जाती हैं। लेकिन बांसवाड़ा का पर्वी इलाका पूरा सूखा हुआ है। वहां. पर आज दिन में और रात में भी पीने के लिए पानी नहीं हैं। पेड़ों के नीचे महिलाएं अपने बच्चे लेकर बैठी हुई हैं, लकड़ियां नहीं है, खाने-पीने को अन्न नहीं हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पूर्वी इलाके का सर्वे कराया जाकर जो छोटे मोटे नदी नाले हैं उन पर डेम बनाये जायं और एनिकट बनाकर उस इलाके को हरा-भरा कराया जाय ताकि वहां की जनता सुख-शान्ति से रह सके।

निवेदन इस प्रकार है कि घाटोल में रैफरल हास्पिटल का उद्घाटन करके वाहवाही लूटकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आये, लेकिन वहां घाटोल कस्बे में आज दिन तक न तो कोई एक्सरे की व्यवस्था है, पंखे दस लगे हुए हैं, एक भी चालू नहीं है 15 बिस्तर ऐसे हैं कि माचिस से जमाया जाय तो जलते भी नहीं हैं, इस हालत में हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि घाटोल रैफरल हॉस्पिटल जो खोला गया है, उसकी और ध्यान दिलाया जाय, ऐसा मेरा सुझाव है। मान्यवर, दक्षिणी राजस्थान में गत सत्र में, अनुसूचित जन जाति का सदस्य होने के कारण पूरे राजस्थान का दौरा करने का मौका मिला है। जगह-जगह जिला अधिकारियों व तहसीलदारों से मेरा सम्पर्क हुआ और ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी करने का मुझे मौका मिला। जन जाति आयोग के कार्यालय में बैठने का भी मौका मिला। दक्षिणी राजस्थान में से सबसे बड़ी समस्या सैटलमेंट पैमाइस की है। वन विभाग और रैवन्यू विभाग की सीमा कायम नहीं हैं, जहां पिछड़े तबके का किसान खेती करता है आज पचास साल हो गये, दक्षिणी राजस्थान उदयपुर डिवीजन में, सैटलमेंट पैमाइश नहीं हुआ, जहां आदिवासी किसानों में लड़ाइयां हो रही हैं, कोर्ट में जाकर खड़े हुये हैं। वकीलों के आधार पर दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी किसान जिन्दा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां पर सैटलमेंट पैमाइश करवाये जाय। राजस्व विभाग और वन विभाग की भूमि की सीमा कायम की जाय और जो जंगलात की जमीन है, उस जमीन में जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, 25-25, 30-30 साल से आदिवासी किसान खाली पड़ी भूमि पर मकान बनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कुयें बना लिए गये हैं, तलाइयां बना दी गई हैं, लेकिन उस जमीन की वन विभाग में आज तक मांग रही हैं अतः मैं मांग करता हूं कि और वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूं, आशा करता हूं अभिभाषण में दर्शायें अनुसार पश्चिमी राजस्थान में सैटलमेंट पैमाइश कराई जाकर पिछड़े तबके के व्यक्तियों को जमीन की व्यवस्था कराई जाय। भाईयों में बंटवारा कराया जाकर राज्य सरकार से मिलने वाले लोन में सहयोग दिलाया जाय और नाजायज कब्जे से, आज भी बांसवाड़ा जिले का नक्शा पेश करूं अकेले बांसवाड़ा जिले का यह रेकार्ड है। गत वर्ष में मैंने इसकी जानकारी दी जो राजस्थान

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

सरकार ने राजस्व अभियान चलाया था, बांसवाड़ा जिले का अकेले का मेरे पास रेकार्ड है, उसमें 3 लाख लगान बकाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लेकिन 22 लाख रुपया नाजायज कब्जे की पैनल्टी से किसानों को सरकार में जमा कराना पड़ रहा है। अतः मेरी मांग है, मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार पिछड़े तबके के व्यक्तियों को लोन देकर, बकरियां देकर, भैंसे और गायें देकर ऊंचा उठाने की योजना बनायें। जो करोड़ों रुपया सरे-आम सरकारी अफसरों द्वारा लूटा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाय और सैटलमेंट पैमाइश कराई जाकर पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने की योजना बनाई जाय, यह मेरी मांग है।

मान्यवर, घाटोल विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रेवन्यू गांव हैं, वे ग्राम पंचायत से सम्बन्धित हैं। राज्य सरकार से मिलने वाला राशन जो रेवन्यू गांव है उससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को मिलता है और वे बाड़े अन्य पंचायतों को लगे हुए हैं। यह सैटलमेंट की कमी का कारण हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिससे जनसाधारण, पिछड़े तबके के व्यक्ति राशन से वंचित रहता है। अतः मैं मांग करता हूं कि इसका सर्वे कराया जाय और जो बाड़े रेवन्यू में घोषित नहीं है, उन बाड़ों को पुनः रेवन्यू में घोषित किया जाय या ग्राम पंचायतों के आधार पर राशन की व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री....

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर, उदयपुर डिवीजन से मैं अकेला ही व्यक्ति खड़ा हूं मुझे थोड़ा समय दें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नवनीतलाल नीनामा : दो तीन दिन से मैंने इस सदन में सुना, मैं माफी चाहता हूं मुझे थोड़ा समय दें। सुना और समझा। विपक्ष के नेताओं ने, अभी मेरे से पूर्व ही माननीय नेता बोल रहे थे और मान्यर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी की वाहवाही की। मैं मानता हूं; वह वृद्ध समझदार, जिम्मेदार नेता है, बुराई नहीं, लेकिन एक बात की इतला कर देना चाहता हूं जो बार-बार मेरे मन में आया करती है दक्षिणी राजस्थान में, बांसवाड़ा जिले से एक ही व्यक्ति समझदार यहां आये जो जनता का पैसा भ्रष्टाचार में पनपाया जाकर के इलाके में अपना नाम कमाया जाकर जगह-जगह पर वाहवाही लूटी गई है। आदिवासी और हरिजनों का तीसरे तबके के लोगों का नेता हूं, गरीबों का हामी हूं इस तरह से जो वाहवाही लूटी जाकर के उदयपुर डिवीजन में जनजाति कार्यालय खोल कर के यह छोटे से छोटे यह थनगा, अजवारा पराई, ढूंढा तराइ रूडा कराई ये क्या योजनायें लाये हैं ?

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

करोड़ों रुपया इन आंगनबाड़ियों में बर्बाद किया जा रहा है इसे तुरन्त रोका जाये। यह खोटे धन्धे भ्रष्टाचारी में पनप रहे हैं और झूठे बिल बनाकर के वह पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है और जब-जब चुनाव आते हैं उस पैसे का भ्रष्टाचारी में उपयोग किया जाता है गरीबों पर लठ चलाये जाते हैं। अभी गत चुनाव में मेरे एरिया के अन्दर मान्यवर जोशी जी के इशारे पर 15 कार्यक-र्ताओं के हाथ टूटे हैं।

आज की तारीख में बांसवाड़ा के गांधी अस्पताल में वे पडे हैं। इस प्रकार से तीसरे तबके, व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार अपनाया जाता है। अतः मान्यवर यह जो वाहवाही लूटी जा रही है वह झूठी है फर्जी है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने इन्हें जवाब तो दे ही दिया है और भविष्य में भी इसी तरह से जवाब देती रहेगी।

अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। आपने मेरे को समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : माननीय सभापति जी, मैं काफी अन्तराल के बाद इस सदन में अपने विचार जाहिर करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लगातार तीन दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उस पर मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार सुनने की कोशिश की। आलोचनाओं में, प्रत्यालोचनाओं में जाकर मैं समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा बल्कि अपने विचार जाहिर करना चाहूंगा।

जैसा हम जानते हैं राज्यपाल का पद एक संवैधानिक व्यवस्था है और गरिमामय पद है जिसका सबको आदर करना चाहिये। मेरा यह सौभाग्य रहा है, कि चन्द दिन मैं भी राज्यपाल रहा। उसके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में और मर्यादाओं के बारे में उसकी पूरी जानकारी है और इसी लिये सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब अपना भाषण दिया, बहुत शालीनता के साथ, शांति के साथ, उन्होंने उनके भाषण को सुना।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह पहली बार हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने रोक कर रखा है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : किसी व्यक्ति के रोकने से काम नहीं चलता, मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि यही परम्परा न केवल इस सदन में बल्कि देश के अन्य सदनों में भी और सभापति महोदय, अगर मैं नियमों का उल्लंघन न करता हूं तो यही बात मैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल और

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

राष्ट्रपति का पद गरिमामय पद है, संवैधानिक व्यवस्था है इसकी गरिमा को बनाये रखना हमारा सबका कर्तव्य है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का उदाहरण सभी सदन लोक सभा और राज्य सभा भी करेंगे और यह परम्परा कायम रहेगी। श्रीमान् जैसा हम सब जानते है राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक नीति संबंधी दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की पिछले कार्यो का कुछ विवरण, और नई सरकार का अपना कार्यक्रम होता है। अगर सरकार चाहे तो एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर संक्षेप में कुछ कह सकती है। मैंने स्वयं ने इसका अनुभव किया कि राज्यपालों को बहुत कुछ कहने को स्वयं का नहीं होता क्योंकि यह राज्य की सरकार का दस्तावेज होता है। श्रीमान् मुझे क्षमा करेंगे, मैं माफी चाहूंगा अपने विचार जाहिर करते समय कम से कम राज्य पाल का अधिकार इतना तो होना ही चाहिये कि छपने से पहले वह अपने भाषण को पढ़ ले जिससे सदन में आकर पढ़ने में उनको कठिनाई न हो। मुझे भी एक बार राज्यपाल का भाषण पढ़ने का सौभाग्य मिला। यह बात अलग है कि सरकार के साथ मेरा तालमेल ठीक था इसलिये मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं छपने से पहले अभिभाषण को पढ़ना चाहूंगा और आपकी सूचना के लिये कुछ तब्दीलियां मैंने सुझाई थी जो सरकार ने मान ली। जहां तक मेरी जानकारी है। राजस्थान में इस बार इस परम्परा का पालन नहीं किया गया, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है और मैं ऐसा अन्दाज लगाता हूं कि शायद इसीलिये राज्यपाल महोदय को यहां अपना भाषण पढ़ने में कठिनाई आई....

अनेक माननीय सदस्य : कोई कठिनाई नहीं आई....

एक माननीय सदस्य : बड़े आराम से पढ़ा....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे बढ़िया पढ़ा उन्होंने। भाषा की कठिनाई हो सकती है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अच्छा, भाषा की कठिनाई थी क्या, थी तो सही कोई कठिनाई। (व्यवधान) आप स्वयं कह रहे हैं भाषा की कठिनाई थी तो मैं मान लेता हूं कोई कठिनाई थी आपने कबूल कर लिया यह अच्छी बात है। मैं आशा करके चलता हूं राज्यपाल को आगे से यदि आप रहें तो आप इस बात का मौका देंगे कि वह पहले से अपने भाषण को पढ़ लिया करें। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीति सम्बन्धी दस्तावेज होता है जिसमें पिछले सालों का कुछ लेखा-जोखा और आगे के कार्यक्रम की चर्चा होती है और जैसा मैंने कहा एक तुलनात्मक अध्ययन सरकार दे सकती है। इस अभिभाषण को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि पिछली सरकार के किसी काम की कोई चर्चा नहीं की गई। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक आगे का कार्यक्रम बनता नहीं और सन् 80 के राज्य पाल का अभिभाषण अगर आप उठाकर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

देखें तो हमने बराबर पिछली सरकार के अच्छे कार्यो की चर्चा की थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काम अच्छे हुए थे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अच्छी बातों की चर्चा आप नहीं कर सकते, मैं यह जानता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : किये ही नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : होते तब भी आप नहीं कर सकते, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आशा करके चलता हूं आगे से इस बात का ध्यान रखा जायेगा। मैं देखता हूं लगातार राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार के रीति नीति सम्बन्धी कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया है बल्कि आलोचना का दस्तावेज इसको बना दिया गया है। (व्यवधान) मैं आज राज्यपाल नहीं हूं। सभापति महोदय यहां तो मैं सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। मैं आशा करके चलता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण को सत्तापक्ष की आलोचना का दस्तावेज नहीं बनाया जायेगा। आलोचना करना उनका अधिकार है। वे आलोचना कर सकते हैं। वह आलोचना वाद विवाद में हो सकती है। वह आलोचना सदन के नेता अपना वक्तव्य देते समय कर सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि राज्यपाल के अभिभाषण को आलोचना का दस्तावेज नहीं बनाया जायेगा बल्कि इसको रीति नीति सम्बन्धी बातों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। (व्यवधान) मैं तो कई बातों पर अंकुश लगाना चाहूंगा यदि मेरे हाथ में हो तो। आप पर पहले लगाना चाहूंगा।

मैं मानता हूं कि आज की सरकार की नीति सम्बन्धी दस्तावेज राज्यपाल के अभिभाषण में शायद संभव नहीं था क्योंकि नीति तो केवल किसी एक पार्टी की होती है। इस बात से हम वाकिफ है कि आज की सरकार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि दो पार्टियां सरकार में शामिल हुई है और वे पार्टियां भी एक नीति नहीं रखती हैं। हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टियां राज्य सरकार में शामिल होती हैं, वे अपनी केन्द्रीय व पार्टी की मर्जी के बिना नहीं शामिल हो सकती हैहम यह भी जानते हैं कि चाहे राज्य के अन्दर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार है, लेकिन केन्द्र में ऐसा नहीं है। हम यह जानते है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज यहां पर राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी रीति-नीति केन्द्रीय सरकार की रीति नीति से शायद मेल नहीं खाती है। कब से अलग हो जायेंगी, कब वे अपने भेद-भाव जाहिर करना चाहेगी, इसको इन्होंने सुरक्षित रखा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा मानते हैं कि यह सरकार इस दस्तावेज के जरिये कोई रीति-नीति की बात कह भी नहीं सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति ही नहीं बल्कि जनता दल की रीति-नीति का भी इसमें समावेश करना पड़ता। इसलिये इस बात को तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिये ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी के विचारों को इसमें जाहिर नहीं किया है। ऐसा लगता है कि पार्टी की कोई रीति

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

नीति की नहीं है। कोई पार्टी दस्तावेज, घोषणा पत्र नहीं है। इन्होंने अपने बड़े नेताओं के विचारों का भी इसमें समावेश नहीं किया है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसलिये वे कह सकते हैं कि मैं बड़ा नेता हूं। मैं इस बात को कबूल करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैं लेकिन फिर भी पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है। बहुत सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही थी उन बातों को नजरअंदाज किया गया है, जिनकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। मुझे इस बात में आपत्ति नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, सरकार का संचालय होता है। उसने विचार ही सर्वोपरि होते हैं। केवल मैं बात नीति की कह रहा हूं कि उन्होंने अपने पार्टी के विचारों को, अपनी पार्टी की रीति नीति को इसमें समाहित नहीं किया है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी से निरंकुश होना प्रारम्भ कर दिया है। इनकी पार्टी के लोग इन पर कोई पाबंदी रख ही नहीं पायेंगे। ऐसा लगता है कि केन्द्रीय नेतृत्व भी अक्षम हो गया है। अगर ऐसा है तो हम को डर लगता है कि जनता दल जो सरकार में शामिल हुआ है वह शायद बहुत दिनों तक इनके साथ तालमेल इसीलिये बैठा पायेगा कि उनको सरकार में रहना है, कुर्सी पर चिपके रहना है या फिर रीति नीति में परिवर्तन करेंगे। खैर, यह बात तो आज हम कह नहीं सकते, यह आगे देने की है। मुख्यमंत्री, जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे कई बातों की जोर-शोर के साथ घोषणाएं करते थे, भाषण देते थे, राज्य के हितों पर किसी कीमत पर कुठाराघात नहीं होने देंगे, अन्त-राज्यीय विवादों का निपटारा राज्य के हक में करायेंगे। पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई सीमा से राज्य में आने वाले तस्करों को रोकेंगे। पाकिस्तान से लगे हुए सीमा-वर्ती क्षेत्रों की बहुत चर्चा करते थे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कहने से नहीं, जो विचार वे स्वयं व्यक्त करते थे, जो विचार उनकी पार्टी व्यक्त करती रही, भविष्य में कम से कम वे उसका ध्यान रखेंगे। कैसे नारे देकर, कैसा भुलावा देकर और जनता को बड़ी-बड़ी आशा बंधा कर ये पार्टियां सत्ता में आई हैं। यह हम सब जानते हैं कि इन्होंने बड़े-बड़े नारे लगाये, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, रिश्वत का उन्मूलन कर देंगे, हर व्यक्ति को काम का अधिकार देंगे, मंहगाई कम कर देंगे, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करेंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, पंजाब समस्या का समाधान कर देंगे। इसके साथ-साथ संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, जिसका कि आरोप केन्द्रीय कांग्रेस सरकार पर लगाया जाता था कि उसको कम कर दिया है, उसको सुरक्षित करेंगे और इलेक्ट्रोनिक मीडिया की स्वायत्तता कायम करेंगे। और भी बातें हो सकती हैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा जो माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की है परन्तु उन्होंने बहुत खुलासा तौर पर कोई बात की चर्चा यहां पर नहीं की। इसलिये मैं बहुत कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि सरकार को सत्ता में आये बहुत दिन नहीं हुए हैं। इनके पास और मौके हैं उस समय वे अपनी रीति-नीति का प्रसारण करेंगे। इसके लिये

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

में बजट का इन्तजार करूंगा जब खास तौर से सरकारी रीति नीति की चर्चा कर सकेंगे। इसलिये मैं अपने आपको सीमित रखना चाहूंगा केवल राजस्थान के अभिभाषण तक। मैं जानता हूं, मुझे कहा जा सकता है कि आप तो राज्यपाल रहे हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिये, नियमों का पालन करना चाहिये इसलिये श्रीमान् में कोई दस्तावेज नहीं उठाऊंगा, केवल एक दस्तावेज राज्यपाल-महोदय का अभिभाषण है, उसी को उठाऊंगा। यह बात कहते हुए मैं अपने आपको चुप नहीं रख सकता। जैसा कि मैंने कहा, संविधान में व्यवस्था है, राज्यपाल का पद एक गरिमामय पद है जिसको पांच साल के लिये नियुक्त किया जाता है। जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने सारे राज्यपालों से इस्तीफा मांगा है वह देश के इतिहास में बेमिसाल है, ऐसा लगता है दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है। दुनियां के कई देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक पार्टियां की सरकार बदलने पर यह व्यवस्थाएं बदलती हैं लेकिन उसके भी कुछ नियम है, उसका भी कुछ समय है, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन आज की केन्द्रीय सरकार ने जिस तरह से राज्यपालों से इस्तीफा मांगा है भेदभाव के जरिये, केवल एक विशेष पार्टी को बाध्य किया गया कि हट जाये। मैं समझता हूं कि यह परम्परा अच्छी नहीं है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को निवेदन करूंगा कि यह परम्परा कांग्रेस ने नहीं डाली है। सन् 1980 में कांग्रेस सता में आई थी उसके पहले विरोधी पार्टियां सत्ता में थी लेकिन उस समय किसी राज्यपाल को हटने के लिये नहीं कहा गया। किसी राज्यपाल को बरखास्त नहीं किया गया

श्री भैरोंसिह शेखावत : राजस्थान के राज्यपाल को पता नहीं है कि उनको हटाने के लिये चीफ जस्टिस आ गये हैं वह ऊपर थे और नीचे से कहा कि आप जाइये और आपकी जगह यह शपथ ग्रहण करेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं करीब एक साल पहले जो राज्यपाल थे उनके साथ मुख्यमंत्री रहा जहां तक मेरी जानकारी है न केवल मैं मुख्यमंत्री रहा उसके बाद माथुर साहब भी आ गये थे स्व. रघुकुल तिलकजी, हमारे श्रद्धेय हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजली अर्पित करता हूं, उन्हें हम ने बरकरार रखा था। मैं कई नाम ले सकता हूं, परन्तु मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं लेकिन सभी राज्यपालों को कहा था कि आप काम करते रहें। जो नहीं रहना चाहें उनकी बात अलग है। श्रीमान् जहां तक मेरा ताल्लुक है, केन्द्र की सरकार बनने के पहले जब विरोधी पार्टी का बहुमत नहीं आया था लेकिन हमारा अल्पमत आया था, मैंने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर दिया था कि मैं राज्यपाल के पद पर अब काम नहीं करना चाहूंगा। इसलिये कुछ एक्सेप्शंस हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्योंकि चुनाव लड़ना है।

श्री यदुनाथ सिंह : उल्टे आभार व्यक्त करें केन्द्र सरकार का वह तो दूर रहा,

(श्री यदुनाथ सिंह)

आप बार-बार कहते थे कि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं, कहां पटक दिया, मुझे वापस राजनीति में आना चाहिये। उल्टे आभार व्यक्त करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं खुला ही कर रहा था, कह ही नहीं रहा था, कर भी रहा था। मेरा एक एक्सेपशन आप मान सकते हैं। मैं आम तौर पर सब बातचीत कर रहा हूं और आशा करके चलता हूं कि इस तरह की परम्परा डालना ठीक नहीं है। न केवल राज्यपाल के पद को इस तरह से डेनीग्रेट किया गया, बल्कि, श्रीमान्, इसी प्रकार से हमारे विदेशों में जो राजदूत हैं उनको भी ह्यूमिलियेट किया गया। अमरीका के अन्दर हमारे राजदूत डाक्टर कर्णसिंह जो सबके लिये सम्माननीय हैं, यू. पी. के अन्दर हमारे हाई कमिश्नर श्रीमान् रसगौत्रा साहब जिनको वहां के सब भारतीय चाहते हैं, जिनके लिये डेलीगेशन भारत सरकार के पास आये हैं, रिप्रेजेन्टेशन आये हैं, मेमोरेण्डम आये हैं उनको भी बदल दिया गया।

श्रीमान्, मैं एक बात इसलिए कहना चाहूंगा, राज्यपालों को बदल दो लेकिन केन्द्र की सरकार ने एक बात कही है कि हम विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं लायेंगे, कंटीन्युटि रखेंगे फॉरेन पालिसी के अन्दर। तो क्या कोई राजदूत रीति-नीति बदल देते हैं। राजदूत तो वह काम करते हैं जो भारत सरकार निर्देश देती है। इस प्रकार से व्यक्तिशः दुश्मनी के तौर पर, अगर वह हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्यों-कि कोई गलती इन्सान कर सकता है लेकिन इस तरफ से राजनैतिक आधार पर राजदूतों को बदला जाना यह कहां तक मुनासिब है। श्रीमान्, हमको और आपको सबको विचार करना पडेगा। श्रीमन्, राज्यपाल की नियुक्ति भी केन्द्र सरकार करती है, इसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में फेरबदल किया गया, वह अब तक की सरकारों के द्वारा किये गये सारे फेरबदल से भिन्न है। मैं सबकी बात नहीं कहना चाहूंगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किस तरह से महकमों के सैक्रेटरी बदले गये, प्रधान मंत्री कार्यालय में परिवर्तन हुए, राष्ट्रपति कार्यालय में किस तरह से परिवर्तन हुए, मुझे आश्चर्य होता है कि खुद अपने द्वारा बनाया गया गृह सचिव जिसको आज के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने चुन कर लगाया था, केवल तीन महीने के अन्दर बदल दिया। इसके मायने क्या हुए? जो व्यक्ति आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से काम करे वह व्यक्ति तो अच्छा है, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करे वह बुरा हो जाता है। चुन-चुन कर वह व्यक्ति जो कि कांग्रेस की सरकार के समय कांग्रेस की खाई खोद रहे थे, गलत आंकड़े दे रहे थे गलत तथ्य दे रहे थे उन सब व्यक्तियों को सर्वोच्च पदों, बड़े-बड़े पदों पर लाकर रखा गया, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : जगमोहन के साथ क्या हुआ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब मैं जगमोहन जी की और डी. पी. की न कहूं तो ज्यादा ठीक है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कह देओ ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं न कहूं तो ज्यादा ठीक है, कड़वाहट हो जायगी, गुड टैस्ट नहीं होगा । मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन जिस तरह से व्यवहार किया गया, जिस तरह से नियुक्तियां करी, जिस तरह से हटाया गया मेरे हिसाब से न कोई परम्परा के अनुकूल है, न कानून के अनुकूल है, न संविधान के अनुकूल है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्र सरकार को कि मेहरबानी करके इस तरह से संविधान की हत्या नहीं करे । इस तरह की गलत परम्परा नहीं डाले जिससे आगे आने वाली सरकार, पार्टियां उनका अनुकरण करें । मैंने तो आपको पहले ही निवेदन कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने शालीनता बरती यह बहुत अच्छा किया । और मैंने इसीलिये आशा व्यक्त की आगे भी सारी पार्टियां सारी सरकारें इस तरह की परम्पराओं का अनुकरण करे ।

मैं, श्रीमान्, एक बात और कहना चाहूंगा । प्रशासन में फेरबदल करना सरकार का अधिकार है । लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को किसी पार्टी विशेष के साथ बांधना यह बहुत मुनासिब नहीं है । कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिये । अगर आज की सरकारें, पार्टियां इस तरह करेंगी तो प्रशासनिक अधिकारियों का मोरल डाउन हो हो जायगा, निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर पायेंगे । श्रीमान्, अगर ऐसा है तो मुझे एतराज नहीं है । भारत के संविधान में एक व्यवस्था कर ली जाय जिस तरह से यू.एस.ए. के संविधान में व्यवस्था है कि जब सरकार बदलती है, पार्टियां बदलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाता है । अगर ऐसा कर लिया जाता है तो मुझे एतराज नहीं है । लेकिन जब तक हमारे वर्तमान संविधान की व्यवस्था है, मेरी ऐसी आशा है, मेरी ऐसी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि उन परम्पराओं, उन नियमों, उन कानूनों, संविधान की व्यवस्थाओं को कायम रखना चाहिये और इस तरह से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का मोरल डाउन नहीं करना चाहिये वरना निष्पक्षता के साथ जिस तरह से आज तक काम करते रहे हैं वैसा नहीं कर पायेंगे । दोनों काम एक साथ हुए हैं । जो उनके मन पसन्द नहीं थे उनको हटाया जाना, जो उनके मनपसन्द थे चाहे वह दूसरी सरकार की नजरों में गलत थे तब ही तो उनको हटाया गया था उनको सर्वोच्च पद दिया जाना, यह दोनों काम एक साथ हुए हैं । मेरे हिसाब से बहुत अनुकूल नहीं है । मेरी आशा है कि आगे चल कर इस तरह के बदलाव नहीं होंगे । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारी भावनाएं जनता तक पहुंच जायं, सरकार तक पहुंच जाय, हमारा काम पूरा हो जाता है ।

अब श्रीमान्, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा, मैं कोई अपने दायरे के बाहर नहीं जाना चाहूंगा, मैंने केवल इसलिये अब इस दस्तावेज को उठाया है जो आपने पेश करा है महामहिम राज्यपाल महोदय के जरिये से । पृष्ठ एक पर आपने पहले ही कह दिया जो कुछ

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आपको कहना है, इससे बड़ी आलोचना और किसी पार्टी की हो नहीं सकती है। मैं तो केवल इतनी आशा कर रहा हूं, जो आपने कहा है कि पिछले चार महिनों में जनता ने दो बार स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश का राजनैतिक परिप्रेक्ष्य बदल दिया और जनता द्वारा किया गया यह परिवर्तन नई व्यवस्था और मूल्यों का परिवर्तन है। श्रीमान् मैं मान लेता व्यवस्था का परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन बशर्ते कि इसमें कोई जिक्र होता। अभी तो केवल व्यक्तियों का परिवर्तन हुआ है। व्यक्ति के परिवर्तन को, पार्टी के परिवर्तन को हम व्यवस्था का परिवर्तन नहीं मान सकते और इसलिये मूल्यों का परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। हां, मूल्यों का परिवर्तन थोड़ा सा हुआ, उसमें गिरावट आई है। जो मूल्य थे, जो तय किये गये थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको ताक पर रख दिया गया। मनमाने ढंग से राज्यपालों को हटाया गया, राजपूतों को हटाया गया, प्रशासनिक फेरबदल किया गया। मैं जानता हूं जब मैं बोलता हूं, मुख्य मंत्री कहेंगे हमने नहीं किया। लेकिन मुख्य मंत्रीजी इस बात से इंकार नहीं कर सकते आखिर केन्द्र की सरकार के साथ उनको चलना है जो केन्द्र सरकार कर रही है वही तो राज्य सरकार भी करेगी। श्रीमन् एक बात नहीं भूल जानी चाहिये, केन्द्र सरकार ने जो फेरबदल किया प्रशासन में वह पहले सैशन के बाद ही किया था। पार्लियामेंट का पहला सैशन तो ऐसे ही निकाल दिया था। जो भी परिवर्तन हुआ वह पार्लियामेंट की जो पहला सैशन है, उसके बाद ही किया गया था। मैं ऐसी आशा करके चल रहा हूं, मुख्यमंत्रीजी इस बात को ध्यान में रखेंगे। परिवर्तन वह करें, उनको अधिकार है, सब अपना सैटअप करते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कम से कम व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर राजनैतिक द्वेष के आधार पर नहीं करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये मैंने कहा कि यह परिवर्तन मूल्यों का नहीं, अगर है तो वह गिरावट के साथ है, यह परिवर्तन व्यक्तियों का है पार्टियों का है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें उन्होंने इस दस्तावेज के जरिये राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवायी हैं उसका वह ध्यान रख कर चलेगें।

उन्होंने कहा है कि यह सरकार का विशेष दायित्व बना है कि जनता की इन आशाओं को पूरा करने के लिये कारगर कदम उठाये। मैंने कहा, कदम उठाये जाने की मुझे आशा है। अभी तो कोई उठाये ही नहीं हैं। मैं मानता भी नहीं हूं कि इतनी जल्दी कोई कदम उठाया जा सकता है। सोच लें, विचार कर लें लेकिन जो कुछ आपने कहा है उसको भी ध्यान में रख कर चलें वरना जनता माता है, सर्वोपरि है, बहुत विचित्र है, इसका पता नहीं लगता कभी आपको वहां बैठा दे, कभी हमको यहां बैठा दे और कभी हमको फिर दुबारा वहां बैठा दे और आपको यहां बैठा दे। इसलिये इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना पड़ेगा। श्रीमन् आपने स्वयं कहा है कि एक लम्बे समय तक सत्ता पर किसी राजनैतिक दल का एकाधिकार प्रशासनिक निरंकुशता, भ्रष्टाचार, जनता के प्रति उदासीनता और भाई भतीजावाद फैलाता है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। उन्होंने खुद ने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कह दिया है, मैं आशा करके चल सकता हूं, हम सब आशा करके चलते हैं कि आप स्वयं ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और जो बात आपने कही है, अगर रहेंगे तो आप भाई भतीजावाद फैलायेंगे । आप निरंकुशता फैलायेंगे । इसलिये आपको याद दिला देता हूं, जो कुछ आपने कहा है, ऐसा आप याद रख कर चलें और बहुत जल्दी यह कुर्सी खाली कर दें जिससे कि जनता की जो आशाएं आप पूरी नहीं कर पाये हैं उसको हम पूरी कर सकें । श्रीमान् एक बात पृष्ठ दो पर जो कही है बहुत गंभीरता से सुनें । उन्होंने कहा है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने को शासक समझने से लगे तो उससे प्रशासन में निरंकुशता पनपती है । उससे जनता व सरकार के बीच में दूरी बढ़ जाती है, सरकार एक वर्ग विशेष की बन कर रह जाती है । मैं मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिये । लेकिन श्रीमान् आपको ताज्जुब होगा, अभी सरकार को बने जुम्मा चुम्मा बीस दिन नहीं हुए, जिस तरह से जनता दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों को पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वह बातें बर्दाश्त नहीं की जायेंगी । चुनाव सुधार की बात यह पार्टी, सरकार करती है, श्रीमन् मेरे 17 पोलिंग बूथों पर एक वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल के लोग खुले आम कहते हैं अब सरकार हमारी आ रही है, सरकार हमारी केन्द्र में बन गई, अब सरकार राजस्थान में भी हमारी आ रही है और पुलिस वाले तमाशा देखते रहे, प्रशासनिक अधिकारी तमाशा देखते रहे । कुछ नहीं कर पाये अधिकारी श्रीमान् यह व्यवस्था तो बहुत ठीक नहीं है । मैं आशा करके चलता हूं इस बात का ध्यान मुख्यमंत्रीजी और उनकी सरकार रख कर चलेगी । अगर जनता के प्रतिनिधि कुछ कहते हैं तो समझ में आता है लेकिन उनके कार्यकर्ता भी मालिक बन जायेंगे तो, श्रीमन् इस शासन का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, इस बात का अन्दाज आप स्वयं लगा सकते हैं ।

श्री यदुनाथसिंह : उस समय आपका प्रशासन ढीला था क्या ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय जोशी जी मुख्यमंत्री थे उस समय । (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान् एक बात और कहूंगा कि चुनावों के पूर्व दो महीनों में पिछली सरकार ने हड़बडी में जो फैसले दिये वह दलगत भावना से प्रेरित ते, सरकार उन पर पुनर्विचार करेगी । पुनर्विचार करने का अधिकार तो सरकार को है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे फैसले भी हैं क्या जो केवल कांग्रेस पार्टी पर लागू हुए हैं या कांग्रेस पार्टी के हितों में किये गये हैं । मैं समझता हूं जितने भी फैसले सरकार ने किये वह फैसले तो सरकार ने जनता के हित में किये । पुनर्विचार आप कर सकते हैं लेकिन मैं आशा करके चलता हूं जनता की भलाई के लिए जो फैसले किये गये हैं उनको आप नहीं बदलेंगे बल्कि उनको आप कायम रखेंगे ।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमान् एक बात और कही। साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कुछ चर्चा है। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने अखबार में मुख्यमंत्रीजी का बयान पढ़ा जिसमें आई. जी. को जिम्मेदार बनाया है। मेरे ख्याल में वह बहुत बड़ा अधिकारी होता है सभी जगह नजर नहीं रख पाएगा। जो स्थानीय वहां के एस. एच. ओ., डी. एस. पी. या एस. पी. होता है। मेरे ख्याल से अगर किसी पर डालनी है तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा एस. पी. पर डालनी चाहिए। उसके ऊपर आप ले जाएंगे तो मेरी राय में शायद इतना कारगर यह नहीं होगा। मैं केवल आपको सुझाव दे सकता हूं कि अगर जिम्मेदारी किसी पर डालनी है तो एस. पी. से ज्यादा ऊंचे अधिकारी पर नहीं डालनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिम्मेदारी नहीं डाली है। आपने शायद सुना नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सुना तो नहीं मैंने पढ़ा ही है। यह बात ठीक है मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा ही है।

मैं सभी बातों की आलोचना करने का आदी नहीं हूं। पृष्ठ 6 पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस दस्तावेज में है कि नये कुओं के लिए बीमा व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाएगा ताकि जिन किसानों के कुओं पर पर्याप्त पानी नहीं आया। उसके द्वारा खर्च की गई राशि का सरकार के द्वारा पुनर्भरण किया जा सकेगा यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं लेकिन आशा करता हूं कि इसकी क्रियान्विति शीघ्र कर दी जाएगी।

एक बात पेज 7 पर ऋण माफी के बारे में कही गई। उन्होंने कहा कि ऋण माफी एक देश व्यापी प्रश्न है और इसकी क्या प्रक्रिया होगी इसका केन्द्र सरकार से परामर्श लेकर फैसला किया जाएगा जिससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी। श्रीमन् मुझे ठीक तरह से अगर याद है तो जब घोषणाएं मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनावों में जब भाषण कर रहे थे तब यह "इट्स और बट्स" उन्होंने नहीं लगाये थे। उन्होंने कोई लिमिट भी नहीं बांधी थी कर्जे की। उन्होंने कोई कैटेगरी भी नहीं बनाई थी कि इतना कर्जा माफ किया जाएगा। आज इस तरह की कैटेग रोज क्यों बनाई जा रही है। जो कर्जदार है। वह कर्जदार है श्रीमान् मेरा विचार भिन्न हो सकता है। इस मामले में। मैं बहुत कर्जा माफी का हामी नहीं हूं लेकिन उनको याद दिला रहा हूं। उनके घोषणा पत्र में लिखा है, बी. जे. पी. का घोषणा पत्र यह मेरे पास में है। उन्होंने सीधे लिखा है--किसान। इसमें छोटे, मंझले, बीच के, ऊंचे, नीचे किसान नहीं लिखा है। किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई है। मैं मान कर चलता हूं कि सरकार ध्यान रखेगी, अपने घोषणा पत्र का और सभी किसानों के कर्जे माफ कर देगी।

ऐसे कर्जे माफ करना मेरी व्यक्तिगत राय में बहुत मुनासिब बात नहीं है। मेरा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सुझाव तो यह होगा। अच्छा तो यह है कि उन कर्जदारों को फिर से राहत दें। उनका फिर उत्पादन बढ़ाएं उनकी कुछ आमदनी बढ़ायें और उनसे कुछ वसूली करें तो इस देश की आर्थिक प्रक्रिया जितनी तेज गति के साथ चलनी चाहिए उतनी चल सकेगी। सभी कर्जे माफ कर दिये तो डर इस बात का है कि कहीं वह परम्परा न बन जाय और यदि ऐसा करना ही है तो पार्लियामेंट में सीलिंग कर देनी चाहिए कि इस साल तक के कर्जे इस साल तक आगे और माफ किये जा सकते हैं। क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हर साल लोग कर्जे लेंगे और माफ कराएंगे। हम को कई अनुभव हैं, बुरा मत मानिए, मैं जिस वर्ग को रिप्रेजेण्ट करता हूं उसी पर यह ज्यादा बोझ है और जब मैं यह बात बोलता हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं जानता हूं कि लोग मेरे खिलाफ होंगे लेकिन मैं ऐसी कोई आदत जो कि गलत आदत है, देश हित में नहीं है, उनके हित में नहीं है, डालना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यदि कोई आप वायदा करें तो उसे पूरा करें। वर्ना मेरा सुझाव तो यह है कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों की आमदनी बढ़े, उनका उत्पादन और उनकी क्षमता बढ़े जिससे कि कि वह कर्ज को वापिस कर सकें। मेरी ऐसी आकांक्षा है कि सरकार इस पर ध्यान देकर चलेगी।

मैं उन बातों को, अभी जो अन्तर्राज्यीय मामले या हमारे सीमावर्ती राज्यों के मामले या अन्तर्राष्ट्रीय मामले हैं उनको नहीं उठाना चाहूंगा। मैंने जैसा कहा है कि थोड़ा समय हुआ है, मैं देखना चाहूंगा। सरकार जब बजट लेकर सामने आएगी। लेकिन एक बात बहुत जोरदार तरीके से लिखी गई पेज 8 पर और सब बातें लेने के बाद उन्होंने लिखा कि चूंकि हितों की रक्षा करेगी उन सब कर्तव्यों के निर्वहन में वह किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेगी। मैं केवल मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा अनुसरण कर लीजिए। मैं नहीं झुका था। ऐसा आपने भी इस सदन में कहा है। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। मुझे शंका पैदा हो गई। यहां तो राज्य के हितों का मामला आ रहा है। अभी तो पार्टी और व्यक्तियों के हित सर्वोपरि हो गये। जो व्यक्ति हमारे राज्य का ही नहीं है। केन्द्र के एक मंत्री को राज्य सभा में भेज दिया गया। एक व्यक्ति जो किसी पार्टी का मेम्बर ही नहीं है महज इसलिए कि वह महाराजा है, राज्यसभा में भेज दिया गया। हमने तो अखबार में पढ़ा था कि मुख्यमंत्री जी दबाव में आ गये....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने बहुत गरीब आदमी को राज्यसभा में भेजा है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पहले से ही बात हुई थी। वह हमारी पार्टी का मेम्बर है। हमारी पार्टी के मेम्बर हैं बिरला जी इसलिए हमने पहले भी भेजा था और भेजा है लेकिन महाराजा गजसिंह किसके मेम्बर हैं? जोधपुर के महाराजा किस पार्टी के हैं मेम्बर मैं जानना चाहूंगा? हमने अखबार में पढ़ा है कि राजमाता सिंधिया के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

दबाव में मुख्यमंत्री जी आ गये। तो एक सीट देने के वास्ते मुख्यमंत्री जी दबाव में आ जाते हैं वह राज्य के हितों के लिए दबाव में नहीं आएंगे इस पर मेरी आशंका है। मैं शंका करके चलता हूं। इस बात को ध्यान में रख कर चलेंगे।

एक बात और उन्होंने कही। बहुत अच्छी है अगर बन जाय तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पेयजल समस्या के समाधान में जनता की भागीदारी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की मन्शा इसको प्राइवेट सैक्टर में देने की भी है। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है बशर्ते की पीने का पानी ठीक तरह से मिल जाय क्योंकि जिस तरह से आज पीने के पानी की दिक्कत हो रही है वह प्राइवेट सैक्टर में हो चाहे पब्लिक सैक्टर में हो, मैं तो उसका स्वागत करूंगा लेकिन एक बात से संशय पैदा हो गया है। निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के भी प्रयास किये जाएंगे। केवल उत्पादन निजी क्षेत्र में चला जाय और वितरण की व्यवस्था फिर सरकार के हाथ में रह जाय तो काम चलने वाला नहीं है। अगर करना ही है तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहीं किया हुआ है उस व्यवस्था को अडॉप्ट करके लागू करें तो मैं समझता हूं कि बिजली की समस्या का समाधान भी जल्दी हो सकेगा। जब इस बात को मैं कहता हूं तो मेरी पार्टी के लोग, पब्लिक के लोग भी कहेंगे कि प्राइवेट सैक्टर को हम तरजीह देना चाह रहे हैं। चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे पब्लिक सैक्टर हो, चाहे जोइन्ट सैक्टर हो, जनता को राहत तो मिले। आज तो हम देख रहे हैं कि बिजली की त्राहि-त्राहि मच रही है। पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है। सब तरफ इस बात की आवाज आ रही है कि बिजली लाओ, पानी लाओ। श्रीमन् यदि यह हो सके कि सरकार समस्या का समाधान कर सकेगी तो यहां जो बैठे हैं हम लोग, जिन्होंने सरकार चलाई है वह भी आपकी तारीफ करेंगे। हमसे ज्यादा सरकार तारीफ करेगी लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं, सब कुछ बनता नहीं आ रहा है। सरकार ने कहा था, चुनावों में बड़ा भारी मुद्दा था किसानों को बिजली दिन में देने का। 20 दिन तो हो गये श्रीमन्, अभी तो दिन में आई नहीं। अभी तो रात में भी नहीं मिल रही है। यह बात जो उन्होंने कही कि 15 दिन के लिए 8 घंटे बिजली किसान को दे देंगे। अभी तो दे नहीं सकते। शायद इतनी जरूरत भी नहीं है, फसल तो पक चुकी है। अभी भी दे दें, बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी मिल नहीं रही है इसकी भी जांच कर लें यदि मिल जाय और दिन में मिल जाय तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कठिन है।

एक माननीय सदस्य : 10 घंटे दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 10 करें, 15 करें लेकिन अभी तो फसल पक गई, कट भी चुकी है। जितना दे दें।

पेज 9 पर आपने एक बात कही जिससे मेरा दोनों तरह का सम्बन्ध है। चूंकि इस वर्ग का हूं इसलिए व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है और एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हूं इसलिए

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सार्वजनिक सम्बन्ध भी है। इसमें कितनी गम्भीरता सरकार दिखायेगी यह मैं नहीं जानता। इसमें है-व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पिछली सरकार ने उन कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन के कार्य को उलझाया और अधिकांश मामलों में सहकारी समितियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों को अपरोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा कर जनता के हितों की उपेक्षा की। यह तो जांच का विषय है। मैं नहीं कह सकता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सहकारी समितियों के नाम पर जिस तरह से एस.सी. और एस. टी. के लोगों की जमीनें ली गई बावजूद कानून के एस. सी., एस. टी. के लोगों की जमीनें किसी और को नहीं बिक सकती। वह सब चली गई बिना बिके। मकानात उन पर बन गये। मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा है, लाभ मिलना चाहिए लेकिन डर इस बात का है कि धीरे-धीरे, अभी तो शहरों में ही जमीनें गई हैं पर गांवों में भी वह जमीनें चली जाएंगी। पहले से ही एस. सी., एस. टी. के लोग भूमिहीन हैं, कल को आशंका इस बात की है कि जो जमीन उनके पास है जिसका मालिकाना हक उनको मिला है कहीं वह जमीन उनकी नहीं चली जाय और सारे के सारे लोग फिर भूमिहीन होकर सरकार के सामने नहीं आने लग जायें कि हम को जमीन चाहिए। श्रीमन्, इस पर पाबन्दी होनी चाहिए। मैंने सुना है कि कलक्टर की मंजूरी से या किसी अधिकारी का नाम उसमें है जिसकी मंजूरी से दिया जा सकता है। तो न कोई कलक्टर को पूछता है, न कमिश्नर को पूछता है। सारे के सारे कब्जे होते चले जा रहे हैं। जमीनें धीरे-धीरे बिकती चली जा रही हैं। मकान बिकते चले जा रहे हैं। उनका परिवर्तन होता चला जा रहा है। मैं आशा करता हूं कम से कम एस. सी., एस. टी. के लोगों की जमीनों का संरक्षण सरकार पूरी तरह से करेगी। श्रीमन्, एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है वह शायद सारे राजस्थान की समस्या नहीं है इसलिए शायद मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में नहीं आयी हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बच्चों की अधिक मृत्यु दर, जनजाति क्षेत्रों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में तपेदिक का फैलाव, पेय-जल जनित नारू व फाइलेरिया रोग, बढ़ता अन्धापन, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, अस्पतालों में गरीब मरीजों की उपेक्षा और अभिजात्य वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान आदि की बातें उन्होंने कही है। यह स्वागत योग्य कदम है, ऐसा कर सकें तो। लेकिन एक बीमारी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्रीमन् पता नहीं क्यों हमारे क्षेत्र में जो हरियाणा से लगा हुआ है और पानी बहुत खारा है और सुना है कि फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, कोई टेक्निकल टर्न है, माफ करना, मैं अगर गलत कहता हूं सुधार लें लेकिन जिसको कहते हुए थोड़ा संकोच होता है। सफेद दाग जिसको कहते हैं, कोढ़ भी कह सकते हैं। लेप्रोसी है श्रीमन् उस इलाके में बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों पर इसका ज्यादा प्रकोप हो रहा है। इन बीमारियों का जिनका उन्मूलन का आपने जिक्र किया है उसके साथ-साथ अगर कोढ़ को भी आप शामिल कर लें और प्राथमिकता के आधार

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पर उस इलाके में ज्यादा व्यवस्था साथ करवा सकें जिसमें खास तौर से भरतपुर का इलाका, अलवर का इलाका हरियाणा से लगा हुआ, हरियाणा में सुना है कुछ इलाकों के अन्दर ज्यादा फैल रही है। उसका सर्वे आपको करवानी चाहिये, सर्वे करवा कर जो भी माकूल व्यवस्था हो सकती है और जितना कर सकते हैं करना चाहिये। मैंने सुना है कि यूनीसेफ की कई स्कीम्स यहां पर आयी हैं, यू. एन. ओ. मदद देने को तैयार है। भारत सरकार भी उसमें बहुत अग्रणी तरीके से मदद करना चाहती है। मेरी प्रार्थना है कि इसके साथ-साथ सफेद दाग और कोढ़ का जो बहुत जोर के साथ प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है उसको नारू के साथ, फाइलेरिया रोग, अन्धेपन के साथ इसको भी आप शामिल कर सकें तो आपका बड़ा उपकार करेंगे। क्योंकि कोढ़ श्रीमन् केवल शारीरिक बीमारी नहीं है एक सामाजिक कलंक है और हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, हमारे बहुत सारे बच्चे इससे पीड़ित हो जाते हैं। उनको समाज से अलग होना पड़ता है, परिवार से अलग होना पड़ता है। उनकी क्या दशा होगी उसका अन्दाजा तो वही लगा सकते हैं। मैं श्रीमन् आपसे इसलिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन बीमारियों के साथ इस बीमारी का इलाज भी प्राथमिकता के तौर पर व्यवस्था हो सके, इसको भी शामिल कर लिया जाय।

श्रीमन् इसी तरह से एक बात मुझे और आश्चर्य और चकित करने वाली लगी। मैं समझता हूं गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार का चारों तरफ से प्रयास होगा लेकिन एक तरफ इस दस्तावेज के जरिये से कहते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या राज्य के सम्मुख प्रमुख चुनौती है। इसके साथ-साथ ऊपर के पैराग्राफ में लिखा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं कि, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य की समीक्षा कर लाभ में नहीं चल पाने वाले उद्योगों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा। श्रीमन् मैं यह समझ रहा था कि जैसी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि उन उद्योगों को चालू किया जायेगा, उत्पादित बनाया जायेगा, रोजगार देने के लिए उत्पादित बनाया जायेगा उसके बजाय चलते हुए उद्योगों को किसी वजह से जो नहीं चल पा रहे हैं उसके कारण देखना चाहिये, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिये वह तो बात ठीक रहेगी लेकिन अगर चलते हुए उद्योग भी बन्द कर दिये तो मुझे शंका है इस बात की कि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं श्रीमन् जिनके उद्योगपतियों ने पैसे ले लिये, जितना कमाना था वह कमा लिया, अब शायद वे उद्योग उनको मुनाफा नहीं दे रहे हैं, घाटे में नहीं चल रहे हैं लेकिन जितना मुनाफा उनको देना चाहिये उतना नहीं दे रहे हैं और शायद उनकी मंशा यह है कि और कोई योजना बनाये और प्रोजेक्ट लेकर के सरकार से और फायदा उठा लें। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि बजाय इसके कि ऐसे उद्योग जो नहीं चल पा रहे हैं उनको बन्द नहीं किया जाय, उनको उत्पादित किया जाय, उनकी मदद की जाय, उनको

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लाभान्वित करने के साथ-साथ उनको रोजगारोन्मुख बनाया जाय, उनको किसी भी दृष्टि से चालू किया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह राजकीय उद्योग है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : राजकीय उद्योग की बात कर रहा हूं, आपने लिखा है वही पढ़ा है। (व्यवधान)

वह बात जो आप कह रहे हो वह मैं समझता हूं लेकिन आज यह राजकीय उद्योगों पर लागू करें कल तो यह प्राइवेट उद्योगों पर भी हो जायेगा। इसलिए इस मामले में बहुत कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसा आप पहले कर चुके हैं, जब पहले आप मुख्य मंत्रीजी थे तब ऐसा आप कर चुके हैं इसलिए मुझे यह कहना जरुरी था।

श्रीमन् एक बात इसी बारहवें पन्ने पर कही गयी है, मेरी आशंका गलत हो सकती है। परम्परागत व्यावसायिक कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जायेगा। तो परम्परा क्या है श्रीमन् मोची का लड़का मोची बनेगा, बुनकर का लड़का बुनकर बनेगा, मेहतर का लड़का सफाई करेगा, चमार का लड़का जूता बनायेगा। चमार का लड़का चर्मकारी का काम करेगा अगर इस परम्परागत व्यावसायिक कार्यक्रमों की यही परिभाषा है श्रीमन् तो माफी चाहूंगा, मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं, इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा सरकार से कि वह ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले, किसी भी अभिजात्य वर्ग, किसी भी वर्ग के हों, किसी क्षेत्र के हों वे लोग ट्रेनिंग लें और आकर के अपनी बेरोजगारी दूर करें। श्रीमन् इसका मतलब तो यह है कि यह सरकार आज भी इस जाति व्यवस्था को बनाये रखना चाहती है, वर्ग व्यवस्था को बनाये रखना चाहती है। एक तरफ तो जाति-विहीन समाज की बात करना, वर्गविहीन समाज की बात करना, समानता की बात करना और दूसरी तरफ इस तरह से परम्परागत तरीके से चलने वाले उद्योगों को बनाये रखना। श्रीमन् मेरी ऐसी आशा है, जिस मुख्य मंत्रीजी ने अन्त्योदय योजना का जिक्र किया। उन्होंने एक बात यहां गलत कह दी कि हमने बन्द कर दिया था। जहां तक मुझे याद है अन्त्योदय योजना को मैंने हमेशा जारी रखा था। सन् 1980 के अन्दर मैंने....(व्यवधान)

केवल नाम बदल गया हो वह अलग बात है, नाम बदला होगा लेकिन मैंने तो बदला ही नहीं था नाम और इसलिए श्रीमन् मैं चाह रहा था कि कम से कम और कुछ नहीं करेंगे तो आज की सरकार सिर पर मैले उठाने की जो परम्परा है उसको दूर करने की कोई न कोई व्यवस्था कर देगी इससे बड़ा अन्त्योदय का काम और दूसरा नहीं हो सकता है। अगर मुझे इजाजत है तो मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा और सारे काम बाद में हो जायेंगे। उद्योग भी बाद में लग जायेंगे, कृषि भी हो जायेगी, बहुत जरुरी है उसके बिना काम चलता नहीं है रोटी चाहिये, कपड़ा चाहिये, मकान चाहिये। लेकिन श्रीमन् कुछ ऐसी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

व्यवस्थाएं हैं जो समाज के लिए कलंक है। सिर पर मैला उठा करके आज भी कोई व्यक्ति चलता है तो हमारे सारे व्यक्तियों का ही नहीं सारे देश का माथा झुक जाता है। श्रीमन् इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम यह परम्परा जो बहुत दिनों से चली आ रही है उस परम्परा को बन्द किया जाय। नगरपालिकाओं को अनुदान दिया जाय, ऐसे औजार उपलब्ध कराये जाय जिससे कि कम से कम मैला ढोने की जो व्यवस्था है सिर पर उसको जितनी जल्दी हो सके बन्द कर सके और केवल अनुदान नगरपालिकाओं को देने से काम नहीं चलेगा उसका भी दुरुपयोग हो जायेगा। एक बार मैंने देकर देखा है श्रीमन् एक साल में मैंने बहुत सारी नगरपालिकाओं को अनुदान दिया था कि वह औजार खरीद लें परन्तु उसकी बजाय दूसरी चीजें खरीद ली गयी। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि एक योजना चली जिसके जरिये से हम परिवार वालों को सहायता देते हैं जिससे कि वह अपनी फ्लश की लेट्रीन्स बना सकें उसको ही प्रोत्साहन हमको देना पड़ेगा और नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन और जगह देनी पड़ेगी तभी यह शायद व्यवस्था हमारी खत्म हो जायेगी। मेरी ऐसी आशा है कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्रीमन् इसी प्रकार से पेज-13 पर उन्होंने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ी जातियों के विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। श्रीमन् मूल्यांकन तो पिछली सरकार बराबर करती रही है। कांग्रेस की सरकारों की यह कोशिश रही है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके, हर क्षेत्र के अन्दर उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी। हम जानते हैं कि यह समस्या बहुत गहरी है। एक दिन का काम नहीं है। बहुत सारी परम्पराएं हैं, सैंकड़ों साल की, बहुत बदली है और बदलेगी। जितना हो सकता था, कर सकती थी सरकार ने, केन्द्र की सरकार ने, राजकीय सरकारों ने कोशिश की लेकिन यह तो बहुत दिनों से चली आयी बीमारी है इसको और ज्यादा तेज गति के साथ करना पड़ेगा। मैं आशा करके चलता हूं कि जो रिजर्वेशन का शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के बच्चों का कोटा है वह आज भी भर नहीं रहा है। सरकार ने कह तो दिया कि पाबन्दी हट गई इसके बावजूद भी नौकरियों में लोग नहीं जा पा रहे हैं। मेरी ऐसी आशा है कि इसका सर्वे करवाया जाय और कम से कम रिजर्वेशन कोटे को पूरा किया जाय। इसमें श्रीमन् एक बात का जिक्र का मैं तलाश कर रहा था और मैं सोच रहा था कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल के लोग बैठे हैं मण्डल आयोग की रिपोर्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं करेंगे। मुझे कहीं इसमें मण्डल आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं मिल रहा है मैं स्वयं बहुत पहले तक मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर हामी नहीं था पर मैंने उसे गहराई से पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर हमको चर्चा करनी चाहिये और केवल चर्चा नहीं करनी चाहिये बल्कि वे जातियां लागू करनी चाहिये जो जातियों

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उसमें शामिल हैं जिसका जिक्र आ गया है चाहे गूजर हो, चाहे माली हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे गडरिया हो। इसी तरह से बहुत सारी जातियां हैं जो कि पीड़ित हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनको भी इस बात का लाभ मिल जाना चाहिये। मेरी ऐसी आशा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर न केवल विचार किया जायेगा बल्कि विचार करके बहुत जल्दी फैसला किया जायेगा और उसको लागू किया जायेगा।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ एक बात हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी के बारे में उन्होंने कह दी। उन्होंने जो बात कही थी, उसको नहीं लिखा गया। उन्होंने कह दिया कि 85 पैसा तक भ्रष्टाचार होने की बात स्वयं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कही थी। श्रीमन्, ये तो मैं श्री राजीव गांधी की दिलेरदिली मानता हूं कि सच्चाई और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ कर के उन्होंने उस बात को कहा था। लेकिन यह कभी नहीं कहा कि भ्रष्टाचार में जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक खर्चों में खर्च हो जाता है। हमारी आशा है कि तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को नहीं रखा जायेगा और वह बात उसी रूप में कही गयी थी, उस रूप में न केवल कही जायेगी, बल्कि आप अगर चाहें तो उसका पालन कर सकते हैं। यह बात उन्होंने सही कही थी, सत्य कही थी। प्रधान मंत्री की हैसियत से भी कोई व्यक्ति सच्चाई बोल सकता है, वह बात तो उसके हित में नहीं पड़ती, उसके खिलाफ पड़ती है, उस बात को वह कैसे कह सकता है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : (झुंझुनू) उन्होंने यह बात भी कही थी कि अगर मुझे दुबारा अवसर दिया तो मैं इस भ्रष्टाचार की राशि को 85 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक ले आऊंगा। यानि, 70 प्रतिशत तो फिर भी होगा। ये भी कहा था, अब पूछ लो इनसे कि क्या कहा था ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे बहुत सारी बातें...

एक माननीय सदस्य : गायें चीनी खा गयीं, यह भी उन्होंने कहा था, आपको याद हो तो...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। समय कम है, इसलिये मुझे समाप्त करना है। श्रीमन् पेज 14 पर कहा : "साधनों की कमी से जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पाई हैं, वहां पुलियाओं का निर्माण कर यातायात में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।" केवल पुलियाओं का निर्माण होगा। मगर सरकार सड़कें नहीं बना सकती है और कांग्रेस की सरकार ने तो एक मास्टर प्लान बना कर के देश के सामने पेश किया। हमारी योजना थी कि दो हजार आबादी वाले गांव सब सड़कों से जोड़ दिये जायें। हम

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ऐसा मान करके चलते थे कि अब इस को सरकार को बताया जायेगा कि दो हजार तक की आबादी के गांव जोड़ दिये जायेंगे। लेकिन अगर केवल पुलियाओं का निर्माण करके छोड़ दिया गया तो काम चलने वाला नहीं है क्योंकि श्रीमन्, सड़कें न बनें, लेकिन रास्ते तो ठीक तरह से हो जायें। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहें तो आप विचार करें यह जिम्मेदारी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की होनी चाहिये कि जो रास्ते खराब हो गये, खास तौर से ट्रैक्टरों की वजह से, उन पर इन्सान नहीं चल सकता एक कदम नहीं चल सकता, कीचड़-कादा हो जाता है, जीप नहीं निकल सकती, बैलगाड़ी नहीं निकल सकती, उन रास्तों को कम से कम ठीक कराने की जिम्मेदारी हर साल बरसात के बाद पंचायत समितियों और पंचायतों की होनी चाहिये। उसके लिए चाहे हमारी पंचायत समितियों और पंचायतों को अनुदान आपको देना पड़े। मेरी ऐसी आशा है कि यह करके कि केवल पुलियाओं का निर्माण होगा, सड़कों के लिये अनुदान नहीं दिया जायेगा. . .

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके लिये पहले सारे सरपंचों को हटाना पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन, एक बात मेरी अपनी आशंका है इसलिये मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। पेज 15 पर जिक्र किया है : "राजस्थान की अपनी सांस्कृतिक विशेषतायें हैं। विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक विविधताओं, गरिमामय इतिहास एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण यह पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। पर्यटन के विकास हेतु दीर्घकालीन नीति बनाई जायेगी, इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा।" श्रीमन्, निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाये, इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन शंका इस बात की हो रही है कि कहीं इस बहाने से पुराने राजामहाराजाओं को उनके गढ़, उनके किले, उनके महल, जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, शायद ठीक करने के लिये सरकार ने सोच लिया है। अगर हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर उनका उपयोग व्यक्तिगत काम के लिये नहीं आना चाहिये, वे व्यक्तिगत आमदनी का जरिया नहीं बनने चाहिये। वे राज्य के काम आने चाहिये, उनकी आमदनी राज्य के जरिये होनी चाहिये, राज्य को मिलनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी सिर हिला रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि जिस बात को मैंने कहा, सुझाव दिये हैं, उसका ध्यान रखेंगे।

(समय समाप्ति सूचक—घंटी)

अब एक बात अन्त में अकाल के बारे में कही है। राजस्थान में अकाल हर साल पड़ता है, एक प्राकृतिक प्रकोप है। हम नहीं चाहते कि यह अकाल हर साल पड़े। प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं। हमारी ऐसी बहुत आशा है कि अकाल के बारे में बहुत आलोचना पिछली सरकार की की गयी। हम जानते हैं कि बहुत सारे दुरुपयोग भी हुए होंगे। हम यह भी जानते हैं कि काम एक जगह हो गया और बार-बार उसी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

काम को कराया गया। ऐसे काम जो स्थाई हैं, वे लिये जाने चाहियें और ऐसे काम जो रोजगार सम्मत हैं, लिये जाने चाहियें। लेकिन, श्रीमन्, हर साल लगातार एक ही जगह पर तीस साल से चालीस साल से अकाल पड़ता रहा, लेकिन वही काम हुए। अगर यह बात अब बंद हो जाये, तो ज्यादा ठीक रहेगा। नतीजा क्या निकलता है। वह इलाका जहां अकाल पड़ता है, पड़ता ही रहता है। दूसरे इलाके चाहे उनमें अकाल पड़ता हो, चाहे वहां पर बाढ़ आ पड़ती हो, अकाल के यह मायने क्या होता है? अकाल का पड़ना, सूखे से केवल नहीं होता है, अकाल वहां भी पड़ जाता है जहां बाढ़ आ जाती है। जहां फसल बर्बाद हो जाती है, वहां अकाल हो जाता है। श्रीमन्, इसके नार्म्स को शायद हमको अध्ययन करना पड़ेगा और जिन स्थानों पर 30 बार चालीस बार लगातार अकाल पड़ चुका शायद हमको वहां पाबंदी लगानी पड़ेगी। दो साल, चार साल, पांच साल और तय कर लीजिये कि, यहां अकाल पड़ेगा। इस के बाद तो बंद कर दीजिये।

श्री नत्थी सिंह : कांग्रेस के राज में राजनैतिक अकाल पड़ता रहा है शायद?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब, तो मैं यही आशा कर रहा हूं कि अब आपके यहां राजनैतिक अकाल नहीं पड़ेगा। अगर अकाल था तो केवल कांग्रेस के राज में नहीं पड़ा, मगर 77 से 80 के बीच में भी यही हाल हुआ था। उसको क्यों भूलते हैं आप? इसलिये, मेरी ऐसी आशा है कि अकाल को राजनीति में नहीं फांसा जायेगा। अकाल को व्यक्तिगत आमदनी का जरिया नहीं बनाया जायेगा, अकाल के जरिये से उन गरीबों का शोषण नहीं किया जायेगा, बहुत सारी परंपराएं ऐसी पड़ गयी। मैं इस पार्टी के राज में ये हुआ, उस पार्टी में ये हुआ, उसमें जाना नहीं चाहता। अकाल की वजह से पैसा बांटा जाये, इस बात की भी चर्चा हुई थी इस साल, बांटा भी गया था। किस राज में बांटा गया, किस राज ने बांटा, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं व्यक्तिगत उसका हामी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि काम मिलना चाहिये। घर बैठे किसी को पैसा देना लोगों को निकम्मा बनाना है और हमारी आदतें खराब करना है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता घर बैठे पैसा लेना। मेरी ऐसी आशा है कि ऐसे काम खोले जायेंगे, तो स्थाई होंगे, जो बार-बार अकाल नहीं पड़ेगा। उसका कोई सोल्यूशन कर दिया जायेगा, यह जो अकाल बार-बार पड़ता है। श्रीमान् कई बातें ऐसी आपने कह दीं, मगर दो सुझाव और आपको देना चाहूंगा। एक तो श्रीमन्, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है आपकी सरकार को उचित नहीं लगे, वैसे तो जब भी चुनाव होते हैं यह सरकार बराबर कहती है, श्रीमन्, कुछ नये जिलों का गठन करना मेरी राय में बहुत आवश्यक है। जब मैं मुख्य मंत्री था, मैंने पांच जिलों के नाम का फैसला किया था। उनमें धौलपुर, दौसा, बारां, राजसमंद, हनुमानगढ़, मुझे याद है। करौली भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। करौली स्टेट रह गया। जो दूसरी रियासत की राजधानी थी, जहां पर अभी जिला नहीं है। प्रतापगढ़ रह गया, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। इन

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

स्थानों पर नये जिले बनें और अगर ऐसी जगह कहीं पर है, जहां पर कि अभी भी बहुत आबादी हैं आवागमन के साधन नहीं हैं, प्रशासन की व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, तो नई तहसीलों का बनाया जाना भी बहुत आवश्यक है। मैं सभी का ले रहा हूं, एक जगह का नहीं ले रहा हूं। श्रीमन्, इन बातों को कहने के बाद मैं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

केवल एक ही मिनट में अपने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मेरे क्षेत्र कठूमर में पीने के पानी की भारी समस्या हैं। कुएं सूख गये हैं, यहां तक कि ट्यूब वैल्स भी सूख गये, मेरे क्षेत्र के दो हिस्से हैं एक कठूमर तहसील और दूसरा लक्ष्मणगढ़ में बहुत सारा पहाड़ी इलाका है। हैंड पम्प नहीं लग पाते हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके ऐसी मशीनों को, जो नलकूप गहरा खोद सकें, वहां कठूमर क्षेत्र में भेज कर के पाताल तोड़ कुएं बनवाये जायें। बिजली का जहां तक संबंध है, बहुत सारे अभी गांव इलेक्ट्रिफायड नहीं हैं जबकि क्षेत्र के अंदर, जहां से मैं आता हूं, वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था, इसलिये लोग उसको देखते हैं। कम से कम ऐसे गांव जो कि मंजूर शुदा हैं, उनमें बिजली जल्द आये। जहां से बिजली की लाइन जा रही है, कम से कम उन गांवों को जल्दी जोड़ दिया जाये। जहां पर ट्रांसफार्मर जले पड़े है, साल-साल, दो-दो साल हो गये, लोग बहुत परेशान हैं, उनको जल्दी रिप्लेस कराया जाये। मेरी ऐसी एक प्रार्थना है आप से और साथ ही सड़कों के निर्माण के बारे में मैं देख रहा हूं रास्ते खराब पड़े हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ ट्रैक्टरों की वजह से रास्ते ज्यादा खराब हो गये हैं। इसलिये सड़कें नहीं बनाइये, लेकिन रास्ते ठीक हो जायें और यह जिम्मेदारी शायद पंचायत समितियों कर हम डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्कूलों की, स्कूल तो खोल दिये गये, बहुत अच्छा किया सरकार ने और इस बात के लिये पिछली सरकार बधाई की पात्र है। जो सुविधायें आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी, इसलिये अच्छा रहा, लेकिन उनमें टीचर्स नहीं हैं। जल्दी भेजना मुनासिब रहेगा। एक बात मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से कही कि कठूमर में सब तहसील तो है, लेकिन तहसील हेड क्वार्टर नहीं हैं। नतीजा क्या निकलता है कि बहुत सारे काम जो होने चाहिये, हो सकते थे, स्थानीय स्तर पर, वह नहीं हो पाते हैं तो कठूमर में सब तहसील को क्रमोन्नत करके तहसील बना दिया जाये। एक सुझाव मेरा यह भी है और इसके साथ-साथ मैंने देखा कि खेजरी नगरपालिका में हालत बहुत गंभीर है। मुख्य मंत्री जी तो हेलीकाप्टर से गये थे वहां, इसलिये उन्होंने देखा नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में विरोध करने के लिये...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य . . . ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कीचड़ बहुत है। रास्ते बन्द हैं, खराब हैं। सफाई नहीं होती है। इसलिये मेरी ऐसी आशा है कि जहां पर गये थे, कम से कम वह तो आपने देखा हेलीकाप्टर से ही सही। तो वहां खेजड़ी नगरपालिका की आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जाये जिससे कि वहां पर सफाई की व्यवस्था हो सके। कीचड़ कम हो जाये, रास्ते वहां पर बन सकें, नालियां बन सकें। मैंने काफी समय लिया। मैं नहीं समझता कि कितने उपयोगी सुझाव मैंने आपको दिये हैं, लेकिन मैं आशा करके चलता हूं कि जो छोटे मोटे सुझाव मेरे दिमाग में थे, मैंने दिया। और, मैं यह भी आशा करता हूं कि जो राजनैतिक बात हमारे साथियों ने यहां पर बैठ कर कही हैं, बहुत मुद्दे की हैं, उन सब बातों को ध्यान में लिया जायेगा और इस बात की कोशिश की जायेगी कि आगे चल करके राज्यपाल का अभिभाषण आलोचना का दस्तावेज नहीं बने; बल्कि प्रदेश की नीति की आलोचना का दस्तावेज बने। इन्हीं शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राम करण जी चौधरी। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापतिजी, सबसे पहले मैं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछली सरकार के दस वर्षों के शासन काल में प्रशासन में आई गिरावट, फिजूलखर्ची, वित्तीय साधनों के अपव्यय को रोकने का जो आव्हान किया है, भ्रष्टाचार समाप्त करने का मुख्य मंत्री के आचरण को लोकायुक्त कानून में आने का जो संकल्प किया है, व्यापक सहमति से जन समस्याओं को हल करने व जनता की भागीदारी होने का जो कहा है और सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग को रोकने व राज्य की चरमराई वित्त व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी नई सरकार ने निडरता से स्वीकार की है, राजनीतिक इच्छा के तहत संवेदनशील व ईमानदार प्रशासन देने का जो जिम्मा लिया है, मैं इन सब का स्वागत करता हूं।

माननीय सभापतिजी, इन सारे विषयों पर इस सदन में दोनों तरफ से काफी बातें कही गई हैं। मैं इस आसन के माध्यम से नई सरकार के समक्ष कृषि और इससे संबंधित सिंचाई, बाढ़, अकाल और पेयजल के मुद्दों को विशेष रूप से रखना चाहता हूं। हमारे देश की आजादी के करीब 38 वर्षों से एक ही पार्टी का शासन इस देश में रहा है और हमारा देश खेती प्रधान देश है, सौ में से अस्सी आदमी खेती पर निर्भर करते हैं, गांवों में रहते हैं, मुख्य धन्धा खेती है। आप लोग देखते आ रहे हैं कि देश का एक हिस्सा बाढ़ में हर साल बरबाद होता जा रहा है और देश का एक दूसरा बड़ा भाग सूखे के कारण मर रहा है। हमारी सरकारों ने जान-बूझ कर देश की जो अर्थ व्यवस्था बिगाड़ी है, जिस पर देश का प्रतिशत भाग निर्भर करता है, गलत योजना

(श्री रामकरण चौधरी)

बनाई, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसलिए बनाई कि यह गरीब रहे, हमेशा के लिए गरीब रहे, हमेशा के लिए हमसे दबते रहें और इनके वोट हम लेकर मौज करते रहें। अगर सरकार व्यवस्थित ढंग से काम करती, जो हमारी नदियों का पानी देश को बरबाद करता हुआ जाता है और पूरा समुद्र में जाता है, पूरे देश की खेती बरबाद करता है, देश का पशु धन बरबाद करता है, उस पानी को योजनाबद्ध तरीके से योजना बना कर सूखी नदियों में डाइवर्ट कर देते और पूरे देश में बिखेर देते, इस चालीस साल के शासन काल में अगर इस प्रकार का काम करते तो इनकी बाढ़ की समस्या दूर हो जाती, अकाल की समस्या दूर हो जाती, पेयजल की समस्या दूर हो जाती, सिंचाई की समस्या दूर हो जाती और देश का जो हर वर्ष अरबों रुपया बरबाद हो रहा है सारा पैसा बरबाद नहीं होता। हमारा बरसात का पानी सारा फालतू बह कर समुद्र में जा रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह इसलिए नहीं किया गया है कि हमारे इस सदन में, संसद में सत्ताधारी पार्टी ने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि गरीब को गरीब रखा जाय ताकि हमारे से दबता रहे और इनके वोट हम लेकर सत्ता में मौज करते रहे। यह तो राष्ट्रीय बात हुई जिसमें हमारे प्रदेश का भी हिस्सा है। आज हमारा पानी जो बरसात से आ रहा है हम इसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो आज हमारी जमीन में है उस पानी को भी हम सही ढंग से निकाल कर खेती के काम में नहीं ले पा रहे हैं। यह हमारी सरकार की असफलता है और सरकार की इस असफलता के कारण आज चालीस साल के बाद हमारे देश का किसान सरकार की मेहरबानी पर नहीं, आज कुदरत की मेहरबानी पर जिन्दा है। सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। हमारे चार माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान थे वे भी यह सोचते हैं कि चालीस साल में किसानों को कुछ नहीं दिया है। आज भी अगर अकाल पड़ता है तो लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। आज हमारा पानी बरबाद हो रहा है, एक इलाके को बरबाद करता है, अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने अकाल से निपटने के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाने का जो एलान किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर इस पानी का सदुपयोग किया जाय, जमीन के अन्दर से निकाल करके ऊपर के पानी को स्टोरेज में रखा जाय तो सारे परपज सोल्व हो जायेंगे। बाढ़ से विनाश होने वाला सारा इलाका बच जायेगा, सूखा इलाका हरा-भरा हो जायेगा, पानी होगा तो पेयजल की समस्या दूर हो जायेगी। एक काम करने से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। इसलिए नई सरकार ने यह जो साहसिक कदम उठाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि योजना बनाते समय हमारे प्रान्त में जमीन के अन्दर जो पानी है उसका खेती के लिए सदुपयोग किया जाय, इसके लिए भी योजनाएं बनायी जाय। बरसात के पानी को रोक कर बाढ़ को रोकने के लिए

(श्री रामकरण चौधरी)

योजना बनाई जाय जिससे अकाल का सारा प्रभाव समाप्त हो जायेगा। बिजली का जो मामला है इसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं विशेष रूप में मेरे क्षेत्र मेड़ता और जिला नागौर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि नागौर में मेड़ता में कोयले का बहुत बड़ा भण्डार मिला है। यह सही है, भारत सरकार ने इसका सर्वे किया है। अच्छी मात्रा व क्वालिटी का कोयला मेड़ता रोड के अन्दर काफी लम्बे-चौड़े इलाके में मिला है। माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इस आसन के माध्यम से कि हमारे इस कोयले से वहां पर ताप बिजली घर बनाया जाय और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय। मेड़ता और नागौर जिले से गोटन के पास काफी लम्बे इलाके में बहुत अच्छा पत्थर मिला है। बड़े-बड़े सीमेंट के कारखाने लगाये गये हैं, कई छोटी-मोटी सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, कली बनाई जा रही है, चूने का अच्छा उत्पादन हो रहा है। एक तरफ यह उद्योग की बात, दूसरी तरफ भगवान की दया से, कुदरत की देन से नागौर के काफी इलाके में, जिसमें मेड़ता, डेगाना, जायल, डीडवाना, लाडनूं, नागौर में बहुत अच्छा पानी बहुत भारी मात्रा में मिला है जिससे काश्तकारों ने बहुत ट्यूब वैल्स खोदे हैं और रोजाना कई ट्यूबवैल्स खुद रहे हैं। इसलिए बिजली का लोड एग्रीकल्चर कनेक्शन्स और उद्योगों पर बढ़ रहा है। मैंने सुना है कि सरकार की यह नीति है कि इस कोयले को यहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह ले जाकर ताप बिजली घर बनाना चाहती है। अगर ऐसा किया गया तो यह नागौर की जनता के साथ धोखा और विश्वासघात होगा, नागौर की जनता उसको कतई सहन नहीं करेगी। इसलिए हमारे इलाके में जो कोयला निकला है, हमारे मेड़ता में जो को कोयले का भण्डार है उसके लिए इस सदन के माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कोयले से वहां ताप बिजली घर बनाया जाय, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय और उस इलाके को पहले बिजली दी जाय ताकि कारखाने और कृषि को पूरी बिजली मिल सके।

पेयजल के बारे में वैसे दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपनी बातें बताई हैं और वास्तव में, मैं मानता हूं कि पेयजल की समस्या पूरे राजस्थान की है। हमारे नागौर जिले में और मेरे मेड़ता और डेगाना क्षेत्र के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है कि एक्सपर्ट्स आये हैं, सलाह करेंगे. योजना बनायेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले की, हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग होती है। हमारे जिले में आज अगर सरकार पानी की व्यवस्था करना चाहती है तो लम्बी योजनाओं में केवल दो बाते हैं--या तो राजस्थान केनाल जिसका नाम इन्दिरा गांधी कैनाल रखा गया है उससे लिफ्ट से पानी देकर दीर्घ-कालीन योजना बना सकते हैं या दूसरे, गंगा का जो फ्लड का पानी है जिसका नागौर तक सर्वे भी हो चुका है, उस पानी

(श्री रामकरण चौधरी)

को नागौर के अन्दर लाया जाय। उससे दोनों काम हो सकते हैं। सिंचाई भी हो सकती है और पेयजल की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मगर उसमें बहुत टाइम लग जायेगा भारत सरकार से, प्लानिंग कमिशन से व कई तकनीकी बातों में समय लगेगा तत्काल जिस मामले को लेना हों। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे इलाके में हमारे गांवों में करीब-करीब सभी गांवों में सार्वजनिक कुऐ हैं और इन कुओं को तत्काल प्राइवेट मशीनों से बोरिंग कराके पानी जो नीचे गहरा चला गया है उसको निकाल कर गांव को पीने के लिये दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि नागौर जिले में जब पेयजल की समस्या के निराकरण की बात रखी जाय तो नागौर के लिए तत्काल पानी की समस्या को दूर करने के लिये और कोई रास्ता नहीं है केवल हर गांव को प्राइवेट बोरिंग से सरकारी मशीनों की बहुत कमी है उसकी रेट सरकार ने बहुत कम रखी है उसके लिए 1600 रुपये मीटर से नीचे प्राइवेट वाले नहीं खोदते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। समय कम है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमारे नागौर जिले में एक इलाका जैसा निवेदन किया पानी बहुत भारी मात्रा में मिल गया है। लोगों ने सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवैल्स खोदकर चालू किये हैं। पूरा इलाका हरा भरा हो गया है और काफी इलाका जिसमें मेरा मेड़ता क्षेत्र, डेगाना क्षेत्र और आगे नागौर और जायल क्षेत्र आता है उसमें करीब 60-70 मीटर गहरा खोदने के बाद बहुत बड़ा पत्थर आता है वह उन मशीनों से नहीं खोदा जा सकता है जिससे सारे ट्यूबवैल्स होते हैं, हो रहे हैं इसलिए मेरा आसन के माध्यम से सदन के माध्यम से विशेष जोर देकर सरकार से निवेदन है कि आप भारत सरकार से सम्पर्क करके उस इलाके में जो स्पेशल शक्तिशाली मशीनें हैं भूगर्भ विभाग के पास है या अन्य विभागों के पास हैं उनसे जगह-जगह सर्वे कराया जाय और पत्थर कितना गहरा है और उसके नीचे कितना पानी है, उसकी पोजिशन है? पानी नीचे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो सारी समस्या पेयजल को समस्याएं और सिंचाई की समस्या दूर हो जायेगी और इस प्रदेश के अन्दर और इसका असर जब होगा तब लोगों को पता चल जायेगा की नीचे की पोजिशन क्या है? इसलिए विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि इस मामले को सरकार प्राथमिकता देकर कराये। बाकी बातें कही जा चुकी हैं समय काफी कम है इसलिए ज्यादा समय न लेकर एक निवेदन और करना चाहता हूं।

आज सब जगह बिजली की जरूरत हो गयी है और जैसा मैंने निवेदन किया है कि हमारे नागौर जिले में पिछले तीन चार पांच वर्षों में पानी इतनी भारी मात्रा में जमीन के नीचे मिला है जो कि करीब पांच सौ फीट पर है और अगर काश्तकार ट्यूबवैल तैयार करता है तो तीन लाख साढ़े तीन लाख रुपया का खर्चा होता है तो इन काश्तकारों को जो बिजली के कनेक्शन हैं वह अगर लम्बे समय तक नहीं

(श्री रामकरण चौधरी)

मिलते हैं और जो उनकी प्रायोरिटी बनायी जाती है उसमें उनका नम्बर नहीं आता है इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से व भारतीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि नागौर जिले की विशेष भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए जब ट्यूबवैल बनाये जा सकते हैं, पिछले तीन चार वर्ष में मेरे मेड़ता क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा ट्यूबवैल्स खोदे जा चुके हैं और आज 10 प्राइवेट पार्टियां ट्यूबवैल्स खोदने में रात दिन लगी हुयी हैं, रात दिन खोद रही है इसलिए बिजली के कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जायें। ट्यूबवैल्स के लिए कोई लिमिट नहीं रखी जाय अगर एक काश्तकार एक ट्यूबवैल खोदकर चार साल तक बैठा रहे तो वह बराबर हो जायेगा उसकी जमीन बिक जायेगी इसलिए तत्काल ट्यूबवैल खोदते ही कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाय जिससे सारी समस्या दूर हो जायेगी। एक बार फिर पुनः आसन को धन्यवाद देता हूं जो मुझे समय दिया गया और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के आये भाषण को यदि हम बारीकी से पढ़ें तो उसमें मौजूदा सरकार के काम करने के जो लक्ष्य हैं, इच्छाएं हैं, एक प्रकार से सीधा निर्देश हैं। तीन चार दिन से बहस चल रही है। उसमें लगातार विपक्ष की ओर से आलोचना की गयी है और मेरा यह निवेदन है कि कोई भी कोम्पीटेण्ट सरकार हो उसके लिए कोम्पीटेण्ट मुख्यमंत्री आवश्यक है और हमारा पक्का विश्वास है कि जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं वे सक्षम हैं और निश्चित रूप से नयी दिशा देंगे। पिछली सरकार ने जो स्थितियां पैदा की हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाय तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थितियां बन गयी थी शायद थोड़े दिन मान लो केन्द्र में राजस्थान में सरकार नहीं बदलती तो शायद पानी की घूंट भी कांग्रेस के लोगों में पूछकर उतारनी होती अभी जब पहाड़ियाजी जो शंकाएं जाहिर कर रहे थे इन सब को पांच वर्ष में निर्मूल हम साबित करेंगे और जो लक्ष्य तय किये हैं जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगले पांच वर्ष में इस तरह की स्थिति बने कि फिर से हम जीतकर आयें और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाये। इस प्रकार की स्थिति की तुलना हम आज करें तो आज आप गांवों में चले जायें जिस तरह धन का दुरुपयोग हुआ और जिस तरह पानी परनाले से नीचे आता है उसी तरह से भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में ऊपर से नीचे आया और नीचे तक इस तरह से फैला कि झूठे-झूठे मुकदमे थाने में दर्ज कराये और केवल हथकड़ी नहीं लगायेंगे उनसे एक-एक हजार रुपये मांगे जाते रहे और लिये जाते रहे इस तरह की दुर्दशा इस पिछले-पिछले 10 वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की बात कही गयी। पीसांगन

(श्री बंशीलाल पटवा)

में छोटी सी घटना घटी तो उस सवाल को लेकर यहां बावेला खड़ा किया लेकिन राजस्थान में इस बार हर जगह एहतियात बरती गयी और पुराने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के क्षेत्र बीगोद में दंगे हुए लेकिन इस बार क्यों नहीं हुए, इस बार इसके लिए हिन्दू और मुसलमान सम्मिलित रूप से होली क्यों खेली, क्योंकि इसके बारे में इच्छा शक्ति थी, हम लोग टिके, लोगों को जोड़ा और इस बार होली साथ-साथ खेली। हिन्दू मुसलमान परिवार की औरतों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनायी यह सारा सरकार का प्रयत्न है।

दूसरा कानून की किताब बहुत अच्छी हो और व्यक्ति खराब तो उसका स्वरूप खराब कर देगा, व्यक्ति अच्छा है और कानून की किताब खराब है तो फिर भी स्वरुप अच्छा बनकर आयेगा। राम का नाम लेकर सारी बातें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारी सरकार के लक्ष्य स्पष्ट हैं। कि हम चाहते हैं कि उपासना पद्धति कुछ भी हो मस्जिद में जाकर मुसलान अजान लगाये, इबादत करे कोई एतराज नहीं, मंदिर में जाकर घड़ियाल बजाये, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम आदर्श पुरुष थे इसलिए हम ने उसको स्वीकार कर लिया और इनका सपना यह है कि केन्द्र की मिली जुली सरकार है, बदल जायेगी राजस्थान में जनता दल और भाजपा की सरकार टूट जायेगी। यह सपना पांच साल तक साकार नहीं होने वाला है। साथ-साथ चल रहे हैं, मिल जुल कर सभी ने सरकार बनायी है। साथ-साथ चलेंगे और साथ-साथ चलेंगे तो उसमें स्वयं साथ-साथ बलिदान होने की बात भी निकलेगी और उसके लिए लड़ेंगे और राजस्थान में 10 वर्षों में जिस तरह की व्यवस्था आपने अपनायी उसको मिनिमाइज करेंगे।

जितने प्रोजेक्टस बनाये, आप ज्यादा दूर नहीं जायं मेरे जिले में चले जायं कोठ्यारी प्रोजेक्ट और मेजा प्रोजेक्ट है, कितने बड़े प्रोजेक्ट हैं। मेजा फीडर बनी हुई है। मेजा फीडर का पानी मेजा में नहीं जाकर उलटा चलता है यह कांग्रेस सरकार का तकनीकी का ख्याल था। मेजा बांध को तैयार करने के लिए पिछली सरकार ने जगह-जगह और बांध लगा दिये जिसके कारण आज मेजा पूरा भरता नहीं है और किसानों का अहित हो रहा है। सिंचित क्षेत्र हम बढ़ाते जा रहे हैं पिछली सरकार ने बढाया है। और उधर से पानी की आवक रुक गयी। केचमेण्ट एरिया का ध्यान नहीं रखा। कोठ्यारी प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक से बना हुआ है वह टर्म्स एण्ड कंडीशन्स का है लेकिन सारी टर्म्स एण्ड कंडीशन्स को रोंधा गया। जगह जगह उसको बांधा गया। कोठारी प्रोजेक्ट को बेकार बनाने की साजिश की गयी। कांग्रेस सरकार की ये नीतियां रहीं, पहले तो समस्यायें पैदा करो, फिर उसको हल करने के लिए हल्ला करो यह स्थितियां रहीं। आज ग्रामीण इकाइयों को मजबूत करने के लिए, देश के गांवों को मजबूत करने की बात कहते हैं, यह पहली बार कहा लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अन्तर रहा। राजनैतिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा, भेदभाव

(श्री बंशीलाल पटवा)

बरता जा रहा था चाहे हैंडपम्पस को लगाने का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे दूसरे सवाल हों, उसमें राजनैतिक भेद बरता जाता रहा। पिछली बार स्कूलें खोली गयीं जहां थोड़ी आबादी है, 250 घर हैं सेकण्डरी स्कूल खोल दी लेकिन हजार घर हैं वहां सेकण्डरी स्कूल नहीं खोली गयी। उनके बारे में नार्म्स हैं उन्हें रोंधा गया और इस तरह स्कूल खोलने में भेद बरता गया। प्राइमरी स्कूलें खोली गयीं। नवें प्लान के तहत जो पैसा आवंटित किया गया था। चुनाव में वोट की राजनीति का खेल खेलने के लिए ऐसे भवनों को नामजद आधार पर आदेश देकर ऐसी स्वीकृतियां जारी की गयी। जहां पर पहले से स्कूल भवन हैं जो अधूरे हैं उनको ठीक नहीं कराया जा सकता और जहां नहीं हैं वहां बनाया नहीं जा सकता। करोड़ों का धन आवंटित कर दिया गया। बिजली के खम्बे डाल दिये गये, पाइप लाइन डाल दी गयी लेकिन इस बार लोग गले तक भर आये और उन्होंने इस सरकार को बदला, ठुकराया सही उसी के परिणाम है कि राजस्थान में जनतादल और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार बनी। आज कहते हैं कि हमने मिली जुली सरकार बनायी है यह टूट जायेगी। कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया। कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस के साथ मिल कर सरकार बनायी। उनके परिणाम क्या निकले। आज कश्मीर से अव्यवस्थायें ज्यादा हैं। आज कश्मीर में दंगे हो रहे हैं। आतंकवाद हावी हैं और वहां जब हम आपकी बातें सुनते हैं तो आप भी क्षमता रखिये और यह डिबेट है, यह हाऊस है। सुनने की क्षमता नहीं है तो इस तरीके का नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब बात कही तो हम लोगों ने सुनी हमारी बात सुनिये। सच्चाई बड़ी कडवी होती हैं हलक से बड़ी मुश्किल से उतरती हैं लेकिन यह आपके खयालात पूरे नहीं होंगे। मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह की जो 10 वर्षों में अव्यवस्थायें चरमरायी हैं। हमारा लक्ष्य है कि साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़े और कभी भी हमारा इस मामले में असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। आज कहते हैं कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाय। कर्मकाण्ड अलग है, मजहब अलग होता है लेकिन धर्म न्याय शब्द है। धर्म का अर्थ न्याय से है जिसके लिए राजनीति को न्याय से नहीं जोडोगे तो देश नहीं बनेगा। आजादी प्राप्त की थी उस समय हमने कहा था कि स्वराज लायेंगे, राम राज लायेंगे। लेकिन सारे सपने बेकार हो गये और न राम राज आया और न स्वराज आया। मेरे ख्याल से ढाई वर्ष को छोड़ कर बाकी 40 वर्षों में आपने जिस तरह से देश का और प्रदेशों का शोषण किया मेरे ख्याल से इस तरह कभी नहीं हुआ। औरंगजेब ने मेरे ख्याल से राज के खजाने से रोटी नहीं खाई टोकरियां बना कर रोटी खाता था अपनी आजीविका चलाता था लेकिन पिछले दस वर्षों में राज के खजाने पर ऐसे लोगों ने डाका डाला है जिनके पास शायद पहले चूहे उपवास करते थे आज वे महल बना कर बैठे हैं। जैसे मानो ऐसी स्थिति है कि लक्ष्मी दीपावली के दिन उनके घर में घुसने के लिए आतुर थी। यह जो स्थितियां

(श्री बंशीलाल पटवा)

पैदा की गयी हैं मेरे ख्याल से जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी और जनता गले तक भर आई थी। सबसे ज्यादा किसानों का यदि शोषण हुआ जो पिछले दस वर्षों में हुआ और किसानों के हितों की अनदेखी की और किसानों के हितों की बात करते थे उनके साथ भेद-भाव बरता गया, कर्जों पर अंगूठे लगा लगा कर उनके कर्ज बढ़ाये जाते रहे। एक कुंए के लिए यदि किसी ने तीन हजार का कर्जा ले लिया और ढाई हजार जमा करा दिया तो ब्याज चुकता हो गया और 15 हजार के कर्जे माफ करने की बात कहीं लेकिन उसको रोक भी नहीं पाये। सरकार कुर्कियां चुनावों के दौरान निकालती रही, वसूलियां की जाती रही। यह सारी स्थितियां इन चुनावों के दौरान आई। कर्जा रोकने वाली बात भारतीय जनता पार्टी और जनतादल ने कही है कि 10 हजार के कर्जे माफ करेंगे लेकिन कांग्रेस ने कहा हम 15 हजार के कर्जे माफ करेंगे। 15 हजार का कर्जा माफ करने की तो बात दूर रही लेकिन उनको रोका भी नहीं गया। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कांग्रेस राज की और क्या हो सकती है। आज हालत यह हो गयी है कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के नाम पर मर्जी आये जिस तरीके से टैंकर्स बना दिये गये न तकनीकी ख्यालात रखा गया। वर्ष 1983 में ग्रेवल रोड्स की सड़कें बनी थीं उसमें पिछले साल एक तगारी रेत नहीं डाली गयी। यह सरकार की व्यवस्था है तो आदमी जब बदलता है तो व्यवस्थायें भी बदलती हैं और दूसरी बात यह मौजूदा सरकार जो हमारी है सच्चाई और अच्छाई के निकट है। यथार्थ पर आधारित है व संकल्पबद्ध है, इसलिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे कि जनता पर हम किस तरह से अपनी साख बनाये रख सकते हैं वह रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे प्रधान मंत्री के बारे में मैं तो बहुत छोटा हूं मुझे किसी बात का घमंड नहीं है लेकिन शायद श्री राजीव गांधी जी को चन्दन के पेड़ और सफेदे के पेड़ में भी फर्क नजर नहीं आता है। पिछले वर्ष जब झोपट गये थे। वहां शिकायत की गयी कि चन्दन काटा जा रहा है और जाने के बाद चन्दन तो कट चुका था लेकिन सफेदे के पेड़ों पर तख्तियां लटका दी नर्सरी वालों ने, कृषि विभाग वालों ने और लिख दिया कि यह चन्दन है चन्दन है और राजीव गांधी मान गये कि चन्दन है। जिस प्रधान मंत्री को चन्दन और सफेदे के पेड़ का पता नहीं है वह देश कैसे चलायेगा। इस पर विचार कर रहा था। आखिर में कोई नतीजा होना चाहिए आधार होना चाहिए अच्छी बिल्डिंग्स के लिए अच्छी नींव होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि अच्छी सरकार के लिए अच्छे आदमी चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, मनःस्थिति चाहिए, संकल्प चाहिए और काम करने के लिए अभावों से गुजरने की आदत चाहिए। हम जब तक अभावों से गुजरेंगे नहीं, देश की परिस्थितियों के अनुरूप योजना नहीं बना सकते। हम देश को खड़ा करना चाहते हैं देश इस तरह से खड़ा नहीं होता। देश के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, पीढ़ियां खपती हैं। गांधी जी की नीतियों का नाम तो खूब लेते हैं लेकिन

(श्री बंशीलाल पटवा)

42 वर्षों में जितनी आयातित नीतियां कांग्रेस ने बनाई, स्वदेशी नीतियों का ह्रास किया मेरे ख्याल से यह साढ़े सात सौ वर्षों की गुलामी में ऐसा नहीं हुआ यह सोचना चाहिये। आज हम विदेशी कोलिबोरेशन की चीजें तो उपयोग में लेते हैं और उस का प्राफिट विदेश में जाता है और स्वदेशी नीतियों की बातें करते हैं। हमको अपने देश की रचना करनी होगी तो 75% गांवों पर विचार करना होगा। 40 वर्षों में गांव उजड़े, शहर बिगड़े इस तरह की स्थितियां बनाई। तकनीकि दृष्टि से जहां नो इंच की नाली से काम चल सकता है वहां दो-दो फुट, डेढ़-डेढ़ फुट की नालियां बनाई। हमारी क्षमतायें थीं, सुपरविजन था। कहने का अर्थ है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमने कोई दिशायें तय नहीं की। इस तरह की दिशा बनायी। केवल नोटों की राजनीति, जंजाल में फंसे रहे, पैसे को बचाने के लिये लगे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे को पकड़ें रहने का खून मुंह लग गया। ऐसी स्थितियों में देश को चला नहीं सकते। आखिर में हाड़ मांस का आदमी रहता है कब तक। लुभावनी बातों से मूर्ख किसको बनाया जाता रहेगा। लोग मूर्ख नहीं बने। जागृत हुये और इस बार जो स्थितियां बनी हैं उसका कारण यह था आज 13 वर्षों से नगर परिषदों के चुनाव नहीं करा सके। लोकतन्त्र की बातें करते हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं चालीस वर्षों में लोकतन्त्र की जड़ें खोखली हुई। कांग्रेस के राज्य में आये दिन इस तरह की स्थितियां निर्मित करते जाते रहे। स्थानान्तरण तो जैसे देश का आदमी तो कुछ नहीं राजनैतिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाते थे। स्थानान्तरण कोई रेमेडी है। स्थानान्तरण कोई रेमेडी नहीं है। आदमी गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन स्थानान्तरण केवल राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर किये गये। एक-एक स्थानान्तरण पर पैसे कमाओ घर भरो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गयी थी। अन्त में मैं केवल अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में एक मिनिट में कह देता हूं। आज भीलवाड़ा नगर में कच्ची बस्तियां बनी, उनका नियमन आवश्यक है। जेल में भी पानी और रोटी मिलती है लेकिन पिछली सरकार ने उनको पानी तक भी मुहैया नहीं कराया। रास्ते ठीक नहीं कराये और आज पानी की समस्या जिस तरह से राजस्थान में है उस तरह से भीलवाड़ा नगर में भी है और मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह से चने बांटते हो उसी तरह से प्लाण्ट बांटे, उद्घाटन किये, ये ऐसी समस्यायें आप लोगों ने खड़ी कर दी हैं। स्कूल तो खोले थे, अध्यापक नहीं है, डिस्पेन्सिरयां खोल दी, डाक्टर नहीं है, आयुर्वैदिक अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। लोगों को इस तरह से जंजाल में फंसा दिया गया जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी सरकार श्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार इसके लिये प्रयत्न करेगी और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पांच साल में नहीं, आपको 5–6 महीने में भी बदलाव नजर आयेगा। इस बार जैसा मैं आपको बताऊं, साम्प्रदायिक दंगों के बारे में हम लगे राजस्थान में पीसांगन के सिवाय और कहीं नहीं, बीगोद में लगे तो नहीं हुये। श्री शिवचरण जी माथुर वहां मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी कांस्टीट्यूएन्सी में झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं। मुख्यमंत्री बदलते हीं,

(श्री बंशीलाल पटवा)

सरकार बदलते ही दंगे बन्द और हिन्दू मुस्लिम एकता शुरू। लोग साथ बैठ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों ? मन साफ होना चाहिये।

श्री हरि सिंह (महुआ) : आप गये थे क्या बीगोद में ?

श्री बंशीलाल पटवा : हां, बिलकुल गया हूं बीगोद में नहीं होने दिये। काम्पीटेंट व्यवस्थाएं की। क्यों हुए इसका जवाब है आपके पास। कोई जवाब नहीं है, हम गये तो नहीं हुआ, नहीं होने देंगे, भविष्य में भी रोकथाम करेंगे। आप कितना भी बांटों, नहीं बटेंगे। सपने पूरे नहीं होंगे। जब सांझी सरकार बनी है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की, मिल जुलकर बनाई है तो साथ-साथ चलेंगे व मरेंगे साथ-साथ सारे लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मेरा अन्त में यही कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना उद्बोधन दिया, अभिभाषण दिया उसका एक-एक शब्द पढ़ने योग्य है और मेरे ख्याल से राजस्थान की समस्याओं को सरकार किस तरह से लेगी इसके लिए दिशा निर्देश है क्योंकि बातें तो मुझे और बहुत कहनी थीं। मैं बराबर सुन रहा था। श्री परसराम जी कह रहे थे, पहाड़िया जी कह रहे थे। यह सारे सपने पूरे नहीं होंगे। उनकी शंकाएं निर्मूल साबित होंगी। यह सरकार चलेगी पूरे पांच वर्ष चलेगी। आगामी पांच वर्षों में हमारे प्रयत्न इस तरह के रहेंगे कि कांग्रेस का नाम लेने वाला राजस्थान में और इस देश में कोई नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हुआ अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है मै उसका समर्थन करता हूं। मेरे झालावाड़ जिले में कुछ समस्याएं हैं। कांग्रेस के शासनकाल में झालावाड़ जिला भंयकर पिछड़ा लेकिन जब हमारी सरकार आयी है, जनता सरकार आयी है तो वहां का विकास होगा, सिंचाई का विकास होगा, बिजली का विकास होगा, कृषि का भी विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में पानी गिरा था, कीचड़ हुआ था। कांग्रेस का कीचड़ बन चुका है और कीचड़ में से कमल खिला है। बन्धुओं, माननीय सदस्यों मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अब कांग्रेस की जड़ें खोखली हो चुकी हैं। सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में कई समस्याएं इस प्रकार की हैं वहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं चम्बल है, काली सिंध व आहू नदियां हैं। यदि उन नदियों का पानी रोक कर एनिकट बनाये जायें बड़े बनाये जायें, बड़े बांध बनाये जायें तो किसानों को उससे लाभ हो सकता है। आज कई गांव झालावाड़ जिले के और मेरे डग विधान-सभा क्षेत्र के ऐसे हैं जहां पर कि बिजली नहीं है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन गावों को विद्युतिकरण में लिया जाये ताकि

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

किसानों को उससे लाभ हो सके । सभापति महोदय, जब जनता सरकार आयी थी तो मेरे क्षेत्र में और झालावाड़ जिले में कई काम हुये । अन्त्योदय योजना में किसानों का, गरीबों का उत्थान हुआ है । गांव-गांव में जाकर के अधिकारियों ने जो खेती-बाड़ी के छोटे बड़े मामले निपटाये इससे गांवों का और गरीबों का उत्थान हुआ । इसी प्रकार अभी जो वर्तमान में पानी की समस्या चल रही है, पानी की समस्या चौमहला, गंगदार, डग, झालरापाटन में है तथा विशेषकर के भवानी मण्डी में पानी की किल्लत बहुत भयंकर है । वहां जो आहू नदी है और सागड़ा डेम है उससे पानी की सप्लाई होती है । वहां पर सुनैल में भी उसी से सप्लाई होती है लेकिन सागड़ा का डेम सूख चुका है । पानी उसमें समाप्त हो चुका है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कुछ इस

(3.55 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाये जिससे कि जनता को पानी और राहत मिल सके । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में किसानों का भयंकर खून चूसा गया, शोषण हुआ है और वहां के जो कांग्रेस के विधायक थे, कुछ मंत्री बनाये थे, उन लोगों ने एजेण्ट पना और एजेण्ट के माध्यम से, ए. ई. एन. के माध्यम से जो सिंचाई कनेक्शन हुये उसमें चार-चार, पांच-पांच हजार रुपये रिश्वत ली गयी । इस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने और विधायकों ने केवल मात्र दलाली करने के सिवाय और कुछ नहीं किया । अभी जो किसान की बात कर रहे थे लेकिन ये किसानों को न्याय देने वाले नहीं हैं । यह किसानों का शोषण करने वाले और किसानों के दुश्मन हैं ।

झालावाड़ जिले में रोड़वेज की भी बहुत भयंकर स्थिति है । रोड़वेज की जो बसें हैं समय पर वहां चल नहीं पाती हैं । अधिकारी भी वहां बैठते नहीं है जिससे कि सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई गाड़ियां इस प्रकार की खराब पड़ी हुई हैं जो कि डिपों से खराब ही निकल जाती हैं और जंगल खराब होने से जनता को भयंकर परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है ।

इसी प्रकार वहां पर झालावाड़ जिले में और मेरे डग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की भी दुर्व्यवस्था हो रही है । कई सड़कें इस प्रकार की अधूरी पड़ी हुई हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सारी सड़कों को बजट देकर के उनको दुरुस्त कराया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जो सड़कें और पंचायत केन्द्रों को जोड़ने वाली जो सड़कें बनी हैं वे भी अधूरी पड़ी हुई हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सड़कें भी कृषि उपज मण्डी के माध्यम से बनाई जायें ताकि किसानों को राहत मिल सके ।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय हरिजनों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। उनकी बारात के ऊपर हमले किये गये। उनको घोड़ी पर बिठाकर जुलूस नहीं निकालने दिया गया। मैं अपनी सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं, उनकी सुरक्षा चाहता हूं और आगे इस प्रकार के हरिजनों के ऊपर अत्याचार नहीं हों। हरिजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो। हरिजनों के साथ न्याय हो यह मैं अपनी सरकार से आश्वासन चाहता हूं विश्वास चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि अपनी सरकार, जनता की जो सरकार है वह हरिजनों का, शिड्यूल्ड कास्ट्स का उद्धार ही करेगी क्योंकि जब जनता सरकार सन् 1977 में आयी थी उनका उद्धार हुआ था। उनका चयन करके, उनकी गरीबी मिटाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि जो सन् 1977 में राजस्व अभियान चला, गरीबों का चयन हुआ, इसी प्रकार अब जो अपनी सरकार राजस्व अभियान और अन्त्योदय योजना लागू कर रही है मैं उसका स्वागत करता हूं और आगे श्री झालावाड़ जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो। उसके साथ में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को अतिरिक्त कार्य-सूची की सूचना मिल चुकी है। 4 बज चुके हैं इसलिये पहले बीच में जो अतिरिक्त कार्यसूची है वह मैं ले रहा हूं। श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मंत्री-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन मंत्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"

श्री अध्यक्ष : किसी को बोलना है ?

एक मिनट ! आप इस पर नहीं बोल रहे हैं ? या इसको पारित करवाने के बाद बोलेंगे ? मैं पहले यह पारित करवा देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में करा लीजिये दोनों साथ में।

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसके ऊपर अपनी बात शुरू करता हूं और साथ ही इस पर कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह यह है कि इस प्रस्ताव की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आवश्यकता नहीं थी । यह कोएलीशन गवर्नमेण्ट है । जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय भैरोंसिंह जी ने यह क्लेम किया कि साहब मेजोरिटी कमजोर पड़ती है तो महामहिम राज्यपाल ने कहा होगा कि आप विदिन थर्टी डेज वोट ऑफ कान्फिडेन्स सीक करें । लेकिन 4 मार्च को जो शपथ ग्रहण हुआ तो जनता दल के नेता नत्थी सिंह जी ने शपथ ग्रहण की, उसी के साथ कोएलीशन मिनिस्टरी है । 84 और 54 = 138 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है । अब यह वोट ऑफ कान्फिडेन्स सीक करने की आवश्यकता नहीं है...

एक माननीय सदस्य : गवर्नर साहब ने कहा है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, गवर्नर साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ? यह अनावश्यक है । गवर्नर साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा जब इन्होंने अपना क्लेम किया उस वक्त कि खाली भारतीय जनता पार्टी की...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें तो मैं बताता हूं ।

महामहिम गवर्नर साहब ने जो लिखित में शपथ लेने के लिये आमंत्रित किया है, इसकी जो लेंगवेज है उसको फालो कर रहे हैं । आप जो बता रहे हैं वह अलग बात है । वैसे ठीक है जो आप कह रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं । इन्होंने क्लेम स्टेक किया, जब उन्होंने यह बात कही कि कोलीशन गवर्नमेण्ट है, उन्होंने यह अपना क्लेम स्टेक किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मैं सरकार बनाना चाहता हूं, मुझे बहुमत प्राप्त है, जनता दल का मुझे समर्थन है । तो समर्थन होना, अध्यक्ष महोदय, एक बात है और पार्ट टाइम गवर्नमेण्ट दूसरी बात है । यह कोलीशन गवर्नमेण्ट है ।

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है । यह इन्टरप्रटेशन जो कर रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं है । चूंकि लिखित में यह शर्त लगी हुई है, उसके बाद में तो कोई लिखा-पढ़ी हुई नहीं, अब परिस्थिति बदली, पर बाद में हुई । फार्मल टैक्निकल बात है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, मैं समझता हूं कि महामहिम किसी को यह नहीं कहेंगे कि आप वोट ऑफ कान्फिडेन्स सीक कीजिये । 138 मेम्बर्स 198 में, अध्यक्ष महोदय, क्लियर 138 मेम्बर्स उनके हैं, यह वोट ऑफ कान्फिडेन्स पास करके क्या बात जाहिर करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : केवल तकनीकी बात है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, This is not required.

श्री अध्यक्ष : टैक्निकल है ।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी अपनी तरफ से नहीं जरूरी हो, मगर जब राज्यपाल

(श्री हरिदेव जोशी)

महोदय ने आपको आदेश दिया है तो उनके लिए जरूरी है वह उसको पूरा करें। लिखित आदेश दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब दिया है?

श्री हरिदेव जोशी : कभी भी दिया हो।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय, ने, जो अभिभाषण दिया है उस सिलसिले में यहां चर्चा हुई। आपने उस चर्चा को सुना है। 40 वर्षों के दरम्यान यह दूसरी बार का मौका है जब कांग्रेस का विरोधी पक्ष ट्रेजरी बेंचेज पर जाकर बैठा है। दूसरी बार यह मौका मिलने पर स्वाभाविक रूप से जब किसी के पास में लम्बे अर्से के बाद पावर आती है, तो उसको खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन खुश इतना हो जाय कि वह अपनी सीमा भूल जाय और विवेक ही खो बैठे, जो साथ में बैठते हैं उनके बारे में लाछंन लगाने लग जायं। लगता ऐसा है कि अपनी बात को कहने के बदले सरकार ने दूसरों की बातें कहने की कोशिश की है। यहां होना यह चाहिये था कि सरकार की रीति-नीति क्या है, क्या करना चाहती है, उसका मेनिफेस्टो क्या है, कैसे इम्पलीमेण्ट करना चाहती है, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का उपयोग इसके लिये करना चाहिये था। मगर दुर्भाग्य से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उपयोग दूसरी पार्टी को कोसने के लिये किया गया। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। यह अपनी बात मैं आपके कानों तक पहुंचा देना चाहता हूं। और यही बात मैं ट्रेजरी बैंचेज को पहुंचाना चाहता हूं। वरना वह जीतकर बहुत दिनों के बाद में आये हैं मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, चाहता हूं कि सफल हों और जो उनके प्रोग्राम्स हैं उनको वह इम्पलीमेण्ट कर सकें। क्योंकि प्रजातंत्र में जहां एक तरफ शासक दल है वहां विरोधी दल भी है। हमारी जिम्मेदारियां बदल गयी हैं और मैं एक ही बात कह सकता हूं अपनी पार्टी की ओर से बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर कि कांग्रेस पार्टी विरोध पक्ष को, जो ट्रेजरी बैंचेज पर गया है, उस गवर्नमेण्ट को रचनात्मक सहयोग देगी। यह हमारा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को हमने ओढ़ा है, स्वीकार किया है। हम यहां इसलिये नहीं आये हैं कि हम गलती ही निकाला करें। हम यहां इसलिये आये हैं कि राजस्थान आगे बढ़े। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि राजस्थान को देखें, कैसा है, क्या है, उसके रिसोंसेज क्या हैं, उसकी कठिनाइयां क्या हैं और भागीदार बनें प्रशासन के अन्दर यह देखें कि हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार जितना सहयोग हमसे लेगी वह सहयोग हम देंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में काफी कहा जा चुका है, मगर फिर भी मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की राजनीति में नयी प्रकार

(श्री हरिदेव जोशी)

की परिस्थिति पैदा हुई है, वह यह है कि जो लोग शासन में थे आज विरोध पक्ष में हैं और जो विरोध पक्ष में थे आज शासन में हैं। मगर केन्द्र में देख लीजिये कोई एक पार्टी को जनता ने बहुमत नहीं दिया है बल्कि आज जो केन्द्र में सरकार है वह अल्पमत की सरकार है, न केवल अल्पमत की सरकार है बल्कि बहुत परस्पर विरोधी विचारों की सरकार है। एक दूसरे को असहिष्णुता की निगाह से देखते हैं। एक पार्टी एक बात के ऊपर एक विचार रखती है, दूसरी पार्टी उसी पर दूसरा विचार रखती है।

पिछली बार 1977 के अन्दर जो चुनाव हुये थे, उस समय आपने देखा होगा, अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी बनी थी, जनता पार्टी, और उस जनता पार्टी ने एक पार्टी के नाम से शासन चलाया था। उसमें कई पार्टियां मिली थी मगर फिर भी डिसिप्लीन के लिहाज से वह ढाई साल तक चली। मगर इस बार हम देखते हैं एक नया ही ढंग है। वह यह है कि जिस दिन सरकार बनी उस दिन से उसमें मनमुटाव हो गये। जो लोग यह सोचते हैं कि हम सरकार में आये हैं, आये तो सही, पर कितने दिन टिकेंगे उसका कोई अन्दाज नहीं है। इसलिये मन में परेशानी होती है कि इस देश के और प्रदेश के भाग्य में क्या है। 5 साल ठहर सकें, रह सकें, मैं तो यह आशा करके चलता हूं, और प्रार्थना भी करता हूं। मगर अपन इस बारे में विचार करेंगे हर साल, रिव्यू करेंगे। आपको पता चलेगा कि आप किस स्थिति के अन्दर हैं।

अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले इस सदन के नेता दिल्ली गये थे और अखबारों में उनका फोटो आया देवीलाल जी को मनाते हुए अब यह धंधा रह गया है। जब यह विरोधी पक्ष के नेता थे, मुझसे कहा करते थे कि दौड़-दौड़ कर दिल्ली जाते हो। मैं आज उनसे पूछता हूं, मैं तो दिल्ली जाता था राजीव जी के पास। आप कहां जाते हो? (व्यवधान) आप कहां जाते हो। अब आज आपका हाल यह है कि जब तक आपके नेता यहां थे तब तक समाधान हुआ और जैसे ही वह विदेश गये, उनके पीछे शगुफा छोड़कर गये हैं वह जनरल सैक्रेटरी साहब बगैर कुर्सी के कर रहे हैं, आज हालत यह है। क्या होगा हिन्दुस्तान का मालूम नहीं है। एक प्रकार का अनिश्चय का वातावरण राजनीति पर छा रहा है और वह देश अभागा है जहां पर राजनीति सही अर्थों में नहीं गलत अर्थों में काम देती है।

आज हम देखें यह सरकार कैसे बनी इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं है, किसी नीति के आधार पर नहीं है, किसी प्रोग्राम के आधार पर नहीं है, बल्कि एक प्रकार का धुंआ उठाया गया, जिसमें शासक पार्टी और शासक पार्टी के नेता के बारे में उल जलूल बातें कही गई और उन उल जलूल बातों का परिणाम यह हुआ कि देश के अन्दर भावनाएं भड़कीं और एक तनाव आया, उस तनाव के तहत काम हुए। आज देश एक तरफ तो साम्प्रदायिकता से लड़ रहा है तथा दूसरी तरफ विदेशी

(श्री हरिदेव जोशी)

शक्तियों से लड़ रहा है और एक नये प्रकार की अस्थिरता पैदा हो गई। यह एक दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय। 15 अगस्त 1948 के बाद पहली मर्तबा कश्मीर के अन्दर हजारों लोग घुस गये और कश्मीर की आज यह हालत है कि जिस दिन देश आजाद हुआ था और जो हालात पैदा हुए थे वही हालात आज पैदा हुए है। तो इन स्थितियों ने देश को आगे नहीं बढ़ाया है। इस सत्ता परिवर्तन ने देश को पीछे हटाया है और देश में अस्थिरता पैदा की है। देश के अन्दर यह हालत पैदा हो गये है कि कल क्या होगा इसके बारे में कोई बड़े से बड़ा आदमी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार बर्खास्त की गई, क्यों की गई यह आपके सामने है। मैं बहुत विगत मेंनहीं जाना चाहता किस को बर्खास्त किया गया है, वहां के चीफ मिनिस्टर को, वहां के गवर्नर को हटाया गया। आज एक नया मिनिस्टर बनाकर बिठाया गया है और नये मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर के जायजा लिया, उस जायजे में उन्होने क्या कहा, आपकी सरकार ने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन के बाबत में वे कहते है, टाइम्स ऑफ इण्डिया के अन्दर जार्ज फर्नाडिस कहते हैं **Mr. Fernandes said "at the moment the only pro-India leader in Kashmir appears to be Dr. Farooq Abdullah" Only pro-India person is Farooq Abdullah, and what did you do?**
आपने डिसमिस किया, भाल के ऊपर आपने कठिनाई उत्पन्न की। कहने का तात्पर्य है, नयी सरकार नये काम कर रही है यह दिखाना चाहती है कि बहुत एक्टिव हैं। और काम ऐसे करती हैं, जो देश के हित में नहीं हैं। अब मै आपको और परिस्थिति भी बताऊं, दो दिन पहले सदन के नेता ने बड़ी तारीफ की थी सरकार की, मैंने उस समय भी कागज ऊंचा करके दिखाया था, मगर उस समय उनकी निगाह दूसरी तरह थी, मेरी तरफ नहीं थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके, अडवाणी साहब आपके नेता हैं, उनको आप मानते हैं अपना नेता, उनका स्टेटमेंट क्या है, वह जरा देखने की कोशिश कीजिए। वे कहते हैं कि इस सरकार ने हमारा सिर नीचा कर दिया, आप क्या महसूस करते हैं? आपका सिर ऊंचा है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : महसूस करना ही बन्द कर दिया।

एक माननीय सदस्य : आप क्या महसूस करते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मै क्या महसूस करता हूं, यह तो आप जानते हैं। मुझे अपनी बात कहने की जरूरत नहीं, हमारे एक्शन बता रहे हैं। मगर आप क्या महसूस करते हैं यह हमें मालूम नहीं। बहुत कम मालूम होता है क्योंकि, आप महसूस कुछ करते है। कहते कुछ नहीं, क्योंकि आप यह कहने की स्थिति में नहीं है कि अपने लीडर की तरह महसूस करते हैं। कई बार मुंह बन्द रखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बहुत अनुभव है इस मामले में। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अब स्थिति यह है कि 40 वर्ष की आजादी में दो बार

(श्री हरिदेव जोशी)

आप इस तरफ बैठे हैं, उन दो बार में यह निश्चय नहीं है कि आप किस दिन इधर आयेंगे। हम यह नहीं चाहते कि यह सरकार टूटे, क्योंकि इससे देश के अन्दर अनिश्चय का वातावरण पैदा होता है, इससे देश की प्रगति रुकती है। डेमोक्रेसी स्वीकार की हैं तो इसके मायने यह हैं कि कभी हम रहेंगे, कभी आप रहेंगे। उस डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है जो डेमोक्रेसी रीजन्स के ऊपर, लोजिक के ऊपर, और नियमों के आधार पर चले और स्वस्थ रूप से देश की प्रगति करे। बड़ी चीजों के ऊपर कोई मतभेद नहीं हुआ करते हैं। काम करने की प्रणाली पर मतभेद हो सकते हैं, मगर सिद्धान्तों पर कोई मतभेद नहीं होते। मगर दुर्भाग्यवश सिद्धान्तों के बारे में यहां कोई चर्चा ही नहीं करता।

आज, अध्यक्ष महोदय, पंजाब का मसला पैदा हुआ इन्दिरा गांधी के जमाने में, और राजीव गांधी ने हाथ में लिया, और उसके बाद वी. पी. सिंह साहब उसको कर रहे हैं। अब हमने एक बार नहीं, दो तीन बार परीक्षण कर लिये, हर आदमी यह परीक्षण कर रहा है कि शक्ति से इसको दबाया जाय या मेलजोल और बातचीत करके इसको दबाया जाय। आप एक दिन शक्ति प्रयोग करते हैं, उससे नसीहत नहीं लेते, फिर बातचीत शुरू करते हैं और नये सिरे से फिर आप यह स्थितियां पैदा करते हैं कि सांप आपके बिल पर आकर बैठ जाय और आप उसे फिर निकालने की कोशिश करते हैं। यह चीज ऐसी है जिन पर आपको बैठकर फैसले करने चाहिए। आपके और हमारे स्वार्थ इसमें एक ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं, इन जुड़े हुए हितों के अन्दर पॉलिसियां अगर अलग होंगी तो देश का नुकसान होगा, चाहे वह नेपाल का मसला हो, चाहे श्रीलंका का मसला हो, चाहे बांगला देश का मसला हो, चाहे पाकिस्तान का मसला हो। पाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए मसले हैं पंजाब और कश्मीर के, इनके अन्दर भारत में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, एक स्वर से बोलना चाहिए। आपने लिख कर दिया कि समन्वय से हम लोग काम करेंगे, आपस में बात चीत करके करेंगे। आपने आपस में बात चीत कहां की? आपने गवर्नर को हटा दिया। और तो और, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, मगर गवर्नमेंट के दो जो पाए हैं, क्रचेज हैं, एक तरफ लैफ्टिस्ट हैं, दूसरी तरफ राईटिस्ट हैं, लैफ्टिस्ट एक बात सोचते हैं जगमोहन के बारे में, राईटिस्ट दूसरी बात सोचते हैं जगमोहन के बारे में, और दोनों ही असंतुष्ट हैं। किस दिन यह क्रचेज हट जायेंगे और यह सरकार गिर जायेगी, किसी को अन्दाज नहीं। जिस दिन तनाव तेज हुआ उस दिन आपकी यह सारी नीतियां गिर जायेंगी। इसलिए आपको एक प्रणाली शुरू करनी है, मिलजुल करके बातचीत करके, समन्वय के द्वारा, तो वह समन्वय पूरा होना चाहिए। फिर उसमें शिकायत क्यों आती है? किन बातों पर आपका समन्वय होना नहीं चाहिए, मेहम के बारे में आपका क्या विचार है? मेहम के बारे में आपका एप्रोच क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो अमेठी के बारे में है।

श्री हरिदेव जोशी : अमेठी के बारे में, मेरा एप्रोच बहुत साफ है, मैं कह चुका हूं, आपका और आपकी पार्टी के लीडर का जो एप्रोच है उसमें मतभेद मालूम पड़ता है। आप अपने नेता का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अपने नेता का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान) फैसला हमने मान लिया, उसको अस्वीकार नहीं किया। मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान का जो आदमी, मेहम के बारे में यह सोचता है कि वहां पर अन्याय नहीं हुआ है वह हिन्दुस्तान के प्रजातन्त्र के बारे में न्याय नहीं कर रहा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कहिये, अपने प्राईं मिनिस्टर से कि इस्तीफा दें। उन्होंने खुद ने कबूल कर लिया कि मेहम में गड़बड़ी हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियों को सोचने की कोशिश कीजिए। इस देश के अन्दर दो घटनाएं हुई, एक घटना हुई, डॉ. रुबिया का अपहरण और दूसरी घटना हुई बंगलौर के अन्दर हवाई जहाज के गिरने की। बंगलौर में हवाई जहाज की दुर्घटना के बाद में इन्डियन एयर लाईन्स के मैनेजिंग डारेक्टर ने स्तीफा दे दिया, अपनी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करके, मगर हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर की लड़की का अपहरण हुआ, इसमें किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। उस मसले को इस तरह से सुलटाया गया कि 6 आतंकवादियों को छोड़ करके आतंकवादियों को अपीज किया गया, और अपीज करके उस बच्ची को रिकवर किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी यह कौनसी समन्वय नीति है, यह आपका कौन सा समन्वय है। किसके साथ यह आप समन्वय कर रहे हैं? आपको समन्वय चाहिए तो जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ आपका समन्वय होना चाहिये। हमारे साथ में बैठ करके, आपका समन्वय होना चाहिये इस प्रान्त की विधान सभा में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ में, और आपके लीडर्स का, या शासन के अन्दर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनका समन्वय होना चाहिये, जो अपोजीशन के नेता बैठे हुए हैं उनके साथ में मगर मुश्किल यह है कि सत्ता में आने के लिये जो तरीके आप अख्तियार करते हैं, वह तरीके एक दूसरे को इतने दूर ले जाने वाले होते हैं कि आप समन्वय रख नहीं सकते, आपस में साथ बैठ नहीं सकते। आपस में बैठ नहीं सकते, तो आपस में बात कर नहीं सकते। यह खाली मुलम्मा है कि हम मिल जुल कर काम करना चाहते हैं, हम समन्वय करके काम करना चाहते हैं, यह एक प्रकार का स्मोक स्क्रीन है जो लोगों के सामने रख कर के कि हम तो मिलकर के काम करना चाहते हैं, सामने वाला काम नहीं करना चाहता हैं, आप यह बतलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह सोचते हैं कि 80 करोड़ का यह देश केवल परीक्षणों के आधार पर चल जायेगा अगर आप यह चाहते हैं कि खाली बातों से यह देश आगे बढ़ जायेगा, तो यह बहुत मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, अभी दो चार दिन पहले रेलवे का बजट आया था। उस बजट में कुछ अमुक चीजें सामने रखी थी। उसके बाद में जनरल बजट

(श्री हरिदेव जोशी)

आया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, वह तीसरा बजट हमारे सामने रखेंगे, उस समय क्या स्थिति पैदा होगी। आज जो स्थिति पैदा हुई है उसका परिणाम यह हुआ है कि पैट्रोल के ऊपर एक रुपया 65 पैसे पर लीटर दाम बढ़े हैं। हाई स्पीड डीजल भी है खाने का तेल भी है, तो लोग कहते हैं कि वाह दण्डवते तेरा खेल, रुपया बढ़ गया हर चीजों पर। आज, हालत यह हो गई है कि कोई चीज ऐसी नहीं बची है जिसका आज शाम को एक भाव हो और कल सवेरे दूसरा भाव न हो। खाने का तेल देख लीजिये, मोटर स्पिरिट देख लीजिये। आज मोटर चलाना तो प्रोहिबिटिव हो गया है, मोटर चलाने की बात छोड़ दीजिये, स्कूटर चलाना भी प्रोहिबिटिव हो गया है। एक तरफ रेल्वे के अन्दर आपने भाड़ा बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, और तो और, इनलैण्ड लैटर, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, यह छोटी-छोटी चीजें यह आज इतनी महंगी हो गई कि आदमी को यूं महसूस होता है। आपका मैनीफेस्टो क्या कहता था, आपका घोषणा-पत्र क्या कहता था, आप अपने भाषणों में क्या कहते थे, और आज आपके एक्शन्स क्या हैं, कोई मेल है उसका? यह किसी भले आदमी डिप्टी सैकेट्री ने बनाया होता तब भी एक बात थी, वह भी छोटी गृहस्थी वाला होता है, सोचता है मेरी बीबी मुझे क्या कहेगी। परन्तु किसी ऐसे आदमी ने इसको बनाया है जिसको गृहस्थी का कोई आधार ही मालूम नहीं है। आप डीजल के दाम बढ़ा देवें, किराया बढ़ा देवें, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देवें, कम्युनीकेशन बढ़ा देवें, और फिर बचता क्या है, किस चीज के ऊपर कीमत नहीं बढ़ेगी? देखना यह है कि जितना घाटा आपने कहा है उतना ही रहता है या उससे ज्यादा रहता है। अगर एग्रीगेट घाटा इससे ज्यादा हुआ तो इनफ्लेशन इतना बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं सकोगे।

ज्यादा बात तो जिस समय राज्य सरकार का बजट आयेगा उस समय कहूंगा, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने कहा अपने कई भाषणों में और स्टेटमेंट्स में कि राज्य सरकार खजाना खाली करके जा रही है। आपके दिमाग में उस जमाने की बात लेकर के चल रहे हैं जब सोना और चांदी बादशाह लोगों के खजाने के अन्दर भरा हुआ रहता था और वह सोचते थे कि हम अपना खजाना बहुत भर करके जा रहे हैं। आज तो युग दूसरा आ गया है कि जो सरकार पैसा खजाने में रखती है वह कम अकली का काम करती है। आज ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत सरकार से लो और ज्यादा से ज्यादा पैसा विकास के अन्दर खर्च करो, यह नीति रहती है। हर फाइनेंस मिनिस्टर यह सोचता है कि मैं अपना प्लान कितना ज्यादा बड़ा बनवाऊं, हर फाइनेंस सैकेट्री यह सोचता है कि सरकार की जो तमन्नायें हैं उन तमन्नाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को हम किस प्रकार से पूरा करने के योग्य बनें। जो फाइनेंस सैकेट्री और फाइनेंस मिनिस्टर सांप की तरह कुण्डली लगा कर के सरकारी खजाने के ऊपर बैठता है उसको मैं असफल आदमी मानता हूं। मैं उस व्यक्ति को

(श्री हरिदेव जोशी)

सफल मानता हूं जिसकी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, जिसकी भावनायें ऊंची हो, जिसकी इच्छाएं ऊंची हों, अर्थात विकास के अन्दर जिसका कोई दृष्टिकोण हो। आपने अपने मैनीफैस्टो के अन्दर तय किया था कि आप कर्जा माफ करेंगे, आपने मांग की थी ...

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने विरोध किया था।

श्री हरिदेव जोशी : हमने विरोध किया था, बिल्कुल सही है....

श्री नवनीतलाल नीमामा : कितने कर्जे आपने माफ किये ?

श्री हरिदेव जोशी : आपको थोड़ा समझना चाहिये। मैं एक प्रश्न को गम्भीरतापूर्वक आपके सामने रख रहा हूं जो आपके लिये भी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी सेन्टर में जीत कर आई है, वह पार्टी अपने मैनीफैस्टो को इम्पलीमेंट करना चाहती है, बार-बार कहती है अपने वादे पूरे करेंगे। और आपके और हमारे ताऊजी हैं वह हर रोज यहां पर कहते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद मैं आपके ऊपर अविश्वास क्यों करूं, क्यों आपको झूठा मानूं, क्यों आपको गप्पें मारने वाला मानूं, मैं तो आपकी नियत के ऊपर विश्वास करके कहता हूं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर वह गप्प थी तो आपने भी गप्प लगा दी।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कोई बड़बड़ नहीं की, मैंने जो देखा उसको किया। मैं तो उनको गप्प लगाने वाला कहता ही नहीं। आखिर जो प्रैक्टिस में है, जो आंखों के सामने आता है, उसको देखकर ही तो आंकलन करेंगे। आपका और हमारा जो आंकलन है वह टेस्ट से होता है। लेबोरेट्री के अन्दर जब चीज कोई टेस्ट में आती है तो रिजल्ट सही आता है। तो आज का जो जनमत है वह लेबोरेट्री है, वह जांच रही है कि कौन कैसी-कैसी घोषणायें करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मिनिस्टर साहब, भंवरलाल जी शर्मा ने घोषणा की यहां पर डवलपमेंट चार्ज के बारे में, कि डवलपमेंट फ्री होगा। अब हमने समझा, भंवरलाल जी होने वाले मिनिस्टर, जयपुर से चुन कर के जायेंगे, तो क्यों अविश्वास करें कि मुगालताबाजी कर रहे हैं ? मगर आज यह हो गया है कि आप मैनीफैस्टो में एक बात लिखो, पब्लिक में एक बात कहो, और मन में आपके दूसरी बात हो। तो यह तरीका जिम्मेदार पोलिटिशियन का नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं जिम्मेदार पोलिटिशियन वह है जो जैसा महसूस करता है वह कहे, और यह खतरा उठावे कि वह किसी एक चीज पर स्टेन्ड लेता है, उसको लोग ना पसन्द करते हैं, उसको लोग कन्डेम करें उसको वोट न दें तो भी कहा, आज आप देखिये हमारी कुछ चीजों के कारण से कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसको आपके खाली हाथ उठाने वाले लोग नहीं समझ सकेंगे।

आप केवल कर्जा माफ करने वाले घोषणा को देखिये। कर्जा कहां से आता है ? देश की आजादी के बाद में बैंकों के

(श्री हरिदेव जोशी)

राष्ट्रीयकरण के बाद एक परिपाटी तय की गयी कि किसानों को खेती के लिये सारे साधन बैंक मुहैया करेंगे। एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। इस सिस्टम से फ्लो शुरू हुआ जिससे किसान को समय पर खेती के लिये खाद, बीज, दूसरे इम्पली-मेंटस व पेस्टीसाइड आदि के लिये कर्जा देते हैं वह सिस्टम इतना सेट हो गया था देश के अन्दर कि बिचौलिया और बनिया एलीमीनेट हो गया था और किसान की चाहे कैसी भी हैसियत हो, छोटे से छोटा किसान हो सकता है, वह भी निश्चिन्त होकर बनिये को छोड़ कर बैंक से पैसा लेता था, खेती करता था, पैदा कर के उस लोन को वापिस जमा कराता था। शार्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लांग टर्म लोन, एक परिपाटी बन गई थी देश के अंदर मगर हरियाणा के अन्दर केवल वोट जुटाने के लिए गलत तरीके से एक प्रकार की घोषणा की गई। रिजर्व बैंक ने ना कहा, नाबार्ड ने उसको अस्वीकार किया, तब भी उसी जिद पर अड़े रहे। आज देश की यह हालात पैदा कर दी, जैसे अनपढ़ आदमियों का गुट हो, समझता नहीं हो कि कल क्या होने वाला है इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि आज आपको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि छोटी हस्ती नहीं, एक बड़ी हस्ती, इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात पकड़ ली है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। हम सब लोगों ने मिल कर उनसे कहा, आपके कहे फैसले पर बहुत दिन से निर्णय नहीं हुआ है, जल्दी फैसला कीजिये। बड़ा अच्छा सा लव लेटर आया भारत सरकार से जिसमें कहा गया कि हम चरण चरण आगे बढ़ेंगे। चरण चरण के मायने यह है कि आप दस साल का, पन्द्रह साल का जो कर्जा है, उसको हर साल कितना कितना करेंगे, क्या करेंगे। एक हजार करोड़ रुपये इस बार के बजट में स्वीकार किये गये हैं। अधिकारिक व्यक्ति यह कहते हैं कि यह 14,000 करोड़ रुपया है, जिसको चरण चरण में जाने में 14 साल लगेंगे और 14 साल से आगे उस ब्याज का क्या होगा। कल उन्हें कर्जा मिलेगा और उस ने किश्त जमा नहीं करायी है तो उसको कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगला कर्जा उसको आप देंगे, या नहीं देंगे इसकी इस बजट में कहीं कोई सफाई नहीं है। एक बहुत बड़ी प्राब्लम इस देश के सामने खड़ी की है, आर्थिक क्षेत्र में। इससे आपका आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। आपके दिमाग में कोई महत्वाकांक्षा इस देश में काम करने की नहीं हो सकेगी। आप बजट एक रखेंगे, इम्पलीमेन्टेशन दूसरे तरीके से करेंगे, अर्थात् काफी लम्बे अर्से तक इसके इम्पलीमेन्टेशन का फैसला नहीं होगा।

आज राजस्थान बिजली के अभाव से परेशान है। राज्य सरकार ने अपनी स्कीम्स बना कर पेश की है गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को। एक प्रोग्राम बना था। यह बजट नहीं बतलाता कि राजस्थान की बिजली की स्कीम्स पूरी होंगी। इस तरह से एक स्कीम की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी स्कीम्स पिछड़ जायेंगी। किसान ने जो पाया है, वह खोयेगा, वह उल्टे पांव जायेगा। देश की जो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है, उससे पीछे हटेगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

और तो और, इस देश के सामने जो सुरक्षा संबंधी परेशानियां पैदा हो गई हैं, छः महिने पहिले यह स्थिति थी कि हिन्दुस्तान के सामने कोई देखने की कोशिश नहीं कर पाता था। सब उसका लोहा मानते थे। आज दुर्भाग्यवश राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया है कि मूंगफली जैसा छोटा देश हिन्दुस्तान को धमकी देता है। क्यों ? इसलिये कि हम ने यह हालत पैदा कर दी है जैसे हम एक्शन लेने वाले देश नहीं है, हम घुटने टेकू देश हैं। यह जो घुटना टेक पालिसी है हमारी उस ने देश की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाया है। वह देश को कमजोर करेगी। दो दिन पहले कुछ घटनाएं घटी थीं, कैसे उसको आप फेस कर पायेंगे, यह में जानना चाहता हूं आपने कहा था हम सौहार्द और प्रेम से इसको चलायेंगे। वाजपेयी जी चाहते हैं, वाजपेयी जी को तो आप राजनीतिक गुरू मानते हैं, वाजपेयी जी चाहते हैं कि चोटाला को इस्तीफा दे देना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चोटाला चोटी में बैठ गया है। कोई कॉंग्रेसी सदस्य ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं आया हो।

श्री हरिदेव जोशी : याद आयेगा, उस को कैसे भूल सकते हैं। उसने देश के अन्दर एक नया इतिहास बनाया है।

श्री अध्यक्ष : उसने चोट की है।

श्री हरिदेव जोशी : केवल चोट ही नहीं की है, उसने जो किया है वह हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर काले पृष्ठों में लिखा जायेगा, काला इतिहास बनेगा उसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहे इतिहास बनायें, चाहे कुछ भी करें। आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आप उचित समझते हैं कि दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री का नाम लेकर यहां चर्चा की जाये ? क्या आप इजाजत देंगे कि आपके मुख्य मंत्री की व्यक्तिशः आलोचना करू ?

श्री हरिदेव जोशी : देखिये, यह व्यक्ति नहीं, यह एक सिम्बोलिक व्यक्तित्व हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी चेन्ना रेड्डी की पोल खोल सकता हूं। चेन्ना रेड्डी के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी ने क्या कहा था, वह बता सकता हूं। चेन्ना रेड्डी के सम्बन्ध में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं वह बता सकता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिये। दुनिया के इतिहास के अन्दर हिन्दुस्तान के चुनावों को महत्वपूर्ण माना जाता है और हिन्दुस्तान के अन्दर निष्पक्ष चुनाव होते हैं इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है। यह एक एतिहासिक घटना है जिसने पूरे देश को ही नहीं, संसार को झकझोर दिया है। अभी मेरे एक मित्र पाकिस्तान गये थे। पाकिस्तान से यहां आने के बाद उन्होंने कहा कि वहां के लोग हमारे यहां जो चुनाव होते हैं उन्हें बह हसरत की निगाह से देखते हैं। अर्थात् हिन्दुस्तान के चुनाव के अन्दर धपले-

(113)

(श्री हरिदेव जोशी)

बाजी बहुत कम, नगण्य सी, हुआ करती है। अलबत्ता इस बार के चुनाव के अन्दर जो कुछ भी हुआ उस से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस हारी तो वोटों की कमी से नहीं सारी धपलेबाजी से हारी है, धांधली से हारी है, गड़बड़ियों से हारी है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप उधर देख कर क्यों बोल रहे हैं ? मैं खड़ा हूं, आप देख नहीं रहे हैं। आप मेरी ओर देखें। यदि मैं खड़ा हूं तो कम से कम आप खड़े मत होइये, मंत्री हैं आप देखिये, विपक्ष के नेता जब बोल रहे हैं, उनका जवाब देने में आपके नेता सक्षम हैं, इसलिये आप मेहरबानी करके बीच बीच में इंटरफियरेंस कर रहे हैं वह मत करिये सुनिये शांति से। (व्यवधान) आप फिर बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे क्या करना चाहिये मैं जानता हूं, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह कहना कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय हुई है इन चनावों से, मैं यह कहता हूं ऐसे उदाहरण कायम हुए हैं जिससे इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा अपमानित हुआ है हमारा सिर नीचा हुआ है और हमको यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं अगर दोहराई जाती हैं तो देश के अन्दर चुनावों की निष्पक्षता पर लोगों को संदेह होने लगेगा। इसलिये प्रत्येक स्वाधीनचेता व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह प्रयत्न करे और यह देखे कि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई न जायं देश के अन्दर शान्ति और व्यवस्था हो और चुनाव प्रेम से होवें, ऐसी घटनाएं नहीं रहें जिससे लोगों के दिमाग में तनाव पैदा हो जाय। अगर चुनाव के बाद तनाव रहता है तो लोकतंत्र की असफलता है। लोकतंत्र वही सफल है जो चुनाव के ऊपर विश्वास पैदा करे और उसको स्वीकार करने में कहीं कोई किसी के दिमाग के ऊपर वजन न हो। अगर चुनाव के बाद यह लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मैं ऐसा समझता हूं, हम असफल हुए हैं, चाहे इधर बैठते हैं चाहे उधर बैठते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या हिंसा की हो गई है। शुरू-शुरू में जब पंजाब का मसला खड़ा हुआ था तो एक आदमी या दो आदमी मरते थे, तो हम परेशानी सी महसूस करते थे। मगर आज हालत यह हो गई है कि गोली चली और 31 आदमी मारे गये या 35 आदमी मारे गये तो हमें जैसे कुछ अनुभूति ही नहीं होती है, मन में परेशानी ही नहीं होती है। अर्थात् कहीं न कहीं कोई गलती हुई है वहां पर कि प्रजातांत्रिक नार्म्स टूटे हैं और उससे लोगों के मन में एक प्रकार की परेशानी पैदा हुई है अथवा विदेशी एजेन्सियां सफल हो रही हैं और हम असफल हो रहे हैं उनके कामों को रोकने में।

उसमें हमें यह देखना है कहीं राजस्थान भी परेशानी के अन्दर न फंसे अब तक राजस्थान की सीमाओं के ऊपर कोई ऐसी घटनाएं नहीं थीं मगर पिछली दो तीन घटनाएं चिन्ता पैदा करने वाली हुई हैं। पुलिस ने एक्शन लिया है मगर देखना यह

(श्री हरिदेव जोशी)

है कि हमारी ओर से सतर्कता पूरी बरती जाय और ऐसी स्थिति न हो कि राजस्थान भी उनके अन्दर आये। सौभाग्यवश चुनाव के दरमियान इस प्रकार की स्थिति रही कि जिससे जो आतंकवादी खालिस्तान के समर्थक लोग थे वह राजस्थान में वहां बैंक नहीं कर सके। मैं विशेषकर गंगानगर की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने साहस रख करके इन सारी चीजों का मुकाबला किया और हमारे अधिकारियों ने और दूसरे लोगों ने साहसपूर्वक इन सब चीजों का मुकाबला किया। आज गंगानगर हमारा सबसे अधिक हराभरा और आगे बढ़ा हुआ इलाका है, उस इलाके के अन्दर प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा न हो, निराशा पैदा न हो, इस बात को संभालने की जरूरत है। वहां जो भी अधिकारी रहें वह चुनिन्दा आदमी हों, वह ठीक हों, वह विश्वास पैदा करने वाले हों तभी जाकर के हमें राजस्थान के वातावरण को ठीक बनाने में सुविधा रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बे उसके ऊपर नहीं जाना चाहता परन्तु राजस्थान सरकार से दो तीन बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी का किसी एक जगह स्टेटमेंट अथवा यहां जवाब सुना था जिसमें उन्होंने कहा था जिलों के बारे में कि हम नये जिले नहीं बनाना चाहते। आप यश लें। या हम यश लें मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूं, पर प्रशासनिक लिहाज से आज कोटा जिले का बायफरकेशन, उदयपुर जिले का बायफरकेशन, जयपुर जिले का बाइफरकेशन, गंगानगर का, और भी कई उपयोगार्थ कार्य कम भी सोच सकते हैं ज्यादा भी सोच सकते हैं, मैं कोई उसमें वह नहीं कहता यह एक बहुत जरूरी बात है। हम यह कह सकते हैं कि साधनों की कमी है। मैं इस पाइंट पर भिन्न प्रकार से देखता हूं। जिस दिन हमने राजस्थान के अन्दर तीन नई यूनिवर्सिटी शुरू की थी उस दिन भी मैं समझता हूं कि पैसे की कमी थी और हमारे एडवाइजर्स कहते थे कि नहीं, हम तीन युनिवर्सिटी तो एक साथ नहीं खोल सकते। मगर हर काम के पीछे एक पोलिटिकल विल चाहिये। अगर आप उसको उस निगाह से देखेंगे तो निश्चित रूप में उस पोलिटिकल विल को आप इम्प्लीमेंट करेंगे।

एक माननीय सदस्य : हमारी निगाह में है।

श्री हरिदेव जोशी : है, तो हो जायेगा अगर पोलिटिकल विल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप में पोलिटिकल विल चार मार्च से पैदा हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : जब मैं यहां आया मैंने तो एक दिन खोया नहीं है। चार मार्च से उस के बाद भी अगर मुझे चुनते तो मैं तो एक दिन खोना नहीं चाहता था। मगर लिटेरचर तैयार हो गया था, सामान छप चुका था इलेक्शन का, इसलिये उस समय करना ठीक नहीं था। वरना मैं तो उसी दिन घोषणा कर देता और आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको दूसरी तरह से मत देखिये, मैं केवल

(श्री हरिदेव जोशी)

एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से देखता हूं। यह एक अनुभव की बात है, छोटे राज्य एडमिनिस्ट्रेटिवली आज के युग में सही साबित होते हैं, छोटे जिले एडमिनिस्ट्रेटिवली आज सही साबित होते हैं, डवलपमेंट के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से उन सब चीजों से छोटे जिले, उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं। उन सारे के लिये हमने फाइनेन्स कमीशन के लिये जो कुछ भी मसाला तैयार किया था उसमें सारी चीजों को रखा है। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि फाइनेन्स कमीशन ने आपको तो झोली भर कर दे दिया है। मेरा ऐसा ख्याल है किसी फाइनेन्स कमीशन ने इतना आज तक उदारतापूर्वक राजस्थान की अपील को नहीं सोचा जितना कि आज के फाइनेन्स ने सोचा था।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो योग्यता की बात है।

श्री परसादीलाल मीणा : लाने वाले ही भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा ऐसा ख्याल है वह एक संवैधानिक कमीशन था उसमें कोई व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट करने की बात नहीं है मगर हम आभारी हैं उनके। उन्होंने हमारी भावनाओं को स्वीकार किया।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने पढ़ा होगा फाइनेन्स कमीशन ने....

श्री हरिदेव जोशी : आपने जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए देखा नहीं है, अभी थोड़ी देर है, आप देखोगे सारी चीजों को, अभी जल्दी क्यों कर रहे हो। मैं यह कह सकता हूं कि फाइनेन्स कमीशन ने राजस्थान के साथ न्याय किया है। इसी प्रकार से प्लानिंग कमीशन ने भी। हमने कई नये मुद्दे उनके सामने रखे और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन मुद्दों को स्वीकार किया गया। आज कई मसले आपके सामने पेंडिंग हैं। आपने पानी और बिजली और उसके बंटवारे की और अधिकार की बात कही। मैं नहीं समझता हमने कोई कमजोरी कहीं दिखाई हो। मैं तो बल्कि यह कहता हूं कि मैं आउट स्पोकन रहा हूं राजस्थान के हितों की रक्षा के अन्दर। प्लानिंग कमीशन के सामने जितने भी मसले हमने रखे उन सब को मंजूर करवाया लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि गाडगिल फार्मूला हमारे हक में नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने संबंध और सम्पर्क का उपयोग करके इस पर ध्यान देंगे।

एक समय तो ऐसा आ गया था कि बंगाल में पीने के पानी की कमी मानी गई थी, राजस्थान में ज्यादा माना गया। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। अरावली हिल एरिया, हिल एरिया नहीं माना गया, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे बोर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर थी, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट की स्पेशल स्कीम्स के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। इन सारे आइटम्स को, चाहे छोटे चाहे बड़े, किसी भी रूप में हो, हमने भारत सरकार से स्वीकृत कर-

(श्री हरिदेव जोशी)

वाया और भारत सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि हमारी गलती थी कि हमने इसको पहले नहीं माना।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसले आज भी पेंडिंग है। विशेषकर बिजली का मसला है। यह हमारे जीवन मरण का सवाल है। अगर इसके अन्दर आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी असर पैदा कर सकते हैं तो कीजिये, और हमारा भी कही सहयोग मांगते हैं तो हम उसके लिये तैयार हैं। जितना भी कर सकेंगे, करेंगे। मगर जैसे गैस टर्बाइन है—दूसरा, तीसरा और चौथा जो है उसके बाबत है, पलाना के बावत भी एग्रीमेंट हो चुका है, एक तरफ से काम शुरू हो चुका है ऐसा समझना चाहिये। इसी तरह धौलपुर थर्मल और कोटा थर्मल है। कोटा थर्मल को स्वीकार करने को भारत सरकार तैयार ही नहीं थी इसके लिए हम को कितना अड़ना और लड़ना पड़ा है इसको आप देख लीजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय विपक्ष के नेता, व्यवधान के लिए क्षमा करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक बढ़ाया जावे जब तक सदन के माननीय नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर दे दें, और सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाय और अनुपूरक कार्य सूची के तहत माननीय सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत मंत्री परिषद् में विश्वास व्यक्त करने संबंधित प्रस्ताव पर विचार पूर्ण हो जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हरिदेव जोशी : मैं पीने के पानी बाबत निवेदन कर रहा था। आपको मालूम है कि 1982 में पीने के पानी के सर्वे के लिए भारत सरकार को 45 लाख रुपये देकर के उसका सर्वे करवाया था और राजस्थान पहला राज्य था देश में जिसने यह कहा कि पानी की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिये, चाहे कोई भी सोर्स डवलप किया गया हो, इरीगेशन या किसी भी दूसरे जरिये से। आज के युग में पीने का पानी नहीं मिलता है तो यह सही बात नहीं है। बाकी सब चीजें सेकेण्डरी हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर नये सिरे से देखने की जरूरत है कि पानी का उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अकालों के कारण हमारे सभी सोर्सेज सूखें हैं और आज जो हैण्ड पम्प हैं वह नकारा हो चुके हैं। यह आज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। तो एक नई नीति अख्तियार करनी चाहिए।

इसके साथ साथ पानी के उपयोग के बारे में दिमाग साफ होना चाहिए। हम जिस प्रकार से पानी का उपयोग कर रहे हैं उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। आज ए. बी. सी. डी- जोन्स सब आउटडेटेड हो गये हैं। कई जगह ऐसी थीं जहां हमने नियम स्वीकार किये थे उनको भी

(श्री हरिदेव जोशी)

रिलेक्स कर दिया और यह स्थिति पैदा कर दी कि सब जगह बिजली जाय, सब जगह पानी जाय, सिंचाई जाय। आज ओवर ड्रावल से पानी घटता गया है और आज जयपुर से पूर्व की तरफ का हिस्सा भी सूखा होता चला जा रहा है। दिल्ली तक की तरफ की कई जगह हैं जहां बहुत अच्छा पानी था, वह कम हो गया है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर घटता चला जा रहा और कुएं गहरे होते चले जा रहे हैं। तो इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि जितना ड्रावल हो रहा है वह हो या न हो। आज अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दस वर्ष में समस्या बहुत खराब होती चली जाएगी और शायद एक दो अकाल और हो गये तो यह सुधार में आने वाली स्थिति नहीं रहेगी और पूरा एरिया डेजर्ट हो जायेगा। इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो खुशी है कि भारत सरकार ने अपने बजट में कुछ नई रेल्वे लाइनें स्वीकार करने की घोषणा की है। उनमें से हर एक का सर्वे हो चुका है और जो सिस्टम है उसके अनुसार फिर से री-सर्वे होगा और यह पूरा वर्ष सर्वे में निकल जाएगा। इसकी अपेक्षा जो पहले का सर्वे है उसी के आधार पर काम शुरू कर दिया जाय तो कोई बुराई की बात नहीं है। इस चीज को कोटा और चितौड़ के बीच में अपनाया गया था और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। जरूरत यह है कि मिनिस्टर एग्री- कर ले और काम शुरू हो जाय। अगर इसी वर्ष शुरू हो जाता है तो इस पंच वर्षीय योजना में काम पूरा हो जाएगा। और इस वर्ष यह शुरू नहीं होता है तो अगली पंचवर्षीय योजना में जाएगा। योजना में कितना प्रोवीजन है बजट में यह अभी तक आउट नहीं हुआ है अगर ठीक प्रोवीजन हुआ है तो यह चीज पूरी हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह निवेदन करना है कि आप एक तरफ डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। आप सोचते हैं। कि सभी लोग समन्वित ढंग में मिल कर काम करें, आपसी विचार विमर्श से काम करें, तो जो सैद्धांतिक बातें आपने स्वीकार की हैं उनके उपर आपको सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाना पड़ेगा। हम उस कदम में आपका जितना साथ निभा सकेंगे, निभाएंगे, और नहीं होगा तो आपसे कह देंगे कि आपकी यह बात हमको ठीक नहीं लगती है। मगर एक बार कहने के बाद भी आप नहीं करते हैं तो इस सदन के जरिये उसको रखेंगे और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि राजस्थान में कुशासन को समाप्त करके.......

एक माननीय सदस्य : दुःशासन को लाये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आप अपने आपको दु:शासन मानते हैं तो मुझे पता नहीं है। खैर, दु:शासन की भी इतवार को हत्या होने वाली है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जनता ने यह परिवर्तन नई व्यवस्था और मूल्यों के परिवर्तन के रूप में किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस परिवर्तन से कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय, यदि आपने विपक्ष के नेता का भाषण सुना हो तो मुझे इस बात की तो खुशी हुई कि राजस्थान के संबंध में चर्चा करने के लिए उनके पास कोई बिन्दु नहीं है। वह जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब पहुंच गये लेकिन राजस्थान का उनके समक्ष किसी प्रकार का कोई बिन्दु नहीं रहा जिसके संबंध में राजस्थान के विषय में चर्चा कर सकें। यदि एक दो भाषण को छोड़ कर सबका संकलन किया जाय तो ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल मात्र दिल्ली की सरकार की आलोचना की है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार के सम्बन्ध में वह एक शब्द भी नहीं कह पाये। मुझे ऐसा लगता है और मुझे अफसोस भी है कि जिन बैंचेज से हम लोग बोलते थे उन बैंचेज पर बैठने का अभी तक इनको मुझे प्रशिक्षण देना है। विपक्ष में कैसे बैठा जाता है और विपक्ष में किस प्रकार से बोला जाता है, विपक्ष के सदस्यों को किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है। मैं समझता हूं मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि आपको समय पर और उचित प्रशिक्षण मिले।

श्री चन्दनमल बैद : वह व्यवस्था आपके काम आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं मैं तो व्यवस्थापक हूं। अभी जिस समय विपक्ष के नेता बोल रहे थे पीछे से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें नींद आ रही है। मैं समझता हूं वह दिल्ली के ऊपर चर्चा नहीं कर यदि राजस्थान को ही अपना केन्द्र बिन्दु बनाते तो हमें कुछ लाभ मिलता। वह अनुभवी है इसमें कोई सन्देह नहीं है राजस्थान का प्रशासन उनके हाथ में कई वर्षों तक रहा है। वह नयी सरकार होने के नाते हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना केन्द्र बिन्दु भाषण का दिल्ली बनाया और दिल्ली बनाने के साथ जम्मू कश्मीर पहुंच गये। जहां विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, जाना तो मुझे भी पड़ेगा और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सदन को कि यह सारी वहां जो अराष्ट्रीय गतिविधियां पैदा हुई हैं। यह पिछली बार जब वहां विधान सभा के चुनाव हुए नेशनल कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस ने मिल जुल कर चुनाव लड़ा और मिल जुल करके सरकार बनायी। उस सरकार बनने के बाद की यह सारी स्थिति है। उस सरकार के बनने के पहले और अराष्ट्रीय तत्व इतने हावी नहीं थे लेकिन दोनों की सरकार बनने के बाद अराष्ट्रीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तत्वों को छूट मिली और मुख्यमंत्री जी श्री फारूख अब्दुल्ला आज जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि कश्मीर में केवल वही एक राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। जोशी जी अनुमान लगायें आज के दो वर्ष पहले कश्मीर का हर नागरिक राष्ट्रीय व्यक्ति था और दो वर्ष में फारूक अब्दुल्ला......

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : हमने थोड़े ही कहा है। आपके मिनिस्टर ने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इसको कोट क्यों किया अगर आप नहीं कहना चाहते तो।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कोट इसलिए किया कि आपकी यह ओपिनियन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी ओपिनियन हमारी जो थी वह स्पष्ट कर चुके हैं। मैं तो मानता हूं उनको राष्ट्रीय। मैं राष्ट्रीय मानता हूं, राष्ट्रीय है। इसमें हमने कभी सन्देह व्यक्त नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैं इतना एक निवेदन कर दूं। आप किसी अखबार को कोट करें तो उसी को कोट किया जा सकता है कि उस अखबारों में प्रकाशित समाचार को हम सही मानें और जिम्मेदारी के साथ उसको कोट किया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था आपका कि आप इस सदन में यह कहें, कि कश्मीर वेली में केवल शेख फारूक अब्दुल्ला के अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने नहीं कहा है। यह फर्नेंडिस ने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कोट क्यों किया?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इसलिए किया कि आपके मिनिस्टर बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : आपके मिनिस्टर ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ऐसा कहा है, आपने उसकी ताईद की है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कोई ताइद नहीं की है। मैंने यह कहा है कि यह इस तरह की स्थिति है। उन्होंने जो कहा है उसको मैंने कोट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप किसी बात को कोट करें, किस संदर्भ में कहा है? वह संदर्भ आप बताते नहीं और सदन में केवल एक लाइन कोट करते हैं और उस एक लाइन कोट करने का मतलब यह है कि आप उसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने का मतलब यह है कि....

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो उन्हें राष्ट्रीय आदमी मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कश्मीर में रहने वाले राष्ट्रीय तत्वों का आप अनादर करना चाहते हैं इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहता हूं आप गलत ढंग से इसको कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आपके मिनिस्टर ने कहा है कि केवल वह ही एक व्यक्ति हैं। मैं यह कहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि दूसरे लोग नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विषय में जरा गम्भीरता से बोला करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मामले में आपने और आपके कई माननीय साथियों ने चर्चा की। यह दो वर्ष में वहां स्थिति बिगड़ी है। क्या उसके लिए जनता दल जिम्मेदार है? क्या वहां पर अराष्ट्रीय तत्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने गये? क्या फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी उस समय नहीं गये? क्या हथियारों की स्मगलिंग उस समय नहीं हुई? क्या वहां पर गोली काण्ड पहले नहीं हुए? क्या वहां से दूसरे समुदाय के लोग पहले नहीं भागे? आज आप कहने लग गये कि कश्मीर की स्थिति सारी बिगड़ गयी। कश्मीर की स्थिति बिगड़ी जिस समय कश्मीर का इन्टीग्रेशन हुआ। मुझे याद है महाराजा हरिसिंह ने उस समय कोई सशर्त इसको इन्टीग्रेट किया जाय यह बात नहीं रखी लेकिन आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय कश्मीर का इन्टीग्रेशन हुआ उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसको एक विशेषदर्जा दिया और इसके लिए विशेष दर्जा बनाये रखने के लिए धारा 370 रखी। यह उस समय एक हमारी भूल हुई जिस भूल के कारण कश्मीर सदा के लिए हमारा संकट का कारण बन गया। मैं तो आपको कहता हूं कश्मीर हिन्दुस्तान का अंग है, कश्मीर हिन्दुस्तान का अंग रहेगा इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर के कारण हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की सेना सब प्रकार का बलिदान करेगी लेकिन कश्मीर की एक ईंच भूमि पर भी दुश्मन की नजर नहीं आ सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी रूप में पंजाब का जिक्र आया। पंजाब के बारे में भी आपको बड़ी चिन्ता हुई। कल प्रोफेसर केदार नाथ ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद 1984, मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता, उसके पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता, आज पंजाब के लोगों में अविश्वास की भावना क्यों पैदा हुई है? 1984 के दंगें। 2700 सिखों को बाजार में खड़ा रख के जिन्दा जला दिया गया था। क्या किया आपकी सरकार ने? किसी को गिरफ्तार किया? एक आदमी की भी हत्या हो जाती है, आन्दोलन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, चालान किये जाते। इस घटना में कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के चालान किये और कितने लोगों को सजा हुई? उस समय आपको दर्द नहीं आया। आज कहते हैं कि 30 आदमी रोज के मरते हैं। जैसे मरने वालों की किसी को चिन्ता ही नहीं है, जैसे उसके कारण से कोई इरिटेशन पैदा नहीं होता,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसके कारण से सैंसिटिवनेस खत्म हो गयी। क्या 2400 आदमियों को जिस समय जिन्दा जलाया गया उस समय आपकी सैंसिटिवनेस नहीं थी? क्या आपको उस समय रीएक्ट नहीं करना चाहिये था? क्या आपको उस समय प्रधान मंत्री जी को सलाह नहीं देनी चाहिए थी? उस समय सलाह नहीं दी बल्कि प्रधानमंत्री जी बोले ऐसी बड़ी घटना होती है तो भूकम्प आता ही है, धरती हिलती ही है। बड़ा भूकम्प आ गया और आपने उस भूकम्प का लाभ उठाया कल माथुर साहब कहते हैं कि लहर आती है, लहर में जीत जाते हैं। 1984 का चुनाव किस लहर में जीता था। 1984 का चुनाव इन्दिरा गांधी की शव यात्रा, इन्दिरा गांधी का शव, इन्दिरा गांधी के पास खड़े हुए राजीव गांधी को रोते हुए यह दिखाकर आपने टी. वी. के ऊपर चुनाव जीता था। वह कौन सी लहर थी? वह लहर आपके ध्यान में नहीं आयी लेकिन अब चर्चा करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपको याद होगा कि ये सारा भिण्डरवाला, और भिण्डरवाला को जन्म किसने दिया? लोंगोवाल समझौता हुआ उस समझौते के वक्त लोंगोवाल स्वयं कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव नहीं कराये जायें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थों के कारण वहां चुनाव कराये। चुनाव कराने में बरनाला जीत गये। बरनाला काम कर रहे थे, उनका राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था, बरनाला को वहां से हटाया। यह किसने किया? क्या समझौता नहीं हुआ था कि चंडीगढ़ उनको दिया जाये। चण्डीगढ़ उनको ट्रांसफेर किया जाने वाला था। लेकिन हरियाणा के चुनाव होने वाले थे। हरियाणा के चुनावों में राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उस समय चंडीगढ़ नहीं दिया। आज उसका नतीजा है कि वहां की जनता का आपकी सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां विश्वास सम्पादित किया जाये। उस जनता का विश्वास प्राप्त करें।

श्री हरिदेव जोशी : आपके केन्द्र में जो बैठे हैं, वे तो उनके विश्वास के हैं, फिर क्या दिक्कत है? अब क्या हो गया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं कह रहा हूं। आप पहले मेरी सुन लीजिये। यह पहला प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान का श्री वी. पी. सिंह, अमृतसर गये, खुली जीप के अंदर अमृतसर के बाजार में से निकले, उनके पास फोर्स और पुलिस नहीं थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने पंजाब में कभी पैर रखा है?

एक माननीय सदस्य : एक बार नहीं दस बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह रहने दीजिये। वह जाने दीजिये। वह बुलेटप्रूफ गाड़ी में।

श्री परसराम मदेरणा : भगत सिंह की समाधि पर, रेलवे फैक्ट्री का शिलान्यास, पब्लिक मीटिंग। कई दफा..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फौजियों के बीच में रेलवे फैक्ट्री का शिलान्यास। संगीनों के साये के अन्दर रेलवे फैक्ट्री का शिलान्यास।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कहीं दो राय नहीं है कि शांति होनी चाहिये आपसे

(श्री हरिदेव जोशी)

में विश्वास होना चाहिये सरकार का शांति होनी चाहिये। हम यह भी नहीं चाहते कि अविश्वास बना रहे। मगर उसके लिये आप विश्वास का वातावरण तो.. कहते हैं आपकी मिनिस्ट्री का कोई आदमी ही नहीं है वहां पर। हम क्या करें.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बना रहे हैं। आपने जो पिछले दस वर्षों में बिगाड़ किया है......

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि वी. पी. सिंह, जब से उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है, खुली जीप पर अब जायें तो खतरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वी. पी. सिंह जी को वहां पर खतरा तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे बोल-बोल कर खतरा पैदा करें तो मुझे कोई मालूम नहीं है।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आखिर उस जनता का विश्वास प्राप्त करना है और, विश्वास के साथ ही जो प्रशासनिक दायित्व हैं उनको भी पूरा करना है। आज कोई टेरेरिस्ट जो कुछ उत्पात करें, उनसे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। टेरेरिस्ट्स को जवाब प्रशासनिक शक्ति के आधार पर देना पड़ेगा और दे रहे हैं। ये कोई टेरेरिस्ट के नाम से डरने वाले नहीं हैं। मैं आज आपको इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की सरहद पर जिस प्रकार की आपने चिंता प्रकट की है, प्रो. केदार जी कल चिंतित थे और हम सब लोग चिंतित हैं। लेकिन जिस प्रकार का गवर्नमेंट का एपरेट्स है, उस एपरेटस का पूरा उपयोग किया जाकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी प्रकार की अशांति पैदा नहीं हो, इस बात का प्रयत्न किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में, मुझे एक बात की तो बहुत खुशी हुई कि मेरे सामने चार भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं और, दो भूतपूर्व राज्यपाल ! चारों बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं।

एक माननीय सदस्य : और चारों पुराने भूत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : They are two in one.

अध्यक्ष महोदय, यह तो कांग्रेस पार्टी को बहुत खुश होना चाहिये कि चारों एक जगह बैठे हैं। इस चुनाव के पहले आपस में बोलते नहीं थे।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो हर घर की है, इसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशी जी, मैंने आंखो से देखा है कि........

श्री हरिदेव जोशी : किसने किसको नहीं देखा है? आपको और आपके साथियों को नहीं देखा है ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्राइवेट में देखा है, यहां मत बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी यहां से बोलते थे तो शिवचरण जी वहां बैठते थे और शिवचरण जी माथुर जब यहां से बोलते थे तो जोशी जी पीछे बैठते थे।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें क्या है? स्वाभाविक है। ट्रेजरी बेंचेज जहां पर बैठेंगी, वे पीछे बैठेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इस तरह से नहीं। बिल्कुल पीछे बैठे हों, इधर बैठे हों। और, जब आप लोग बैठते थे तो, पहाड़िया जी सेक्रेट्री के कमरे में मिलते थे। जनता ने आप तीनों को एक जगह ला दिया, उस जनता के प्रति थोड़ा आभार तो व्यक्त करते। लेकिन आभार व्यक्त नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, तीनों को दर्द केवल एक बात का हो रहा है, सारे सदन को दर्द केवल एक बात का है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो तीसरे पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी गयी हैं। वह लिखा है: "लम्बे समय तक सत्ता पर किसी राजनैतिक दल का एकाधिकार, प्रशासन में निरंकुशता, भ्रष्टाचार, जनहित के प्रति उदासीनता और भाई भतीजावाद फैला था। पिछले दस वर्षों में प्रदेश के प्रशासन में गिरावट आयी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, फिजूल खर्ची व वित्तीय साधनों के अपव्यय के कारण अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विकास विनियोग कम रहा जिसके फलस्वरूप विकास की गति प्रदेश में धीमी हुई है, प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही समाप्त सी हो गयी है।" ये छः सात लाइने हैं जिसके बारे में लगभग सभी माननीय सदस्य यह बोले हैं कि राज्यपाल महोदय के मुंह से यह बात नहीं कहलवानी चाहिये थी। एक तो यहां तक कह गये कि राज्यपाल का दुरुपयोग किया है। लेकिन, पहाड़िया साहब, मैं आपको अपना ही भाषण याद दिलाता हूं। 1980 का उस 80 में आपने क्या कहलवाया था जनता शासन के लिये? आप शायद याद नहीं रखते, लेकिन मुझे याद है। पर, आपकी और सदन की जानकारी के लिये मैं पढ़ कर सुना देता हूं:" मतदाता ने फासिस्ट, सम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, सामंती एवं जातीय तत्वों को खुले रूप से ठुकराकर एक बार फिर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं गुटनिरपेक्षता की प्रगतिशील नीतियां एवं कार्यक्रम में अटूट आस्था एवं निष्ठा प्रकट की है।" कोई आपकी डिक्शनरी में और शब्द बाकी रहा था क्या? मैं समझता हूं, आपके शब्द कोश में कोई शब्द बाकी नहीं था....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इनके बाद में मेरा नंबर आयेगा, तब इस्तेमाल करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो इसी उम्मीद में बैठे रहें। हमेशा आप यही सोचते थे कि शिवचरण जी गये तो मेरा नंबर आयेगा, जोशी जी गये तो मेरा नंबर आयेगा, लेकिन यह दोनों ऐसे चतुर है, जैसे राजस्थान में कहावत है "भीखा की घोड़ी, अबके मेरी बारी" उसी तरह से जोशी जी गये तो....

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय, आप यदि इस भाषण के बारे में कह रहे हैं आपत्ति जनक तो शिक्षा लेंगे भविष्य में इस तरह की बातें नहीं कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे लिखते हैं अध्यक्ष महोदय, "गत तीन वर्षों में दिशाहीन शासन को राज्य की जनता ने जिस लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से विदा किया, इसके लिये सरकार मतदाताओं के अपूर्व साहस, एवं विवेक की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती। राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिये जिन सर्वमान्य सिद्धांतों और नीतियों को पिछले दिनों तिलांजलि दे दी गयी थी, उनकी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पुनः स्थापना के लिए दृढ संकल्प से नये प्रयत्न किये जायेंगे।" मैं समझता हूं...(व्यवधान) मैंने देख कर नहीं लिखा है। अब जो मैंने राज्यपाल महोदय ने जो यह बातें कहीं, उसकी पुष्टि इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने कर दी और, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को। उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसकी पुष्टि की। उन्होंने अभी बोलते हुए कहा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल रहा है, और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आपने दृढ उपाय किये तो विपक्ष साथ देगा। ये मानते हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है? तो मैंने इसमें कह दिया तो क्या अन्याय कर दिया? आपने सरकारी अधिकारियों को "ढीठ" कहा। मैंने "अकर्मण्य" कह दिया तो इसमें क्या बुरा कह दिया। क्या मैं "ढीठ" शब्द का प्रयोग करता तो अच्छा लगता? मैं समझता हूं ठीक नहीं था। राज्यपाल महोदय के मुंह से "ढीठ' कहलवाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपने सारी प्रशासनिक मशीनरी को ढीठ बता दिया। आपने भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर लिया। अब मुझे बता दीजिये मैंने दो बात के अलावा क्या कही है।' अब आप फिजूल खर्ची की बात कहें तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान के राजस्व खाते में जो आय होती है, उसका 80 प्रतिशत वेतन, सुविधायें और पेंशन में जाता है और, इसके अतिरिक्त भी आप सुनना चाहें, तो कई माननीय सदस्यों ने सफाई दी कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि सौ में से 85 रु. भ्रष्टाचार में जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों ने अपनी मर्जी से छाप दिया? उनकी कही हुई बातें और चुनाव हुए उस समय तक आपने खण्डन नहीं किया। राजीव गांधी जिस समय तक प्रधान मंत्री रहे आपने खण्डन नही किया और राजीव गांधी चले गये तो उनकी बात का आपने खण्डन कर दिया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने प्रशासनिक व्यय के बारे में कहा था। उनको आपने गलत रूप से इस अभिभाषण में रखा है। राजीव जी ने कभी नहीं कहा कि 85 प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार में जाता है। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय में खर्च होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजीव गांधी ने तो यह नहीं कहा और यह सही है कि कोई आदमी पद पर जब नहीं रहता तो कोई भी आदमी उनके खिलाफ बोल सकता है। आज वह प्रधान मंत्री नहीं है इसलिए आप उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं अगर बाहर आप कहें तो जनता आपको कृतघ्न बतायेगी। सदन में तो इस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कृतघ्न बतायेगी, जो हकीकत है वह बताई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसी स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यपाल महोदय के मुंह से मैंने कौन सी असत्य बात कहलवा दी, जो सत्य है वह कहलवाया है। अब उस जो सत्य के लिए भी लोग नाराज हों तो मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए विवश हूं। मैं तो इस नाराजगी का कोई समाधान नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ियाजी तो एक लाईन लिख दी उसके ऊपर बड़े जोर से बोले कि राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में लिख दिया। तो कोई सामन्ती परम्परा तो नहीं आ रही है। अब गौरवपूर्ण इतिहास है राजस्थान का, पहाड़ियाजी इसको स्वीकार करें या न करें, सारी हिन्दुस्तान की जनता और संसार इस बात को मानता है कि राजस्थान का इतिहास गौरवपूर्ण है। पहाड़ियाजी जरा ऊंची गर्दन कर के देखें....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पूरी लाइन पढ़ें, जिसके लिए मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पढ़ ली। यह आपका भाषण है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरा ही भाषण है लेकिन पूरी लाइन पढिये जिसके लिए मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह पुराना अभिभाषण 1980 का है। जिस भाषण में आपने कहा है कि राजस्थान अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए सदा याद किया जायेगा....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो कल भी कह रहा था। आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आप बहुत जल्दी इन चीजों को भूल जाते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, किन बातों को लेकर यहां नाराजगी प्रकट की गई, मुझे समझ में नहीं आता। अब इस भाषण का विरोध किया गया है। इस भाषण में कौन सी बात है जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? एक बात मुझे ऐसी नहीं लगी जिसके लिए आप विरोध कर सकते हैं। मैंने इस भाषण का बिन्दु बनाया है राजस्थान के गरीब को, मैंने इस भाषण के द्वारा उसको आश्वासन दिया है कि राजस्थान की कोई भी योजना बने, राजस्थान का कोई विभाग हो, गरीब की गरीबी कैसे मिटे, यह केन्द्र बिन्दु प्रशासन का होगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कि आप इसका विरोध करना चाहते हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं, जब मैंने कहा है गरीब का, गांवों का, किसान का इस खजाने पर पहला हक होगा तो क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : किसी एक भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। हमारी साईड से एक भी वक्ता ने बोला क्या कि गरीब का विरोध करते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि इस भाषण का हम विरोध करते हैं। कहा है या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : इस भाषण में जो गलत बातें कही हैं उनका विरोध किया है। हमने गरीब की बात का कभी विरोध नहीं किया। आप देखिये, आधा सत्य और आधा असत्य मत बोलिये। यह आपकी पुरानी आदत है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप किस सेन्टेन्स को कहां जोड़ दो, एक लाइन तो आपने इसमें से बोल ली और एक पहाड़ियाजी के में से बोल दी....

श्री पूनमचन्दविश्नोई : इस पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है जी। यह सही है, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया कि हम इस भाषण में लिखी हुई चीजों का विरोध नहीं करते। यदुनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि यह बात आप पहले कह देते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस भाषण के माध्यम से यह कहा कि खजाने का 60 प्रतिशत गांव, कृषि और किसान, ग्रामीण विकास के लिए खर्च होगा, मैं पूछता हूं, आप विरोध करेंगे ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमारे टाईम में 70 प्रतिशत था....

श्री परसराम मदेरणा : 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कीजिए लेकिन कौन-कौन से सौगें में, किस-किस सेक्टर में कितने रुपये हैं, यह तो कुछ है ही नहीं। कौन से 60 प्रतिशत, कहां से 60 प्रतिशत लायेंगे, किस-किस कार्यक्रमों का 60 प्रतिशत है, यह बताइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है वह। यह सही है कि आप कभी वित्त मंत्री नहीं रहे इसलिए गवर्नर की स्पीच में और बजट स्पीच में क्या अन्तर होता है, शायद इसकी जानकारी नहीं है और अगर यह जानकारी होती तो यह बातें बजट की है, बजट के समय सब चीजें आ जायेंगी, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने विरोध किया है कि पिछले दस वर्षों में जनता और प्रशासन के बीच एक खाई पैदा हो गई, कोई नहीं मानते कि खाई पैदा नहीं हुई ? मैं ऐसा समझता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : नहीं हुई। आप समझते होंगे, हम नहीं समझते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो सरकार में थे नहीं। आपके और सरकार के बीच में तो खाई थी ही नहीं। लेकिन आप सरकार में पहुंच गये, जनता और आपके बीच में खाई पैदा हो गई। उस खाई के एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ जनता थी......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके दल से प्रतिशत वोटों का हम ज्यादा लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पर भी मैं आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस भाषण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का मैं सारा उल्लेख नहीं करना चाहता। मैंने सारी बातों को देखा है और मुझे अफसोस है कि गरीबों के हितों की, गांव के हित की, किसान के हित की, मजदूर के हित की और राजस्थान के विकास के हित की बातों का आपने विरोध किया है, इससे ज्यादा मुझे किसी और बात से दुःख नहीं हो सकता....

श्री चन्दनमल बैद : इससे ज्यादा असत्य बात कोई हो नहीं सकती......

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैंने तो आपको टोका नहीं है....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस भाषण का इस्तेमाल केवल मैंने किया है अभी तक........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जितनी बार टोकेंगे, उतनी बार मेरा लम्बा भाषण होगा। मैं बैठ जाता हूं....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लम्बा आप करिये, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन आप मिस कोट करेंगे, आधी बात कहेंगे, यह बात बर्दास्त नहीं की जायेगी। आप पूरी बात कहिये। मैंने कहा था इस बात को, लेकिन यह बात मैंने कोट नहीं की थी। नीचे की लाईन पढिये आप मेहरबानी करके और वह कहिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पढ़ी हो तो मैं पढ़ता। आपने जो पढ़ी है वह मैंने पढ़ी है....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने तो पढ़ी ही नहीं, उस चीज को आप पढ़ रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान के सम्बन्ध में चर्चा की गई। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाषण के अंत में राज्यपाल महोदय ने एक बात कही है कि हम सब मिल कर बैठें, सार्थक विचार-विमर्श करें और एक ही मनोभाव से एक-दूसरे की विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करें....

श्री शिवचरण माथुर : उसका तो स्वागत किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री माननीय सदस्यों ने मुझे चुना है, राजस्थान की जनता ने इन सदस्यों को चुना है लेकिन आज आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्री नहीं हूं, राजस्थान की जनता ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका ट्रस्टी मात्र हूं और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को किस प्रकार से मैं पूरा कर पाऊंगा उसके लिए चिंतित हूं...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, एक करेक्शन के लिए मुझे माफ करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी को सारे सदस्यों ने नहीं चुना है, केवल बी.जे.पी. के लोगों ने नेता चुना है।

128

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : सारे सदन के नेता मुख्य मंत्री हैं। आप इस बात को समझते हैं कि सदन के नेता मुख्य मंत्री हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता हूं। जनार्दन सिंह जी, पहाड़िया जी मुझे बार-बार खड़े होकर कह रहे हैं। आप तो यहां यह भी कह गये एम्बेसेडर्स और गवर्नर्स को हटाना ठीक नहीं है और उसके साथ-साथ यह कह गये कि प्रशासन के अन्दर अधिकारियों को, कौन किस का विश्वासपात्र है और कौन किसका विश्वासपात्र है, यह कह कर भी हटा दिया। श्रीमान्‌जी, आपको याद है आप मुख्य मंत्री बने थे तो आपको अपना सैक्रेट्री भी राजस्थान की सर्विस में नहीं मिला जो खैरवाल को बाहर से लेकर आये थे। क्या राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा सैक्रेट्री राजस्थान का आई. ए. एस. ऑफिसर था। खैरवाल आई. ए. एस. ऑफिसर था। फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप क्यों सोचते हैं कि केवल आपको ही है, महारथ इनको भी है।

श्री चन्दनमल बैद : अर्द्ध सत्य बोलने में माहिर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इसलिए कह रहा था कि सरकारी अधिकारियों को किसी पार्टी से या दल से जोड़ कर समझना वह पूरे प्रशासन तंत्र को खराब करने की एक दिशा होगी। जो भी सरकार आयेगी उस सरकार के आदेशों का, नीतियों का प्रशासन तंत्र को पालन करना पड़ेगा। हम किसी पार्टी से जोड़ कर चलें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आज यदि प्रशासनिक मशीनरी ने जोशी जी के समय में, शिव चरण जी के समय में और पहाड़ियाजी के समय में काम किया, मैं इन सब को यदि कांग्रेस के सदस्य मान कर चलने लगा तो इस प्रशासनिक मशीनरी से मैं काम ले ही नहीं सकता। इसलिए इतना अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अगर अविश्वास करता तो मेरे पास जो सैक्रेटरी हैं वही जोशी जी के पास सैक्रेटरी थे।

श्री हरिदेव जोशी : काफी देर से कहना चाहते हैं यह बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहना चाहता था। मै घुमा फिराकर नहीं कहना चाहता था। मैं घुमा फिराकर कहूं तो यों कहूं कि यह जो श्रीमान् बीच में बोल रहे थे कि प्रशासनिक मशीनरी पर विश्वास किया जा सकता है आपको याद होगा श्री मीठालाल मेहता मेरे सैक्रेटरी थे जिनको आपने विकटीमाइज किया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरे सैक्रेटरी कौन थे, आपको याद होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे सक्रेटरी आप तो कितने दिन रहे?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कितने दिन भी रहा आपको याद है क्या? आपने खैरवाल की बात की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैरवाल छुट्टी पर गये थे, आये तो आप नहीं थे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने तो खैरवाल की बात की इसका मतलब आपका पता नहीं है कि मेरे सेक्रेटरी कौन थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे सब याद है आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी शादी कब हुयी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने तो खैरवाल बता दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये। ठीक है।....

श्री परसराम मदेरणा : आपके सेक्रेटरी थे उनको मैंने मेरे पास सेक्रेटरी लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी तारीफ करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप तारीफ तो करते हैं मगर बड़ी कंजूसी से करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस स्तर पर नहीं जाऊंगा आखिर मुझे इसी प्रशासनिक मशीनरी से काम लेना है। मैं इस प्रशासनिक मशीनरी को हटा नहीं सकता हूं मैं इस प्रशासनिक मशीनरी से काम ले सकता हूं। उनमें विश्वास पैदा करूंगा जनता और उनके बीच में जो खाई और अविश्वास पैदा हो गया है। इस सरकार को संवेदनशील बनाकर उनको जनता की सेवा में लगाऊंगा और यदि किसी ने कोई गलती की, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो किसी भी हालत में बख्शने वाला नहीं हूं। यह भी विश्वास दिला सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं माननीय शिवचरण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभिभाषण पर बहुत जोर का भाषण दिया। डेढ़ घण्टे...

श्री चन्दनमल बैद : एक घंटा 34 मिनिट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1 घंटा 34 मिनिट। बहुत लम्बा चौड़ा भाषण। मैं समझता हूं कि मैं चाहता था कि डेड घंटे के भाषण में शिवचरण जी माथुर हमारा कुछ मार्ग दर्शन करेंगे लेकिन मार्ग दर्शन करने के बजाय वह तो अपनी सफाई में लगे रहे। पूरा भाषण अपनी सफाई पे। 1981 का समझौता और 1984 का समझौता केवल दो बातों पर डेढ़ घण्टे भाषण दिया....

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो शायद एक घंटा 34 मिनिट में से एक घंटा तो जो आपने कही और जो गलत बयानी की की और जो राजनैतिक मुद्दे उठाये उनका जवाब दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है आपने सफाई दी बहुत ठीक है। अच्छा किया।

श्री शिवचरण माथुर : जिन आधारों पर आप वहां बैठे है उनका विश्लेषण किया उनका विश्लेषण करके मैंने बात कही...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन इन दोनों विषयों पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी थी। आप मुख्यमंत्रीजी थे उस समय भी चर्चा हो गयी। जोशीजी थे उस समय भी, मुख्यमंत्री थे। उस समय भी हो गयी, मैं विपक्ष में था उस समय भी हो गयी। न आप उस समय सदन को संतुष्ट कर सके...

श्री शिवचरण माथुर : मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया क्योंकि प्रस्तावक महोदय ने इसका जिक्र किया है इसलिए उस का सरकजरी तौर पर जिक्र किया था। मैंने उन राजनैतिक हालातों का जिक्र किया था जिसके आधार पर यह चुनाव सम्पन्न हुआ और जिसके आधार पर आप वहां बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1981 और 1984 के समझौते की वकालत करें लेकिन आपका मन जानता है। चन्दनमल जी के शब्दों में यह राज्यपाल महोदय, के भाषण की पुस्तिका एक काली पुस्तिका है और मैं यह कहना चाहूंगा कि 1981 और 1984 के समझौते यह राजस्थान के हितों का बलिदान करने वाले एक काला दस्तावेज हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो आप हमेशा कहते आये हैं। इसलिए जो मैंने कहा यह तो दृष्टिकोण का फर्क है। इसको तो इतिहास ही बतायेगा कि कौन सही था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतिहास जरूर बतायेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय परसरामजी बैठे हैं क्या आप और परसरामजी इस बात के लिए तैयार नहीं हो गये थे कि 1981 के समझौते को स्क्रेप भी किया जा सकता है अब जिस समझौते को स्क्रेप किया जा सकता है तो मैं आज भी कहता हूं कि उस समय यदि 1981 का समझौता स्क्रेप हो जाता तो राजस्थान को कोई नुकसान नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैंने उसमें पहले 15 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता उसमें 17 18 मिलियन एकड़ फीट तक ले आये लेकिन 1955 के समझौते में इनबिल सिस्टम है, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो प्रोरेटा राजस्थान और पंजाब का हिस्सा बढ़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने भी यही बात कही है। फ्लो सीरीज बढ़ने के बाद चाहे पानी की एवेलेबिलिटी बढ़ गयी हैं लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोरेटा होगा, पर्सेण्टेज हमारा वही रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं अगर आप 1981 का समझौता नहीं भी करते तो 1955 के एग्रीमेण्ट में यह इन बिल सिस्टम है उसमें एक क्लोज है उस क्लाज के चलते 1981 का समझौता करने की आवश्यकता नहीं थी। आपने वह समझौता किया उसका नतीजा है कि आज हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी को नहीं मिले। पर आप नहीं मानेंगे। आपने कल कहा कि 1979 में ही जब मोरारजी देसाई ने आदेश दिया था हैड वर्क्स बी बी एम बी को दिये जायं और आपने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि बादल की सरकार को बचाने के लिये मैंने यह अटेम्पट नहीं किया। मै ऐसा समझता है आपको यह तो ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया था उस समय बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बादल और हमारी मीटिंग के अन्दर प्रधानमंत्री ने कहा, बादल की उपस्थिति में कहा, बरनाला उस समय इरिगेशन के मिनिस्टर थे, उनकी उपस्थिति में कहा हैं, कि बी बी एम बी को यह हैड वर्क्स ट्रान्सफर किये जायं और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी किये जायं। 1979 में आपको पता है कि पंजाब की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दी गयी, शायद आप वह तथ्य नहीं कहना चाहते है।

श्री शिवचरण माथुर : वही तो कह रहा हूं 1981 का समझौता हुआ रिट पेश करने के कारण ही हुआ, हरियाणा की रिट थी, पंजाब की रिट थी वही कारण बना है। दोनो स्टेट गवर्नमेण्ट 1976 का जो फैसला हुआ उसके खिलाफ दोनों स्टेट गवर्नमेण्ट सुप्रीम कोर्ट में गयी स्टेलमेण्ट क्रियेट हो गयी थी। तीनों सरकारें पार्टी-सिपेटिंग स्टेट थीं। राजस्थान का उसमें होना स्वाभाविक था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उस समय भी सदन के दोनों तरफ बैठने वाले लोगों ने जो संकल्प लिया था कि राजस्थान के हितों के लिए पूरा सदन एक रहेगा उसके हितों के लिए लड़ाई लड़ेगा। यह आपकी तरफ से हुआ था और हमारी तरफ से हुआ था। सदन एक मत था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दिल्ली जाकर बदल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गहलोत साहब यह पांचना डेम होता तो आप बोलते तो अच्छा लगता। पाचने के बारे में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के झगड़े हैं इन को जरा आप देख लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप विरोधी दल के नेता थे इस सदन के अन्दर यह सामुहिक रूप से यह बात उठी थी आपने कहा कि इस मामले में सदन को एक रहना चाहिए अब भी राजस्थान के हितों में आज भी एक हैं जैसे पहले एक थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक है और एक रहेगें। आज के पहले भी एक थे। राजस्थान के हितों का सवाल आता है वहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल इसमें मैं कोई विभाजन करके इस केस को कमजोर नहीं करना चाहता। हम एक हैं और मुझे खुशी है कि विपक्ष के नेता और बाकी के सदस्यों ने भी इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि अन्तर्राज्यीय विवादों में यदि किसी प्रकार की उनकी मदद की आवश्यकता होगी तो हम इस मुद्दे पर मदद लेंगे।

मैं इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि अगले महीने ही इन सारे अन्तर्राज्यीय विवादों को संकलन करके, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? यह तैयार करा लूं उसके बाद आप लोगों से सलाह मशविरे के लिए बुलाऊंगा ताकि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। लेकिन मैं तो माथुर साहब ने कहा उसकी चर्चा कर रहा था कि आप जोर लगाते तो मोरारजी भाई ने जो आदेश दिया उसकी तामील करवा लेते।

श्री शिवचरण माथुर : आप मेहरबानी करके समझने की चेष्टा करें। मैंने जिस संदर्भ में कहा था उसको मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि आज पंजाब की जो स्थिति है उससे ज्यादा अच्छी स्थिति बी. बी. एम. बी. के हैड वर्क्स को उस समय लेने की मौजूद थी। उस संदर्भ में सोचे तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि उस वक्त पंजाब के सुरजीत सिंह बरनाला इरिगेशन मिनिस्टर थे यहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : सन् 1981 और 1984 के समझौते का प्रश्न नहीं है प्रश्न आपके इस वाक्य का है कि उससे नयी सरकार के समक्ष उलझनें पैदा हो गयी है। यह उलझनें क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो बता रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मदेरणा साहब ने जो बात कही उससे लगता है कि एलिबी तो नहीं है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एलिबी नहीं हूं मैं तो केवल इसी पाइन्ट पर कहना चाहता हूं। आपने यह कहा कि 1979 में तत्कालीन प्रधान मंत्री के आदेश की यदि पालना हो जाती तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। हम तो 80 में चले गये थे। 1980 से लेकर 1990 तक आप थे जो दो महीने की तो आपको शिकायत हो गयी कि प्रधान मंत्री के आदेश की दो महीने तक तामील नहीं हुई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दस वर्ष तक आपने क्या किया ? केन्द्रीय सरकार ने क्या किया ? जैसे कल तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे गंधेली साहबा योजना के लिए 1975 में योजना बनी 1977 से लेकर 1980 में काम नहीं हुआ। 80 से 90 तक क्या हुआ ? मैं बता रहा हूं आप नाराज मत हों।

श्री चन्दन मल बैद : नाराज नहीं हो रहा हूं मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इसको आप बन्द मत कर देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं आपसे मैं ज्यादा उस विश्लेषण में नहीं जाना चाहता जो लाल चन्द जी डूडी चले गये। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि दस वर्ष के अन्दर, यह स्कीम कितने वर्षों की थी ? कितने वर्ष में पूरी होनी चाहिए थी ? मगर हमने दो वर्ष तक काम नहीं किया ? तो आपने दस वर्ष तक क्या किया ? यह स्कीम पूरी क्यों नहीं हुई ? गावों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। आप किसी पर आरोप लगाये तो यह समझ कर लगाये कि आरोप कहीं हम पर उल्टा नहीं लग जाये। लेकिन आरोप ऐसे सीधे लगा रहे हैं जैसे सारी योजना का काम मेरे कारण से रूक गया। दस वर्ष में आपका शासन था। पांच वर्ष तक आप यहां मंत्री रहे हैं। आप यहां पांच वर्ष तक मंत्री रह कर पांच वर्ष की योजना में दस वर्ष लग रहे हैं इसके बारे में चिन्ता करते। आप गंधेली साहबा योजना से जो लाभान्वित होने वाले गांव हैं उन गांवों में जाकर भाषण दे सकते हैं लेकिन विधान सभा में मैं आपको भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि आपने दस वर्ष तक इस स्कीम पर काम क्यों नहीं किया ? आप उस समय बोले क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि 1977 से 1980 के बीच में क्या आपने उस योजना पर एक भी पैसा खर्च किया था क्या ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मंत्रिमण्डल का निर्णय करके कोलायत, मजनेर, चुरू, फलौदी लिप्त हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उस समय प्रोफेसर थे–कहां चक्कर में पड़ रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं राजनीति में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप प्रोफेसर होकर राजनीति करते थे। यही दुर्भाग्य है और इसी कारण से विश्वविद्यालयों का पतन हुआ है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कोई पतन नहीं हुआ है। आप मुझे कह रहे हैं मुझे भी कहना आता है कि आप पहले क्या थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सिपाही था इससे ज्यादा आप कुछ कहेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अलग-अलग खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न माननीय माथुर साहब ने उठाया कि 1984, में पहले भी लगातार कहता रहा कि जो मामला जस्टीसियेबल नहीं था आपने 10 मई, 1984 का समझौता कर इसको जस्टीसियेबल बनाया। यह इसी का परिणाम है कि 10 मई, 1984 को समझौता हुआ आज 1990 है, 6 वर्ष निकल गये आप दोनों मुख्य मंत्री रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह मामला सुप्रिम कोर्ट में क्यों नहीं गया ? आप अपनी कमजोरी स्वीकार करें। जिस बात के लिए तीन मुख्य मंत्रियों के हस्ताक्षर हों जिस बात के लिए केन्द्रीय उर्जा मंत्री के हस्ताक्षर हों सब मिल कर कमिटमेण्ट करें और यह कहें कि मामला सुप्रिम कोर्ट में चला जायेगा और इसी विधान सभा में माथुर साहब आपने कहा था 15 दिन में मामले का रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जायेगा। वह 15 दिन आज 6 वर्ष में निकल गये और 6 वर्ष के लिए या तो मैं यह समझूं कि दिल्ली में आपकी चलती नहीं आप दोनों में एक बात स्वीकार करे। या तो दिल्ली में आपकी कहीं गिनती ही नहीं और गिनती होती तो मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाता। यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर नहीं हुआ। आपने ऐसी योजनाओं को जस्टीसियेबल बना दिया जिसके कारण आज समस्या पैदा हो रही है। माननीय मदेरणा साहब कह रहे थे कि समस्या क्या पैदा हुई यह समस्या पैदा हुई। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने उसके अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं होगा उस समय तक राजस्थान को केन्द्रीय योजनाओं से बिजली मिलेगी। मैं तो कहता हूं आप आयें, जिस समय आप चाहे मैं आपके घर आ जाऊं, आप मेरे पास आ जायें। आपने अपने पत्रों में लिखा है। इन पत्रों में लिखा है कि इस समझौते के अन्तर्गत जितनी बिजली हमको मिलनी चाहिये थी वह बिजली नहीं मिली। यह मैं नहीं कह रहा यह माथुर साहब आप कह रहे हैं यही बात फिर हरिदेव जी जोशी ने अपने पत्रों में लिखी है उस आधार पर जब बिजली नहीं मिली....

श्री शिवचरण माथुर : उसके बाद में यह भी तो कहा है। उस चिट्ठी को आपने

(श्री शिवचरण माथुर)

पढ़ा होगा हमने यह कहा है कि आप पिंगरोली से नरोरा से और ओरिया से और दूसरे जो सोर्सेज हैं बिजली के वह हमको दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : समझौता नहीं होने की स्थिति में आप शौचनालय में जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं माननीय मदेरणा साहब को तो याद होगा आप कुर्सी पर बैठे थे। वहीं बैठे थे और वहां से आपने भाषण दिया था कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है, कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर लिया हैं। यह सरकार कभी घुटने नहीं टेकेगी। यह सरकार झुकेगी नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : चूहे नहीं जो बिलों में घुस जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चूहे नहीं हैं जो बिलों में घुस जायें। येह सब बातें आपने कही थी। लेकिन समझौता करके आये तो उस समय मैं नहीं कहता कि चूहे बिल में चले गये या चूहे कुर्सी के नीचे दुबक गये। और मैं यह नहीं कहता कि कुर्सी के लालच में यह समझौता कर लिया। मैं मानता हूं इनकी चली नहीं मजबूरी है आखिर बिजली पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्य मंत्री का पद है। इस पद की आपने सुरक्षा कर ली। पद बना रहा। यह तो राजीव गांधी की प्रकिया थी कि वे किसी को टिकने ही नही देते। कभी आपको हटा दिया कभी जोशी जी को हटा दिया कभी पहाड़िया जी को हटा दिया पता नहीं लगता कि क्यों हटाया और क्यों लाये। कभी किसी को पता नहीं लगता। मर्जी आये तो हटा दिया मर्जी आये जो कर दिया। अब ऐसी स्थिति में कहना चाहता हूं। समझोता तो कर लिया उस समझौते के सम्बन्ध में क्या किया जाये? भारत सरकार भी कहती है 6 वर्ष हो गये इसको अब तक रेफर क्यों नहीं किया गया? मैंने भी इसका अध्ययन किया और लोगों से सलाह लेने की मैं समझता हूं आवश्यकता है और ले रहा हूं। इस मामले में हमें किस प्रकार से प्रोसीड करना है। अध्यक्ष महोदय, यहां चार सुपर थर्मल प्लान्ट का भी जिक्र है। वह बहुत जरूरी है। अभी जोशी जी ने कहा कि हमने सारी योजनायें भारत सरकार को भेज दीं और प्लानिंग कमीशन ने सब स्वीकार कर लीं। मैं पूछना चाहता हूं कि धौलपुर की क्यों नहीं स्वीकार की? सूरतगढ़ की क्यों नहीं स्वीकार की मांडलगढ़ की? क्यों नहीं स्वीकार की? आपने कहा इसलिए कह रहा हूं नहीं मैं बोलता ही नहीं। आपने जो कहा है वह मैनें सुना है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप दो-दो मत बोलिये मैं तो अकेला हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ के बारे में कोल लिंकेज की बात माननीय शिवचरण जी ने परसों एक्सप्लेन की थी। लेकिन धोलपुर में जहां से आप माननीय सदस्य हैं उन्होंने एतराज यह किया है कि गैसेज की वजह से यह ताजमहल है इसका डिसकलराइजेशन हो जायेगा यह एनवरनमेन्टल मिनिस्ट्री ने एतराज किया है। 20 तारीख के वक्तव्य में आपने जो इसका

(श्री परसराम मदेरणा)

रिटन रिप्लाई दिया है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बता देता हूं। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा था माननीय जोशी जी ने कहा कि प्लानिंग कमीशन सब ने योजनायें मंजूर करीं। हालांकि माथुर साहब ने सही स्थिति बता दी। आपने बता दी थी कि धौलपुर सुपर थर्मल प्लान के लिए तो कोल लिंकेज का प्रश्न विचाराधीन हैं। और धौलपुर के लिए आपने एनवायरमेन्टल प्रोबलम्स बता दी। लेकिन मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान साठे जब ऊर्जा मन्त्री थे उनके नेतृत्व में जब ऊर्जा मन्त्रियों की कॉनफ्रेन्स हुई क्या उस कॉनफ्रेन्स में यह तय नहीं हुआ कि कोई भी थर्मल प्लान्ट पिट हैड के अलावा दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता। आप कहेंगे भटिंडा में लगाया। यही तो कहना चाहते हैं आप। भटिंडा का आधार बना कर मैं मूव कर रहा हूं आज आप कह सकते हैं। आप नहीं थे उस समय।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कल बहुत लैटेस्ट बात आपको निवेदन की थी कि मिनिस्ट्री आफ कोल एण्ड एनर्जी के आफिसर्स, मिनिस्टर के साथ बातचीत होकर के तय हुई थी कि 1975, बल्कि लास्ट ईयर ऑफ दी एट्थ प्लान उसमें हम सूरतगढ़ के कोल लिंकेज के डिस्टेन्स की बात करते हैं क्योंकि चार पांच साल आपको वैसे ही एक यूनिट को बनाने में लगेंगे। हमने दलील यह दी थी कि जब आप भटिण्डा में कोल लिंकेज आप तय कर सकते हैं तो सूरतगढ़ और भटिण्डा के डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है। इस पर मैंने यह कहा था कि आप दोनों मिनिस्ट्री की प्रोसीडिंग्स निकलवा कर देख लीजिए। उसके बाद यह बात तय हुई थी कि सूरतगढ़ को हम लास्ट ईयर ऑफ दी एट्थ प्लान में कोल लिंकेज तय कर देंगे लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है। कल मैंने कहा था अब इसको नाइन्थ प्लान तक इसको टालने वाली बात.........

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुन लिया। मैं समझता हूं आपने अगर कोल लिंकेज उस समय करा लिया होता, धौलपुर सुपर थर्मल प्लाण्ट में वह दूसरी जगह सुपर थर्मल प्लाण्ट लगाने के लिये कह रहे थे उसको एप्रूव करा लिया होता तो दोनों योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती...

श्री शिवचरण माथुर : धौलपुर की तो साइट की बात....

श्री भैरोंसिह शेखावत : साइट आपने नहीं देखी।

श्री शिवचरण माथुर : देखी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखी तो फिर दे क्यों नहीं दी, इस योजना को एप्रूव क्यों नहीं करवाया?

श्री शिवचरण माथुर : हमने तो यह दलील दी थी कि धौलपुर में पानी की उपलब्धि ज्यादा है, चम्बल का पानी

(श्री शिवचरण माथुर)

अवेलेबल है और ईस्टर्न राजस्थान को बिजली भेजने के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त स्थान वह हो सकता है। हमने यह कहा था कि अगर साइट बदलना है तो आप हमें टीम एक्सपर्ट भेज दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के मामले में चिन्ता आपने बहुत प्रकट की और दोनों योजनाएं एप्रूव नहीं हो सकी मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज के हालात में मुझे अपनी पूरी शक्ति और सहयोग, आपका सहयोग और लोगों को लगाकर मैं इन योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से शामिल करूं इसका प्रयत्न करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : धौलपुर का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। मुख्य मंत्री जी मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इस पंचवर्षीय योजना में धौलपुर का आप विशेष ध्यान रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बोले इसलिए हैं कि कल अखबारों में यह आ जाये कि धौलपुर के लिये राजाखेड़ा के सदस्य ने भी वकालत की। इतना सा ही है। आपका परपज सर्व हो गया। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कल आपने भी जिक्र किया, जोशीजी ने भी जिक्र किया सिंगरोली का और कई बातों का आप दोनों ने जिक्र किया। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहता हूं क्या इस उर्जा मन्त्रियों की कान्फ्रेंस में यह तय नहीं हुआ कि बिजली के मामले में जिस राज्य सरकार का जितना विनियोजन होगा उसी के अनुपात में केन्द्रीय योजनाओं से बिजली मिलेगी? यह तय हो गया तो विनियोजन तो राजस्थान का सबसे कम है। सैण्ट्रल प्रोजेक्ट्स में हमें बिजली कहां से मिले और यह उसी का नतीजा है कि आज हाइडल पावर और थर्मल पावर का मिक्स्ड आज के कुछ वर्षों पहले हाइड्ल पावर ज्यादा थी, आज थर्मल पावर ज्यादा हो गयी और इस कारण से बिजली महंगी हो गयी। मैं इसलिए कह रहा हूं आज निर्णय इस प्रकार के हो गये हैं जिन निर्णयों की यदि गहराई में जायें तो हमारे सामने समस्याएं खड़ी होंगी।

आप गैस बेस्ड प्लाण्ट के बारे जिक्र कर कर रहे थे। मैं समझता हूं लोकसभा के चुनावों के बाद विधान सभा के चुनाव नहीं हुए, मैंने उस समय आरिफ साहब को पत्र लिखा जिसमें सारे डिटेल्स हैं और सरकार के आने के बाद मैं भी उनको पत्र लिखा। मैं अब फिर जाऊंगा और उनसे इस बात का प्रयत्न करूंगा कि गैस कारखाने से बिजली पैदा हो रही है उसकी कीमत को घटाया जाये और इस गैस के आधार के ऊपर और प्लाण्ट लगायें जाये जिसके कारण से राजस्थान के अन्दर बिजली की जो कमी दिख रही है उस कमी का समाधान हो सके। मैं ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, और कुछ ज्यादा न कह-कर एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप विकास की तो कल्पना कर रहे हैं लेकिन आपने किस प्रकार का राजस्थान मुझे दिया है उसका भी थोड़ा सा नक्शा यदि सदन के सामने रख दूं तो उचित होगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साक्षरता में 1951 में हम नीचे से दूसरे नम्बर पर थे और 1981 में हम नीचे से दूसरे नम्बर पर हैं। साक्षरता की दृष्टि से हिन्दुस्तान के 17 राज्यों में 17 वां राज्य दूसरा है और सोलहवां हमारा है। किस लेबल पर हम पहुंच गये हैं 81 में? राजस्थान में केवल एक प्रगति हुई है कि बर्थ रेट में हिन्दुस्तान में हम सबसे ज्यादा आगे हैं और इसलिए माथुर साहब ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं...

श्री शिवचरण माथुर : यह हमारी सबकी चिन्ता होनी चाहिए 32.64 परसेण्ट इस डिकेड में 1971-81, के डिकेड में सबसे ज्यादा परसण्टेज...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है कि हम सब मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है कि आज जो प्रचलित योजनाएं हैं, इस सम्बन्ध में, इस कार्यक्रम में इसमें भी आप कोई सुधार करने का सुझाव देंगे तो वह सुधार भी होगा और इस कार्यक्रम को हम किस प्रकार से लागू करें और किस प्रकार से यह सफलता प्राप्त करें हम दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को लागू करने की चेष्टा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों की भी यही स्थिति है। सड़कों में 100 वर्ग किलोमीटर पर जो इण्डीकेटर्स हैं उन इण्डीकेटर्स के हिसाब से राजस्थान नीचे से तीसरे नम्बर पर है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि किस प्रकार का राजस्थान आपने हम को दिया है। अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर यह सब आपकी किताबें हैं आपके राज्य की बनी हुई किताबें हैं। मेरी एक भी किताब नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उनको तो आपने अलग कर दिया। जब मैंने कहा कि तीन गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। जब मैंने कहा कि 13 हजार गुना बिजली...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक गलती कर गये यदि बाबर के जमाने से आप तुलना करते तो कई गुना ज्यादा हो जाते। आप बाबा आदम के जमाने में जाते एक किलोवाट बिजली नहीं थी, सड़क एक किलोमीटर की भी नहीं मिलती बाबा आदम के जमाने से तुलना करते 1952 से कहां तुलना कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यहीं कहा था कि हमने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इनहेरिट किया था राजस्थान में वह 1952 में जो था मैंने बताया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने उसको सुन लिया।

श्री शिवचरण माथुर : तो उसको सही दृष्टि से...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कह रहे हैं आपने जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनके हिसाब से राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर का इण्डीकेटर सारे राज्यों के मुकाबले में नीचे से दूसरे नम्बर पर है। यह आप की किताब में है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं 1952 की बात कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आज की कह रहा हूं 52 की नहीं, आपने पिछले बजट के समय जो बजट स्टडी पेश की है उसके अन्दर लिखा हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं । बिजली में पर केपिटा कन्जम्पशन में हमारा आठवां नम्बर है । यह तो आप स्वीकार करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं फिर आप नाराज होंगे कि 1978-79 में राजस्थान के बिजली बोर्ड ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हिन्दुस्तान में एक नया कीर्तिमान कायम किया था और उसके लिये उनको शील्ड मिली थी । आपको यह भी याद होगा कि उन ढाई वर्षों में हमने लगभग 77 हजार कुओं पर बिजली दी थी और अब 1985 से लेकर 1990 तक अभी तक 77 हजार की आप पूर्ति नहीं कर पाये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा डिस्टार्शन हुआ था मेंटिनेंस एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स बिल्कुल सब डिसऐरे में चली गई थीं और नतीजा यह हुआ मुझे एज ए पावर मिनिस्टर आठ हजार और सात हजार करने पड़े । आपने डिस्टार्शन खड़े कर दिये, वोल्टेज नहीं दिये, लाइनें नहीं दीं । आपने कनैक्शन दे दिया । आज मैंने जो कहा कि थम्बरूल है वह थम्बरूल जनरेशन और आग्यूमेन्टेशन बराबर होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मदेरणा साहब जो पीछे हुआ, हुआ । अब आगे क्या होना है वह सुनने दीजिए । आप हमें आपत्ति करके पीछे मत धकेलिये । यह सदन के सदस्य आगे की बात सुनना चाहते हैं । आप खड़े होकर बार बार बोलते हैं तो उनको भी जवाब देना पड़ता है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना सही है....

श्री अध्यक्ष : आप डिस्टरबैन्स नहीं करेंगे तो आगे की बात बोलेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का राजस्थान आपने मुझे दिया है क्या उसका जिक्र नहीं करूं ? वही तो कह रहा हूं कि आपने मुझे किस प्रकार का राजस्थान दिया है । मैं वही बता रहा हूं । जो आपको बुरा लग रहा है । आप पहले सुधार लेते ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 22 या 24 राज्य है तो उसमें कोई न कोई तो 24 वां होगा ही । आप पहले यह बताइये कि हम पांचवें नम्बर पर थे आप कम्पेरीजन में बताइये । आप तो पहले यह बताइये कि हम पांचवें नम्बर पर थे अब ग्यारह में चले गये तो वह भी बुरा हुआ ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो हुआ है उसको उदाहरण नहीं समझें । यह पुराने लोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से बाकी सदस्य नहीं करें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम अगर पीछे गये हों तो वह बताइये । 17 वें 18 वें नम्बर पर मैंने कहा ना नम्बर तो कोई न कोई होगा, पीछे गये हो तो आप बताइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पीछे गये हैं तो क्या नागालैण्ड की राजस्थान से तुलना करूंगा, मिजोरम का राजस्थान से मुकाबला करूंगा, अरूणाचल प्रदेश का राजस्थान से मुकाबला करूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, वह तो छोटे राज्य हैं 15, 16 जो बड़े राज्य हैं उनसे कीजिए। जिनकी आबादी एक करोड़ से ज्यादा है उनसे मुकाबला कीजिए न आप।

श्री हरिदेव जोशी : मुकाबला नहीं हो सकता...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इन्टरप्ट करते करते सब थक जायेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : आप खुद ही करवा रहे हैं चालाकी से रैस्ट करने के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन राज्यों के ये आंकड़े हैं उनको गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया से परकैपिटा ऐड ज्यादा मिलती है। इसलिये उनकी प्राब्लम यह है कि उसको कहां लगायें।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं जाल में फंस रहे हैं, आप उनको आगे बोलने दीजिये वर्ना सारा टाइम इसी में खराब हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो बोल रहा हूं। वह बात तो मैंने इसलिये कही कि विश्नोई साहब ने कहा कि 22-24 की गिनती करवाओ ना, हम कहां है? तो आप खुद ने जवाब दे दिया कि सारी स्टेट्स हैं उनमें भारत सरकार की ऐड बहुत ज्यादा है और ऐड देने का पैटर्न भी कुछ ऐसा है कि कई स्टेट्स में तो टैक्स ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन स्टेट्स से मैं तुलना नहीं कर रहा था। रेल की लम्बाई में, हम 12वें स्थान पर हैं। पर कैपिटा इन्कम के सम्बन्ध में कल माननीय श्री शिवचरण जी माथुर ने एतराज किया कि हमें जबर्दस्ती बता दिया कि हम 10 में हैं लेकिन पिछली बार आपने जो बजट स्टडी पेश की थी उसमें हम 13वें स्थान पर हैं। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप देख लेना। खाद की खपत में हमारा 16वां स्थान है। एक लाख लोगों में कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस दृष्टि से हमारा 12वां स्थान है। प्रति व्यक्ति उद्योगों में लगी हुई राशि के हिसाब से हमारा स्थान 13वां है। राजस्थान में जनता शासन में जब राज्य के साधनों पर ढिलाई करते थे तब केन्द्रीय प्रवर्तक योजनाओं का कुल 27-28 प्रतिशत था। अब यह विनियोग 62 प्रतिशत हो गया है। यह बहुत खतरनाक चीज है मैं यह इस सदन को कहना चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक से या बाकी की जितनी भी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से जो योजनायें बनकर आती हैं उन योजनाओं में आज हमारी डिपेन्डेण्ट 62 पर्सेन्ट है, 62 पर्सेन्ट। और दोनों तीनों पूर्व मुख्य मंत्री जानते हैं कि जितनी भी स्पेशल स्कीम्स आती हैं उन स्पेशल स्कीम्स के कारण से हमें अपने रेवेन्यू खाते से कुछ खर्च करना पड़ता है, पूंजीगत खाते से कुछ खर्च करना पड़ता है। स्कीम्स को ओरिजिनेट करने वाले और दूसरे होते हैं। वह हमारी क्लाइमेट को सूट करती है या नहीं करती है, हमारे यहां के एन्वायरमेण्ट को

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सूट करती है या नहीं करती है, हमारे यहां की पापुलेशन को सूट करती है या नहीं करती है लेकिन चूंकि वर्ल्ड बैंक हमको पैसा दे रहा है, उस पैसे के कारण से हम अपने रेवेन्यू अकाउन्ट से, कैपिटल अकाउन्ट से पैसा लगाकर उसमें खर्च करते हैं। एक प्रकार से हम बंध जाते हैं इसलिए अब हमारी डिपेन्डेण्ट ज्यादा हो गयी। 27 प्रतिशत से बढ़कर हम 62 प्रतिशत पर पहुंच गये। यह मैं समझता हूं कि अर्थ शास्त्रियों के विचार करने का प्रश्न है कि इस प्रकार की ऐड किस सीमा तक ली जाय, किस प्रकार उसका उपभोग किया जाय, और राजस्थान के सारे वातावरण और राजस्थान की सारी ज्योग्राफी में किस प्रकार से उसकी फिटिंग की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से मैंने आपको कहा कि किस प्रकार का राजस्थान इस समय हमको सम्भलाया है....

श्री रामसिंह बिश्नोई : ऐसी स्थिति के अन्दर भी आप राजस्थान को रखना चाहते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक और बता देऊं। मैं जो आगे कर रहा हूं वह भी बता देऊं। पहले आपने क्या किया वह बता देऊं। अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम अपनी, वर्ल्ड बैंक की स्कीम विदेशी और जितनी भी पूंजीगत संस्थायें हैं जहां से हमको सहायता मिल सकती है उनकी मैंने आज ही मालूम किया है कि अगले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये की योजनायें बनी हैं, 1500 करोड़ रुपये की। अलग-अलग राज्यों की ओर केन्द्र को 1500 करोड़ रुपये फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स और वर्ल्ड बैंक से योजनाओं के कारण से मिलेंगे। मुझे रात को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1500 करोड़ रुपये में से राजस्थान को केवल 11—12 करोड़ रुपये मिलेंगे। जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की तारीफ कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन से हमने यूं करा लिया, फाइनेन्स कमीशन से यूं करा दिया, नेशनल डवलपमेण्ट कमीशन से यह करा दिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई योजनायें बनायी हैं ? कोई योजनायें नहीं बनायीं। अगर आपने योजनायें बनाकर योजनाओं का ढ़ेर लगा दिया होता तो हम किसी न किसी योजना में वर्ल्ड बैंक से क्या फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा राजस्थान की सहायता के लिये लेकर आते। इसलिये अब के हमने तय किया है कि 4 महिने में इतने प्रोजेक्ट्स बनाकर, करोड़ों-अरबों रुपयों के प्रोजेक्ट् बनाकर भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक को, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स को भेज दिये जांय कि जिसके कारण से कोई योजना के अभाव में राजस्थान की उपेक्षा नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं....

श्री शिवचरण माथुर : एक तरफ आप 62 पर्सेन्ट से 27 पर्सेन्ट पर आना चाहते हैं पर उसमें डिपेन्डेण्ट की फायदा लेने वाली बात कहां आती है ? उसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता लेने वाली बात क्यों करते हैं ? अभी थोड़ी देर पहले डिपेन्डेन्स को कम

(श्री शिवचरण माथुर)

करने की बात कही है, दो मिनट पहले कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे यह बता दीजिये कि आप तो डिपेन्डेंट भी रहे हो और पैसा भी नहीं मिला है। आपने तो दो बातें कर ली हैं गुलामी भी स्वीकार कर ली और श्रेय भी नहीं मिला।

श्री शिवचरण माथुर : दो मिनट पहले आपने कहा कि डिपेन्डेन्स को कम करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं अब भी कह रहा हूं कि, स्टेट गवर्नमेण्ट जितनी ज्यादा इस प्रकार से डिपेन्डेंट होकर उन स्कीम्स को लेगी, जो स्कीम हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, क्लाइमेट को सूट नहीं करती उतना ही नुकसान होगा। आपने स्कीम्स बनायी थीं, याद होगा "गरीब की छप्पर", यह उसी में से निकला था। "जंगल में मंगल" यह आपकी ही स्कीम्स हैं। "जलधारा" "कुटीर ज्योति" यह सब आपकी उपज है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : "जंगल में खलीफा"। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे, बोलने दीजिये आप।

श्री शिवचरण माथुर : अभी आपने एक स्कीम निकाली है "गोपाल-गणेश" क्या है वह ? "गोपाल" और एक 'गणेश' अभी निकाली हैं ना आपने ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : लिखा है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो फेजीलोजी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 'गोपाल है।' क्यों 'गोपाल' से नफरत है क्या आपको ? है, लागू करूंगा। 'अन्त्योदय योजना' लागू की थी, संसार में उसकी प्रशंसा हुई थी। "काम के बदले अनाज योजना" लागू की थी जिसे आज राजस्थान के गांव-गांव का मजदूर जानता है, गरीब जानता है। जिस गरीब ने होली-दीवाली को गेंहू नहीं खाये उन ढाई वर्षों में 12 महीने उस गरीब को खाने को गेहूं मिले। आपको जलन है, मुझे कोई चिन्ता, नहीं है। आप जलें तो जल भुनकर नुकसान आपका ही करेंगे, मेरा कुछ नहीं है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, चुनाव की गणित पर आना चाहता हूं। माननीय परसराम जी ने चुनावों की भी गणित बतायी। चुनावों की गणित बताकर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल निर्दलीय और कम्युनिस्टों ने लोक सभा के चुनाव में कितने वोट प्राप्त किये और विधान सभा के चुनाव में कितने वोट प्राप्त किये, इस आधार पर वे बताना चाहते थे कि कांग्रेस की पापुलेरिटी बढ़ी। अब पापुलरिटी कैसे बढ़ गयी ? कांग्रेस को... (व्यवधान) आप मेरे को बोलने दो।

श्री परसराम मदेरणा : पापुलरिटी में जो कमी आयी है गिरावट आयी है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : पापुलरिटी का ग्राफ बढ़ा है, यही तो कहा न आपने ?

श्री परसराम मदेरणा : 45.51 आपकी आयी, 3.40 हमारी आयी, आयी

(श्री परसराम मदेरणा)

तो हमारी भी गिरावट है लेकिन आपकी ज्यादा आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका ग्राफ बढ़ा है। लोक सभा में 63.02 पर्सेन्ट वोट और विधान सभा में 66.42 पर्सेण्ट वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े। फिर भी आप कहें कि हमारी पापुलरिटी बढ़ी है तो इस का कोई मापदण्ड मेरे पास नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 40–40 उम्मीदवार खड़े थे इसलिये आपके उम्मीदवार को कितने मिले, आप कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं काहे को कन्फ्यूज कर रहा हूं?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 30–30 केन्डीडेट्स खड़े थे, आपको कितने वोट मिले वह बता दीजिये?

श्री चन्दनमल बैद : आज मान गये आपको।

श्री परसराम मदेरणा : आप 84 हैं आपको 25.43 पर्सेन्ट वोट मिले हैं।

श्री हरिदेव जोशी : चित भी मेरी पुट भी मेरी यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में जो स्थिति है उससे स्पष्ट है। पापुलरिटी। सरकार किस की बनी है और विरोध में कौन है, स्पष्ट है। इसमें क्या अन्तर दिखा रहे हैं आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के आंकड़े तो परसरामजी ने बता दिये, मैंने तो केवल कांग्रेस पार्टी के आंकड़े बताये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : हमें तो एक ही बात बतलानी है कि 40 साल में आप लोग दो बार वहां पर बैठे हैं और हम 6 बार बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे के लिये बैठे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कोई विवाद है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आप हर चुनाव में जीतने के लिये खड़े हुये थे और हारे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल, हारे।

श्री हरिदेव जोशी : बस?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या हुआ इसमें? यह बस क्या हुआ? हार गये तो हार गये, इसमें क्या है? हार गये तो हार गये और जीत गये तो जीत गये, इसमें कोई आपत्ति क्या है?

मैं अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनू, कोटा,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

झालावाड़, चित्तौड़, पाली, सिरोही, जैसलमेर की 40 सीटों में से एक सीट कांग्रेस को नहीं, मिली। (व्यवधान) एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जोशीजी के मंत्रिमण्डल में, जोशी जी सहित 30 मंत्री थे...(व्यवधान) मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, सब लोग बोलने के लिये खड़े हो गये हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, एक-एक करके बोलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नेता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मिसगाइड कर रहे हैं हाउस को। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपको धन्यवाद प्रस्ताव पास करवाना है तो आप सदन को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिये। हम लोग तो हारे हुये हैं हमारी बुराई में, हमारी योजनायें गलत थीं उसका परिणाम तो हमको मिल गया। अब आप क्या करना चाहते हैं? चूंकि आपको वह अच्छा नहीं लगता, आप डिबेट्स के पाइन्ट्स पर बोलें....

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको हाउस को संतुष्ट करना चाहिये कि आप आगे क्या करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, आप स्वयं उनके जाल में फंसते जा रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जाल में से निकल रहा हूं। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि आप सदन को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप निकल नहीं रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि आप सदन को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी बुराई से आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि हमारी बुराई का परिणाम तो हमने भुगत लिया। आप क्या करना चाहते हैं उसका जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चुनावों के परिणामों की बात कहूंगा। विश्नोई साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां मेहम का बहुत उल्लेख किया गया। किया गया, ना?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह आप याद दिला दीजिए, ताकि और बुराई हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेहम का आपने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि दूर हुई पहाड़ी पर लगती आग तो सबको दिख जाती है घर में लगती हुई आग किसी को दिखती नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का इतिहास उठा कर देख लें, 1952 से लेकर 1990 तक। 1990 से 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे, इतिहास उठा कर देख लें। यह पहला अवसर है कि विधान सभाओं के चुनाव में 206 मुकदमे पंजीबद्ध हुए। राज उस समय मेरा नहीं था। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : हरियाणा के लोगों ने आकर कराये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 88 मुकदमें तो फर्जी मतदान के रजिस्टर हुये । बूथ कैप्चरिंग, मत पत्र या मत पेटियां उठाकर ले जाने और शेष मुकदमें मारपीट के, इस प्रकार 77 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुआ । तब सरकार हमारी नहीं थी, सरकार उस समय आपकी थी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : री पोलिंग तो हुआ है दूसरे दिन, जिस दिन रीपोलिंग हुआ है उस दिन परिणाम आ गये थे । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, मैं यह जिक्र कर रहा था कि आपको और बातों की तो जानकारी मिल गयी । लेकिन आप चुनावों के दिनों में कहां-कहां कितने मुकदमे बने, किस प्रकार के मुकदमे बने कहां बूथ कैप्चरिंग हुआ, कहां री-पोलिंग हुआ, कहां मत पेटियां लेकर चले गये, कहां मत पत्र चोरी कर ले गये, इन सारी बातों की जानकारी भी इस सदन में देते । फिर जिक्र करते महम का तो हम अमेठी का जिक्र करते । फिर लोगों का बराबर ध्यान होता है कि अमेठी में किस प्रकार की स्थिति हुई और यहां पर किस प्रकार हुई । आप मुझे तो नेताओं के बारे में कह रहे थे क्या संजयसिंह के गोली लगी ? उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते ?

श्री हरिदेव जोशी : हमने की है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब की है कि राजीव गांधी नाराज हो जायेंगे ? फिर भी अगर कर दी तो..

श्री हरिदेव जोशी : वह नाराज हुये तो हो गये पर आप कहते हैं क्या कि महम में ठीक हुआ ?

Are you supporting Meham ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लोकतन्त्र के बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, यह हमारा बुनियादी आब्जेक्शन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नेता महोदय, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रश्न इस बात का है कि सारे देश में अखबारों में और विरोधी पार्टी ने उस समय संजय सिंह, संजय सिंह को तो उठाया पर हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर को चाकू मार दिया गुजरात में, उसका किसी ने जिक्र किया ? उसके लिए तो आपने भर्त्सना की नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने निंदा की और आज भी करते हैं । आप अपने मुंह से कहिये कि अमेठी में संजय सिंह पर गोली चलाई उसकी हम निंदा करते हैं और गोली चलाने वाले को पकड़ा जाय, इसकी मांग करते हैं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसे तत्वों की जो देश में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं, भर्त्सना हमेशा की है और आज भी कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है ।

श्री चन्दनमल बैद : महम में जो हुआ आप भी उसकी भर्त्सना करते हैं ? महम

(श्री चन्दनमल बैद)

की भी तो आप कहिये । अडवाणी जी ने कहा है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है आप क्यों शर्मा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही निवेदन कर दूं कि आपको अटलजी और अडवाणीजी का जिक्र करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : आवश्यकता क्यों नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताऊं, आपको, आवश्यकता नहीं है । बुराई होगी तो सब बुरा बतायेंगे ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय नेता महोदय, आपने जो आंकड़े दिये हैं बूथ कैप्चरिंग के पीलीबंगा में कौनसी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग किया ? सत्तारूढ़ दल के कौनसे लोगों ने बूथ कैप्चरिंग किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखवात : कांग्रेस ने ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कांग्रेस ने नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के सदस्यों ने कहां-कहां किया, इसकी मुझे जानकारी है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय रामप्रतापजी पीलीबंगा से आते हैं, निर्दलीय सदस्य हैं, इनसे पूछिये, किन्होंने किया ।

श्री चन्दनमल बैद : बोलिये ।

श्री डूंगरराम पंवार : कांग्रेस ने किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर बूथ कैप्चरिंग और उसकी बात करता हूं तो भी नाराजगी होती है ।

श्री चन्दनमल बैद : कोई नाराजगी नहीं ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय नेता महोदय, आप तो एक इन्क्वायरी करवा लीजिए कि कौनसी पार्टी बूथ कैप्चरिंग किया था । (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मैंने इस सवाल को उठाया, आप यह सोचते हैं कि मेरा यह कहना गैर वाजिब था कि फण्डामेण्टली ये चीज गलत है और प्रजातंत्र को कमजोर करती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं बोलने मे पहले आपसे एक संरक्षण चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं आप लोगों से अपना संरक्षण चाहता हूं । मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है । माफ करिये, जिस तरीके से यह चल रहा है, यह उदाहरण आप नये सदस्यों के लिए गलत पेश कर रहे हैं । हो सकता है कि भविष्य में यह कठिनाई आप सब लोगों को उठानी पड़े ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं । जो इण्टरप्शंस हो रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं । उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि ये उदाहरण गलत हो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक शक्तियों के ऊपर किसी भी घटना से आक्रमण होता है, कमजोरी आती है तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसकी निंदा नहीं करे । इस प्रपंच में मैं पड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिद्धान्ततः पहले भी मैंने मामला उठाया था और आज भी उठाता हूं । किसी राज्य के मुख्य मंत्री और राज्य की घटना को लेकर इस राज्य की विधान सभा में चर्चा हो, अध्यक्ष महोदय, इस सदन से कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं कि जो व्यक्ति इस सदन में नहीं हो, उसकी चर्चा नहीं की जाए । इस राज्य के बाहर की कोई घटना हो, उसकी कोई चर्चा नहीं हो । बाकी सारे मुख्य-मुख्य नेता केवल महम-महम-महम लगा रहे हैं । दुबारा चुनाव होंगे उस चुनाव में फिर कांग्रेस की कब्र खोद दी जाएगी । आप वहां फिर आकर देख लीजिए, कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : आप वहां जाकर महम में लड़ने वालों की रक्षा करना, हमें उसमें एतराज नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के संबंध में । अभी जोशी जी नहीं है, माननीय शिवचरण जी माथुर का मैं आभारी हूं और उसी के साथ पहाड़िया जी का भी आभारी हूं । आपके और जोशी जी के बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन खुले रूप से मतभेद प्रकट हुए, और आपने बड़े साहस पूर्वक उन मतभेदों को प्रकट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । यह मतभेद क्या प्रकट किया ? जोशी जी ने कहा कि जनता दल और बी. जे. पी. ने दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की । आज आपका भाषण सुनने के बाद में तो मुझे ऐसा लगा कि आपने तो 15 हजार रुपये की जो घोषणा की वो जनता को धोखा देने के लिए की । स्पष्ट रूप से धोखा देने के लिए । इस राजस्थान की जनता के साथ यदि कोई मुख्य मंत्री के रूप में धोखा करता है तो, जोशी जी उसकी निंदा करने के सिवाय और कोई बात नहीं करते । लेकिन आपने धोखा किया, आज आपने भाषण दिया कि कर्जा माफ करने से गरीबों को कर्जा नहीं मिलेगा, कर्जा माफ करने से आर्थिक संतुलन बिगड़ जायेगा । शिवचरण जी माथुर कहने लगे कर्जा माफ करने से बैंकों की स्थिति बिगड़ जायेगी, पहाड़िया जी कहने लगे कर्जा माफ किया ही नहीं जा सकता ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मैंने जो कहा उसको ट्विस्ट किया जा रहा है । मैंने कहा कि यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुए हैं । इनके कारण से नुकसान होगा यह स्पष्ट चीज है, मैंने यह कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैंने आपसे पूछा....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैंने आपसे पूछा ! आपने बिलकुल सही कहा है कि जब तक रुपया रीएम्बर्स नहीं हो जाता तब तक माफ नहीं होगा ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने भी यह नहीं कहा, मैंने कहा बैंकों में आप खजाने से पैसा दे दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : आपको यह अधिकार है, केन्द्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को यह अधिकार है कि वह प्लान को रोक कर के सारा कर्जा दे दे । लेकिन जब तक आप बैंकों में पैसा नहीं जमा करायेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक बैंक के अन्दर रीइम्बर्समेंट नहीं होगा तब तक कर्जा माफ नहीं होगा । अब मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं, आपने समझा होगा....

श्री हरिदेव जोशी : आप कहेंगे कि आप नियमों को तोड़ रहे हैं । जोशी जी से पूछना चाहता हूं, सवाल करते हैं और मैं जबाब देता हूं तो यह फिर कहते हैं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप यह क्यों भूल जाते हैं कि पिछले चार साल से, यह आपसे पूछते ही रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं उत्तर देता रहूंगा । अगर क्वेश्चन करते हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं उत्तर दूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की, उस समय तक भूतपूर्व मुख्य मंत्री को यह मालूम नहीं था कि कर्जे का अमाउण्ट कितना है । उस समय इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया वह मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार लिया गया लेकिन इसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशंस कितने होते हैं, उसकी जानकारी मंत्रिमण्डल को नहीं थी । मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं, जैसा माननीय माथुर साहब ने कहा कि जब तक रीएम्बर्समेंट की व्यवस्था नहीं होती, उस समय तक कर्जा माफ नहीं होगा । मुझे चिंता इस बात की है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने घोषणा तो की कि पंद्रह हजार रुपये का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन रीएंबर्समेंट करने के लिये एक कौड़ी खजाने में नहीं छोड़ी । आज वह किस बात की घोषणा कर रहे हैं ? क्या उन्होंने जनता को धोखा नहीं दिया ? पंद्रह हजार का कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है ? आपकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सरकार है, वहां एक कौडी का कर्जा माफ करवा दीजिये । वहां कांग्रेस के लोगों से मांग की जाती है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चेन्ना रेड्डी और वीरेंद्र पाटिल से जब मांग की गई कि कर्जा माफ करो तो कहने लगे आल इंडिया घोषणा पत्र में नहीं लिखा हुआ है। यह तो कई अलग-अलग राज्यों में फोल्डर्स निकाल दिये, उन फोल्डर्स में पंद्रह हजार का कर्जा माफ करने की घोषणा की है। मैं मुख्य मंत्री के कार्य की कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य मंत्री के रूप में आपने चुनावों के दिनों में जितने निर्णय लिये हैं, अगर कोई शब्द मेरे पास है, तो इतने आपत्तिजनक निर्णय लिये हैं कि जिसमें राजस्थान को डुबोने के सिवा आपका दृष्टिकोण कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसे फौज जब भागती है स्कॉर्च्ड अर्थ पालिसी के अनुसार सारी चीजों को तहस-नहस करके जाती है, आप श्री हरिदेव जोशी जिस समय राजस्थान से जाने लगे तो आपकी इच्छा थी कि इस राजस्थान को तहस-नहस करके मैं जाऊं और तहस-नहस करने का मौका आपको नहीं मिला। आपने किस रूप में छोड़ा? राजस्थान को कहां ले जाकर छोड़ा? 27 तारीख को चुनाव हो गये और 28 तारीख को ऐसे निर्णय लिये जा रहे हैं, जिन निर्णयों के फाइनेन्शियल इंप्लीकेशंस जबर्दस्त हो रहे हैं। मुझे आपत्ति है और सदन चाहेगा तो मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार हूं कि किस प्रकार से यह निर्णय लिये गये, उनकी भूमिका क्या है, मंत्रिमण्डल में किस प्रकार से निर्णय लिये जाते हैं, इसके कितने फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशंस होंगे। आप कहते हैं आप कि कर्जा माफ करने की दस हजार की घोषणा की थी और बजट में एक हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यह आपकी पूरी फौज बैठी है। आज तक एक करोड़ रुपये का कर्जा भी माफ किया? (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कौड़ी कर्जा माफ नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इस तरह की चीजों का मुझे जवाब देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो सही बात कहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : या तो आप मुझे बाद में टाइम दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कोई बात ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं मैं सही बात कह रहा हूं। कांग्रेस के मित्र अपने आप ही ट्विस्ट हो जाते हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात तो सुन लीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन की परंपरा रही है कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है और विरोधी दल के नेता खड़े भी हो जाते हैं तो माननीय सदस्य बैठ जाते हैं और जब विरोधी दल के नेता बोलते हैं उस वक्त सदन के नेता यदि खड़े हो जाते

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हैं, तो विरोधी दल के नेता बैठ जाते हैं और उनको सुना जाता है यह जो परंपरा में आज कायम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस सदन के लिए उचित नहीं है। व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस संबंध में व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : असली बात यह है कि इस तरह की परंपरा पिछले 35 साल से चल रही है और नेता महोदय खुद छेड़छाड़ आमंत्रित करने के आदी हैं।

श्री अध्यक्ष : और मैं बार-बार कह रहा हूं, कि आप इनके जाल में फंस रहे हैं, आप मानते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये निवेदन करना चाहता था। आपने मधु दण्डवते के सम्बन्ध में न मालूम किस कवि की बात कह दी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें मधु दण्डवते को इस बात का धन्यवाद देना चाहिये था कि उन्होंने दस हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने की भूमिका में एक हजार करोड़ रुपये माफ करने की बात कही है। मैं योजना बना रहा हूं। जो सरकार आज तक एक कौड़ी कर्जा माफ नहीं कर सकी उस सरकार का क्या....

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझूं यह टोकन प्रोविजन है क्या एक हजार करोड़ रुपये का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो जोशी जी ने जवाब दे दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे क्षमा करेंगे कि यह एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि 14 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर आपने बजट में केवल टोकन प्रोविजन रखा हो और उसके बढ़ाने वाला बात आये, तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम यही कहेंगे कि 14 हजार करोड़ रुपये छोड़िये। यही मैंने आपसे कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने खुद यह कह दिया।

श्री यदुनाथसिंह : कोई सीक्रेट इनको नहीं बताने है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि एक शुरूआत हुई है, एक अच्छी शुरूआत है, उस शुरूआत को आप एनकरेज करें। आप यह कहते कि एक हजार करोड़ की जगह दो हजार करोड़ होने चाहिये, दो की जगह तीन होने चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : 14 होने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहां इनके चक्कर में फंस गये ? कोई 14 हजार करोड़ रुपये का इनके पास हिसाब है क्या ? आप इनके पास में बैठ कर ऐसी-वैसी बात मत करो। पहले भी आपको सैंडविच कर रखा है। 14 लाख करोड़ नहीं हैं, चौदह लाख और करोड़ में बहुत अंतर होता है।

श्री चन्दनमल बैद : लाख और करोड़ में फर्क होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो व्यापारी के घर में जन्म लिया है, मुझसे ज्यादा जानते होंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : व्यापारी के घर में जन्म लिया है, राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्टर भी दो साल रहा हूं । वह भी आपको अनुभव करना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिये मुझे मालूम है कि काश्तकारों का एक हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ हुआ, इसकी सबसे ज्यादा जलन भी आपको हुई । ये भी मैं कहना चाहता हूं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप अब इनको रोकिये ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बोलूंगा । क्योंकि इन्होंने कहा है, इस तरह की कटु और जली हुई बातें कह कर आप मेरे चरित्र का हनन करना चाहते हैं तो वह बुरी बात है । मेरे को जलन क्यों हुई है ? आप ये कैसे साबित कर सकते हैं ? इस तरह की बात कह करके मेरा जो चरित्र हनन आप करना चाहते हैं, उसका मैं सख्त विरोध करता हूं । ये नेता के लायक बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यदि इससे दुःख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं । मैंने इस दृष्टि से नहीं कहा था । मेरी इतनी-सी बात आपको पसंद नहीं आयी कि आप मधु दण्डवते की तारीफ करते, मैंने बात तो नहीं की । आपने रेलवे मिनिस्टर का जिक्र कर दिया । उन्होंने पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया, डीजल पर टैक्स लगा दिया । क्या आप लोगों के मुंह बंद कर दिये गये थे कि पहली बार राजस्थान में एक हजार इकतालीस किलोमीटर की लाइन इस बजट के अंदर शामिल कर दी गयी । आप तारीफ करते । मीटर गेज से ब्रॉडगेज का कन्वर्सन, नई रेलवे लाइन की बात, आप तारीफ करते, कम से कम मुझे यह कहते । (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : रेलवे बजट तो मैंने भी देखा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रेलवे बजट यहां का विषय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डीजल और पैट्रोल की कीमत बढ़ेगी, टैक्स लगा दिया, इसकी आपने आलोचना की । ये आपका अधिकार है, मैं इसको रोकना नहीं चाहता । लेकिन रेलवे लाइन के संबंध में राजस्थान में मीटर गेज को ब्रांडगैज में कन्वर्ट करने की बात भी कही है, नई रेलवे लाइन की बात भी कही है । 1041 या 1042 किलोमीटर लाइनों की बात कही गयी है, उस मामले में यदि आप थोड़ी तारीफ कर देते, तो मैं जा कर भारत सरकार को कहता कि सारे सदन ने आप की तारीफ की है कि इतनी रेलवे लाइन आपने इन्क्लूड की । आज अगर रेलवे मिनिस्टर के पास चली गयी तो कहेंगे, आपकी विधान सभा कहती है, कांग्रेस के मित्रों ने विरोध किया है । तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का विकास होगा या राजस्थान की हानि होगी, उसका आप अंदाज लगा लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, यहां फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया । मैं समझता हूं कि फाइनेंस कमीशन ने हमारे राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहायता की है। मैं उनके लिये राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ, उसका क्रेडिट लेना चाहती है भूतपूर्व सरकार। लेकिन फाइनेंस में कुछ ऐसे कान्स्ट्रेन्ट्स क्रीएट हो गये, जिसके कारण राजस्थान को आगे नुकसान होगा। आप दोनों तीनों मुख्य मंत्री जानते हैं, आठवें फाइनेंस कमीशन ने रिलीफ के लिये एक पैटर्न इन्स्टाल कर दिया। अब वह पैटर्न तो सारा समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद एक व्यवस्था कर दी कि जिस व्यवस्था में अब तक राज्य को जो राहत फण्ड स्थापित किया गया है, उसके अनुसार 90-95 की अवधि के लिये अकाल राहत पेटे में अधिकतम 620 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा सकती है। भारत सरकार का जिसमें योगदान 465 करोड़ का ही होगा तथा राज्य सरकार को 165 करोड़ रु. उपलब्ध कराने होंगे। पुराने फार्मूले के आधार पर हमें पिछली बार 933 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। यह नुकसान हुआ। आप उसका जिक्र करते तो मैं भारत सरकार से जाकर कहता कि हमारे साथ क्या अन्याय किया है, लेकिन उस पर आप बोले नहीं। (व्यवधान) मैं इसके ऊपर बजट पर चर्चा करूंगा, तब सारी बातें आपके सामने रखूंगा। जो हुआ बहुत अच्छा है और जो कमियां रही हैं उनका मिलजुल कर हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में आपका सहयोग मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के एड्रेस में हम ने अकाल और पानी के सम्बन्ध में चर्चा की है। पानी के सम्बन्ध में आपको जानकारी है। 1952 से लेकर आज तक 1054 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, प्लान का एक्सपेन्डीचर है और तरह का एक्सपेन्डीचर है। 33,000 गांवों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है। मैं, माननीय बिश्नोई साहब, आप से पूछना चाहता हूं, एक हजार करोड़ रुपये के लगभग खर्च करने के बाद भी आज राजस्थान की क्या स्थिति है ? गांव-गांव में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्थिति और खराब होगी, 25 साल से मैं आपके समक्ष कह रहा हूं कि गलत नीति अपनायी है उसी का परिणाम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। आपने परसों जो भाषण दिया, मैं समझता हूं बड़ा रचनात्मक भाषण था। और उसी भाषण के आधार पर सरकार विचार करेगी। लेकिन मैं इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, एक हजार पैंतालीस, या चौवन करोड़ रुपया खर्च करने के बाद राजस्थान के 33,000 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कर दिया गया है, इस प्रकार की बात करने के बाद भी आज राजस्थान के प्रत्येक गांव और कस्बे में पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। यह कह दीजिये अकाल की वजह से है। क्या हम ने अकाल के समय पानी का प्रबंध करने के लिये सावधानी नहीं बरती थी ? राजस्थान में अकाल फ्रीक्वेन्टली आता है, तो पीने के पानी का संकट आ सकता है। हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने उस पर विचार नहीं किया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कहा है कि यह समस्या पूरे राजस्थान की है, पूरा राजस्थान इस से प्रभावित है। राजस्थान की जनता दुखी है। हम सब आपस में बैठ कर इस समस्या का कैसे समाधान कर सकते है, और मुझे खुशी है कि कल समिति ने कुछ निर्णय लिये। मैं आश्वासन देता हूं कि इन निर्णयों का ईमानदारी से पालन करवा कर इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, इसकी मैं चिन्ता करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं अकाल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हम ने राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में कहा है कि अकाल के सम्बन्ध में भी हम योजना बनायेंगे। यह योजना बनाने की आवश्यकता इसलिये है, आपको याद होगा, पिछले वर्ष के अकाल में और उसके पहले वाले अकाल में 857 करोड़ रुपये हमने भारत सरकार से लिये और खर्च किये। लगभग, मैं डेफिनिटली नहीं कह सकता, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, 123 करोड़ रुपये या 138 करोड़ रुपये हम ने राजस्व खाते से इसमें डाले कुल मिला कर हमने 900 करोड़ रुपये दो साल में अकाल के लिये खर्च किये। लेकिन आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि हम यहां बैठ जायें, बाहर बैठ जायें, सचिवालय में बैठ जायें, और हम बैठ कर इस बात पर विचार करें कि अब तक जो राशि खर्च की गई है और 900 करोड़ रुपये जो हमने दो वर्ष में खर्च किये है उससे क्या अकाल का स्थायी समाधान ढूंढने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं, आप कह सकते है कि हम सफल हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता है कि हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिये उतनी सफलता नहीं मिली है। इसलिये हमने योजनाबद्ध विकास के साथ-साथ फैमीन की योजना भी बनाने को सोचा है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह हमें इस प्रकार का संकट नहीं दे। राजस्थान की जनता इस संकट से ऊब चुकी है। वर्षा हो, अच्छी खेती हो और लोगों का आर्थिक जीवन अच्छी प्रकार से सुधरे, ईश्वर से यह मेरी प्रार्थना है लेकिन मान लीजिये कि इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो प्लान के साथ एडजस्ट कर के हम यदि अकाल के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेंगे तो इसका लाभ जैसे पहले हमें नहीं मिल पाया, इस बार भी हम को लाभ नहीं मिल पायेगा। इस दृष्टि से मैंने कहा कि फैमीन की भी एक पंचवर्षीय योजना बना कर दोनों को कोआर्डिनेटिंग कर के इस प्रकार से काम करेंगे जिस से राजस्थान में इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बेकारी की समस्या का भी उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है। बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिये हमें निश्चित रूप से मन बनाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का उद्योग, चाहे लघु हो, मध्य हो, चाहे किसी प्रकार का बड़ा उद्योग हो, उस उद्योग से कितने लेबर को एम्पलायमेंट पोटेन्शल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्रियेट होता है, उस एम्पलायमेंट प्रोटेन्शल को एक आधार बना कर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेकारी की समस्या का समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस राजस्थान की अकाल की समस्या के लिये और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये एक एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम लगा कर एक अच्छी शुरूआत की है। इस शुरूआत के अन्तर्गत हम समस्या का समाधान कर पायेंगे। इसके अलावा और साधन है, उन साधनों को किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जा सकता है और बेकारी की समस्या का समाधान हो, यह आपकी भी चिन्ता का विषय है, हमारे लिये भी चिन्ता का विषय है। इतना ही विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस चिंता का निराकरण किस प्रकार किया जाये, इसमें आपका मैं सहयोग चाहूंगा। और मैं तो खुले रूप से कह सकता हूं कि बेकारी की समस्या का समाधान करने में यदि आप इस सरकार को कोई सुझाव देंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा ताकि देश में व्याप्त बेकारी की समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण छोटा कर रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ पिछली सरकार ने किया, उस सरकार से सबक लेकर, उस सरकार ने कितना किस प्रकार का काम किया है, उसमें क्या-क्या त्रुटियां हैं, क्या-क्या कमियां है, उन लूपहोल्स को किस प्रकार प्लग किया जा सकता है, प्लग करने की कोशिश करूंगा। अंत में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा है मैं मुख्य मंत्री के पद पर हूं, लेकिन राजस्थान के ट्रस्टी के रूप में काम करूंगा। और उस ट्रस्टी के रूप में काम करने की मैंने घोषणा की थी कि मैं भ्रष्टाचार का ढिंढोरा तब तक पीटता रहूंगा जब तक लोग नहीं मानेंगे। इसलिये यदि मैं अपने आपको इस भ्रष्टाचार को मिटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं करूंगा तो जनता में किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं होगा। इसलिये मैंने कहा, इस पर भी माननीय सदस्य नाराज हो गये की भैरोंसिंह का नाम इसमें क्यों आया? माननीय चन्दनमल जी बैद, आपको तो मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जिस समय शासन में थी राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे बजट भाषण हो, चार बार राजीव गांधी का नाम आना चाहिये, दो-तीन बार इन्दिरागांधी का नाम आना चाहिये, एक-दो बार संजयगांधी का नाम आना चाहिये। मेरा नाम यदि मैंने खुद ले लिया तो यह आत्मश्लाघा का प्रश्न नहीं है, पिंजरे में फंसाने के लिये मैंने अपने आपको ले लिया तो आपको चिन्ता हो गई। मैं समझता हूं, अगर जोशीजी ने, पहाड़ियाजी ने और शिवचरण माथुर जी यह काम कर के अपना नाम लेते तो मैं तीन-तीन बार उनके नाम का उल्लेख करता लेकिन दस वर्ष में लोकायुक्त से मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर ने अपने आपको अलग रखा, पहाड़िया जी ने जोशी जी ने अपने आपको अलग रखा। यह सब कुछ बातें हुई।

एक सवाल माननीय जोशीजी ने उठाया डवलपमेन्ट चार्जेज का। उदाहरण दिया कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि डवलपमेन्ट चार्जेज कोई नहीं लेंगे । मैं आप से पूछना चाहता हूं किस प्रकार के डवलपमेन्ट चार्जेज ? मेरी सुनिये इस जयपुर में डवलपमेन्ट चार्जेज की समस्या किस ने पैदा की है ? माननीय माथुर साहब बैठे हैं, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन 1981 में जो आपने परिवर्तन के नियम बनाये उससे आपने जयपुर शहर का विनाश कर दिया राजस्थान के खजाने के ऊपर डाका डाला । सरकारी जमीन लोगों ने हड़प ली । अलस(में आंने वाली जमीन हड़प ली । लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में आने वाली जमीन हड़प ली। उस हड़पने की चीज के लिये आपने रेगुलराइज करने के नियम बनाये । इन नियमों की यह उत्पति है जिसके कारण डवलपमेन्ट की समस्या पैदा हुई । आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसने दोष किया है उसको सजा मिलेगी और जो निर्दोष है, उसको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी । आप डवलपमेन्ट की बात कह रहे हैं । आपको याद होगा, माननीय माथुर साहब आपने 78/—रुपये डवलपमेन्ट चार्जेज रखे । क्या गलत था ? आपने क्यों रखा ? जोशी जी ने इसको 44/—रुपये कर दिया और चुनाव के पहले कोई इनको यह कह देता एक रुपया करने से हम को वोट मिलते हैं तो यह एक रुपया डवलपमेन्ट चार्जेज कर देते । जिस चीज का कोई रेशनल नहीं वह बात कहने में मतलब क्या ? हमने कहा था हम इसको रेशनलाइज करेंगे । क्या आवश्यकता पड़ी है, उस आधार पर इसको देखेंगे । आप शीघ्र ही सुन लेंगे कि हम ने इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया है ।

अन्त में, एक बात को लेकर मैं सदन का सहयोग चाहूंगा । पिछली सरकार की कुछ कार्यवाहियों से राजस्थान में जगह-जगह एन्क्रोचमेन्ट हुआ है, सरकारी जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट हुआ है, प्राइवेट लोगों की जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट हुआ है । यह सब कुछ एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है । इसको प्रोत्साहन मिला है इलेक्शन के दिनों में मैं आप सब लोगों से सहयोग चाहूंगा और जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि एन्क्रोचमेन्ट को यह सरकार सहन नहीं करेगी और जो भी एन्क्रोचमेन्ट हुए हैं उसको हटायेगी । मैं माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में जिस जगह लोगों ने एन्क्रोचमेन्ट किया हो उसको सलाह दें कि यह सरकार एन्क्रोचमेन्ट को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी । एन्क्रोचमेन्ट को हटा लें वर्ना सरकार को मजबूर होकर सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं । कि आपने इस अभिभाषण पर कई रचनात्मक बातें कहीं कई व्यंग्यात्मक बातें कहीं-कहीं दिल्ली को ले आये, कहीं हरियाणा को ले आये, लेकिन सब कुछ लाने के बाद राजस्थान सरकार के खिलाफ एक शब्द आप नहीं बोल पाये, इसके लिये धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाये ।

मंत्री परिषद के प्रति विश्वास प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : पहले मैं मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है ?

(ध्वनि मतदान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ आर्डर। विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं तो यह तो सदन में चर्चा का विषय है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बात हो गई, साहब।

एक माननीय सदस्य : चलो माफ किया।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : मंत्री परिषद में सदन द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर ही नहीं दिया। आप को ठहरना चाहिये था। आप तो अपना अनुमान बताइये।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप पहले अपना अनुमान बताइये कि कौन जीता है।

श्री अध्यक्ष : आप डिवीजन चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : डिवीजन कराना चाहते हैं ? नहीं तो फिर काहे के लिये।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : एक बार अन्तिम बार मैं फिर पूछ लेता हूं, अंतिम बार। प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही 26 तारीख को सुबह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक सायं 6.43 बजे सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची

जिन गांवों में हैण्डपम्प पूर्ण असफल हैं उनकी सूची—

क्र.सं. 1	तहसील 2	गांव का नाम 3	कोड नं. 4
1.	पाली	दीवास	96
2.	,,	प्रतापगढ़	146
3.	सूरी	बरारी	26
4.	,,	दुदबार	80
5.	बाली	फतेहपुरा	34
6.	,,	फतापुरा	88
7.	,,	गुढाकल्याणसिंह	107
8.	,,	बडली	8
9.	,,	नेतरा	53
10.	,,	पुरादा	89
11.	,,	सादोलरिया	87
12.	,,	कानपुरा	90
13.	सोजत	बासनीं अजन्स	34
14.	,,	बासनी जोधराज	51
15.	,,	छितरिया	75
16.	,,	गुढाश्यामा	99
17.	जैतारण	कोटरिया	77
18.	रायपुर	बगडी	26
19.	,,	बेलपना	23
20.	,,	कोटकिराना	25
21.	,,	नोख	4
22.	,,	सम्बलपुरा	19
23.	,,	कालबखुर्द	30
24.	,,	पावनपुरा	29
25.	,,	सोडपुरा	55
26.	,,	शहपुरा	57
27.	,,	चैनपुरा	58
28.	,,	देवली खेर्द	60

1	2	3	4
29.	रायपुर	केसरपुरा	66
30.	,,	जगमालपुरा	31
31.	मारवाड़ जंक्शन	फूलिया	30
32.	,,	गुण्डागिरी	40
33.	,,	भीवली	42
34.	,,	हमीरवास	44
35.	,,	सचिवावास	48
36.	,,	बोरीमाडा	49
37.	,,	गुढा सूरसिंह	84
38.	,,	ढाल	89
39.	,,	चौकडिया	91
40.	,,	आसन डाकियाना	92
41.	,,	आसन जोधवान	93
42.	,,	सगोड़ा	105
43.	,,	गुढा हिम्मता	98
44.	,,	गुढा मेहकरन	80

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूची

जोधपुर लिफ्ट केनाल पर मदवार अनुमानित लागत एवं अब तक हुआ खर्चा

क्र.सं.	मद	अनुमानित लागत करोड़ रुपये	अब तक खर्च करोड़ रुपये
1.	पम्प स्टेशन एवं संबंधित कार्य।	13.27	—
2.	निर्माण कार्य हेतु जल व्यवस्था।	10.23	4.82
3.	नहर के लिए मिट्टी का कार्य।	16.15	6.51
4.	नहर में लाइनिंग का कार्य।	24.55	2.95
5.	राईजिंग मैन्स	16.82	0.85
6.	विद्युतीकरण	11.16	10.12
7.	अन्य कार्य	10.96	3.91
	योग :-	103.14	29.16 करोड़

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

गोदियान, टिकावड़ा (किशनगढ़) सड़क की मरम्मत

41. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में गोदियान, टिकावडा, डामर की सड़क कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो किस वर्ष ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कबसे ?

(3) क्या इस कारण आवागमन में भारी असुविधा होती है ? क्या सरकार इस सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष, 1982 में निर्माण कराया गया है ।

(2) जी हां । वर्ष, 1983 में जुलाई माह में अधिक वर्षा के कारण सड़क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है ।

(3) मरम्मत के अभाव में खास कर वर्षा ऋतु के समय आवागमन में असुविधा होती है । इस समय मण्डी के पास पर्याप्त वित्तीय राशि उपलब्ध नहीं है, जिससे कि मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जा सके । आय की तुलना में मण्डी निर्माण के ऋण का पुनर्भुगतान व संस्थापन व्यय 4.88 लाख रुपये अधिक है ।

अनाधिकृत बस्तियों में विकास कार्य

42. जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की नगरों में अनाधिकृत रूप से बसी हुई कॉलोनियों को नियमित कर उनमें विकास कार्य करवाने के बारे में क्या नीति है ?

(2) अलवर में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन, रूपान्तरण तथा नियमितिकरण) नियम 1981 तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18-1-90 के प्रावधानान्तर्गत यदि कालोनी नियमितिकरण के योग्य है एवं कालोनी के निवासी विकास शुल्क की राशि जमा करा देते हैं तो विकास कार्य करवाये जा सकेंगे ।

(2) अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

परिशिष्ट—ब

अलवर नगर में निम्न कॉलोनियों का अनाधिकृत निर्माण की सूची

1.	राम नगर कालोनी (फतेहसिंह गुम्बद के पास)	न्यास की दयानन्द योजना में धारा 32 (2) के अधिसूचित है।
2.	जवाहर नगर कालोनी (मुंगस्का देहली रोड)	,, ,,
3.	श्री राम नगर कॉलोनी (मुगंस्का के पीछे)	,, ,,
4.	विजय नगर कालोनी (मुगस्का के पीछे)	,, ,,
5.	आजाद नगर (दाउदपुर)	,, ,,
6.	शास्त्री नगर (दाउदपुर)	,, ,,
7.	पी. एन. टी. कॉलोनी (दाउदपुर)	,, ,,
8.	कृष्ण नगर (दाउदपुर)	,, ,,
9.	सुभाष नगर (खुदनपुरी)	न्यास की दयानन्द योजना में।
10.	कृष्णा कालोनी (आर्ट कालेज रेल्वे लाइन के पास)	,, ,,
11.	पुष्पा कालोनी (देहली रोड)	न्यास की वेयर हाउसिंग एवं गोदाम योजना में।
12.	किसान गृह निर्माण समिति (देहली रोड)	न्यास की दयानन्द नगर योजना में धारा 32 (2) क के तहत अधिसूचित है।
13.	शक्ति नगर (विजय मन्दिर रोड)	न्यास की विजय नगर योजना में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है।
14.	आर. एस. ई. बी. वालों की कालोनी (विजय मन्दिर रोड)	न्यास की बुद्धविहार योजना में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।
15.	तिजारा रोड पर (रेल्वे फाटक के पास)	न्यास की दयानन्द नगर योजना में धारा 32 (2) क के तहत अधिसूचित है।
16.	संजय कालोनी	न्यास की योजना नं. 12 में धारा 38 में स्वीकृत है।

164

17.	इन्द्रा कालोनी	न्यास की योजना नं. 11 में न्यास द्वारा ड्रोप किये जाने का निर्णय लिया।
18.	संजय कालोनी (आकाशवाणी अलवर के पास)	न्यास की कोई योजना नहीं है।
19.	मेहन्दी बाग कालोनी (मेहन्दी बाग)	न्यास की योजना नं. 6 में राज. आवासन मण्डल को दे दी गई है।
20.	बाभाई जी के बाग वाली कालोनी	न्यास की अशोक नगर योजना में न्यास निर्णय अनुसार ड्रोप किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।
21.	हाकमल कालोनी (मेहन्दी बाग के पास)	"
22.	कामरेड रामानन्द नगर (लालडिग्गी के पास)	न्यास की कोई योजना नहीं है।
23.	विवेकानन्द नगर (काला कुआ के पास)	न्यास की एस. डब्लू. बी. योजना में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।
24.	कालोनी सर्किट हाउस के पास।	न्यास की मालवीय नगर योजना में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।
25.	मीणा कालोनी (जगन्नाथ जी के मन्दिर के पास रूपवास)	न्यास की मालवीय नगर योजना में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है।

ह.
उप सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर (राज.)

राजगढ़ एवं तारानगर तहसीलों के ग्रामों का विद्युतिकरण

43. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) एवं **श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 में वर्षवार कुल कितने ग्राम विद्युतिकृत घोषित किये गये ? क्या उनमें से सभी ग्राम विद्युतिकृत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इन गांवों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त तहसीलों के सभी गांवों में एल. टी. लाइन पोल लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में ? यदि नहीं तो कितने ग्राम शेष हैं और उनमें एल. टी. लाइन पोल कब तक लगा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 के माह फरवरी, 1990 के अन्त तक क्रमशः 37 एवं 26 कुल 63 ग्राम विद्युतिकृत किये गये हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	तहसील राजगढ़	तहसील तारानगर
1985-86	6	6
1986-87	6	6
1987-88	7	2
1988-89	4	5
1989-99 (फरवरी, 90 तक)	14	7
कुल	37	26

उपरोक्त सभी ग्रामों में 11 के. वी. लाईन खेंचकर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर लगा कर ही विद्युतिकृत घोषित किया गया है। वर्ष 1989-90 के वार्षिक कार्यक्रम में तहसील राजगढ़ एवं तहसील तारानगर के प्रस्तावित क्रमशः 32 एवं 18 ग्रामों में से 14 एवं 7 ग्रामों को माह फरवरी, 1990 के अन्त तक विद्युतिकृत किया जा चुका हैं। शेष ग्रामों का माह मार्च, 1990 के अन्त तक विद्युतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) प्रश्न संख्या 1 में वर्णित 63 ग्रामों में से 50 ग्रामों में एल. टी. लाइन का कार्य कर दिया गया है। शेष 13 ग्रामों में एल. टी लाइन डालने का कार्य, मांग व उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रगति पर हैं। जिन ग्रामों में एल. टी. लाइन नहीं खेंची हुई है उनका तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

(ऊर्जा मंत्री)

वर्ष	तारानगर तहसील के ग्रामों की संख्या	राजगढ़ तहसील के ग्रामों की संख्या	कुल
1985-86	—	—	—
1986-87	—	—	—
1987-88	—	—	—
1988-89	1	—	1
1989-90	6	6	12
	7	6	13

बाड़मेर जिले के गांवों को पेयजल

44. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की साउथ गिराव सालारियों योजना कब स्वीकृत हुई एवं इसमें कितने ग्राम सम्मिलित है ?

(2) उक्त योजना में सम्मिलित कितने गांवों में पानी अब तक नहीं पहुंचाया गया यदि हां, तो क्यों ?

(3) बाड़मेर जिले का गिराव खड़ीन एवं गिराव खड़ीन रिवाइज योजना कब कब स्वीकृत हुई थी और उनमें कितने कितने ग्राम शामिल है ? कितने गांवों में अभी तक पानी नहीं जाता और क्यों ? वंचित गांवों में कब तक पानी पहुंचा दिया जायगा ?

(4) बाड़मेर जिले के रामसर ग्राम में ग्रामीण नल योजना कब स्वीकृत हुई थी ? उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं होने के क्या कारण है ? अब कब तक रामसर ग्राम में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल योजना साउथ गिराव सालारिया वर्ष 1982-83 में स्वीकृत हुई थी। वर्ष 84-85 एवं 85-86 में 6 विस्तार योजनाएं स्वीकृत हुई। स्वीकृत योजनाओं में कुल 36 गांव हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) इस योजना के गांव सालारियां में पानी अब तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। यह गांव दूरस्थ होने के कारण अब जोड़ा जा रहा है।

(3) बाड़मेर जिले की गिराव खड़ीन जल योजना वर्ष 72-73 व पुनर्गठित जल योजना गिराव खड़ीन वर्ष 84-85 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना में 29 गांव हैं, जिनमें से तीन गांव में पानी नहीं जा रहा है। इन 3 गांवों की पाइप लाइन इसी वित्तीय वर्ष में डाली गई है एवं पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 90-91 में इन गांवों में पानी पहुंचा दिया जाएगा।

(4) ग्राम रामसर, क्षेत्रीय जल योजना गिराव खड़ीन के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में स्वीकृत हुआ है। इस ग्राम में 6 सार्वजनिक नलों से जल वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गांव में जलाशय का निर्माण करवाया गया है व पाइप लाईन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है जो शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावेगी।

रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

45. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला अलवर में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां क्रियाशील हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में और कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोलने की सरकार की योजना है?

(3) उक्त क्षेत्र के किन-किन पशु चिकित्सालयों में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा है?

(4) इन चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि खर्च की?

(5) मेवात बोर्ड के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत कितनी धन राशि प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में दो पशु चिकित्सालय क्रमशः रामगढ़ एवं बहाला में और दो पशु औषधालय क्रमशः नौगांव एवं ऊँटवाल में कार्यरत हैं।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में नई चिकित्सा संस्थाएं खोलने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(3) वर्तमान में क्षेत्र की सभी संस्थाओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा हैं।

(4) राज्य सरकार से चिकित्सालयवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। जिला पशु पालन अधिकारी को जिले की समस्त संस्थाओं हेतु राशि आवंटित की जाती हैं।

(5) मेवात बोर्ड के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 1988-

(पशुपालन मंत्री)

89 के दौरान अलवर एवं भरतपुर जिलों के लिए एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई हैं।

बालोतरा लूनी नदी पर पुल निर्माण

46. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बालोतरा-जसोल के बीच लूनी नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ? अब तक कितनी रकम इस कार्य पर खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य राजस्थान पुल निर्माण निगम की आपत्ति के कारण रोका गया है ? यदि हां, तो क्या तथा इसके पुनः आरम्भ करने के संबंध में क्या विचार है ? इस वर्ष इस कार्य पर कुल कितना रुपया खर्च करने तथा कितना कार्य पूरा करने का लक्ष्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस पुल के निर्माण हेतु दिनांक 14.6.84 को सरकार द्वारा रुपये 150.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति के अन्तर्गत उच्च स्तरीय पुल का निर्माण प्रस्तावित था तथा इस कार्य हेतु पुल निगम को रुपये 10.00 लाख की अग्रिम राशि दी गई थी। प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिये पुल निगम द्वारा सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य कर लिया गया है। तथा जसोल की तरफ से पुल एप्रोच पर मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ है। इन कार्यों पर अब तक पुल निगम द्वारा रुपये 7.34 लाख खर्च किये जा चुके है।

पुल निगम द्वारा किये गये सर्वे एवं अनुसंधान के आधार पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से सबमरसीबल पुल बनाया जाना उचित समझा गया है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 301.28 लाख का तखमीना संशोधित स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। पुल के डिजाइन के प्रश्न को लेकर पुल निर्माण निगम द्वारा अपने सुझाव दिये गये थे। उन सुझावों पर विचार विमर्श एवं निर्णय में लगे समय के कारण काम को गति नहीं दी जा सकी।

पुल के निर्माण कार्य को उपरोक्त विचाराधीन स्वीकृति के पश्चात् पुल निगम द्वारा पुनः प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा।

कर्जों की माफी

47. **श्री डूंगर राम पंवार** (टीबी) : क्या मुख्य (मंत्रिमण्डल सचिवालय) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार 10 हजार रुपये तक के कर्ज माफ करने का विचार रखती है ?

(श्री डूंगरराम पंवार)

(2) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या मानदंड तय किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसानों व शिल्पकारों को 10000 रुपये बैंक उनके द्वारा लिये गये ऋणों में राहत देने के लिए एक योजना की घोषणा की है इसके अंतर्गत 2.10.89 को अल्पावधि व दीर्घावधि ऋणों की अतिदेय राशियों में राहत दी जावेगी । जिन दोषी ऋणकर्ताओं ने सक्षम होते हुए भी विगत में जानबूझकर ऋणों की अदायगी नहीं की है उन्हें राहत नहीं दी जायेगी । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जिन किसानों व शिल्पाकारों ने ऋण लिया है उनको भारत सरकार द्वारा राहत दी जायेगी । किसानों व शिल्पाकारों को सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर भी इसी प्रकार की राहत देने के लिए राज्य सरकार एक योजना बनायेगी । योजना के मापदण्ड अगले दो महीने में तय कर दिये जायेंगे ।

जायल (नागौर) पंचायत समिति के अप्रशिक्षित सेवामुक्त अध्यापक

48. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) :—क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जायल, जिला नागौर में मार्च, अप्रेल 1985 में 57 अप्रशिक्षित अध्यापकों को रु. 400/- समेकित माहवार वेतन पर नियुक्ति दी गई थी और उनकी 12 दिसम्बर, 1988 को सेवा समाप्त कर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार के अप्रशिक्षित 94 अध्यापकों को पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में तथा 18 अध्यापकों को पंचायत समिति डेगाना में नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(3) पंचायत समिति के उक्त अध्यापकों को राज्य सेवा से पृथक् करते वक्त क्या बहुत से अध्यापक अधिक आयु पार कर चुके थे ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मानवीय आधार पर उक्त अध्यापकों को सेवा में पुनः लेकर प्रशिक्षित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह सही नहीं है कि सेवा से पृथक करते समय बहुत से अध्यापक आयु सीमा पार कर चुके हो ।

पृथक किये गये अध्यापकों को पुनः सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बिना प्रशिक्षित हुए वे नियुक्ति अर्हता नहीं रखते ।

विद्युत उपभोग के मिनियम चार्जेज

श्री अमृतलाल परमार (बाली) :—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमृतलाल परमार)

(1) क्या राज्य सरकार किसानों के विद्युत उपभोग के मिनिमम चार्जेज माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या गत सरकार द्वारा ऐसे चार्जेज माफ करने की घोषणा के बावजूद किसानों से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 16.1.1990 की अनुपालना में मण्डल ने दिनांक 16.2.1990 को इस आशय के आदेश जारी कर दिये थे। आदेश जारी करते समय मण्डल ने यह एतराज किया था कि इन निर्देशों की अनुपालना से मण्डल को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पडेगी, जिसका राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। चूंकी उक्त आदेश जारी करने के समय चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी और इन आदेशों की अनुपालना में विद्युत मण्डल को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी हानि होगी, राज्य सरकार इस मामले में पुनर्विचार कर रही है।

891

परिशिष्ट –4

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूचना

वर्ष 89 –90 में दान स्वरूप दी गई राशि का विवरण: —

क्र. सं.	नाम स्पिनिंग मिल	नाम संस्था	राशि
1.	राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा	1. मन्दिर निर्माण कमेटी, गंगापुर (मन्दिर निर्माण हेतु)	5,000.00
		2. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाडा का सम्मेलन	7,500.00
		3. गांधी विद्यालय, गुलाबपुरा (स्काउट गाईड जम्बूरी हेतु)	800.00
		4. जिला अस्पताल विकास समिति, भीलवाडा	5,00,000.00
		5. सहकारी प्रशिक्षण विकास भवन, जयपुर निर्माण हेतु	2,00,000.00
		योग :	7,13,300.00
2.	गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल लि., गंगापुर	1. नेशनल यूनियन आफ अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारी संघ (अधिवेशन हेतु)	500.00
		2. नगरपालिका, गंगापुर (संडासेडा व प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचरें क्रय हेतु,	5,000.00
		3. चेयरमैन हास्पीटल डवलपमेन्ट कमेठी, भीलवाडा (महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा के विकास हेतु।)	5,00,000.00
		4. राजकीय बालिका उ. प्रा. विद्यालय, गंगापुर (शील्ड बनवाने हेतु)	192.50
		5. लायन्स क्लब, गंगापुर (नेत्र चिकित्सा हेतु)	5,000.00
		6. रा. उ. मा. विद्यालय, लक्ष्मणियास (विद्यालय बाउन्ड्री हेतु)	11,000,00
		योग :	5,21,692.50

परिशिष्ट (ब)

नाम स्पिनिंग मिल	31.3.89 तक कुल हानि	ऋण बकाया				अवधिपार			
		केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें		शीर्ष सहकारी बैंक		केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें		शीर्ष सहकारी बैंक	
		मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
1. गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल लि.गंगापुर	(—)5,02,06,755	रु.470 लाख	—	रु.15लाख	—	—	—	—	—
2. राज.कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.गुलाबपुरा	(+)8,29,88,478	रु.505.62,,	—	—	—	रु.241.14 लाख	रु.194.55 लाख	—	—

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूचना

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति 30.6.89 का विवरण (राशि लाखों में)

क. सं.	नाम बैंक	कार्यशाली पूंजी	प्रदत्त हिस्सा पूंजी	सुरक्षित कोष	सदस्यों पर ऋण बकाया	लाभ/हानि वर्ष का	लाभ/हानि कुल
1.	अजमेर	371.86	37.86	111.46	333.55	(—) 3.88	(—) 66.73
2.	भीलवाड़ा	486.19	37.88	0.07	328.06	(—) 8.26	(—) 75.27
3.	केकड़ी	178.16	17.26	23.71	153.53	(—) 2.65	(—) 11.91
4.	टोंक	544.17	42.48	0.69	448.00	(—) 4.96	(—) 11.04
5.	अलवर	593.64	52.48	58.46	465.91	(+) 18.15	(—) 26.58
6.	भरतपुर	620.54	28.60	27.41	444.94	(—) 16.40	(—) 73.97
7.	धौलपुर	461.06	60.82	—	372.51	(+) 1.29	(+) 19.95
8.	हिण्डौन	501.34	42.48	—	401.97	(—) 7.28	(+) 13.03
9.	सवाईमाधोपुर	762.03	53.21	—	625.10	(+) 0.44	(+) 21.75
10.	बीकानेर	218.62	19.49	17.74	163.30	(+) 2.32	(+) 11.58
11.	हनुमानगढ़	266.34	30.20	0.24	208.01	(+) 7.13	(+) 17.40
12.	नोहर	44.00	4.17	0.15	28.25	(+) 0.08	(+) 3.37
13.	रायसिंहनगर	238.49	25.93	10.51	206.82	(+) 6.70	(+) 9.34
14.	श्रीगंगानगर	467.25	46.67	16.29	385.96	(+) 10.87	(+) 37.28
15.	चूरू	530.63	44.91	14.33	393.64	(+) 0.78	(+) 30.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	जयपुर	1197.00	108.01	0·98	983.50	(-)	2.60	(-)	52.55
17.	झुंझुनू	1198.64	93.57	1.56	1039.51	(+)	3.57	(+)	61.88
18.	सीकर	1245.65	97.00	35.54	1007.44	(+)	16.73	(+)	13.64
19.	बालोतरा	306.85	27.83	11.80	255.83	(+)	1.90	(+)	19.27
20.	बिलाड़ा	206.95	21.28	3.88	166.65	(+)	0.27	(+)	5.75
21.	जोधपुर	159.11	15.25	4.86	117.47	(—)	1.89	(—)	1.98
22.	नागौर	956.38	59.20	51.75	729.67	(+)	0.55	(+)	9.62
23.	बाँरा	525.05	35.16	12.33	436.01	(+)	0.92	(—)	1.73
24.	बून्दी	274.79	22.03	16.86	208.42	(—)	5.51	(—)	16.53
25.	झालावाड़	899.29	71.27	23.06	732.31	(-)	5.12	(—)	4.33
26.	कोटा	582.00	46.85	3.93	460.70	(—)	15.46	(—)	15.46
27.	जालौर	1357.87	74.73	33.45	919.71	(+)	6.44	(+)	133.74
28.	पाली	674.28	45.35	38.47	487.42	(+)	0.50	(+)	6.48
29.	सिरोही	507.71	33.47	38.67	361.51	(—)	2.89	(—)	15.30
30.	बांसवाड़ा	486.97	33.26	0.79	295.16	(—)	1.79	(+)	8.02
31.	चित्तौड़गढ़	647.07	44.99	38.06	503.60	(—)	4.02	(+)	7.53
32.	डूंगरपुर	418.38	24.90	0.16	63.50	(—)	1.40	(+)	8.67
33.	प्रतापगढ़	81.74	9.98	0.43	63.50	(+)	0.05	(—)	0.41
34.	उदयपुर	567.71	43.70	61.64	398.36	(—)	11.58	(—)	57.16

171

परिशिष्ट—ब

राज्य भूमि विकास बैंक लि. की वित्तीय स्थिति 30.6.89

(राशि लाखों में)

ऋण बकाया		योग	कार्यशील पूंजी	हिस्सा राशि	रिजर्व फंड	हानि	संचित लाभ
सामान्य	विशिष्ठ योजना						
3815.84	11465.19	15281.03	21115.17	746.76	423.68	171.76 (—)	247.57(+)

(173)

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1990

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	15	18	रामेश्व.	रामेश्वर
2.	64	24	श्री प्रद्युमन सिह	श्री प्रद्युम्न सिंह
3.	64	31	श्री प्रद्युमन सिह	श्री प्रद्युम्न सिंह
4.	65	12	श्री प्रद्युमन सिह	श्री प्रद्युम्न सिंह
5.	68	6	श्री मोहमम्द	श्री मोहम्मद
6.	98	16	(भोपागढ़)	(भोपालगढ़)
7.	175	26	श्री गुलाबसिह शक्तावत	श्री गुलाबसिंह
8.	232	फोलियो	धन्यवाद प्र. रप वा.वि.	धन्यवाद प्र. पर. वा.वि.
9.	236	7	वैद	बैंद
10.	258	5	वैद	बैंद
11.	321	29	मिनियम	मिनिमम